जानलेवा कफ सिरप

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से दस से ज्यादा बच्चों की मौतों के बाद जहां तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल ने कोल्ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से छह राज्यों की 19 दवा बनाने वाली यूनिटों की जांच शुरू हो गयी है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत पिछले एक महीने के दौरान हुई है, जबकि राजस्थान में पिछले दस दिन में ये मौतें हुई हैं. आशंका है कि कफ सिरप के सेवन से बच्चों की किडनी फेल हो गयी. सिर्फ यही नहीं कि तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ के सैंपल की जांच में खतरनाक डाइएथिलीन ग्लाइकॉल तय सीमा से अधिक मिला है, बल्कि यह सिरप भी तमिलनाडु में तैयार बताया जाता है. एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूड्स में इस्तेमाल होने वाला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल निगलने पर किडनी फेल होने का खतरा होता है. मध्य प्रदेश में इसी कफ सिरप की आपूर्ति हुई थी. दरअसल कफ सिरप को पतला और मीठा करने के लिए उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, पर सिरप की मात्रा बढ़ाने के लिए कई कंपनियां इस सस्ते पदार्थ को तय सीमा से ज्यादा मात्रा में मिलाती हैं, जिससे ये नुकसानदायक हो जाती है. पता यह चला है कि 2023 में केंद्रीय स्तर पर सभी राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया था कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड्रिफ नहीं दी जाये. पर इसका उल्लंघन किया गया. मध्य प्रदेश में मारे गये सात बच्चे चार साल या उससे कम उम्र के थे. मध्य प्रदेश पुलिस ने छिंदवाड़ा के एक बाल रोग विशेषज्ञ को बच्चों को कोल्ड्रिफ दिये जाने के कारण गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि कफ सिरप के सेवन से 2019 में जम्मू क्षेत्र में ग्यारह बच्चों की मौत हुई थी, जबकि 2022 में गाम्बिया में भारत में तैयार कफ सिरप के सेवन से 66 बच्चों की मौत हो गयी थी. ऐसे में, कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों पर जहां सख्त निगरानी की जरूरत है, वहीं छोटे बच्चों को सिरप देने के मामले में सतर्कता बरते जाने की भी आवश्यकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने तथा बच्चों में खांसी की दवा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की सलाह दी है. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दो साल से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप कदापि नहीं दिया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से छोटे बच्चों की मौत के बाद संदिग्ध दवा पर प्रतिबंध लगाने और दवा कंपनियों की जांच के फैसले स्वागतयोग्य हैं. दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब दोषी दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है.

गाजा में शांति की जरूरी पहल

अनिल त्रिगुणायत
पूर्व राजनयिक
amb.trigunayat@gmail.com

पिछले करीब दो साल से अशांत गाजा में ट्रंप की योजना के कारण फिलहाल शांति की उम्मीद बनी है. इस्राइल और हमास, दोनों भले पूरी तरह लड़ाई खत्म करने के इच्छुक न हों, पर अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव फिलहाल काम कर रहा है. इसी का नतीजा है कि इस्राइल ने गाजा पर हमले रोकने पर सहमति जतायी है, तो हमास भी इस्राइली बंधकों को लौटाने पर राजी हुआ है. हालांकि इस्राइल-फिलिस्तीन के विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने की बात तो दूर, ट्रंप की योजना में स्वतंत्र फिलिस्तीन को मान्यता देने के मुद्दे पर भी अस्पष्टता है, पर युद्धविध्वस्त पृथ्वी में गाजा में शांति बहाली को उम्मीद की तरह देखा जाना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाली के उद्देश्य से हाल ही में जिस 20 सूत्रीय योजना की घोषणा की थी, उस दिशा में प्रगति दिख रही है. ट्रंप की इस योजना में जहां इस्राइल को गाजा में सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने के लिए कहा गया है, वहीं हमास को इस्राइली बंधकों को रिहा करना है, लेकिन इस योजना में गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका भविष्य में नहीं होगी. अच्छी बात यह है कि हमास ने, अनिच्छा और संदेह के बावजूद, इस योजना पर सहमति जतायी है. दरअसल ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हमास ने बहत्तर घंटे में यानी रविवार शाम छह बजे तक इस योजना पर सहमति नहीं जतायी, तो अमेरिका इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा. उनका यह भी कहना था कि हमास को आखिरी मौका दिया जा रहा है.

ट्रंप की इस पहल की प्रशंसा हो रही है, तो इसे समझा जा सकता है. दो साल से जारी इस संघर्ष में गाजा में लगभग 70,000 फिलिस्तीनी मारे गये हैं. इस्राइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट का शासन संभाल रहे फिलिस्तीनी अधिकारियों ने ट्रंप की इस योजना को गंभीर और दृढ़ निश्चय वाला बताया है. यूरोपीय देशों के साथ-साथ भारत ने भी इस योजना का स्वागत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह योजना फिलिस्तीनी और इस्राइली लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए लंबे समय तक चलने वाली स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक कारगर रास्ता प्रदान करती है. बहरहाल, याद रखना चाहिए कि भारत ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जो फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण हल-यानी द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है. उससे पहले भारत ने गाजा के हालात पर भी चिंता जतायी थी.

इन सबके बावजूद मौजूदा घटनाक्रम को पश्चिम एशिया में एक छोटी-सी शुरुआत ही मानना चाहिए. एक तो इसलिए कि दोनों प्रमुख खिलाड़ी- इस्राइल और हमास आधे-अधूरे मन से ट्रंप की योजना के साथ हैं. ट्रंप द्वारा इस्राइल को हमला रोक देने के लिए कहने के बावजूद इस्राइली सैनिकों ने हवाई हमला कर जिस तरह 60 से अधिक लोगों को मारा, उसी से लगता है कि इस शांति योजना पर फौरी तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव ही काम कर रहा है. फिर अभी मुख्य फोकस गाजा पर है, स्वतंत्र फिलिस्तीन का मुद्दा नेपथ्य में चला गया है.

इस मामले में संदेह का एक दूसरा कारण यह है कि आगे के चरणों में भी फिलिस्तीन को किसी तरह का अधिकार देने की बात दिखाई नहीं देती, जबकि असल मुद्दा तो द्विराष्ट्र समाधान का है, लेकिन ट्रंप की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना में इसका कोई स्पष्ट रोडमैप दिखाई नहीं दिखता. इसके बजाय इस योजना में हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा को अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस से चलाने की शर्त शामिल है. योजना के तहत इस्राइल को चरणबद्ध तरीके से गाजा से हटना है, बंधकों की अदला-बदली होनी है और अरब देशों को पुनर्निर्माण का खर्च उठाना है, जबकि बदले में फिलिस्तीन को भविष्य में राज्य का अस्पष्ट वादा किया गया है. ऐसे में, पाकिस्तान और कई अरब राष्ट्रों पर फिलिस्तीन के मुद्दे से धोखा करने के आरोप लग रहे हैं और इसे 'टू स्टेट सॉल्यूशन' की जगह 'टू स्टेट सरेंडर' भी बताया जा रहा है. जाहिर है, इसकी वजह इस्राइल की आक्रामकता के साथ-साथ अमेरिका का रवैया भी है. अमेरिका ने जहां फिलिस्तीनी अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सेदारी करने से रोक दिया, वहीं नेतन्याहू ने स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की धमकी दी है. सीधी-सी बात है, फिलिस्तानियों को विश्वास में लिये बगैर या उन्हें समुचित अधिकार दिये बगैर पश्चिम एशिया में कोई भी पहल अधूरी ही रहेगी. बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इस मुद्दे के हल की कोशिश गंभीरता और सर्वसम्मति के अभाव में विफल हो चुकी है.

जो ट्रंप हाल-हाल तक गाजा के मुद्दे पर नेतन्याहू के साथ खड़े थे, उन्हें अचानक यह पहल क्यों करनी पड़ी? दो तात्कालिक कारणों ने पश्चिम एशिया मुद्दे के हल के लिए ट्रंप पर दबाव बनाया होगा. एक तो इस्राइल की आक्रामकता को देखते हुए पश्चिमी देशों ने जिस तरह फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू की, उससे ट्रंप को लगा होगा कि समाधान की दिशा में सक्रियता दिखानी चाहिए. पिछले महीने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता दी थी. यह एक बड़ा कदम इसलिए था, क्योंकि पहली बार जी-7 की उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी. फिर पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को मान्यता दी. नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों पर नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि वह फिलिस्तान को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय मान्यता को इस्राइल पर हमले के रूप में चित्रित करते हैं.

ट्रंप के अचानक सक्रिय होने का दूसरा बड़ा कारण इस्राइल द्वारा हाल में कतर में हमास के सदस्यों पर किया गया हमला था. इससे ट्रंप नाराज हो गये, क्योंकि कतर अमेरिका का सहयोगी है. ऐसे में, ट्रंप को महसूस हुआ कि पश्चिम एशिया के मामले में अमेरिकी उदासीनता गंभीर साबित हो सकती है. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता भी ट्रंप के लिए चेतावनी की तरह है कि अगर इस्राइल की मनमानी इसी तरह जारी रही, तो मुस्लिम देशों की एकजुटता एक अलग किस्म की चुनौती खड़ी कर सकती है. इसीलिए ट्रंप पश्चिम एशिया की समस्या के हल के लिए आनन-फानन में 20 सूत्रीय योजना लेकर आये, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप का पूरा जोर फिलहाल इस्राइली बंधकों की रिहाई पर ही है. हालांकि ट्रंप को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने फिलिस्तीन-इस्राइल का विवाद सुलझाने की दिशा में कई बार कोशिश की. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह पश्चिमी तट को इस्राइल द्वारा हथियाने नहीं देंगे, जबकि नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी लंबे समय से पश्चिमी तट के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करना ही असंभव हो जाये. अभी अगर इस्राइली सैनिक गोलीबारी बंद करने पर सहमत हुए हैं, तो उसके पीछे ट्रंप की सक्रियता ही है, लेकिन उनकी इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना के आगे के चरणों के बारे में जब तक स्पष्टता नहीं आयेगी, तब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

खाद्य प्रसंस्करण : स्थानीय क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन तक

चिराग पासवान
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
delhi@prabhatkhabar.in

वह समय गया, जब संभावनाएं कमजोर कड़ियों के कारण खो जाती थीं. अब स्थानीय उद्यम वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं. जो शुरुआत मुजफ्फरपुर में एक स्थानीय क्रांति के रूप में हुई थी, वह अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है.

सच्चा विकास सामूहिक प्रयास एवं सामंजस्य से संभव होता है. मुजफ्फरपुर के व्यस्त बाजारों में यह सिद्धांत रोज साकार होता है. यहां महिलाएं लगन और दक्षता से मसालेदार अचार तैयार करती हैं, युवा उद्यमी मखाना खीर तथा भुना और स्वादयुक्त मखाना सलीके से सजाते हैं. किसान गर्व से देखते हैं कि उनके आम पटना से दुबई तक खाने की मेजों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं. इसका सजीव उदाहरण मैंने वर्ल्ड फूड इंडिया, 2025 के उद्घाटन के मौके पर देखा, जब आधुनिक खाद्य-प्रसंस्करण तकनीकों वाले पैवेलियन में भागलपुर की स्वीटी कुमारी प्रधानमंत्री के सामने आत्मविश्वास से खड़ी थीं.

उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमइ) की मदद से उन्होंने सत्तू और जीआइ-टैग प्राप्त कतरनी चूड़ा को आधुनिक ब्रांड में बदल दिया. यह मेरे लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और एक बिहारी होने के नाते, गर्व का क्षण था. बिहार में सदैव ही आर्थिक विकास के मूलभूत घटक विद्यमान रहे हैं. दशकों तक इन संभावनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक पुल अनुपस्थित रहे, लेकिन जब हमने ये पुल बनाये, तो पूरा आर्थिक ताना-बाना बदल गया. यह सत्य समस्त भारत के लिए प्रासंगिक है. वर्षों तक हम केवल कच्चा माल निर्यात करते रहे और वही माल ब्रांडेड उत्पाद के रूप में वापस आता रहा. परिणामस्वरूप, फसलोपरांत नुकसान की दर उच्च रही, आय अल्प रही, मजबूरी में बिक्री होती रही और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र में भी स्थानीय रोजगार का अभाव रहा. प्रश्न यह था कि क्या स्रोत पर ही मूल्यवर्धन किया जा सकता है, ताकि लोग पलायन किये बिना व्यवसाय स्थापित कर सकें? इस प्रश्न का उत्तर हमें 2020 में मिला. कोविड-19 महामारी में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रेखांकित किया.

इस दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय स्तर पर ठोस परिणाम दिये हैं. जून 2025 तक 1.44 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के तहत मंजूरी दी जा चुकी है और 1.11 लाख से अधिक लोगों को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया, जिससे कुशल स्थानीय कार्यबल तैयार हुआ है. इस तस्वीर में बिहार सबसे अलग और प्रेरक रूप से उभरा है, क्योंकि देश में सबसे अधिक स्वीकृत इकाइयां यहीं हैं. जून, 2025 तक बिहार में पीएमएफएमइ के अंतर्गत 25,000 से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मदद प्राप्त हुई. इसने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को प्रोत्साहित किया और प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से 78,000 से अधिक नये रोजगार सृजित किये. 'बिहार' को ब्रांड के रूप में गढ़ने की दिशा में केंद्र ने बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति की जीविका पहल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु 1.18 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. सतत विकास के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने हाल में पटना में पीएमएफएमइ योजना के तहत एक क्षमता निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया. यह उद्यमियों को उन्नत तकनीकी ज्ञान, गुणवत्ता मानक और बाजार-तैयार कौशल से लैस करता है.

बिहार की पीएमएफएमइ कहानी में महिलाएं केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं. राज्य में 8,953 महिला-नेतृत्व वाली इकाइयों को ऋण मिला है और 24,924 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्याओं को 90.12 करोड़ की बीज पूंजी दी गयी है. यह सहयोग महिलाओं को मखाना, सत्तू, अचार और मसालों को रिटेल-तैयार उत्पादों में बदलने में मदद कर रहा है. इससे महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयां बढ़ रही हैं, परिवार की आय बढ़ रही है और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएं सशक्त हो रही हैं. दरभंगा की पूनम टेकरीवाल इसकी मिसाल हैं. पीएमएफएमइ के जरिये उन्होंने अपनी छोटी इकाई को 30 लोगों की टीम वाला मखाना ब्रांड बना दिया.

वित्त, अनुपालन और क्षमता का मजबूत आधार तैयार होने के बाद हमारा ध्यान मजबूत बाजार कड़ियां बनाने पर केंद्रित हुआ. इस जरूरत ने हमें मई, 2025 में पटना में पहली बार इंटरनेशनल बायर-सेलर मीट (आइबीएसएम) आयोजित करने के लिए प्रेरित किया. इसमें 20 देशों के 70 अंतरराष्ट्रीय खरीदार बिहार पहुंचे और स्थानीय उद्यमियों से 500 से अधिक संरचित व्यापार बैठकों में मिले. इसके परिणाम तुरंत दिखाई पड़े, जिनमें बिहार के चावल, दाल, मसाले, फल, सब्जियों और मखाना के लिए सहमति पत्र और खरीद प्रतिबद्धताएं शामिल थीं. मिथिला मखाना, मुजफ्फरपुर लीची, आम और शहद-के इर्द-गिर्द सबसे संभावनाशील परियोजनाओं की पहचान की, बैंकों ने जोखिम-रहित प्रस्ताव देखे, उद्यमियों को समय पर प्रशिक्षण और तकनीकी मदद प्राप्त हुई. पीएमएफएमइ का अनुभव आत्मनिर्भर भारत का व्यावहारिक उदाहरण है. जब जिले अपनी उपज का प्रसंस्करण करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा बढ़ती है, क्योंकि बर्बादी घटती है, आय और रोजगार बढ़ते हैं, क्योंकि बेहतर मूल्य मिलते हैं, पूरे साल उत्पादन चलता है और निर्यात और भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है, जो शुरुआत मुजफ्फरपुर में एक स्थानीय क्रांति के रूप में हुई थी, वह अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है.

देश दुनिया

कुपोषण से जूझते बच्चों के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत

The Daily Star

शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में सफल होने के बावजूद बांग्लादेश बाल कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पा रहा है, जो चिंताजनक है. देश में पांच वर्ष से कम आयु के लगभग दो-तिहाई बच्चे खाद्य गरीबी, जबकि पांच में से एक बच्चा अत्यधिक खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है. इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध, अंडे, डेयरी, अनाज व फलियां, मांस व मछली, और विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं. परिणामस्वरूप, देश के 24 प्रतिशत बच्चे बौनेपन (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) से जूझ रहे हैं, 11 प्रतिशत बच्चों का वजन लंबाई के हिसाब से कम है और 22 प्रतिशत उम्र के हिसाब से कम वजन वाले हैं. बढ़ती खाद्य कीमतें जहां अपने परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की लोगों की क्षमता को सीमित कर रही हैं, वहीं कम उम्र में विवाह कुपोषण का एक और प्रमुख कारण बना हुआ है. दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में बाल विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है. किशोर माताएं, जो अधिकांशतः निम्न आय वाले परिवारों से होती हैं और अक्सर स्वयं रक्त की कमी और कुपोषण से पीड़ित होती हैं, कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिनके मस्तिष्क का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है. हालांकि कुपोषण के मूल कारणों- जैसे गरीबी, शिक्षा का अभाव और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा- को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किये गये हैं, परंतु ये प्रयास मुख्यतः जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित रहे हैं. विशेषज्ञ अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कार्यक्रमों को बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं. यह अच्छी बात है कि सरकार ने 150 गरीबी ग्रस्त उप जिलों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल भोजन कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. यहां सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता न हो.

बोधि वृक्ष

आत्म ज्ञान और अज्ञानता

आत्म ज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है. ज्ञान प्राप्ति तो असीमित अज्ञानता को छूना है. हर किसी की अज्ञानता की कोई न कोई सीमा होती है. पर आत्म ज्ञानी व्यक्ति की अज्ञानता असीमित होती है, वह हर बंधन से मुक्त होती है. जब जिंदगी सीमित तरीकों से चलती है, तो हर चीज बिल्कुल साफ मालूम पड़ती है. जब आपकी सीमा से परे की चीजें घटित होने लगती हैं, तब कुछ भी स्पष्ट नहीं रह जाता. आप में से जो लोग किसी खास मार्ग पर हैं- वैसे मार्ग शब्द एक धोखा है, क्योंकि मार्ग से यह उम्मीद की जाती है कि वह आपको कहीं न कहीं लेकर जायेगा- परंतु जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप और ज्यादा भटका हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप खुशी-खुशी खोये हुए हों. परंतु खोये हुए तो हैं. जब आप बिल्कुल भटक जाते हैं और आपको कहीं भी पहुंचने की कोई आस नजर नहीं आती, तो समझिए, उद्देश्य पूरा हुआ. आप खोये हुए तभी रह सकते हैं, जब आप कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हों. जब आप समझ जाते हैं कि आप पूरी तरह और पूरी निराशा के साथ भटक गये हैं, और जब कुछ पाने की आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो आप सही मायनों में बिल्कुल ठीक होते हैं. जब आपकी अज्ञानता सभी सीमाएं पार कर लेती हैं और आप पूरी तरह से अज्ञानी बन जाते हैं, तब जानिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं. पूर्ण रूप से अज्ञानी बनने का मतलब है आप खाली हो गये हैं और खालीपन ही वास्तव में अज्ञानता है. यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे लगा हुआ है, तो यह जान जाइए कि उसकी इस तलाश का कोई अंत नहीं है, यानी यह प्रक्रिया अंतहीन है. हालात कितने भी सुंदर क्यों न हों, जिस पल आपको लगता है कि आपकी तलाश पूरी हो गयी, उसी पल आप स्वयं को अज्ञानता की एक खास अवस्था में जकड़ लेते हैं. जब आप जान लेते हैं कि हर एक चोटी एक आधार है अगली चोटी पर पहुंचने के लिए और अगली चोटी भी कोई मंजिल नहीं है, तो आपका एक ही लक्ष्य हो जाता है और वह है परम विस्मृति.

-सद्गुरु जग्गी वासुदेव

प्रबंध सूत्र

तकनीक बदली, स्वभाव वही

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

कुमार साहब रिटायर हो गये हैं. उठते ही सुबह लग जाते हैं तमाम व्हाट्सअप समूहों में. रिश्तेदारों के समूह में. उन्हें बताना कि उनका बेटा पूरे कुटुंब में सबसे होशियार है, वह अमेरिका में सेट्ल हो रहा है. किसी को बताना कि उन्होंने नया फ्लैट लिया है दो करोड़ का. किसी समूह में बताना कि उनके शेयरों ने छह महीनों में ही दोगुना रिटर्न दे दिया है. तुलसीदास लिख गये हैं, 'काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु, भजहिं जेहि संत.'

यानी काम, क्रोध, मद, लोभ सब नरक के रास्ते हैं, इनसे दूर जाकर राम के नाम का भजन करे, वही संत है. पहले रिटायरमेंट के बाद आदमी भजन-पूजन कर लेता था, पर अब मोबाइल ने सारा समय ले लिया है. काम, क्रोध, मद, लोभ-सब मोबाइल के जरिये साधा जा रहा है. इंसान ने तकनीक को भी लोभ, मद के रास्ते में लगा दिया है.

तकनीक बदलती रहती है, पर मनुष्य का स्वभाव, उसका लालच, भय, प्रेम और अहंकार कम ही बदलता है. हम ऐसे युग में हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल क्रांति और इंटरनेट के महासागर में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इंसान का मूल स्वभाव पहले जैसा ही है. पुराने जमाने में चिट्ठी लिखने का सलीका था, अब व्हाट्सएप के 'सीन' और 'टाइपिंग' से भावनाएं तय होती हैं. पहले हम रिश्तों को समय देकर निभाते थे, आज नोटिफिकेशन देखकर निभाते हैं. तकनीक ने स्पीड दी है, पर गहराई छीन ली है. लोग वही हैं, जो दिखावा करना चाहते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखना चाहते हैं, जो अपने अहंकार में सीमित रहते हैं. बस उनके हाथ में कलम की जगह की-बोर्ड है और घर के आंगन की जगह वर्चुअल चैट ग्रुप. पहले लोग अपनी प्रतिष्ठा गांव की पंचायत में ढूंढते थे, आज प्रतिष्ठा सोशल मीडिया के 'लाइक' में ढूंढी जाती है. तकनीक बस उस तलाश का नया माध्यम भर है. हाथों में स्मार्टफोन आने पर जिज्ञासा बढ़ी, पर सहानुभूति घट गयी. अब 'ट्रेंड' इंसान तय नहीं करता, तकनीक करती है. आज 'काम' सोशल मीडिया की लालसाओं में, 'लोभ' शेयर मार्केट की चकाचौंध में और 'मद' फॉलोअर्स की गिनती में है. तकनीक की रफ्तार ने इंसान को तेज तो कर दिया, पर समझदार नहीं. आज भी इंसान वही है, जो पहले था- वही दोष, वही आकर्षण, वही भावनाएं. फर्क इतना है कि पहले वह बैलगाड़ी चला रहा था, अब इलेक्ट्रिक कार. पहले वह चूल्हे के धुएं में जीवन ढूंढता था, अब वाई-फाई के नेटवर्क में.

युग बदलते हैं, साधन बदलते हैं, पर मनुष्य की प्रवृत्ति वैसी ही रहती है. थोड़ा रुककर खुद से पूछना बनता है कि दिन भर मोबाइल पर जो मैं कर रहा हूं, उसमें से कितना काम, क्रोध, लोभ, मद की परिधि से बाहर है.

आपके पत्र

लापरवाही से बढ़ती दुर्घटनाएं

आजकल 10वीं-12वीं में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी बाइक या स्कूटी से विद्यालय जा रहे हैं. इसके लिए माता-पिता दोषी हैं. अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना कानूनी रूप से अवैध तो है ही, यह चालक और सड़क पर चलने वालों के लिए भी असुरक्षित है. किशोरों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं होने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. जब तक किशोर कानूनी रूप से वैध तथा सड़क पर वाहन चलाने के लिए परिपक्व न हो जाएं, उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

प्रेम प्रकाश शुक्ला, डालटनगंज

सोशल मीडिया से फैलते भ्रम

सोशल मीडिया पर अधिकांश समय बिताने के कारण आज युवा पीढ़ी पर इसका गहरा प्रभाव नजर आ रहा है. इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक जैसे मंचों पर मौजूद हर सूचना में तथ्य नहीं होता. जटिल मुद्दों की आधी-अधूरी समझ से ही आंदोलन भड़कते हैं. सोशल मीडिया बदलाव की चिंगारी तो देता है, पर नयी व्यवस्था का खाका खींचने की योजना गहरी राजनीतिक समझ और संस्थागत प्रयासों की मांग करती है. ऐसे में सोशल मीडिया को सकारात्मक, सही और तथ्यात्मक सूचनाएं ही परोसनी चाहिए.

अमृतलाल मारू, इंदौर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

अभिव्यक्ति

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025

विशेष • वीके मल्होत्रा जी की उपलब्धियों से हम प्रेरणा पाते रहेंगे

भाजपा परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक को खोया

स्मरण

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

वे हमेशा लोगों की मुश्किलों में साथ खड़े रहे

उनकी पहचान ऐसे व्यक्तित्व की रही, जो हमेशा लोगों की मुश्किलों में साथ खड़े रहे। जहां भी मदद की जरूरत पड़ी, वहां आगे बढ़कर योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी दायित्वों से पीछे नहीं हटे।

कुछ दिन पहले, भाजपा परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा जी को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कीं। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा के मूल संस्कार क्या हैं। विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन, स्वयं से ऊपर सेवा भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही।

वीके मल्होत्रा जी के परिवार ने विभाजन का दौर झेला। उस आघात और विस्थापन ने उन्हें कड़वा या आत्मकेंद्रित नहीं बनाया। इसके बजाय, उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा में राष्ट्रसेवा का रास्ता नजर आया। बंटवारे का समय चुनौतीपूर्ण था। मल्होत्रा जी ने सामाजिक कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने हजारों विस्थापित परिवारों का जीवन संवारने और उन्हें फिर से खड़े होने में मदद की। यही जनसंघ की प्रेरणा थी। उन दिनों उनके साथी मदनलाल खुराना जी और केदारनाथ साहनी जी भी सेवा कार्यों में शामिल होते थे। उनकी सेवा को आज भी दिल्ली के लोग याद करते हैं।

1967 के लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तब अपराजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले थे। इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक कम चर्चित चुनाव भी हुआ। वो था, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का पहला चुनाव। उसमें जनसंघ ने शानदार जीत दर्ज की। आडवाणी जी काउंसिल के चेयरमैन बने और मल्होत्रा जी को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की जिम्मेदारी दी गई, जो मुख्यमंत्री के लगभग बराबर का पद था। तब उनकी उम्र 36 वर्ष थी। उन्होंने अपने कार्यकाल को दिल्ली की जरूरतों और लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया।

इस जिम्मेदारी ने मल्होत्रा जी का दिल्ली से जुड़ाव और मजबूत कर दिया। जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर मल्होत्रा जी सक्रिय रूप से जनता के साथ खड़े होते और उनकी आवाज बुलंद करते। आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। दिल्ली की सड़कों पर जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब वे शांति और सद्भावना की आवाज बनकर सिख समुदाय के साथ मजबूती से खड़े रहे। उनका मानना था कि राजनीति, चुनावी सफलता के अलावा सिद्धांतों, मूल्यों और लोगों की रक्षा के लिए भी है, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

अपने लंबे सेवाकाल में मल्होत्रा जी ने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, राज्य विधानसभा में भी पहुंचे और देश की संसद में भी मौजूदगी दर्ज कराई। 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ उनकी जीत समर्थकों और विरोधियों के बीच आज भी याद की जाती है। उन्होंने पॉजिटिव कैंपेन चलाया और 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की। ये जीत मल्होत्रा जी की जमीन पर मजबूत पकड़ की वजह से मिली थी। कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध बनाकर रखने और मतदाताओं के मन की थाह लेने में वो माहिर थे।

मल्होत्रा जी संसद में सटीक तैयारी के साथ अपनी बात रखते थे। वो पूरी रिसर्च करके आते थे और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते थे। यूपीए-1 के दौरान विपक्ष के उपनेता के रूप में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए एक मूल्यवान सबक की तरह है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार का प्रभावी ढंग से विरोध किया। उन दिनों मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अक्सर मल्होत्रा जी से बातचीत होती थी। वो हमेशा गुजरात की विकास यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे।

राजनीति, वीके मल्होत्रा जी के व्यक्तित्व का केवल एक पहलू थी। वो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद भी थे। उनके परिवार से मुझे पता चला कि उन्होंने स्कूल में डबल प्रमोशन हासिल किया। उन्होंने मैट्रिक और ग्रेजुएशन निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली। उनकी हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषणों का हिंदी अनुवाद प्रायः वही करते थे।

उन्हें नई संस्थाएं और नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी जाना जाता है। वे आरएसएस से जुड़ी कई संस्थाओं के संस्थापक और संरक्षक रहे। उनके प्रयासों से अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ और मार्गदर्शन मिला। इन संस्थाओं के माध्यम से कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन में बनी संस्थाएं प्रतिभा और सेवा की पाठशालाएं बनीं। उन्होंने एक ऐसे समाज का विजन दिया, जो आत्मनिर्भर हो और मूल्यों पर टिका हो।

वीके मल्होत्रा जी को आज लोग उनके द्वारा संभाले गए पदों के साथ ही उनकी संवेदनशीलता के लिए भी याद कर रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्तित्व की रही, जो हमेशा लोगों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। जहां भी मदद की जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटे। वे आदर्श पार्टी कार्यकर्ता थे, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे जिससे हमारे कार्यकर्ताओं या विचारधारा को ठेस पहुंचे।

कुछ दिन पहले, मैं दिल्ली भाजपा के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां मैंने स्नेहपूर्वक वीके मल्होत्रा जी को याद किया था। इस वर्ष तीन दशक बाद जब भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो वो बहुत उत्साहित थे। उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिन्हें हम पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और उपलब्धियों से प्रेरणा पाती रहेंगी।

सीनियर सिटीजन

आर्थिक साथी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी जीरो होने से कितना लाभ?

इन तरीकों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा व दवाओं के बजट में 25% तक होगी बचत

रश्मि खुराना
हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट

यश खंडेलवाल
सीए, जीएसटी एक्सपर्ट

नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है देश में 75% बुजुर्गों को एक से अधिक पुरानी बीमारियां हैं। वहीं स्वास्थ्य बीमा सिर्फ 18% के पास है। इसकी बड़ी वजह पॉलिसी प्रीमियम महंगा होना भी है, लेकिन अब इस पर 18% जीएसटी खत्म हो गया है। जीवनरक्षक दवाएं टैक्स फ्री, शुगर व बीपी दवाइयों पर 13 से 7% की राहत मिली हैं। इससे स्वास्थ्य बीमा और मेडिसिन बजट 25% तक कम हो जाएगा।

3 सवाल व 4 बातों से जानिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितनी राहत

• 20 हजार प्रीमियम तो कितनी बचत होगी?
यदि पहले प्रीमियम 20 हजार रुपए था, तो उस पर 18% के हिसाब से 3600 रु. जीएसटी देना होता था। अब जीएसटी जीरो होने से यह राशि बचेगी।

• घटे हुए जीएसटी का फायदा किसे मिलेगा?
उन्हें फायदा मिलेगा जिनकी पॉलिसी 22 सितंबर या उसके बाद रिन्यू हुई या जो अब नई पॉलिसी लेंगे। पहले चुकाए प्रीमियम पर लाभ नहीं मिलेगा।

• कौन सी बीमा पॉलिसी जीएसटी से मुक्त हैं?
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, री-इंश्योरेंस पॉलिसी जीएसटी मुक्त रहेंगी। हालांकि जीएसटी के नए नियमों से आपकी पॉलिसी के नियम और शर्तें नहीं बदलेंगी।

ये बातें ध्यान रखें, प्रीमियम की राशि 10% तक कम हो जाएगी

- लंबी अवधि की पॉलिसी जैसे 3-5 साल को चुनें, क्योंकि इनमें 5 से 8% तक छूट मिलती है।
- फ्लोटर प्लान लें, इसमें व्यक्तिगत पॉलिसी की तुलना में प्रीमियम 2 से 5% तक घट जाता है।
- को-पेमेंट विकल्प चुनें। इसमें इलाज का एक निश्चित प्रतिशत देना पड़ता है, पर प्रीमियम 5% तक घट जाता।
- सुपर टॉपअप लेना किफायती होता है, क्योंकि इसे बेटे की पॉलिसी के साथ उपयोग कर सकते हैं।

शुगर, बीपी, कैंसर की दवाइयों पर मिली बड़ी राहत

• कौन सी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी कम किया गया है?
शुगर, बीपी की दवाइयां 5% के दायरे में लाई गई हैं। पहले इन पर 12 से 18% तक जीएसटी लग रहा था। जैसे मान लीजिए पहले कोई मेडिसिन 100 रुपए में मिल रही थी तो वह अब 87 से 93 रुपए में मिल जाएगी। वहीं चश्मे, उसके लेंस 7% तो एनेस्थीसिया, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर जैसे उपकरण 7% तक सस्ते मिलेंगे।

आपके अनुभव लोग कहते हैं चीजें याद नहीं रहतीं

66 की उम्र में मेमोरी ऐसी कि 7 हजार से ज्यादा लोगों के जन्मदिन याद हैं...

लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में हम चीजें भूलने लगते हैं, लेकिन इंदौर के 66 वर्ष के डॉ. अरविंद जैन (रंजन सर) को देखिए, इस उम्र में भी इनकी मेमोरी इतनी तेज कि 7 हजार से ज्यादा लोगों के जन्मदिन याद हैं। कोई व्यक्ति इन्हें मिले तो वे उनकी जन्म तारीख के साथ अभिवादन करते हैं। यह सुनकर संबंधित व्यक्ति चौंक जाता है। अभिवादन का तरीका भी खास। नमस्कार की जगह 'जय भारत' बोलते हैं। पढ़ने का ऐसा जुनून कि रोज अखबार, मैगजीन व किताबों के 30-40 पेज पढ़ते हैं।

रोज करते हैं 3 से 4 घंटे वर्कआउट

• शेड्यूल ऐसा कि रोजाना 3 से 4 घंटे तक वर्कआउट करते हैं। सुबह 5 बजे ब्रिस्क वॉक, रनिंग, बैक रनिंग के बाद 5 किमी साइकिल चलाते हैं। इसके बाद डेढ़ घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं।

सप्ताह का स्वास्थ्य मंत्र

इससे फेफड़े मजबूत रहेंगे

गुब्बारे फुलाना फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए गहरी सांस लें, फिर मुंह से गुब्बारे में धीरे-धीरे हवा भरें। इसे रोज 5-10 बार दोहराएं। यह आपके डायाफ्रॉम (छाती के हिस्से) की क्षमता को बढ़ाता है। इससे फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना आसान होता है। गुब्बारे फुलाते वक्त ज्यादा थकान होने पर रुक जाएं।

अपने ऐसे अनुभव, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, srcitizen@dbcorp.in पर भेजें। चुनिंदा पत्र प्रकाशित करेंगे।

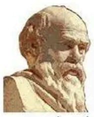

संतोष स्वाभाविक दौलत है, जबकि विलासिता कृत्रिम गरीबी।

- सुकरात, यूनानी दार्शनिक

खुशी की गाइड

पर्वों से मिलने वाली खुशी के मायने

डॉ. रितु पाण्डेय शर्मा, reetupost@yahoo.com

त्योहार उत्सव और मेले केवल सांस्कृतिक परंपराएं ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जब लोग साथ मिलकर गीत गाते हैं, नृत्य करते और उत्सव मनाते हैं, तो उनमें जुड़ाव और अपनेपन की भावना बढ़ती है। यह प्रक्रिया अकेलेपन, तनाव और अवसाद की भावना को कम करने में सहायक सिद्ध होती है।

- आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार, सामूहिक गतिविधियों के दौरान मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। जब हम किसी को मुस्कराते देखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के विशेष न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, मानो हम स्वयं मुस्करा रहे हों। यही कारण है कि मुस्कान संक्रामक होती है। वैज्ञानिक इसे ब्रेन मिररिंग कहते हैं।
- समूह में संगीत और नृत्य करना एंडॉर्फिन्स (खुशी के हार्मोन) को बढ़ाता है, लय और समन्वय का आनंद लेते हुए मन और शरीर एक प्रवाह में जुड़ जाते हैं, जिससे मुक्ति, शांति और पूर्णता का एहसास होता है। साथ ही यह सामाजिक बंधन को मजबूत करता है और व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वह अकेला नहीं है।
- भारतीय परंपरा भी कहती है मिलकर चलो, मिलकर बोलो। योगसूत्र में भी मुदिता (दूसरों की खुशी में खुशी) को साधना का मार्ग बताया गया है। ▪ 1 मिनट रीड

सकारात्मक संकल्प

सुबह में सुकून हो...

विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह-सुबह बहुत सारे फैसले नहीं लेने चाहिए। सुबह एक साथ बहुत सारी चीजें सोचने से दिमागी थकान हो सकती है, जिससे पूरे दिन की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सम्भव हो तो दिन की शुरुआत न्यूनतम विचारों से करें। बेहतर होगा अगर ध्यान, प्राणायाम, टहलने आदि को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्वयं को एक व्यस्त दिन के लिए इत्मीनान से तैयार करें। फैसलों की जगह प्रतिबद्धताओं पर जोर दें। आत्मचिंतन की शैली अपनाएं। बीते दिन पर विचार करें और नए दिन की योजनाएं बनाएं, लेकिन स्वयं पर बोझ ना डालें। दिन की एक बेहतर शुरुआत करें।

सकारात्मक संकल्प लें कि दिन की शुरुआत सुकून, धैर्य और आत्मचिंतन से करेंगे। ▪ 1 मिनट रीड

उम्मीद के 7 मिनट

जहां धैर्य खोया, वहीं तनाव को आमंत्रित किया

जीवन-सूत्र

स्वामी ज्ञानवत्सल
प्रेरक वक्ता और विचारक

तनाव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह एक पैकेज डील है। हर परियोजना तनाव के साथ आती है, पैसा कमाना तनाव के साथ आता है, कोई भी रिश्ता शुरू होता है उसमें तनाव का एक बीज होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह कि जीवन है तो तनाव भी होगा ही। लेकिन हमें इसे प्रबंधित करना होगा। हर सुबह आपको तनाव का अच्छी तरह से आकलन करना होगा, उससे अच्छी तरह से निपटना होगा और अंतिम परिणाम को प्राप्त करना होगा। तनाव की तरह असफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं, बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, गिरना भी जीवन का एक हिस्सा है।

सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की छोटी उम्र में अपनी अंतरराष्ट्रीय पारी शुरू की थी। कराची में पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच था और वे इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। 95 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से हो रही गेंदबाजी ने उन्हें कई बार परेशान किया। वे 15 रन पर आउट हो गए। पैवेलियन लौटते समय उनके दिमाग में यह विचार था कि यह मेरी पहली और आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारी है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। रवि शास्त्री उन्हें मिले। सचिन को परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है? सचिन ने कहा, मैं नहीं खेलना चाहता, यह मेरे बस की बात नहीं।

शास्त्री उनके साथ बैठे और कहा, याद रखो कि तुम्हें तनाव-मुक्त रहना है। मैच में तुम एक स्कूली लड़के की तरह खेल रहे थे, जबकि यह एक अंतरराष्ट्रीय मैच है। स्कूली लड़का हर गेंद पर शॉट मारना चाहता है, लेकिन यहां तुम विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हो। तुम्हें उनकी क्षमता का सम्मान करना होगा, कुछ गेंदों को छोड़ना होगा। पहले 30 मिनट बस मैदान पर नजरें गड़ाए रखो, लाइन और लेंथ का उचित निर्णय लो, स्कोरबोर्ड मत देखो।

उम्मीद अच्छी है, उस उम्मीद पर काम करना भी अच्छा है, लेकिन जब वांछित परिणाम नहीं आए तो इस बात को याद रखें कि आप हर गेंद पर रन नहीं बना सकते।

शास्त्री के इस सबक ने सचिन की थोड़ा शांत होने में मदद की और फैसलाबाद के दूसरे टेस्ट में वे पहले 30 मिनट तक पिच पर मौजूद रहे। स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं देखा। उन्होंने 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। और इस प्रकार एक महानतम क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई, जो 200 टेस्ट मैचों और 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों तक चला। यह हम सभी के लिए एक सबक है।

हम एक नया कारखाना शुरू करते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, तब हर गेंद पर रन बनाना चाहते हैं। हर ग्राहक जो आपके पास आता है, आपको लगता है कि वह मुझे बड़ा व्यवसाय देने वाला है। उम्मीद अच्छी है, उस उम्मीद पर काम करना भी अच्छा है, लेकिन जब वांछित परिणाम नहीं आए तो इस बात को याद रखें कि आप हर गेंद पर रन नहीं बना सकते। तब आप तनाव को हैंडल करने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात, वहीं टिके रहें। शुरू में स्कोरबोर्ड न देखें। धैर्य न खोएं। क्योंकि जिस क्षण आप धैर्य खोते हैं, तनाव को आमंत्रित कर बैठते हैं। ▪ 2 मिनट रीड

इस जीवन सूत्र को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

संघर्ष की कहानी **यशस्वी जायसवाल,** भारतीय क्रिकेटर

क्रिकेट के लिए घर छोड़ा, टेंट में बितानी पड़ीं रातें; अब टीम इंडिया के उभरते सितारे

यशस्वी जायसवाल (23) भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे हैं। हाल ही में यशस्वी को टाइम मैगजीन ने दुनियाभर के 100 उभरते सितारों की लिस्ट में शामिल किया है। वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। उनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। जानते हैं यशस्वी की संघर्ष से सफलता की कहानी...

यशस्वी जायसवाल 10 साल के रहे होंगे, जब वे क्रिकेट के लिए अपना घर छोड़ कर मुंबई आए थे। यहां परेशानी इतनी थी कि कई बार उनकी मां ने यशस्वी को घर वापस आने को कहा। लेकिन जायसवाल ने अपनी मां से कहा था कि मैं मैदान में ही रहूंगा तो आसान होगा। सुबह उठते ही सामने क्रिकेट दिखता है।

संघर्ष : डेयरी पर काम किया, पैसों के लिए पानी पुरी भी बेची

यशस्वी जब मुंबई आए तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने एक डेयरी पर काम किया। इसके बदले यशस्वी को रहने की जगह मिली। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने आजाद मैदान के पास मालियों के तंबू में रहना शुरू किया। यहां पर कई बार माली ने यशस्वी से डांट-डपट की और बाद में टेंट से निकाल भी दिया। यही नहीं अपने खर्चे के लिए यशस्वी ने पानी पुरी तक भी बेची। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी उन्होंने क्रिकेट का अभ्यास नहीं छोड़ा। यशस्वी दिन में पसीना बहाते और रात में टेंट में भूखे पेट सो जाते थे। इस बीच यशस्वी की क्रिकेट की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें कोच ज्वाला सिंह ने ट्रेनिंग दी। यशस्वी ने 2018-19 में रणजी खेलना शुरू किया। लेकिन कोविड-19 के बाद जब सब कुछ बंद था तब यशस्वी को लगा कि वह कभी भी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे।

सफलता: टेस्ट डेब्यू में शतक आईपीएल में 18 करोड़ में रिटेन

यशस्वी सिर्फ 13 साल के थे, तब उन्हें मुंबई की अंडर-16 टीम में जगह मिली। 2018 में अंडर-19 एशिया कप में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 2023 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 171 रन बनाए। वहीं 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो दोहरे शतक लगाकर इतिहास रच दिया। टेस्ट में उनका औसत लगभग 50.20 है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2020 में ₹2.4 करोड़ में खरीदा। 2023 के आईपीएल सीजन में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से यशस्वी ने 625 रन बनाकर 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' का पुरस्कार जीता। यहीं नहीं इसी साल यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। क्रिकेट के अलावा यशस्वी बूस्ट, जेबीएल इंडिया और फायर बोल्ट जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ▪ 1 मिनट रीड

असाधारण रिकॉर्ड **रॉबर्ट गार्साइड,** एथलीट

5 सालों तक दुनिया दौड़ कर बनाया रिकॉर्ड

ब्रिटिश धावक रॉबर्ट गार्साइड, जिन्हें 'द रनिंगमैन' कहा जाता है। उन्होंने इतिहास रचते हुए दुनिया भर में दौड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 20 अक्टूबर 1997 को भारत के इंडिया गेट से अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की और 13 जून 2003 को इंडिया गेट पर आकर ही समाप्त की। इस दौरान उन्होंने लगभग 35,000 मील यानी 56,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जो 29 देशों और छह महाद्वीपों से होकर गुजरी। इस साहसिक यात्रा में उन्हें जेल में बंद होने, शारीरिक हमले और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गार्साइड ने अपने सफर को पूरी तरह दस्तावेजित किया। उनकी इस दौड़ को गिनीज ने 27 मार्च 2007 को आधिकारिक मान्यता दी। यात्रा के शुरुआती दौर में उनका कहना था कि 'रिकॉर्ड तोड़ना अच्छा लगेगा' लेकिन जैसे-जैसे उनकी यह यात्रा आगे बढ़ी, उनकी दुनिया को देखने की चाहत भी बढ़ने लगी। उनकी यह उपलब्धि न केवल शारीरिक साहस का प्रतीक है, बल्कि आत्मविश्वास का भी उदाहरण है। ▪ 1 मिनट रीड

सीख : रॉबर्ट का कहना है कि इस यात्रा को उन्होंने जीवन के अनुभव के रूप में लिया। उनका मानना है कि असल जीवन वही है, जब आप रुकते नहीं सिर्फ चलते रहते हैं।

सबक वाला पाठ

शक का नतीजा

एक जोड़ा सालों से सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन पति ने पत्नी को किसी के साथ देखा। उसे शक हो गया। दो दिन बाद उसके घर फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उधर से एक पुरुष ने कहा कि वादे के अनुसार आज मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। पति को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का किसी से सम्बंध है।

जब पत्नी कमरे में आई तो व्यक्ति ने उसे जोरों से धक्का दिया। वह सिर के बल गिरी और कोमा में चली गई। तब उसने पत्नी के हाथ में एक पत्र देखा, जो कह रहा था कि वह मां बनने वाली है और बरसों से बिछड़ा उसका डॉक्टर भाई उसका ख्याल रख रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। वही पुरुष सामने था, जो बताने आया था कि उसकी बहन जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है। पर बहुत देर हो चुकी थी।

मोरल ऑफ द स्टोरी : रिश्तों में अनावश्यक कदम उठाने में जल्दबाजी न करें। ▪ 1 मिनट रीड

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 197

अनिश्चितता से बढ़ी चमक

कीमती धातुओं ने वर्ष 2025 में अधिकांश वित्तीय परिसंपत्तियों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष अपनी अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहा है और सोना तथा चांदी लगातार तेजी पर बने हुए हैं। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सोना 48 फीसदी ऊपर है जबकि चांदी ने जनवरी 2025 से अब तक 65 फीसदी का रिटर्न दिया है। दोनों धातुओं ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है। अब त्योहारी मौसम चल रहा है जो पारंपरिक रूप से सोना-चांदी खरीदे जाने का समय है। ऐसे में भारतीय परिवारों की नजर इन दोनों धातुओं पर है। कई लोग सोच रहे होंगे क्या उन्हें इतनी महंगी कीमत पर केवल नाम मात्र की ही खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि यह मानने की वजह मौजूद हैं कि यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है। भले ही इसकी गति का अनुमान लगाना मुश्किल हो। कई कारक ऐसे भी हैं जो विश्व स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। वर्षों से सोने और चांदी को मूल्यवान माना जाता है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये मुद्रास्फीति को मात दे सकती हैं और अनिश्चित आर्थिक माहौल में सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही वजह है कि निवेशकों की रुचि इन धातुओं में बनी रहती है।

कीमतों में इजाफे की एक वजह मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव भी है। खासतौर पर कमजोर अमेरिकी डॉलर अक्सर तेजी को गति देता है क्योंकि दोनों धातुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतें डॉलर में ही निर्धारित होती हैं। एक अन्य कारक है भूराजनीतिक तनाव। कीमती धातुओं का बाजार बहुत नकदीकृत होता है और युद्ध, बाढ़ तथा अन्य उथलपुथल की हालत में भी इन्हें भंडारित करना या लाना-ले जाना बहुत आसान होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ ने आधुनिक समय में इन मूल्यवान धातुओं को रखना और आसान किया है। ईटीएफ ऐसे डिजिटल साधन हैं जो इन धातुओं की कीमतों पर करीबी नजर रखते हैं। भूराजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की वजह हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुल्क वृद्धि की जो जंग छेड़ी है, वह मुद्रास्फीति को भी गति दे सकती है। खासतौर पर अमेरिका में। इससे मुद्रा बाजार में भी अस्थिरता उत्पन्न हुई है, क्योंकि वैश्विक बाजार अमेरिकी शुल्क संबंधी मांगों से पैदा हुई अनिश्चितताओं को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनवरी से अब तक अमेरिकी डॉलर विभिन्न मुद्राओं की एक बास्केट के मुकाबले 10 फीसदी से अधिक गिर चुका है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। वैश्विक स्तर पर डॉलर कमजोर होने के बावजूद रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में इन धातुओं की कीमतें और अधिक बढ़ गई हैं।

भूराजनीतिक तनाव भी ऊंचे स्तर पर है। गाजा में चल रही जंग को इस सप्ताह दो वर्ष हो जाएंगे। रूस- यूक्रेन युद्ध अपने चौथे वर्ष में है। अमेरिका ने वेनेजुएला के जहाजों पर हमला किया है, जिससे मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ तनाव उत्पन्न हो गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध भी शुल्क दरों को लेकर चल रही खींचतान के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं। यह वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता के लिए एक खतरा बन सकता है। इन हालात को मिलाकर देखा जाए तो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि वैश्विक आर्थिक विकास के मजबूत संकेत, शुल्क दरों को लेकर स्पष्टता, और भूराजनीतिक तनावों में कमी नहीं आती। पिछले कुछ वर्षों में कई केंद्रीय बैंकों ने अपने भंडार को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विश्वास लगातार घट रहा है।

व्यापक आर्थिक भूराजनीतिक हालात से इतर निवेशकों को इन धातुओं के औद्योगिक उपयोग पर भी विचार करना चाहिए। चांदी (प्लेटिनम जैसी धातु की तरह जो जनवरी से अब तक 84 फीसदी बढ़ी है) का कई उद्योगों में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा और जल शुद्धीकरण आदि शामिल हैं। उधर सोने का आभूषण उद्योग से बाहर बहुत कम उपयोग है। यह आगे चलकर व्यापारिक प्रवृत्तियों में अंतर उत्पन्न कर सकता है।

भारत और हिंदू विरोध है पाकिस्तान की विचारधारा

पाकिस्तान की सेना एक ऐसी सेना है जो अच्छी बोली लगाने वाले के लिए किराये पर उपलब्ध है। उसने कभी किसी मुस्लिम की सहायता नहीं की। गाजा वासियों और फिलिस्तीनियों की भी नहीं।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

यह पिछले सप्ताह इसी स्तंभ में प्रकाशित आलेख की अगली कड़ी है। उस आलेख में मैंने लिखा था कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते जैसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और भारत के साथ शांति स्थापना से बहुत पहले ही वह इजरायल को मान्यता दे देगा। तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। पाकिस्तान अब वैसी किसी घोषणा के करीब है जिसकी कल्पना पिछले सप्ताह तक शायद ही किसी ने की होगी जब मैंने पिछला आलेख लिखा था।

लगभग किसी पटकथा की तरह डॉनल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गाजा के लिए 20 बिंदुओं वाले समाधान की घोषणा की और संकेत दिया कि फिलिस्तीन का व्यापक प्रश्न इसमें शामिल किया जा सकता है। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ऐसा पहला इस्लामिक देश बन गया जिसने इसका पूरा समर्थन किया। शहबाज शरीफ की लंबी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालिए। यह वैसा ही है जैसे कि कोई छोटा सामंत अपने बादशाह की चापलूसी में लगा हो। इस चापलूसी से बादशाह कितने खुश हुए यह इसी बात से जाहिर है कि उन्होंने फील्ड मार्शल के उन शब्दों को 'सबसे सुंदर' बता दिया जिनमें बादशाह को 'अमन का मसीहा' कहा गया था।

यहां तक कि भारत ने भी समर्थन के पहले पूरा एक दिन इंतजार किया। शायद वह जानना चाहता था कि क्या नेतन्याहू पूरी तरह इस विचार के साथ हैं। यकीनन उस समय तक पाकिस्तानियों ने भी उसका पूरा पाठ किया और यह भी कहा गया होगा कि यह बयान वह नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था। लेकिन वे पीछे नहीं हटे और इस मामूली भ्रम से हमारी इस समझ पर फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान कैसे सोचता है?

पाकिस्तान की बात करें तो उसके संविधान या उसकी विचारधारा के मुताबिक तो वह इस्लामिक राष्ट्र है। परंतु यदि यह सही है तो पाकिस्तानियों ने किसी इस्लामिक उद्देश्य के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उसके पश्चिम में तमाम इस्लामिक देशों को कई खतरों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान उम्मा (मुस्लिम ब्रदरहुड) की बात करता नहीं थकता और अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर वह इस्लामिक सहयोग संगठन में कश्मीर को लेकर ऐसी बातें करता है। परंतु वह इसके लिए कुछ ठोस काम नहीं करता।

ऐसा नहीं है कि उसकी सेनाएं कभी साथी इस्लामिक देशों में लड़ाई के लिए नहीं गईं। परंतु यह कहना गलत होगा कि उन्होंने किसी इस्लामिक उद्देश्य के लिए बलिदान दिया। जॉर्डन में (1970, फिलिस्तीन विद्रोह) और सऊदी अरब (मक्का की घेरेबंदी, 1979) में उसने ऐसा सत्ताधारी शाही परिवारों के बचाव के लिए किया।

अगर आप मुझे यह याद दिलाएं कि योम किप्पुर युद्ध के समय पाकिस्तान ने जॉर्डन में अपनी सेना (खासकर वायु सेना) भेजी थी तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि दोनों देशें के बीच अत्यधिक गहरी और पुरानी सैन्य साझेदारी है जिसकी जड़ें पश्चिमी गठजोड़ में निहित हैं। यह पूरी तरह पारस्परिक मामला था क्योंकि 1971 की जंग में जॉर्डन ने 10 एफ-104 स्टारफाइटर विमान पाकिस्तानी वायु सेना को मजबूत बनाने के लिए दिए थे। इसके जो ब्योरे जॉर्डन की शाही वायु सेना डायरी में दर्ज हैं उन्हें पुष्पिंदर सिंह, रवि रिख्ये और पीटर स्टाइनमैन ने अपनी पुस्तक 'फिजायाः साइकी ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स' में प्रस्तुत किया है।

पहले खाड़ी युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों ने अपनी फौज मुस्लिम देश इराक की रक्षा के लिए नहीं बल्कि कुवैत पर इराक के कब्जे के बाद सऊदी अरब को सद्दाम के कोप से बचाने के लिए भेजा था। वे कभी किसी वैचारिक वजह से नहीं लड़ रहे थे। अफगानिस्तान के उदाहरण से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। पहले अफगान जिहाद में पाकिस्तान सोवियत समर्थक सत्ता के खिलाफ गठबंधन में शामिल था और वे कह सकते थे कि मुजाहिदीन का काम इस्लामिक प्रकृति का था। लेकिन वर्ष2001 में 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिकी सेनाएं वापस आईं तो क्या हुआ? पाकिस्तानी दोबारा उसके साथ हो गए लेकिन इस बार तालिबान के विरुद्ध। अब भला उनसे अधिक इस्लामिक कौन हो सकता है? ऐसी तमाम बातें बोली गईं और दर्ज की गईं जो दोनों पक्षों को सताने वाली हैं। इससे भी हमारा तर्क स्थापित होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के बुश प्रशासन के रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने पाकिस्तान को 'आतंकवाद के विरुद्ध दिग्गज सहयोगी' कहा था। यह बात 26/11 के संदर्भ में कही गई थी।

लब्बोलुआब यह कि पाकिस्तान की सेना और रणनीतिक पूंजी हमेशा किराये पर उपलब्ध है। फिर चाहे उसके बदले नकदी मिले, वस्तुएं मिलें (पश्चिम एशिया के अरब देशों से) या फिर सामरिक और आर्थिक लाभ (अमेरिका से)। अफगानिस्तान के दो अमेरिकी युद्धों में पाकिस्तान ने इस्लामिक मुजाहिदीन और तालिबान के विरुद्ध लड़कर अरबों डॉलर की राशि और सैन्य एवं असैन्य सहायता हासिल की।

कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना किराये पर उपलब्ध है और वह किसी भी उदार बोलीकर्ता के लिए काम कर सकती है फिर चाहे वह मुस्लिम हो या ईसाई। आपने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान, ईरान या उसके सहयोगियों जैसे हूतियों की मदद के लिए आगे आया हो, जब उन्हें इजरायल और उसके अमेरिकी सहयोगियों द्वारा कुचला जाता है। इसके अलावा खाड़ी के अरब देश भी, जो कभी-कभी यमन जैसे मामलों में सीधे लड़ते हैं, ज्यादातर ईरान-विरोधी गठबंधनों में मूक भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुस्लिम की मदद के लिए आगे नहीं आया। चाहे वे फिलिस्तीनी हों या गाजा के निवासी। वह बस कुछ आवाजें उठाता है। अब, वह जिस योजना का इतना अधिक समर्थन कर रहा है, वह नेतन्याहू को प्रसन्न करती है, गाजा को पश्चिमी प्रबंधन के तहत एक बंद कॉलोनी में बदल देती है और दो-राष्ट्र समाधान की अवधारणा को दफन कर देती है। फिलिस्तीन के मुद्दे और यरूशलम को लेकर पाकिस्तान का समर्थन केवल एक दिखावा है। इसमें गंभीरता कम और नाटक अधिक है। पाकिस्तान की सेना कोई इस्लामी सेना नहीं है, और चूंकि सेना ही राज्य की मालिक है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान स्वयं भी कोई इस्लामी राज्य नहीं है।

ऐसे में प्रश्न है कि पाकिस्तान क्या है? अगर हम यहां लिखी बातों पर दोबारा नजर डालें तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि पाकिस्तान का वैचारिक आधार इस्लाम नहीं है। वह भारत-विरोध या हिंदू-विरोध है। भारत को कमजोर करने के लिए वह हर तरह का समझौता करने को तैयार है। फिर चाहे उसे अपनी सेना किराये पर देनी पड़े, ईरान को छोड़ना पड़े या फिलिस्तीन को और या फिर मुस्लिमों को ही क्यों न मारना पड़े? पाकिस्तान के नेता इसे समझते हैं। जब तक भारत-विरोध (हिंदू-विरोध) उनके राष्ट्रवाद की पहचान बना रहेगा, तब तक सत्ता पर सेना का नियंत्रण बना रहेगा, चाहे राजनीतिक दलों के पास बहुमत ही क्यों न हो। यही कारण है कि नवाज़ शरीफ और बेनजीर भुट्टो जैसे नेताओं ने भारत के साथ स्थायी शांति की कोशिश की और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहां तक कि मुशर्रफ़ को भी, जो स्वयं सेना प्रमुख थे, शांति प्रयासों के लिए नहीं बख्शा गया। भारत के साथ स्थायी शांति की कोशिश करने वाले इन सभी नेताओं को सेना ने और अंततः उस विचारधारा से प्रभावित जनमत ने पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ माना।

भारत के शहरों को बचा सकता है वित्त आयोग!

अमित कपूर

शहरों और जलवायु परिवर्तन की कहानियां अक्सर जानी-पहचानी आपदाओं जैसे कि झुलसा देने वाली गर्मी, नदियों में उफान और दम घोंटने वाले धुएं के जरिये बताई जाती हैं। ये सभी आज के दौर की गंभीर चिंताएं हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन गौर करने की एक अहम बात यह भी है कि सभी भारतीय शहर आज एक अधिक चिंताजनक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।

नए जोखिम किसी एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित बदलाव के रूप में सामने आ रहे हैं जो शहरों के विकास के तरीके, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए रखने और पूंजी जुटाने के तरीकों को भी बदल रहे हैं। इनमें से सबसे अहम बदलाव पलायन से जुड़ा है। विश्व बैंक की 2021 की 'ग्राउंडस्वेल' पहल का अनुमान है कि जलवायु संबंधी दबावों के कारण 2050 तक लगभग 21.6 करोड़ लोग अपने ही देश के भीतर विस्थापित होने पर मजबूर हो सकते हैं। यह पलायन अभी से शुरू हो गया है क्योंकि सूखे की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन मुश्किल होता जा रहा है और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग तटीय इलाकों को छोड़कर शहरों के मुख्य हिस्सों में जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट मानती है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों के चलते बने प्रवासियों के लिए शहरी क्षेत्र ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि ये जगहें सुरक्षित हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वहां सेवाएं, रोजगार और जीवन जीने की संभावना है। बिना सोची-समझी योजना के, नए आने वाले लोग उन अस्थायी बस्तियों में रहने को मजबूर हो सकते हैं जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो चीज पलायन के दबाव जैसी लगती है, वह असल में एक अवसर है।

हालांकि, शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी स्थिरता अब और भी ज्यादा जोखिम में है। आईपीसीसी ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ अलग स्तर पर ही झटके नहीं देता है बल्कि यह बेहद जटिल और एक के बाद एक आने वाले खतरे पैदा करता है। बिजली, पानी, परिवहन और संचार के नेटवर्कों से जुड़े शहर यह महसूस कर रहे हैं कि एक विफलता अक्सर दूसरों को भी नीचे खींच लेती है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि जब शहरों में वातानुकूलन तंत्र अचानक काम करना बंद कर दें तब मृत्यु दर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, खासतौर पर उन घरों में जहां गर्मी से बचाव के लिए कोई खास डिजाइन नहीं होता है। इसी तरह, बाढ़ भी अब सिर्फ उफनती नदी या एक तूफान तक ही सीमित नहीं है। अब ऊंचे ज्वार, भारी बारिश और नदियों की बाढ़ एक साथ आती हैं। ये साथ मिलकर ऐसी बाढ़ लाती हैं जो अलग-अलग खतरों से निपटने के लिए बनाए गए सुरक्षा इंतजामों को भी नाकाम कर देती है। असल में, समस्या यह है कि इन जोखिमों को अभी अलग-अलग तरीके से संभाला जा रहा है।

भविष्य में जलवायु अनुकूलन के लिए यह जरूरी है कि हम हर चीज को आपस में जोड़कर योजना बनाएं। जरूरी तंत्रों के लिए अतिरिक्त बैकअप रखें, प्राकृतिक और मानव निर्मित बुनियादी ढांचे को एक साथ जोड़ें। साथ ही, स्वास्थ्य और आवास से जुड़ी नीतियों को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के विमर्श का हिस्सा बनाएं।

पैसा अब भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 'अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024' से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर साल 194 से 366 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन 2022 में उन्हें सिर्फ 28 अरब डॉलर ही मिल पाए। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जो धन मिलता है, उसका 10 फीसदी से भी कम हिस्सा बदलते हालात के हिसाब से ढलने यानी अनुकूलन पर खर्च होता है क्योंकि ज्यादातर धन जलवायु परिवर्तन को रोकने पर लगाया जाता है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि भारतीय शहरों को अपने बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए वर्ष 2050 तक 2.4 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तब हर साल बाढ़ से होने वाला नुकसान 4 अरब डॉलर से बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। शहरों के दिग्गजों को यह तय करना होगा कि वे बार-बार चीजों को दोबारा बनाते रहेंगे या लंबी अवधि के लिए ऐसे मजबूत इंतजाम करेंगे जो उनके राजनीतिक कार्यकाल के बाद भी काम करते रहेंगे।

इस संबंध में 16वें वित्त आयोग का काम बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। आयोग का काम यह सिफारिश करना है कि केंद्र सरकार के कर राजस्व को राज्यों के साथ कैसे बांटा जाए। इससे जलवायु जोखिम को राजकोषीय हस्तांतरण की मुख्यधारा में लाने का एक संवैधानिक मार्ग उपलब्ध होता है।

अगर आयोग भविष्य की सोच रखते हुए एक ऐसा मापदंड बनाए जिसमें शहरों की जलवायु संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाए, तो विकास कर रहे लेकिन जलवायु जोखिम में घिरे शहरों को बदलते हालात से तालमेल बिठाने के लिए पहले से तय और नियमों के आधार पर मदद मिल सकेगी। इससे उन्हें सिर्फ आपदा के बाद मिलने वाली राहत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी राज्यों के बीच पैसे बांटने का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसमें 10 फीसदी हिस्सा 'वन और पारिस्थितिकी' के लिए है। लेकिन यह केवल एक पुराना और स्थिर पैमाना है। यह जलवायु से जुड़े बदलते खतरों या मजबूत पारिस्थितिकी तंत्रों से होने वाले संभावित नुकसान में कमी के महत्त्व को नहीं दर्शाता है।

इंस्टिट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस ने अपनी 'अ क्लाइमेट रिस्क लेंस ऑन फिस्कल डेवल्यूशन' शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि धन हस्तांतरित करने के मौजूदा फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए जाएं। इसके तहत, जनसंख्या और क्षेत्रफल का हिस्सा 15 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी किया जाए और वन व पर्यावरण का हिस्सा 10 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया जाए। इस तरह, जो 5 फीसदी हिस्सा बचेगा, उसे जलवायु से जुड़े खतरों से निपटने के लिए अलग से रखा जाए। यह समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी, बाढ़ और कम अनुकूलन क्षमता का सामना कर रहे राज्यों को पूर्वानुमानित, नियम-आधारित सहायता प्राप्त हो।

पलायन, एक के बाद एक होने वाली आपदाएं और ऐसे हालात में पैसों की कमी ये सब मिलकर दिखाते हैं कि शहरों में जलवायु परिवर्तन का खतरा किस तरह बदल रहा है। ये सभी एक-दूसरे की तीव्रता को और भी बढ़ाते हैं। अगर पलायन का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाए तो खतरा बढ़ जाता है। कमजोर बुनियादी ढांचा हर झटके की तीव्रता को और गंभीर बना देता है और पैसे की कमी से ये दोनों समस्याएं सुलझ नहीं पातीं। भारत में यह जलवायु जोखिम सबसे ज्यादा दिखाई देता है। दिल्ली एक साथ बाढ़ और भीषण गर्मी से जूझती हुई दिखी, वहीं पंजाब में कई दशकों के बाद भयावह बाढ़ की स्थिति रही। इसके अलावा, बेंगलूरु और मुंबई जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों को भी बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे और पैसों की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ये शहर वैश्विक स्तर की व्यापक चुनौतियों को दर्शाते हैं। जब तक जलवायु अनुकूलन की योजना और वित्त, शहरी विकास के साथ-साथ नहीं चलेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव असमानता और कमजोरी को और भी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत का शहरी बदलाव मजबूती या टिकाऊपन के लिए एक प्रयोगशाला बन सकता है जो ग्लोबल साउथ के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए अहम सबक होगा।

(लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के चेयरपर्सन हैं)

आपका पक्ष

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वसूले गए शुल्क वापस मिले

इस साल देश में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा त्योहारी सेल में डार्क पैटर्न का मामला सामने आया है। सेल के दौरान कुछ ऑनलाइन कंपनियों ने कैश ऑन डिलिवरी के लिए ग्राहकों से 7 से 10 रुपये तक अलग से वसूले हैं। इसके अलावा भुगतान प्रणाली पर कुछ सामान की खरीदारी पर अलग से प्लेटफॉर्म शुल्क भी लगाया गया है। ग्राहकों ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर की है। इसके बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय इस मामले की कड़ी जांच कर रहा है और उचित कदम उठाने की बात कही है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार पर जीएसटी दरों में कटौती की सौगात देने की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की चार दर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत में दो दरों को खत्म कर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत 22 सितंबर से लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से त्योहारी सीजन में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों ने सेल में ग्राहकों को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ तो दिया मगर अलग से शुल्क भी वसूले। अतः सरकार को इस मामले की जांच कर ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिक वसूले गए शुल्क को ग्राहकों को वापस करने का निर्देश देना चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

ई-कॉमर्स के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है

देश की समृद्धि में वंचित वर्ग की भागीदारी आवश्यक

लेख 'लोकलुभावनवाद से रहना होगा सावधान' वर्तमान कालखंड में लोकलुभावनवाद को दक्षिणपंथी मानस और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है जिसके पीछे विभिन्न देशों में लोकलुभावनवाद के हारने के उदाहरण इंगित किए गए हैं। निश्चित रूप से अधिकांश देशों में वामपंथी शासन के पैर उखड़ गए हैं। चीन जैसे देशों में वामपंथ मुख्यतः पूंजीवाद का रूप धारण कर चुका है और प्रारंभ से ही निरंकुश और दमनकारी शासन के सहारे चल रहा है। वामपंथी शासन में अंततः जनता का दमन और शोषण होता है। यह धारणा उचित नहीं है कि लोकलुभावन नीतियां केवल दक्षिणपंथी सरकारें अपनाती हैं। वास्तव में समाज के वंचित वर्ग पर राजनीति तो खूब होती है परंतु उनकी सुध लेने वाले कम ही होते हैं। लोकलुभावन नीतियां संवेदनशील सरकारें ही बना सकती हैं। भारत के शासन को दक्षिणपंथी सरकार कह सकते हैं परंतु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत में विभिन्न शासनकालों में जनकल्याणकारी योजनाएं चलती रही हैं और यही कारण है कि जब विश्व भर में जनाक्रोश भड़क रहा है, वहीं भारत में स्वतंत्रता के बाद से कोई बड़ा जनाक्रोश नहीं उभरा है या हिंसक आंदोलन नहीं हुए हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा इतना सशक्त है कि जनकल्याण केंद्र और राज्य सरकारों के शासन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। यह राजनीति का विषय नहीं है। देश के स्थायित्व, विकास एवं प्रगति के लिए समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन की जरूरत है। पश्चिमी देशों में जनाक्रोश को भारत के परिप्रेक्ष्य में जनकल्याणकारी योजनाओं की असफलताओं को आरोपित करना उचित नहीं है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने समग्र सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप पश्चिमी हिंद महासागर में आठ दिवसीय व्यापक युद्धाभ्यास शुरू किया। विमानवाहक पोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में ब्रिटेन के 'कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' (सीएसजी) को 'कोंकण' युद्धाभ्यास के लिए तैनात किया गया है।

संपादकीय

“ जागरुकता सूर्य की तरह है। जब यह चीजों पर चमकती है, तो ये रूपांतरित हो जाती हैं। -थिक नात हान्ह

दो राज्यों में कफ सिरफ से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा-नियामक व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। इस त्रासदी के बाद नीति नियामकों में जो सक्रियता दिख रही है, उम्मीद है कि उसके ठोस नतीजे निकलेंगे, ताकि ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो।

मासूमों की मौत

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से जहरीले कफ सिरप से ज्यादातर पांच वर्ष से कम उम्र के मासूमों की मौत की दिल दहलाने वाली खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह संकट दवा निर्माण, वितरण और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में गंभीर खामियों को दिखाता है। दरअसल, सितंबर की शुरुआत में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जब पांच वर्ष से कम आयु के कई बच्चे एकाएक स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते मरने लगे, तो अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जमीनी जांच शुरू हुई, दूषित जल स्रोत, रोग फैलाने वाले चूहे और मच्छरों की आबादी-सभी कुछ जांचा गया, लेकिन कुछ ठोस नहीं पता चल सका। माता-पिता की असहमति से बच्चों का पोस्टमार्टम न करा पाना जांच में बाधा बना रहा। फिर जब सभी बच्चों की किडनी के काम करना बंद होने की बात सामने आई, तब इसे कफ सिरप से जोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। इसी तरह राजस्थान से भी करीब तीन बच्चों के मरने की खबर है, जिनका जिम्मेदार कायसन फार्मा के एक कफ सिरप को माना जा रहा है। जांच में पाया गया कि तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे विषैले रसायन निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाए गए हैं। यह त्रासदी 2022 में गांबिया और उज्बेकिस्तान में कथित भारतीय सिरप से हुई मौतों की याद दिलाती है। सवाल उठता है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा? ऐसी घटनाएं देश की दवा-नियामक व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। हर राज्य में ड्रग कंट्रोलर दवा के प्रत्येक बैच की जांच के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि निरीक्षण औपचारिकता बनकर रह गया है। ऐसे भी दृष्टांत हैं, जिनमें गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही दवाएं सरकारी योजना के तहत फिर से वितरित की जा रही हैं। ऐसे में, सवाल यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटी जाने वाली दवाएं कितनी

सुरक्षित हैं। यह तंत्रगत भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है। ऐसी विडंबनाओं से देश की 'दुनिया के फार्मेसी हब' वाली छवि पर आघात पहुंचेगा। अब समय है कि दवा उद्योग और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। वहीं डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को भी बच्चों को कोई सिरप या एंटीबायोटिक दवा देने से पहले पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। त्रासदी के बाद दोनों राज्य सरकारों ने विवादित सिरपों पर प्रतिबंध लगाया है और जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। उम्मीद है कि यह कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहेगी और इससे व्यवस्था में ठोस बदलाव आएंगे।

ताकि दवा जहर न बन जाए

भारत का फार्मा और जेनेरिक दवा क्षेत्र जीवंत है और बच्चों की मौतों जैसे हादसे इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं। निरीक्षण, तर्कसंगत नुस्खे और पारदर्शी संचार के मजबूत तंत्रों के साथ, हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौतों की हालिया खबरें जो कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं, जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि शुरुआत में यह बताया गया था कि दूषित कफ सिरप के कारण किडनी में गंभीर क्षति हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के संदूषण से इन्कार किया है। वर्ष 2022 में गांबिया में भारत में निर्मित कफ सिरप से होने वाली मौतों से जुड़ी ऐसी ही खबरें सामने आई थीं। सरकार ने उन मौतों का भी खंडन किया था और दावा किया था कि उनका कफ सिरप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से भारतीय दवाओं और सिरप की गुणवत्ता पर सवाल तो उठते ही हैं।

डॉ चंद्रकांत लहारिया
वरिष्ठ चिकित्सक

भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, जो देश के भीतर और अन्य निम्न व मध्यम आय वाले देशों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराता है। भारत कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां भी बनाता है। ऐसे में, ये घटनाएं देश के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकती हैं और जनता के विश्वास एवं दवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती हैं। यह घटना व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर करती है, जिनके लिए दवा नियमन और निरीक्षण में कमियों, आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों, असुरक्षित और अत्यधिक नुस्खे लिखने और देने के तरीकों की जांच और जनता के विश्वास में आई कमी का विश्लेषण बेहद जरूरी है। सबसे पहले, रिपोर्टों के बाद अधिकारियों ने नमूने जब्त कर लिए, जिनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) का स्तर खतरनाक रूप से उच्च पाया गया। डीईजी-दूषित कफ सिरप कोई नई घटना नहीं है: गांबिया में बच्चों की मृत्यु की एक अंतरराष्ट्रीय जांच में घटिया सिरप की पहचान की गई और 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की।

यह घटना दवा जांच की गड़बड़ियों की ओर इशारा करती है और ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों के प्रति जनता के मन में संदेह पैदा होता है। ऐसी मौतें और सरकारी एजेंसियों की विरोधाभासी रिपोर्टें भारतीय दवाओं

के विदेशी खरीदारों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। दवाओं के निर्माण में (जिनमें सिरप भी शामिल हैं) हर कदम पर, यानी परिवहन के लिए प्रमाणित आपूर्तिकर्ता, मजबूत आंतरिक परीक्षण, कड़े बैच नियंत्रण और पारदर्शी आपूर्ति-शृंखला रिकॉर्ड इत्यादि पर गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता होती है। जब इनमें से एक भी कड़ी टूटती है, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। दीर्घावधि में, नियामकों को घटना हो जाने पर सक्रिय होने की जगह घटना से पहले ही सक्रिय रोकथाम की ओर बढ़ना होगा। बेहतर विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) ऑडिट, रियल-टाइम बैच ट्रैकिंग, और एक ऐसी उद्योग संस्कृति विकसित करनी होगी, जहां दवा अनुपालन को बढ़ावा मिले, न कि उसे टाला जाए।

यह स्थिति खांसी की दवा जैसी दवाओं के अत्यधिक उपयोग या डॉक्टर के पर्चे के बिना ली गई दवाओं की याद भी दिलाती है। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अंतर्निहित बीमारी का एक लक्षण है। ज्यादातर मामलों में, यह अपने आप ठीक हो जाती है और खांसी की दवा केवल सहायक देखभाल के काम आती है। लेकिन भारत में खांसी से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नतीजा है कि बच्चों के लिए सिरप का व्यापक और अक्सर अनावश्यक इस्तेमाल, जिससे मांग बढ़ती है और तेजी से उत्पादन और वितरण को बढ़ावा मिलता है। यह मांग बदले में, कम लागत वाले या अनुचित तरीके से परीक्षण किए गए उत्पादों के बाजार में आने का जोखिम बढ़ा देती है।

भारत में खुदरा दवाइयों का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सामुदायिक फार्मेसी सर्वेक्षणों और क्षेत्रीय अध्ययनों का अनुमान है कि देश भर में आठ लाख लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानें हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर औषधि निरीक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियों में सैकड़ों स्वीकृत निरीक्षक के पद खाली पड़े हैं, जिससे उनका निरीक्षण नहीं हो पता और राज्य भी इसी तरह की कमियों की रिपोर्ट कर रहे हैं। नियामकों और फार्मेसियों के अलावा, दवा प्रचार प्रथाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। आक्रामक विपणन रोगियों को नुकसान पहुंचाते हैं और चिकित्सकों को अधिक दवा लिखने के लिए प्रभावित करते हैं। साथ ही, भारत को जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देते रहना चाहिए, पर बाजार में आने के बाद कड़ी निगरानी और स्वतंत्र गुणवत्ता सत्यापन के साथ, ताकि चिकित्सकों और आम जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि जेनेरिक दवाएं न केवल सस्ती हैं, बल्कि सुरक्षित और उतनी ही कारगर भी हैं।

दो राज्यों में हुई बच्चों की मौतों से स्थानीय फार्मासिस्टों, चिकित्सकों और नियामकों पर भरोसा कम हो रहा है; इस आपदा को रचनात्मक सुधार में बदलने के लिए दवाओं और औषधियों के उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति के बेहतर नियमन और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरा, स्वीकृत औषधि निरीक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरना चाहिए। फार्मेसियों और अस्पतालों से निरंतर निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, तर्कसंगत दवाइयां और जनता में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा में निवेश करना चाहिए, ताकि माता-पिता अनावश्यक दवाओं की मांग कम करें। चौथा, दवाओं की मंजूरी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारों की विनियमन क्षमता लचीली है, और मंजूरी में भ्रष्टाचार की भी खबरें आती रहती हैं। राज्य दवा नियामक निकायों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। पांचवां, विश्वास बहाली के लिए पारदर्शी संचार व्यवस्था हो। परीक्षणों के परिणाम, रिकॉल की समय-सीमा और स्पष्ट सलाह क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए। तेज और ईमानदार संचार विश्वसनीयता बनाए रखता है। छठा, गुणवत्ता-आधारित जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भारत का फार्मा और जेनेरिक दवा क्षेत्र जीवंत है और ऐसी घटनाएं इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती हैं और उपभोक्ताओं को ब्रांडेड और महंगे उत्पादों की ओर धकेल सकती हैं। निरीक्षण, तर्कसंगत नुस्खे और पारदर्शी संचार के लिए मजबूत तंत्रों के साथ, हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और साथ ही सस्ती दवाओं के विशाल लाभों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हमें ऐसी घटनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि भारत में फार्मा क्षेत्र और दवाओं के नुस्खे और उपयोग प्रथाओं को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए।

जीवन धारा

मार्कस ऑरेलियस

प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और देखें कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। इसे अपनाने से, हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं।

अच्छे जीवन का मतलब निरंतर सुधार है

देवताओं के प्रति समर्पण करना, मानवजाति के प्रति न्यायपूर्ण होना, और प्रत्येक प्रभाव की इतनी सावधानी से जांच करना कि कोई भी ऐसी चीज प्रवेश न कर जाए, जिसकी अच्छी तरह जांच न की गई हो, यह हमेशा और हर जगह आपके वश में है। इन सिद्धांतों का पालन करना हमेशा और हर व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, और यह आंतरिक शांति और सदाचार प्राप्त करने की कुंजी है। दूसरों के विचारों के बारे में कभी भी बेतरतीब सवाल न करें, बल्कि सीधे उस लक्ष्य को देखें, जो प्रकृति ने आपके लिए निर्धारित किया है। प्रकृति या तो ब्रह्मांड की है या आपकी अपनी। पहली, आपको ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाती है और दूसरी, आपको अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब जो चीजों की संरचना के अनुकूल है, वही उन्हें उपयुक्त लगता है। प्रकृति और संसार को बुद्धिमान प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों की सेवा और उपयोग के लिए बनाया गया है और तर्कसंगत प्राणी एक-दूसरे के लाभ के लिए बने हैं। अब सामाजिक स्वभाव वह है, जिसके लिए मानव प्रकृति मुख्य रूप से अभिप्रेत है। हमारे अस्तित्व में अगली चीज भौतिक प्रभावों से सुरक्षित रहना है, क्योंकि यह तर्क का विशिष्ट विशेषाधिकार है कि वह अपने भीतर गति करे, और संवेदना या वासना को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि ये दोनों पशुवत और निम्न गुणवत्ता के हैं। लेकिन समझ का हिस्सा शासन करने का दावा करता है, और पदार्थ या इच्छा के आगे नहीं झुकता, क्योंकि वह आदेश देने और उनका उपयोग करने के लिए ही पैदा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपनी तर्कसंगत बुद्धि का उपयोग सहमति की प्रक्रिया की पवित्रता को समझने और उसे बनाए रखने के लिए करता है, तो वह अपने स्वयं के जीवन, निर्णयों और अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। और फिर वह अपनी हर चीज का स्वामी बन जाता है। भीतर की शांति मन की व्यवस्थित अवस्था है, जिसे सद्गुणों को पोषित करके और नैतिक मूल्यों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की धारा में बहते हुए, हमेशा याद रखें कि सुख और दुख, दोनों ही क्षणिक हैं, इन्हें अपनी आत्मा पर हावी न होने दें। अच्छा जीवन वह है, जिसमें हम अपनी भूमिका को समझें, जैसे कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा होकर हम दूसरों की सेवा में बिना किसी अपेक्षा के योगदान दें। हर निर्णय में स्वयं से पूछें कि क्या यह न्यायपूर्ण है, क्या यह आवश्यक है, और क्या यह मेरी आत्मा की शांति को बनाए रखेगा? सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक सद्गुणों में निहित है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और देखें कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। इसे अपनाने से, हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। अच्छे जीवन का अर्थ है निरंतर सुधार की यात्रा है, जहां हर कदम हमें ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने की ओर ले जाता है। हमेशा मानव जाति के लिए कुछ-न-कुछ उपयोगी करते रहें, और इस निरंतर उदारता को ही अपने जीवन का आनंद बनाएं।

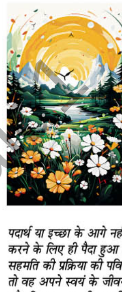

हरदम प्रयास करें

सूत्र

बाहरी विचारों को बगैर जांचे अपने जीवन में न उतारें, और कभी भी दूसरों के बारे में बेतरतीब पूछताछ न करें, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इन बातों का ध्यान रखकर ही आप आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, और बाहरी उलझनों से बच सकते हैं। हरदम पहले से खुद को बेहतर करने का प्रयास करते रहें।

दूसरा पहलू

लोग कुत्तों को अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदते हैं और सड़कों पर छोड़ देते हैं, आंकड़े चिंताजनक हैं।

वह कार कौन-सी है, जो मुझे मेरे घर ले जाएगी

वह अगस्त की एक बरसाती शाम थी, यमुना एक्सप्रेस-वे पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों के बीच दूर से वह एक काला धब्बा-सा नजर आ रहा था। छह या सात माह का काला-भूरा जर्मन शेफर्ड कारों के पीछे आड़ा-तिरछा दौड़ रहा था। इस कोशिश में कई बार वह कारों से टकराते-टकराते बचा। उसे शायद उम्मीद थी कि इन्हीं में से कोई कार उसके मालिक की होगी। वे कार रोकेंगे और उसे वापस घर ले जाएंगे। पर शायद इन्सान की दुनिया में इन्सानियत नहीं है। इस प्यारे से डॉग को उसके मालिक ने बीमार होने या किसी और वजह से यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा टोल प्लाजा के पास छोड़ दिया। यह सिर्फ उस अकेले जर्मन शेफर्ड की सच्चाई नहीं है। शौक-शौक में महंगी कीमत पर विदेशी नस्ल के श्वानों की खरीद तो होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस जिम्मेदारी को उठा पाते हैं। उन्हें तो बस अपने बच्चों के लिए एक खिलौना चाहिए होता है। एक अनुमान के तहत, देश भर में हजारों कुत्तों को उनके मालिक सड़कों पर छोड़ जाते हैं। इनमें दस फीसदी विदेशी नस्ल के शहरी पालतू कुत्ते होते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशंस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच साल में शहरों में पालतू कुत्तों को छोड़ने की प्रवृत्ति में 50 फीसदी तक इजाफा हुआ है।

भूपेंद्र कुमार

1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार, किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ना अपराध है।

शौक-शौक में विदेशी नस्ल के श्वानों की खरीद तो होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस जिम्मेदारी को उठा पाते हैं। एक अनुमान के तहत, देश भर में हजारों कुत्तों को उनके मालिक सड़कों पर छोड़ जाते हैं।

1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार, किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ना अपराध है, दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो फिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? असल में किसी पिल्ले को अपनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका एहसास शौक-शौक में खरीदने वालों को उस वक्त नहीं होता। समय से टीका लगवाना, वेटरनरी डॉक्टरों को दिखाना, बाहर टहलाने ले जाना और सबसे जरूरी समय देना। कोविड के समय घर में बोर हो रहे लोगों ने बड़ी संख्या में कुत्तों को खरीदा या गोद लिया, पर कोविड बीतते ही ज्यादातर को सड़कों पर यों ही छोड़ दिया गया। आगरा में कैस्पर होम डॉग शेल्टर चलाने वाली विनीता अरोड़ा कहती हैं कि इस समस्या का समाधान माइक्रो चिप में है। इससे कुत्ते के मालिक के बारे में पता चल सकेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ज्यादातर लोग बीमार कुत्तों को छोड़ देते हैं। नोएडा में डिस्पेंसरी फॉर स्ट्रे एनिमल चलाने वाले संजय महापात्र कहते हैं कि कुत्तों को पालने का फैसला लोग सोच-समझकर नहीं करते। उनके पास माह में 15 से 20 छोड़े गए कुत्ते आते हैं। इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर आहट पर उन्हें लगता है कि उनके मालिक लेने आए हैं। यही शायद यमुना एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों के पीछे भाग रहे उस जर्मन शेफर्ड ने भी सोचा होगा।

आंकड़े

भोजन की बर्बादी

दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, जबकि ब्राजील में लोग खाना फेंकने के मामले में हर साल रिकॉर्ड बना रहे हैं।

ब्राजील	94
चीन	76
अमेरिका	73
भारत	55
फिलीपींस	26

बर्बाद खाने के आंकड़े प्रति वर्ष के हिसाब से किलोग्राम में हैं। | स्रोत : UNEP FWI

एक दिन काम से लौटते हुए शिव कुमार से डाकुओं ने रास्ते में सारा सामान छीन लिया। अंत में, भगवान की लीला से डाकुओं का हृदय परिवर्तित हो गया।

सब शिव कृपा है

एक गांव में शिव कुमार नाम का एक परम भक्त रहता था। वह दिनभर काम करने के बाद भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता था। एक दिन, काम से लौटते समय जंगल के रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और पैसे मांगने लगे। शिव कुमार के पास केवल दो दिन के भोजन के लिए चावल थे, जो उसने अपने काम के बदले में लिए थे। उसने डाकुओं से कहा, 'मेरे पास पैसे नहीं हैं, केवल ये चावल हैं। कृपया मुझे छोड़ दें।' लेकिन डाकुओं ने चावल के साथ-साथ उसके गले की चांदी की माला भी छीन ली और उसे खाली हाथ छोड़ दिया।

शिव कुमार निराश होकर घर लौटा और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उधर, डाकू जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें हर रास्ता एक-सा दिखाई देने लगा। वे भटकते हुए उसी जगह पहुंच गए, जहां शिव कुमार का घर था। डाकुओं को लगा कि यह कोई जादूगर है। डरकर वे शिव कुमार के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। शिव कुमार ने कहा, 'अपनी गलतियों की माफी भगवान भोलेनाथ से मांगो। यह सब उनकी ही कृपा है।' इस घटना से डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने डकैती छोड़ दी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। वे मेहनत करके कमाने लगे और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़े।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

अमेरिका में 1927 में पहली बोलती फिल्म का प्रीमियर

अमेरिकी सिनेमा के इतिहास में छह अक्टूबर की तारीख की अपनी एक खास अहमियत है। दरअसल, 1927 में छह अक्टूबर के दिन ही अमेरिका के मूक सिनेमा ने बोलना सीखा। यह वह दिन था, जब देश की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर का न्यूयार्क में प्रीमियर हुआ। सिनेमा की बात हो तो भारत का जिक्र होना लाजिमी है। भारत में 14 मार्च 1931 को मूक सिनेमा को आवाज मिली थी। इसी दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। 1949 : तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खडगवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की आधारशिला रखी। 1957 : सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया। 1981 : मिस्र के सैन्य अधिकारी और 1970 से देश की सत्ता पर काबिज मोहम्मद अनवर अल सादत की हत्या कर दी गई। उन्होंने इजराइल के साथ गंभीर शांति वार्ता के लिए प्रयास किए और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

स्वच्छता, साहित्य और सीवर

उर्दू शायरी से लेकर परंपरागत हिंदी कविताओं तक में स्वच्छता और सफाईकर्मी की जान की परवाह क्यों नहीं दिखती?

श्यौराज सिंह बेचैन

मुद्दा

अभी-अभी हमने गांधी जयंती मनाई है। गांधी जी ने स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाया था। व्यावहारिक प्रयोग के तौर पर वह 'साबरमती आश्रम' के निकट बसाई गई भंगी बस्ती से जुड़ गए थे। जब 1993 में 'सिर पर मैला ढोने' की प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया और हाथ से सफाई करने-कराने और बिना सुरक्षा उपकरणों के जहरीले गैस भरे सीवरों में उतरने पर रोक लगा दी गई, तो सीवर में मौतों का सिलसिला अविराम क्यों चलता दिखाई दे रहा है?

हाल ही में दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आकर कासगंज (उत्तर प्रदेश) निवासी चालीस वर्षीय मजदूर अरविंद यादव की मृत्यु हो गई और चार मजदूर अस्पताल में मौत से जूझते रहे। ठेकेदार ने मजदूरों को लालच देकर रात के अंधेरे में

सीवर के मैनहोल में उतारा था। जेहन में प्रश्न कौंधा कि ऐसी कौन-सी शिक्षा, सलाह या मानवीय प्रशिक्षण है, जिससे आम इन्सान की जान की अहमियत समझ आए, जो कार्य स्वास्थ्य के प्रतिकूल न हो, जोखिम कम से कम किए जा सकें और अप्राकृतिक मौतें रोकी जा सकें।

भारतीय साहित्य, शेरो-शायरी और कविता-कहानी में यह मसला अभिव्यक्त क्यों नहीं हुआ? तरक्कीपसंद उर्दू शायरों से लेकर परंपरागत हिंदी कवियों के यहां स्वच्छता और स्वच्छकार की जान की परवाह क्यों नहीं हुई? महबूबा के रुखसार का रोमांटिक चित्रण और मेहनतकशों के पेट की आग पर खामोशी क्यों? जब साहित्यकार आंखें बंद करे, तो सरकारों को सचेत कौन करे? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि 'जाके पांव न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई' वाली कहावत लागू हुई है। यानी जो समुदाय भुक्तभोगी है, वह तो साहित्य में रहा नहीं, जो है, उसने पराई पीर से सरोकार नहीं रखा?

ऐसा नहीं है कि मैला ढोने या मुर्दा मवेशी उठाने की प्रथा को आधुनिक तकनीक के सहारे मानव-श्रम और गरिमा के संरक्षण का सवाल बौद्धिक हल्कों में कभी उठा ही नहीं है। बेजवाड़ा विल्सन की संस्था हो या बिंदेश्वरी पाठक का शुलभ शौचालय, काम तो इधर के दिनों में भी हुए हैं, पर सरकारों से संबंधित मंत्रालयों ने क्या किया? बिना कोई प्रभावी कदम उठाए 'योजना आयोग' लंबी उम्र जीकर चला गया।

एक बार केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम ने कहा था, मलिन पेशे जब तक एक समुदाय तक महदूद रखे जाएंगे, उनकी आर्थिक दशा उन्हें वैकल्पिक पेशों में जाने नहीं देगी और लाभार्थी लोग जब तक इसे अपनी भी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक रास्ते नहीं निकलेंगे। उस समय एक हिंदी पत्रिका में प्रसिद्ध कथाकार शिवानी ने जगजीवन राम से लंबा परिवाद किया था। उनका कहना था, आखिर यह काम करना तो इन्सान को ही पड़ेगा, बाबूजी क्या सवर्णों को भी सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हैं? तब बाबूजी का जबाव था, हम आधुनिक तकनीक के जरिये विकसित देशों की तरह मशीनों से सफाई कराएंगे। तब न सीवर मौतें होंगी, न किसी और को हाथों से मानव मल उठाने का असम्मानित कार्य करना होगा। हालांकि बाबूजी के गुजर जाने के बाद मुद्दा डीप फ्रीजर में चला गया। वर्तमान सरकार ने खुले में शौच जाना बंद करवा कर घरों में शौचालयों के निर्माण की योजनाएं चलाई हैं। यह बात दीगर है कि यह पूरी तरह सफल नहीं हुई है, खासकर ग्रामीणों के बीच, जहां शौचालय हैं, पर पानी नहीं है। घर से बाहर रात में कैसे जाएं, बिजली नहीं है, निर्भरता अधिक है। स्वयं सहायता और जागरूकता इत्यादि की जरूरत है। साहित्य में सामंती शुद्धतावाद के चलते 'गंदगी' को कविता का विषय नहीं बनाया जा सकता था। दलित साहित्य अपवाद है, वहां यह समस्या चित्रित हुई है। इसी वर्ष का 'नयी धारा सम्मान' पाने वाली प्रो. रजत रानी 'मीनू' ने 1992 में जेएनयू से 'नब्बे के दशक की हिंदी दलित कविता पर आंबेडकर का प्रभाव' शीर्षक से एम.फिल का लघु प्रबंध तैयार किया था, उसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि की एक कविता 'झाड़ूवाली' का उल्लेख किया गया है। डॉ. 'मीनू' ने अपने कविता संग्रह 'पिता भी तो होते हैं मां' में स्वयं भी 'झाड़ूवाली' शीर्षक से एक कविता लिखी है।

मनुष्य की गरिमा, जीवन सुरक्षा, और सफाई की अनिवार्यता की दृष्टि से भी समस्या गंभीर है। मानव मल-मूत्र मानव ही के हाथों साफ कराया जाना कोई सम्मान की बात नहीं है। इसमें तकनीक सहायक हो सकती है। विकसित और विकासशील देशों में यह हुआ है और भारत में भी आंशिक शुरुआत हो रही है।

Special arrangements by Amar Ujala

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 133 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

अगर आप क्वॉलिटी चाहते है तो शुरू से ही उसका ख्याल रखना होगा। आखिर में क्वॉलिटी पर माथापच्ची करना ठीक नहीं
-विलियम एडवर्ड्स डेमिंग, इकॉनमिस्ट

कड़ी निगरानी हो

दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक है। इससे स्पष्ट है कि इस फील्ड में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है।

घटना के बाद एक्शन । तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के नमूने में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई। घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर जारी है। दवाएं वापस ली गई है, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी CDSCO ने कई राज्यों में जांच की है।

कफ सिरप से मौत

पुरानी गलतियां । सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद WHO ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई।

मानक से नीचे । भारत के फार्मास्यूटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। CDSCO ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं, जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68% MSME फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65% कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं।

जांच में तेजी । सरकार का अनुमान है कि इस साल देश का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। वहीं, 2030 तक फार्मा मार्केट के 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन, इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। दवाओं की जांच और निगरानी अभी तक की कमजोर कड़ी साबित हुई है। रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल इकॉनमी या देश की छवि ही नहीं, अनमोल जिंदगियों से जुड़ा है।

नश्तर

साहित्य के विमोचनवीर

सर्दी आने वाली है। मौसम खुशनुमा है। यह लेखकों, बुद्धिजीवियों के कोटरों से बाहर निकलने का मौसम है। लेखक भले ही कठोर यथार्थ की बात करे, पर होता वह नाजुक मिजाज ही है। उससे न तो धूप की तपिश बर्दाश्त होती है, ना ही शीत की तीव्रता। ऐसे में गर्मी और सर्दी की वयसंधि का समय उसके अनुकूल होता है। साहित्य के कैलेंडर में सितंबर से दिसंबर तक का मौसम विमोचन और सम्मेलनों का है।

सौरभ श्रीवास्तव

लखनऊ में दो पुस्तक मेले लग चुके हैं। रायपुर वाला सम्मेलन तो राष्ट्रीय सुर्खियों में आ चुका है। दिल्ली वाले मेले के लिए लेखकों ने कुर्तों में कलफ कर ली है। इस दौरान इतनी किताबों का विमोचन होता है कि मुझे पेड़ों की चिंता होने लगती है। इस दौरान कई विमोचनवीर भी सक्रिय हो जाते हैं। आयोजक की सूचना पर ये घंटे भर के भीतर मंच पर पहुंच जाएंगे। किताब किसी भी विषय पर हो, ये फ्लैप पर लिखा ब्लर्ब और भूमिका पढ़कर श्रोताओं को घंटों फंसाए रख सकते हैं। हालांकि कौन किसे फंसाए हुए है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। किसी भी शहर में थोड़ा वक्त बिताने के बाद आप विमोचनवीरों को खुद-ब-खुद पहचान लेंगे। 10-12 ऐसे चेहरे जो आपको ज्यादातर कार्यक्रमों में नजर आएंगे।

किसी कार्यक्रम में विमोचनवीरों के पहुंचने की एक ही शर्त होती है - यदि वे आएं, तो आपको भी उनके कार्यक्रम में जाना होगा। हर विमोचनवीर का अपना नेटवर्क होता है। यदि वह आपके कार्यक्रम में आया तो उसकी खबर अखबारों में व वेबसाइटों पर अगले दिन जरूर दिखेगी। बरसों से वह पत्रकारों को निर्विकार भाव से 'गुड मॉर्निंग' मैसेज यूं ही तो नहीं भेज रहा। अगर आप अपनी किताब को चर्चा में लाना चाहते हैं तो कंटेंट-वंटेंट छोड़िए। बस शहर के चुनिंदा विमोचनवीरों को विमोचन में जरूर बुलाइए। यह भी बताइए कि कार्यक्रम के बाद गला तर करने और डिनर की भी व्यवस्था है। विमोचनवीर आपकी किताब में वे गहराइयां तलाश निकालेंगे, जिसकी हवा आपको लिखते वक्त भी नहीं लगी होगी।

एकदा

संकलन : हरिप्रसाद राय

जाति से मुक्ति

बसंत लाल वर्मा उस समय ईस्ट रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय के हेडमास्टर थे। एक दिन छठी कक्षा के एक विद्यार्थी ने उन्हें अपने नाम से सरनेम को हटवाने का आवेदन किया। हेडमास्टर ने आश्चर्य से पूछा, 'सरनेम क्यों हटवाना चाहते हो?' बच्चे ने उत्तर दिया, 'क्योंकि इससे जाति का बोध होता है।' जवाब सुनकर हेडमास्टर हैरान रह गए। उन्होंने फिर पूछा, 'क्या तुमने अपने अभिभावक से सहमति ली है?' बच्चे ने कहा, 'जी, वे बाहर खड़े हैं।' बच्चे के मामा बिंदेश्वरी प्रसाद ने दृढ़ स्वर में कहा, 'बच्चा चाहता है, इसलिए, सरनेम हटा दीजिए।' आगे चलकर जब उस बालक ने 1925 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, तो लोग उसे 'शास्त्री जी' कहकर पुकारने लगे। इस संबोधन में किसी श्रेष्ठता का भाव नहीं था, बल्कि उस शिक्षण संस्थान की महिमा झलकती थी, जिसकी आधारशिला स्वयं महात्मा गांधी ने रखी थी और जिसके वह शुरुआती विद्यार्थियों में से एक थे। यही विद्यार्थी आगे चलकर देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना - लाल बहादुर शास्त्री। उनके लिए उपाधि से अधिक महत्व विनम्रता और मानवीयता का था। बचपन से ही उनका सपना था कि भारत जातिवाद के विष से मुक्ति हो।

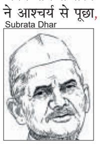

Subrata Dhar

अमेरिका के ग़ाज़ा प्लान पर पहले जीतना होगा फ़लस्तीनियों का भरोसा

क्या ट्रंप कार्ड से लौटेगा अमन

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए जो शांति योजना पेश की है, उसे लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, खासकर हमास की प्रतिक्रिया के बाद। ट्रंप बेहद उत्साहित हैं, लेकिन आशंकाएं भी कम नहीं।

मनीष गुप्ता, न्यूयॉर्क से

योजना के पॉइंट्स । इस शांति-प्रस्ताव के अनुसार, यदि दोनों पक्ष सहमति दें तो लड़ाई तुरंत रुकेगी और 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों (जीवित और मृत) को लौटाया जाएगा। गाजा से इस्राइल की आंशिक वापसी होगी। हमास व अन्य गुटों का असैन्यीकरण जरूरी है। गाजा प्रशासन एक अस्थायी सरकार चलाएगी, जो 'Board of Peace' नामक अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के अधीन होगी। एक अंतरराष्ट्रीय बल भी गाजा में तैनात रहेगा, जिसका काम होगा स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना और सुरक्षा व्यवस्था तय करना।

हमास का रुख । फलस्तीनी प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव के प्रति सशर्त समर्थन जताया है, जबकि हमास ने बंधकों को रिहा करने के संकेत दिए हैं। हालांकि पीस डील के कुछ हिस्सों पर करने की जरूरत बताई है, लेकिन उसका यहां तक हामी भरना भी अपने आप में बड़ी घटना है। पिछले सारे प्रस्ताव उसने सिरे से खारिज कर दिए थे।

खुली जेल । गाजा कभी इजिप्ट का हिस्सा था। 1967 के युद्ध के बाद इस्राइल ने इस पर नियंत्रण पा लिया। 2005 में इस्राइल ने अपनी सेना हटा ली, लेकिन 2007 में जब हमास ने सत्ता संभाली, तो स्थिति फिर से विस्फोटक हो गई। जब से इस्राइल और इजिप्ट ने गाजा की सीमाएं सील कर दी यह इलाका एक खुली जेल की तरह है।

Adobe Stock

अतीत से सबक
- फलस्तीनी जनता को जगह देनी होगी
- सारी शर्तों व वादों का पालन किया जाए
- अंतरराष्ट्रीय कानून और सीमाओं का सम्मान

अधूरी शर्तें । पिछले दो दशकों में अनेक प्रयास हुए - Oslo Accords, Annapolis Conference, संयुक्त राष्ट्र समर्थित सीजफायर, लेकिन हर बार कोई न कोई शर्त अधूरी रह गई। एक तरफ इस्राइल की सुरक्षा की जिद, दूसरी तरफ फलस्तीनियों की आत्म निर्णय की पुकार - एक तरफ बस्तियों का फैलाव, दूसरी तरफ जमीन की वापसी का सपना, और बीच में फंसी हमास की सत्ता की लड़ाई।

फलस्तीन का भविष्य । साल 2020 में ट्रंप प्रशासन ने Abraham Accords के जरिए UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान को इस्राइल से औपचारिक संबंध बनाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन, इन समझौतों में फलस्तीनियों को न तो शामिल किया गया, न ही उनका पक्ष गहराई से समझा गया। अबकी बार मामला अलग है। प्रस्ताव में एक संभावित भविष्य के फलस्तीन राज्य की रूपरेखा पूरी तरह नहीं नकारी गई है, बशर्ते राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार हों, लेकिन हमास को जाना होगा।

थोपी हुई शांति । आज फलस्तीनियों की सबसे बड़ी जरूरत है जीवन स्तर में सुधार, बुनियादी सुविधाओं की बहाली और भविष्य के लिए उम्मीद। यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में शांति युग के आगमन का संकेत देता है। इतिहास बताता है कि जब भी बाहरी ताकतों ने भरोसे और सहभागिता के बिना शांति थोपी है, उसका टिकना मुश्किल रहा है।

दोहरा रवैया । वैश्विक सियासी शतरंज की बिसात पर काले-सफेद को पहचानना आजकल मुश्किल हो चला है। दोस्त के दुश्मन या दुश्मन के दोस्त से कैसा व्यवहार रखा जाए? जैसे कतर ने हाल ही में ट्रंप को लग्जरी बोइंग 747 विमान गिफ्ट किया है और यही कतर हमास का सबसे बड़ा फंडर भी है।

राजनीतिक खेल । 20 पॉइंट प्लान की घोषणा के पहले नेतन्याहू से कतर पर किए अटैक के लिए खेद व्यक्त करवाया गया, जो नेतन्याहू के मंत्रिमंडल को चुभा भी। लेकिन, जियो पॉलिटिक्स रोमांचक खेल है। ट्रंप इसे शांति स्थापित करने वाला प्लान बता रहे हैं। हालांकि उनके कहने में दिक्कत यह है कि वह बहुत कुछ 'ऐसे' भी कहते रहते हैं। शांति भरोसे की भाषा में लिखा दस्तावेज होती है, और अभी उस का अनुवाद बाकी है।

भरोसे की चुनौती । 2020 के डॉनल्ड ट्रंप के प्रस्ताव (Deal of the Century) पर तुर्किये के राष्ट्रपति अर्दोआन ने सख्त आपत्ति जताई थी और यरुशलम को मुस्लिमों की रेडलाइन बताया था, जिसके उल्लंघन से गंभीर या हिंसक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इस बार उन्होंने प्रस्ताव को 'वार्ता की नई खिड़की' करार दिया है। यूरोपीय संघ और जर्मनी-फ्रांस ने प्रस्ताव का स्वागत तो किया, लेकिन चेतावनी भी दी कि स्थायी शांति अंतरराष्ट्रीय कानून और 1967 की सीमाओं का सम्मान करने पर होगी। इस प्रकार नई योजना को लेकर समर्थन और संदेह, दोनों मौजूद हैं और फलस्तीनी जनता का भरोसा जीतना अब भी सबसे बड़ी चुनौती है।

(लेखक फिल्मकार, कॉलमनिस्ट और राइटर हैं)

शरद ऋतु से मिलती है संतुलन की सीख

ऋतुओं के बीच छुपम-छुपाई का खेल हो, तो ताज शरद ऋतु के सिर ही सजेगा। बिना आहट के पीछे से आकर धप्पा मारने में कोई नहीं पछाड़ सकते इसे। गर्मी और सर्दी के बीच में चुपके से आ बैठ जाती है यह ऋतु - जब मॉनसून के बादल घर लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, धूप धीरे-धीरे नरम पड़ने लगती है और शाम ठंडी, जब सूरज अपनी रोशनी अगली गर्मियों के लिए बचाने लगता और रातें पैर फैलाने लगती हैं। इन दिनों में मौसम के साथ मन भी बदल जाता है - लगातार आने वाले पर्वों के उत्साह से सराबोर।

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

शरद ऋतु ट्रांजिशन पीरियड है - एक मौसम से दूसरे मौसम का बदलाव, गर्मियों से सर्दियों की यात्रा। प्रकृति अपने पन्ने बदलती है, जैसे जीवन में नया अध्याय जुड़ना। बीच का यह समय ज्यादा संवेदनशील बनाता है और ठहरना सिखाता है। पसीने की लकीरें गर्मियों का ऐलान कर देती हैं और हाथों का सर्द होना बताता है कि ठंड आ चुकी है, लेकिन शरद के आगमन को जानने के लिए उसे महसूस करना होता है।

इस ट्रांजिशन में गहरा आनंद है - यह हमें अस्थिरता में स्थिरता ढूंढना सिखाता है। बताता है कि परिवर्तन डरने की चीज नहीं, स्वाभाविक हिस्सा है जीवन का। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता - सूरज का ताप भी नहीं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है और असली कमाल है उसके साथ सामंजस्य बैठाने में। यह उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि बदलाव अच्छे के लिए ही होगा।

शरद ऋतु में पेड़ों से पत्तझड़ भी कहते हैं, जब पेड़-पौधे पुरानी पत्तियों को छोड़ने लगते हैं। शाखों से गिरते पत्ते याद दिला रहे कि किन को छोड़ना भी जरूरी है। जब पुराना जाएगा, तभी नया आएगा। कुछ आदतें, कुछ सोच को भी ऐसे ही छोड़ने की जरूरत पड़ती है ताकि नई उम्मीदों और नई सोच के लिए जगह बन सके। और जाना हमेशा नकारात्मक ही नहीं होता। वह विदाई बहुत भव्य होती है, जब कोई अपनी भूमिका निभाकर और अपनी विरासत को मजबूत हाथों में सौंप कर जा रहा हो।

यह मौसम है संतुलन का - ऐसा समय जब न धूप परेशान करती है, न ठंड काटती है और हवा की सहजता आसान कर देती है सफर। ऐसा ही बैलेंस चाहिए जीवन में, जहां रफ्तार उतनी ही हो, जिससे रिश्ते-नाते पीछे न छूट जाएं, लेकिन ऐसा ठहराव भी न आए कि बाकियों से हम पीछे रह जाएं। इसी प्रकार शरद ऋतु सिखाती है कि दोनों के बीच एक जगह है जहां कदम भी बढ़ते हैं और सांसें भी संतुलित रहती हैं। जहां सपने और संबंध, दोनों साथ रहते हैं। दो ताकतवर ऋतुओं के बीच खुद को बचाए हुए है शरद। वह कभी कोशिश नहीं करती गर्मी या सर्दी बन जाने की। ऐसा ही भरोसा तो चाहिए जीवन में।

काटें की बात

शुभमन गिल को वनडे की कप्तानी दिए जाने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। 2027 वनडे वर्ल्डकप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि गिल जल्द ही सभी फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे।

सुनील गावसकर, पूर्व भारतीय कप्तान

अमीर बर्बाद कर रहे खाना और भी गर्म हो रही धरती

दुनिया भर में भोजन से संबंधित जितना उत्सर्जन होता है, उसमें से 70% के लिए दुनिया के सबसे अमीर 30% लोग जिम्मेदार हैं। EAT-लांसेट की हालिया स्टडी भोजन और प्रदूषण के बारे में बताती है

डेटा Window

बढ़ती गर्मी
- 35 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों का अध्ययन
- 6-17.7 गीगाटन CO_2e/वर्ष-फूड सिस्टम का उत्सर्जन
- 30% वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सा
- 1/3 खेती, 1/3 भूमि परिवर्तन, 1/3 प्रसंस्करण, परिवहन
- $15 ट्रिलियन- प्रतिवर्ष नुकसान

समाधान
- 33% कम हो रेड मीट प्रॉडक्शन
- 63% बढ़े सब्जी-मेवे व शाकाहार
- 1/3 कम हो गाय, बकरी उत्पादन
- सुलभ स्वस्थ आहार
- पारंपरिक आहार का संरक्षण
- टिकाऊ उत्पादन पद्धतियां
- पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा
- खाद्य अपव्यय में कमी

सुझाव मानें तो
- 15% कम होगा कृषि उत्सर्जन
- 1.5 करोड़ जानें प्रतिवर्ष बचेंगी

AI Image

चुनाव हारने पर कमला हैरिस को कैसा लगा

मृत्युंजय राय

2024 राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप से मुकाबले के लिए कमला हैरिस को 107 दिन मिले थे। यही कमला हैरिस की नई किताब का नाम है, जो संस्मरण है। कमला को मौका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन के पीछे हटने से मिला। बाइडन स्वास्थ्य और अधिक उम्र की वजह से चुनाव से हटे थे। '107 डेज' नाम की किताब में कमला ने अपने प्रत्याशी चुने जाने के बाद और चुनावी नतीजे आने तक का हाल बयां किया है।

बाइडन का फोन आया । वह लिखती हैं कि लाइव टीवी पर ट्रंप के हाथों डिबेट में मुंह की खाने के बाद बाइडन पर चुनाव से हटने का दबाव बढ़ गया था। मगर वह करीब महीने भर तक अड़े रहे। तब उन्हें लगा था कि बाइडन चुनाव लड़कर ही रहेंगे, लेकिन 2024, जुलाई के आखिर में उनका बाइडन का फोन आया। इसमें बाइडन ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी। कमला का कहना है कि उन्हें बहुत सोचने का भी वक्त नहीं मिला। वह यह भी दावा करती हैं, 'डेमोक्रेट्स की ओर से मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी थी। पार्टी की ओर से मेरे जीतने की संभावना सबसे अधिक थी।'

अलग आशा । संस्मरणों को लेकर अक्सर शिकायत रहती है कि इसमें पूरी सचाई बयां नहीं की जाती। इस किताब को लिखने में कमला ने Pulitzer Prize से सम्मानित उपन्यासकार जेरल्डीन ब्रूक्स (Geraldine Brooks) का सहयोग लिया है। इसलिए, इस संस्मरण के कुछ अलग होने की आशा थी। मगर ऐसा हो न सका। कमला ने किताब में अपना कोई कमजोर पहलू सामने नहीं आने दिया है। हां, कुछ निजी क्षणों का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। ऐसा ही एक प्रसंग उनके पति डगलस एमहॉफ से जुड़ा है। कमला लिखती हैं कि चुनाव प्रचार के बीच में ही उनका जन्मदिन आया तो डगलस ने उसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई आयोजन नहीं किया। बकौल कमला, उन्हें इससे काफी दुख पहुंचा था।

तथ्यों पर बात । हालांकि, उन 107 दिनों के दौरान जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटा,

विचार विंडो

उसके बारे में कमला ने किताब में लिखा है। उस दौरान जो विवाद खड़े हुए, उन पर भी उन्होंने सफाई दी है। वह भी तथ्यपरक अंदाज में। वह लिखती हैं- मुझे इस बात का अफसोस है कि ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान जो हमले कर रहे थे, हम उसका कहीं बेहतर ढंग से जवाब दे सकते थे। इससे ट्रंप के हमलों की धार कुंद की जा सकती थी।

बहरूपिया वांस । उपराष्ट्रपति जेडी वांस को कमला ने किताब में बहरूपिया बताया है। वह लिखती हैं कि वांस रंग बदलने में माहिर हैं। कमला उनसे जुड़े एक प्रसंग का जिक्र करते हुए लिखती हैं- चुनाव प्रचार के दौरान विस्कॉन्सिन में वांस ने सुरक्षा नियमों को तोड़ा था। वह एयरफोर्स टू की ओर बढ़ रहे थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से गलत था। हालांकि, बाद में उन्होंने रिपोर्ट्स से कहा- मैं तो यह देखने जा रहा था कि भविष्य में जो प्लेन मुझे अलॉट होने वाला है, वह कैसा है। वैसे, रिपोर्ट्स को कहीं गई उनकी यह बात सच साबित हुई। एयरफोर्स वन जहां राष्ट्रपति को मिलता है, वहीं एयरफोर्स टू उपराष्ट्रपति को।

बाइडन से रिश्ते । कमला लिखती हैं- मैं बाइडन के प्रति वफादार थी, लेकिन बाद में रिश्ते उलझ गए। उनका आरोप है कि बाइडन प्रशासन में उनकी अनदेखी हुई, उन्हें दरकिनार किया गया। कमला लिखती हैं कि जब ट्रंप पॉप्युलर वोट और इलेक्टोरल वोट दोनों में जीत गए तो वह और उनके पति इस खबर से इस कदर आहत हुए कि आज तक दोनों ने हार के बारे में बात नहीं की है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

मन की गति पर ब्रेक नहीं, तो दुर्घटना का ख़तरा

सलिल पाण्डेय

जहां गतिशीलता है, वहां नियंत्रण भी जरूरी है। वह चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान नहीं, तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। वाहन चालक स्थिति-परिस्थिति के अनुसार ब्रेक का प्रयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। इसी तरह का नियंत्रण मन के स्तर पर भी जरूरी है।

तुलसीदास ने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की है। उन्होंने 'पीपर पात सरिस मन डोला' चौपाई में यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार पीपल के पत्ते हवा चलने से पीपल के पत्ते हिलने-डुलने लगते हैं, उसी प्रकार किसी भी तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो सबसे पहले मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रसन्नता के क्षणों में मन उछलने लगता है, जबकि दुख के क्षणों में निराशा, कुंठा से सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं।

AI Image

मनन करें तो पाएंगे कि जहां सब कुछ अनुकूल होने पर मन के निरंकुश होने का खतरा बन जाता है और व्यक्ति मनमानी करने लगता है, वहीं विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक कार्य करने लगता है। दोनों स्थितियां संकट उत्पन्न कर देती हैं। समाज को नियंत्रित करने के लिए हर देश में संविधान, नियम-कानून होते हैं। इसी तरह हर धर्म में संयम-नियम से जीने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे में स्व-अनुशासन या आत्म नियंत्रण, कुछ भी कहा जा सकता है।

किसी भी युग का उदाहरण लें, जिसने भी आत्म-नियंत्रण नहीं किया, उसको संकट का सामना करना पड़ा। सतयुग में हिरण्यकश्यप रहा हो, त्रेता में रावण या द्वापर में दुर्योधन - सबने आत्म नियंत्रण खो दिया। इसलिए, ये सब प्रतापी और बलिष्ठ होते हुए भी मारे गए और उनका उदाहरण निंदनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें समझ नहीं थी, लेकिन वे खुद पर लगाम नहीं लगा सके।

हर किसी को खुद अपने जीवन का संविधान बनाना चाहिए। पहला अध्याय तो उसमें यही होना चाहिए कि जिस कार्य से खुद को कष्ट मिले, वह कार्य दूसरों के साथ न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चिंत जीवन जी सकता है।

मीम बहार

जहां थरूर होते है, वहां इंग्लिश को भी अपने लिए इंग्लिश ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, फिर ट्रंप क्या चीज है

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

युद्ध लड़ने का तरीका

4 अक्टूबर का संपादकीय 'तालमेल चाहिए' पढ़ा। भारतीय वायु सेना प्रमुख दो टूक बात करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलोचना हो या फिर पाकिस्तानी सेना को उसका असली चेहरा दिखाना। पिछले दो दशकों में युद्ध लड़ने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। अब युद्ध में तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। हमें यह समझना होगा कि न केवल मशीनों और सैन्य बलों में तालमेल की जरूरत है बल्कि तीनों सेनाओं में भी अच्छा तालमेल होना जरूरी है।

बाल गोविंद, ईमेल

readersmail.nbt@gmail.com
पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

दलदली भूमि जाल

भारत को अपनी चिंताओं का समाधान करना होगा

पाकिस्तान की गतिविधियों पर सावधानी से विचार

एक सर क्रीक से सटे इलाकों में पाकिस्तान की भारी सैन्य गतिविधियों की खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है। श्री सिंह का यह बयान कि "कराची जाने का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है" भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और कूटनीति के अभाव को देखते हुए हैरान और परेशान करने वाला है। उनकी टिप्पणी की तुलना 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से की गई, जब भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाके में आगे बढ़ी थी। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक निर्जन, बड़े पैमाने पर दुर्गम दलदली भूमि है, जिसमें जलमार्गों और बदलते ज्वार-भाटे का एक जटिल जाल है। यह दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। नौवहन बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए इलाके के विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। भारत की ओर, मुहाना क्षेत्र पहले से ही स्तरित सुरक्षा के अधीन है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायु सेना की मजबूत उपस्थिति है। भारत इस क्षेत्र को तेल और गैस की खोज के साथ-साथ शिंग राइट्स के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है। कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाह, मुंद्रा और कांडला, भी निकटवर्ती क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान चलाना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ सड़कें, नागरिक आबादी और प्रशासनिक ढाँचे का अभाव है। हालाँकि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर लगभग 400 ड्रोनों से सैन्य ढाँचे पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने उनमें से कई को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन यह संभवतः दोनों देशों के बीच मोर्चे के विस्तार का संकेत था।

रणनीतिक रूप से, यहाँ मोर्चा खोलना दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन संघर्ष अक्सर तर्क या युक्तिसंगत नहीं होते। श्री सिंह, जो विजयादशमी का जश्न मनाने के लिए कच्छ में थे, का सर क्रीक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। भुज सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने बातचीत के ज़रिए मुद्दे को सुलझाने के भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इरादे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, और आगे कहा कि "सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल देगा"। गुजरात के पास कच्छ के रण के पाकिस्तानी हिस्से में चीन समर्थित खनन और बिजली परियोजनाएँ भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा रही हैं। भारत को डर है कि अगर बीजिंग और इस्लामाबाद ने मिलकर इन परियोजनाओं का फायदा उठाया, तो ये एक रणनीतिक-सैन्य चुनौती बन सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक स्थितियों में अस्थिरता को देखते हुए, भारत को सावधानी और समझदारी से कदम उठाने चाहिए। रणनीति को घरेलू राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। नई दिल्ली को अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए - लेकिन सबसे पहले कूटनीति।

जापान की लौह महिला

ताकाइची एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति है जो एक विखंडित गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है

संसद में मतदान से पहले ही

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद, साने ताकाइची ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।

जापान की प्रमुख लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। शुक्रवार को पार्टी चुनावों में अपने अधिक मध्यमार्गी प्रतिद्वंद्वी शिंजो कोइज़ुमी को हराने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 64 वर्षीय शिष्या सुश्री ताकाइची को एक सामाजिक रूप से रूढ़िवादी दक्षिणपंथी के रूप में देखा जाता है। यदि वह संसदीय वोट जीत जाती है, जैसी कि उम्मीद थी, तो उसे दशकों पुरानी कांच की छत को तोड़ने से ज्यादा कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, सुश्री ताकाइची जापानी प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला में नवीनतम हैं जिन्हें पद से हटा दिया गया है, भले ही एलडीपी और उसके सहयोगी कोमेइतो ने दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है, और उन्हें विपक्ष तक पहुंचकर एक विखंडित गठबंधन का नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी। उनके पूर्ववर्ती शिगेरु इशिबा ने एक वर्ष से भी कम समय तक सेवा करने के बाद एलडीपी के बहुमत खोने के बाद पद छोड़ दिया। यह देखना बाकी है कि सुश्री ताकाइची, जिन्होंने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, पार्टी और सरकार को एकजुट रखने में "लौह महिला" की सफलताओं का अनुकरण कैसे कर पाती हैं। इस समय स्पष्ट रूप से सबसे लोकप्रिय पार्टी नेता होने के बावजूद, वह एक ध्रुवीकरणकारी राजनीतिज्ञ हैं, जो आव्रजन के विरुद्ध अपने कड़े विचारों और जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन के पक्ष में हैं। वह कोई नारीवादी एजेंडा प्रस्तुत नहीं करतीं और विवाहित महिलाओं द्वारा उपनाम रखने या जापानी राजघराने में महिला उत्तराधिकार के अधिक विवादास्पद मुद्दे पर पुराने जापानी कानूनों की समीक्षा करने से इनकार करने के लिए उनकी आलोचना की गई है। दूसरी चुनौती भू-राजनीतिक है - संयुक्त राज्य अमेरिका में जापान का सार्वजनिक विश्वास ट्रम्प प्रशासन की कार्रवाइयों से डगमगा गया है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते पर कठोर सौदेबाजी भी शामिल है। सुश्री ताकाइची चीन के प्रति एक सख्त रुख रखती हैं, जो उन्हें बीजिंग के साथ टकराव की राह पर ला सकता है। दक्षिण कोरिया, जो जापान के प्रति गर्मजोशी दिखाने लगा था, में भी उनके उदय को कुछ चिंता की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि जापानी युद्ध नायकों की पूजा करने के लिए या-सुकुनी मंदिर में उनकी यात्राएँ और युद्ध क्षतिपूर्ति के प्रति उनका कड़ा रुख एक लाल निशान बन सकता है। अंततः, पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री सुश्री ताकाइची को जापान की दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियों और जनसांख्यिकीय गिरावट से निपटना होगा।

भारत में, उनकी जीत को काफी हद तक सकारात्मक रूप से देखा जाएगा, क्योंकि शिंजो आबे के साथ उनका जुड़ाव रहा है, जिनके कार्यकाल में भारत-जापान संबंधों में तेज़ी से सुधार हुआ। सरकार कई मोर्चों पर, खासकर तकनीक और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में, अपना सहयोग जारी रखने का प्रयास करेगी। सबसे बढ़कर, क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता और श्री ट्रम्प की हिंद-प्रशांत नीति के प्रति प्रतिबद्धता के बीच, नई दिल्ली टोक्यो में एक मज़बूत नेता की उम्मीद करेगी, जो इस क्षेत्र में वर्तमान में व्याप्त भू-राजनीतिक उथल-पुथल को कम करने में मदद करेगा।

ट्रम्प की गाजा युद्ध विराम योजना का आगे का रास्ता

टीएस तिरुमूर्ति

राजदूत थे/ स्थायी इसका प्रतिनिधि भारत से संयुक्त राष्ट्र नेशंस, न्यूयॉर्क (2020-22) और पहला इसका प्रतिनिधि भारत को गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण (1996-98)

एस की दूसरी वर्षगांठ से कुछ समय पहले हमास का इज़राइल पर हमला (7 अक्टूबर, 1944) 2023), संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी 20 सूत्री योजना का अनावरण किया गाजा संघर्ष विराम। हमास ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है लेकिन संकेत दिया है कि उसे योजना के कुछ हिस्सों पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता होगी। इससे कबूतरों के बीच बिल्ली पैदा हो गई है। श्री ट्रम्प ने इसे पश्चिम एशिया में शांति लाने के अवसर के रूप में सराहा है, जबकि इज़राइल हमास की स्वीकृति से जुड़ी शर्तों से नाखुश है। इस योजना की प्रगति पर संदेह इस साल जनवरी में जो हुआ उसे देखते हुए समझ में आता है जब अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटको द्वारा बातचीत की गई संघर्ष विराम, जिसे विस्तृत, क्रमबद्ध और दोनों पक्षों द्वारा सहमति दी गई थी, को पहले कदम के बाद इज़राइल द्वारा एकतरफा रूप से फाड़ दिया गया था। लेकिन इस बार, श्री ट्रम्प सहित सभी प्रमुख खिलाड़ी चाहते हैं कि यह योजना गाजा में शांति के आखिरी मौके के रूप में सफल हो - शायद इज़राइल सरकार को छोड़कर।

संक्षेप में, इन 20 बिंदुओं में वह सब कुछ शामिल है जो अमेरिका निकट भविष्य में गाज़ा में देखना चाहता है; और, नहीं, फ़िलिस्तीनी राज्य उनमें से एक नहीं है। यह योजना ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा युद्ध को समाप्त करने और फ़िलिस्तीनियों के लिए उनकी नष्ट हो चुकी ज़मीन पर सामान्य स्थिति लाने के इरादों का एक बयान है — और सबसे बुरा, आत्मसमर्पण का एक साधन है।

एक अकेली समय-सीमा को छोड़कर, जहाँ युद्धविराम के 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा इज़राइली बंधकों को रिहा किया जाएगा, बाकी सब कुछ एक रोडमैप बनने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। फिलिस्तीनी पक्ष द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इसका विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है—बंधकों (72 घंटों के भीतर रिहाई); हमास (निरस्त्रीकरण और/या गाजा छोड़ना); फिलिस्तीनी प्राधिकरण (सुधार या विनाश); गाजा का शासन (कट्टरपंथ-विरोधी, विसैन्यीकरण और श्री ट्रम्प की अध्यक्षता वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के अधीन टेक्नोक्रेट शासन), और सुरक्षा (गाजा में अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता बल)।

हालाँकि, इज़राइली दायित्वों (लड़ाई कब रुकेगी), क्षेत्र (इज़राइल के पास कितना और कब तक रहेगा), और इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) की भविष्य की भूमिका (गाज़ा से वापसी की कोई समय-सीमा नहीं) के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। बेशक, योजना पश्चिमी तट के बारे में चुप है।

यह योजना फिलिस्तीनियों की युद्ध थकान का लाभ उठाने तथा हमास पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई है। चाहे कोई इसकी विषयवस्तु से सहमत हो या न हो, यह सुरक्षा, आर्थिक विकास, शासन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से जुड़े पहलुओं को शामिल करता है। गाजा में जातीय सफाया की संभावना को खारिज कर दिया गया है। यदि जनादेश स्पष्ट और क्षेत्रीय हो और इसमें शामिल अन्य पक्ष प्रतिबद्ध भूमिका निभाएँ, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल एक सकारात्मक कारक हो सकता है। एक विसैन्यीकृत गाजा और एक निरस्त्र एवं विकट कट्टरपंथ मुक्त हमास के साथ इज़राइल अपनी सुरक्षा प्राप्त करेगा।

दुर्भाग्यवश, समयसीमा पर स्पष्टता का अभाव

इस योजना को दो तरीकों से देखा जा सकता है - एक तो यह कि इस योजना को समाप्त करने के इरादे का एक बयान है।

गाजा युद्ध, या आत्मसमर्पण का एक साधन

और अनुक्रमण इस ढाँचे को गाजा से इज़राइल की वापसी और सामान्य स्थिति बहाल करने के विश्वसनीय मार्ग के बजाय, केवल असंबद्ध इरादों के बयान में बदल देता है। यह पूर्ण युद्धविराम समझौता भी नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत, कार्यान्वयन के साथ-साथ लड़ाई भी जारी रह सकती है। यही वह बात है जिस पर हमास को गंभीर आपत्ति है। अगर अमेरिका और प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियाँ इज़राइल के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठातीं , तो यह शत्रुता घातक हो सकती है। यही कारण है कि श्री.

ट्रम्प का इज़राइल से गाज़ा पर बमबारी रोकने का आह्वान महत्वपूर्ण है। बेशक, ऐसा नहीं है कि इज़राइल ने अभी या पहले कभी अमेरिका की बात सुनी हो।

स्पष्ट रूप से कहें तो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी इज़राइली बंधकों की रिहाई पर रहा है, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिहा कराने के लिए भारी घरेलू दबाव में हैं। युद्धविराम के 72 घंटों के भीतर ऐसा हो जाने पर, फ़िलिस्तीनियों के भाग्य के एकमात्र निर्णायक अमेरिका और इज़राइल ही रह जाएँगे, जो संयोगवश अब वास्तविकता बन गया है। शर्तों को पूरा करने की दिशा में फ़िलिस्तीनियों की हर प्रगति, या कमी, का फ़ैसला ये दोनों ही करेंगे। कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

इसके अलावा, इज़राइली बंधकों के बदले 250 फ़िलिस्तीनी आजीवन कारावास और 1,700 फ़िलिस्तीनी बंदियों की रिहाई स्वागत योग्य है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों को अपनी इच्छानुसार गिरफ़्तार करने, कैद करने और रिहा करने की इज़राइल की घूमती हुई नीति के कारण, योजना में इस शर्त का ज़मीनी स्तर पर कोई व्यावहारिक महत्व नहीं हो सकता है। इस समीकरण को समझने के लिए, 7 अक्टूबर, 2023 से अब तक इज़राइल ने सिर्फ़ पश्चिमी तट पर ही कम से कम 18,000 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है।

ज़िम्मेदारी हमास और फ़िलिस्तीनियों पर आ जाती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह योजना युद्ध रोकने का भार हमास और फ़िलिस्तीनियों पर डालकर, गाज़ा में रोज़ाना होने वाली हत्याओं के लिए इज़राइल पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करती है। अगर वे इसे लागू नहीं करते हैं, तो गाज़ा में इज़राइल की निरंतर उपस्थिति वैध हो जाएगी और उसके लगातार हमले जायज़ हो जाएँगे। जब श्री नेतन्याहू ने घोषणा की है कि आईडीएफ गाज़ा में रहेगा, तो गाज़ा से बाहर निकलने का फ़ैसला इज़राइल को सौंपना एक बेतुका कदम है।

प्रभावी रूप से, यह योजना शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल बोर्ड के माध्यम से शासन और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखती है। यह एक संभावित अस्थायी व्यवस्था हो सकती है बशर्ते क्षेत्रीय देश प्रतिबद्ध रहें और जहाँ आवश्यक हो, इज़राइली उल्लंघनों को रोकने के लिए अमेरिका पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में संकोच न करें। अब तक, गाजा युद्ध में खाड़ी देशों की भागीदारी न्यूनतम रही है क्योंकि उन्होंने ईरान और उसके सहयोगियों के खतरे को कम करने को प्राथमिकता दी है, जिसमें इज़राइल ने उनकी मदद की है। वे क्षेत्र में अपने व्यापक हितों, जैसे अब्राहम समझौते, और ईरान के साथ अपने सैन्य संबंधों, से समझौता करने के लिए भी उतने ही अनिच्छुक हैं।

अमेरिका और सीरिया के बीच नव-निर्मित सौहार्द, एक मायावी द्वि-राज्य समाधान की वेदी पर।

एक बार गाजा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में आ गया, यह योजना भविष्य में किसी समय संभावित रूप से सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को छोड़कर, चुनावों या प्रतिनिधि शासन संरचना के लिए कोई मार्ग नहीं बताती है।

विडंबना यह है कि 2006 में, कब्ज़े वाले क्षेत्रों में हुए पिछले विधान सभा चुनावों में हमास ने जीत हासिल की थी, जिसे 44.45% वोट और 132 में से 74 सीटें मिलीं, जबकि फ़तह को 41.43% वोट और 45 सीटें मिलीं। इसके परिणामस्वरूप फ़िलिस्तीनी नेतृत्व में विभाजन हुआ और अंततः गाज़ा और पश्चिमी तट के बीच संबंध टूट गए।

अब, इस योजना में 'फ़िलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों' वाली एक तकनीकी समिति की परिकल्पना की गई है, जिसका नगरपालिका क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय शासन और एक सुरक्षा ढाँचे के तहत काम करेगा, और सीधे श्री ट्रम्प के अधीन होगा। हमास गाज़ा के शासन से हटकर एक फ़िलिस्तीनी तकनीकी समिति में शामिल होने पर सहमत हो गया था। लेकिन इस योजना के तहत, फ़िलिस्तीनियों का अपने भविष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। हमास ने इसे अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि शासन पर निर्णय व्यापक फ़िलिस्तीनी आम सहमति से लिया जाना चाहिए, जिसमें हमास भी भाग लेगा।

स्वयंभू 'ट्रम्प' आर्थिक योजना संभवतः गाजा के समुद्र तट पर 'रिवेरा' बनाने और 'आधुनिक चमत्कारिक शहर' बनाने के विचार का ही एक नया रूप है, ताकि गाजा में 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, जबकि पश्चिमी तट में हजारों लोगों को उनके शहरों, भूमि और आजीविका से उखाड़ दिया जा रहा है और गरीबी की ओर धकेला जा रहा है।

पहले, किसी ने तर्क दिया था कि फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए बातचीत में प्रक्रिया आमतौर पर ठोस तथ्यों पर भारी पड़ती है। इस बार योजना में आत्मनिर्णय के एकाध संदर्भ के अलावा कोई प्रक्रिया भी नहीं है, जो कि अमेरिका और इज़राइल दोनों जानते हैं कि इतनी दूर की बात है कि शायद कभी नहीं हो पाएगी। श्री.

नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी राज्य को कभी न देने की शपथ ली है। उनके अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों ने इस साल पश्चिमी तट पर कब्ज़ा करने की शपथ ली है।

इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह योजना अंतरराष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों या यहाँ तक कि फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए 1967 की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हालिया फ़ैसले पर आधारित नहीं है। बल्कि, यह योजना इसके बिल्कुल उलट है।

नतीजतन, बंधकों की अदला-बदली के बाद युद्धविराम कितने समय तक चलेगा? अगर ऐसा नहीं होता, तो अमेरिका और खाड़ी देश इज़राइल को आगे के हमलों से रोकने के लिए कितनी पूँजी खर्च करेंगे? फिलिस्तीन राज्य का बड़ा सवाल दरकिनार कर दिया गया है - जैसा कि बार-बार होता रहा है। पश्चिमी तट पर तेज़ी से बदलती ज़मीनी हक़ीक़त, जिसमें इज़राइली बस्तियों का निर्माण और फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करना शामिल है, अब पाठ्यक्रम से बाहर हो गया है।

रोज़गार को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानें

Sanjiv Bajaj

पूर्व राष्ट्रपति हैं, परिसंघ भारतीय उद्योग (सीआईआई)

Chandrajit बनर्जी

महानिदेशक हैं, परिसंघ भारतीय उद्योग

मैं भारत सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे युवा देशों में से एक है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अनुमान

अनुमान है कि अगले 25 वर्षों में, भारत अपनी कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) की आबादी में लगभग 13.3 करोड़ लोगों को जोड़ेगा, जो कुल वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 18% है। हालाँकि, भारत के पास इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि श्रमिक आबादी 2043 के आसपास चरम पर पहुँचने की उम्मीद है।

समानता के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है और समावेशन। बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकती हैं, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम कर सकती हैं, और विकास लाभों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित कर सकती हैं। विकास और लचीलेपन के लिए रोज़गार सृजन भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसी उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था में, अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के माध्यम से उपभोग का विस्तार विकास को गति और स्थिरता प्रदान करता है।

दीर्घकालिक रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए, रोज़गार को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी सुसंगत विकास नीतियों की आवश्यकता है जो खंडित या अल्पकालिक दृष्टिकोणों के बजाय स्थिर निवेश और दीर्घकालिक रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करें। कौशल विकास से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक, केंद्र और राज्य सरकारों की पहलों के बावजूद, भारत में अभी भी एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव है जो रोज़गार और आजीविका को व्यापक रूप से संबोधित करता हो।

रोजगार सृजन के लिए श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मांग आर्थिक और क्षेत्रीय विकास से प्रेरित होती है, जबकि आपूर्ति कौशल, गतिशीलता और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती है। इन अंतरालों को पाटे बिना, नीतिगत प्रभाव सीमित ही रहेगा। एक विशेष चिंता स्नातकों की रोजगार क्षमता है। स्नातकों को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए कॉलेज पाठ्यक्रमों की केंद्रित समीक्षा की आवश्यकता है, साथ ही उद्योग और उभरते क्षेत्रों से जुड़े कौशल कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति की तत्काल आवश्यकता है। इससे मौजूदा योजनाओं को समेकित किया जाना चाहिए और विविध पहलों को एक साथ लाया जाना चाहिए। इसे राज्यों, प्रमुख मंत्रालयों और अन्य के साथ समन्वय में विकसित किया जाना चाहिए।

भारत में अभी भी एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे का अभाव है जो रोजगार और आजीविका के मुद्दे को संबोधित करता हो

शासन की देखरेख सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जा सकती है, तथा कार्यान्वयन का नेतृत्व जिला योजना समितियों द्वारा किया जा सकता है जो स्थानीय चुनौतियों को समझती हैं।

नीति में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने, उच्च रोज़गार क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और रोज़गार सृजन को अधिकतम करने के लिए व्यापार, औद्योगिक, शिक्षा और श्रम नीतियों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। इसमें श्रम बाज़ार की बाधाओं, क्षेत्रीय असमानताओं और महिलाओं व हाशिए के समूहों के सामने आने वाली बाधाओं से भी निपटना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि कौशल विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों को शामिल किया जाए।

एक और चुनौती लोगों और नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल है। केंद्र और राज्यों को प्रवासन नीतियों और सहायता प्रणालियों पर मिलकर काम करना चाहिए जो राजनीति को बाधा बनने दिए बिना, गतिशीलता को रचनात्मक रूप से बढ़ावा दें। रोज़गार गतिशीलता के लिए "एक भारत" का निर्माण महत्वपूर्ण होगा।

चार श्रम कानूनों का समय पर क्रियान्वयन संहिताओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा व्यवसायों के लिए स्पष्ट संक्रमण दिशानिर्देश और सलाहकार सहायता आवश्यक होगी।

रोजगार सृजन के प्रयासों को श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित करना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र, जो पहले से ही 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है, को "रोजगार के साथ विकास" उत्पन्न करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी, कौशल और बाजारों तक पहुँच को शामिल करते हुए एक व्यापक समर्थन रणनीति की आवश्यकता है। शहरी रोजगार संकट को दूर करने के लिए, चुनिंदा शहरों में एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है।

एक बड़ा अवसर विस्तारित हो रही गिग इकॉनमी में निहित है, जो 80 लाख से 1.8 करोड़ कर्मचारियों को रोजगार देती है और 2030 तक बढ़कर 9 करोड़ हो सकती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में भागीदारी के विस्तार के साथ, इसमें रोजगार सृजन और औपचारिकीकरण की अपार संभावनाएँ हैं। गिग इकॉनमी के लिए एक राष्ट्रीय नीति इस क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकती है।

नीति को क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना चाहिए

कौशल, वित्त और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री निर्बाध ऑनबोर्डिंग को सक्षम कर सकती है, कार्य इतिहास को संरक्षित कर सकती है और प्रवेश बाधाओं को कम कर सकती है। निष्पक्ष अनुबंध, सुरक्षा मानक और शिकायत निवारण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सही संस्थागत और नियामक समर्थन के साथ, गिग अर्थव्यवस्था भारत के समावेशी कार्यबल की आधारशिला बन सकती है।

संख्याओं से परे, बेहतर वेतन, सुरक्षित परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से रोज़गार की गुणवत्ता में सुधार ज़रूरी है। औद्योगिक केंद्रों के पास किफायती आवास गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। 100 सबसे अविकसित ज़िलों में लक्षित हस्तक्षेप, स्नातकों के लिए ग्रामीण इंटर्नशिप, और शहरों में दूरस्थ कार्य और बीपीओ के माध्यम से क्षेत्रीय रूप से संतुलित रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़ाना एक और प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए रोज़गार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के तहत प्रोत्साहन, आंगनवाड़ी और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं को औपचारिक रूप देना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में निवेश, और महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने वाले सामाजिक मानदंडों को दूर करने के लिए अभियान चलाना आवश्यक है।

रोज़गार आँकड़ों की ज़रूरत: अंततः, उच्च-गुणवत्ता वाला, वास्तविक समय का रोज़गार आँकड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समर्पित कार्यबल कार्यप्रणाली को मज़बूत कर सकता है, अनौपचारिक और ग्रामीण कार्यबल तक पहुँच का विस्तार कर सकता है, और आँकड़ों के संग्रह और प्रकाशन के बीच के अंतराल को कम कर सकता है।

समन्वित सुधारों, लक्षित निवेशों और एक समावेशी राष्ट्रीय रोज़गार रणनीति के साथ, भारत अपने रोज़गार परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। ऐसा करना न केवल अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि समतापूर्ण, सुदृढ़ और सतत विकास प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

ये रोज़गार-केंद्रित उपाय उस व्यापक सुधार एजेंडे से भी जुड़े हैं जिसे सीआईआई ने प्रतिस्पर्धी भारत के लिए नीतियों पर अपनी हालिया रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। जैसा कि इस लेख में ज़ोर दिया गया है, रोज़गार सृजन एक प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है।

द टटर्सटूदएडिटर

फार्मा गुणवत्ता एवं नियंत्रण मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल औद्योगिक विलायक हैं

ग्लिसरीन जैसी दवाइयों के अवयवों को दूषित करना। या,

आपूर्तिकर्ता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सस्ती औद्योगिक सामग्री का उपयोग करके गुणवत्ता से समझौता करते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दवा उत्पादन सुविधाओं पर अधिक कठोर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना चाहिए।

और अच्छे विनिर्माण प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

डॉ. थॉमस पालोकारेन, वेल्लोर, तमिलनाडु

यह अजीब है कि मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर को सिरप लिखने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया है। समझ नहीं आता कि आख़िर किस तरह से...

डॉक्टर सिरप की सामग्री के लिए जिम्मेदार था क्योंकि उसने इसे बाजार में किसी भी अन्य दवा की तरह निर्धारित किया था।

वह न तो निर्माता है और न ही गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी। भारत में दवा उत्पादों की गुणवत्ता मुख्य मुद्दा है।

जेपी रेड्डी, नलगोंडा, तेलंगाना

हाथ से लिखना इस डिजिटल युग में, हस्तलिखित पत्रों और नोटों की गर्मजोशी और निजी स्पर्श धीरे-धीरे गुमनामी में खोते जा रहे हैं। कभी संवाद करने का एक पसंदीदा तरीका, आज की पीढ़ी का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपलब्धता के कारण इससे कोई लेना-देना नहीं है।

संचार। इलेक्ट्रॉनिक संदेश रोबोटिक और गैर-भावनात्मक संचार हैं ('ओपन पेज', 5 अक्टूबर)।

रूद्र बेनीवाल, संगरिया, राजस्थान

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में पूरा डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

राष्ट्रीय सहारा
पटना • सोमवार • 6 अक्टूबर• 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कीर्ति का नशा शराब के नशे से भी तेज है।
शराब छोड़ना आसान है, कीर्ति छोड़ना आसान नहीं
-सुदर्शन

मोदी की सोच से आगे बढ़ता भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में 75 वर्ष के हो गए है। इस अवसर पर देश ने न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा और उपलब्धियों को याद किया, बल्कि यह भी महसूस किया कि उनकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच ने देश को नई दिशा दी है। मोदी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन विचारों और मूल्यों की कहानी है जो भारत को विकास और गौरव के पथ पर ले जाने का लक्ष्य रखते है। इस मौके पर मुझे मोदी का 7 फरवरी 2013 का वह भाषण याद आता है, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दिया था। मुझे याद है मोदी के भाषण में विकास, प्रगति और वृद्धि मुख्य शब्द रहे थे। उन्होंने उस भाषण में जो कुछ कहा था, उसे पीएम बनने के बाद जिस प्रकार धरातल पर साकार किया है, उससे जाहिर है उन्होंने देश के बारे में कितना कुछ पहले ही सोच रखा था। नियति ने मोदी की सकारात्मक सोच के चलते उन्हें देश की सत्ता के सर्वोच्च शासनाध्यक्ष पद पर पहुंचाया। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में मोदी ने राष्ट्र सर्वोपरि माना और इसी के अनुरूप वह काम कर रहे हैं।

मुझे स्मरण है मोदी कॉलेज में वैश्विक परिदृश्य में उभरते व्यावसायिक मॉडल विषय पर व्याख्यान देने आए थे। उस अद्भुत अवसर का साक्षी होने का मौका मुझे भी मिला। मीडिया मोदी के उस भाषण को उन पांच भाषणों में मानता है, जिन्होंने मोदी को एक प्रखर वक्ता और राष्ट्रीय राजनेता के रूप में स्थापित किया। मेरा सौभाग्य है कि न केवल मैंने मोदी का भाषण सुना बल्कि जब वह कार्यक्रम के बाद प्रस्थान कर रहे थे तो उनसे हाथ मिलाने का मौका भी मिला। इस दौरान पता नहीं किस भावना से प्रेरित हो कर मैंने उनसे कह भी दिया कि आप पीएम बनेंगे और देश आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी बात सुन मोदी कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ गए। जब वह बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उनके जेहन में एक ही बात थी और वह था-देश का भविष्य। उन्होंने देश को केन्द्र में रखकर काम करना शुरू किया और लगातार करते आ रहे है। कॉलेज में मोदी ने अपने भाषण में डेवलपमेंट शब्द को बीस बार, चुनौतियां शब्द 16, यूथ शब्द 15, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी 9, गवर्नेंस 8, होप 6, ब्रांड 5, प्राइड 5, मॉडल 4 और फ्रेंड्स शब्द को 180 बार बोला था। उस समय इसकी मीमांसा मैंने नहीं की थी लेकिन अगर आज इस पर गौर करते है तो हमें अहसास हो जाता है कि मोदी के मन में देश के लिए किस तरह की परिकल्पनाएं थीं। भले ही मोदी ने पीएम पद की महत्वाकांक्षा कभी नहीं रखी पर देश की अर्थ व्यवस्था को पंख लगाने, विकास की ऊंची उड़ान और युवाओं के बूते भारत की तकदीर बदलने तथा भारत को विश्व गुरु बनाने की महत्वाकांक्षा उन्होंने जरूर पाल रखी थी। नियति ने इसी वजह उनके देश पीएम पद पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया।

पीएम बनने के बाद मोदी ने देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए। पीएम गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के विकास के मार्ग को मजबूत किया। इन पंक्तियों को लिखते समय मुझे स्मरण हो रहा है कि भ्रष्टाचार, कुशासन और आर्थिक गतिरोध जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा था कि भारत इन बाधाओं से तभी पार पा सकता है जब वह अपने अवसरों का सही उपयोग करे। और उनके नेतृत्व में यह हुआ भी है। मोदी सरकार ने जनधन योजना, जीएसटी सुधार, ई-गवर्नेंस पहल और आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। आज भारत वैश्विक स्तर पर गर्व के साथ अपनी पहचान बना रहा है।

पीएम बनने के बाद मोदी ने अपनी सोच को मूर्त रूप देते हुए युवाओं के लिए अनगिनत अवसर सृजित किए। उनकी सरकार ने कौशल विकास मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया मिशन और युवा उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर करोड़ों युवाओं को सशक्त बनाया है। आज भारत के युवा न केवल देश में, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे है। पीएम बनने के बाद मोदी ने ई-गवर्नेंस, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मोदी ने अपने भाषण में तीन स्तंभों यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास का मॉडल पेश किया था। यह सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू करके अपने संकल्प को सिद्धि में बदला। कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और कृषि विपणन सुधार के माध्यम से किसानों को सशक्त किया गया है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक व्यापार के केंद्र में खड़ा कर दिया है। आज मोदी के प्रयासों से भारत की नई पहचान बनी है और भारत विश्व मंच पर गर्व के साथ उभरा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, युवा शक्ति सशक्त है, और तकनीकी क्षेत्र में देश अग्रणी बन रहा है।

सांस्कृतिक/ धरोहर

कथक सम्राट बिरजू महाराज

नृत्य की एक जीवंत कथा

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में कथक का नाम आते ही सबसे पहले जो नाम मन में उभरता है, वह है पंडित बिरजू महाराज। वे केवल एक नर्तक नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत परंपरा थे जिन्होंने कथक को लोक और शास्त्र, भाव और ताल, सौंदर्य और साधना सबका अद्भुत संगम बना दिया। उनका जीवन एक कथा की तरह है, जिसमें कला, समर्पण और परंपरा का गहरा ताना-बाना बसा है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ। उनका असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। वे प्रसिद्ध कालका-बिंदादिन घराने से संबंध रखते थे, जो कथक की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित शाखाओं में से एक है। बचपन से ही घर में संगीत और नृत्य का वातावरण था। उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज स्वयं लखनऊ घराने के सुप्रसिद्ध नर्तक थे। पिता के सानिध्य में ही बिरजू महाराज ने नृत्य की पहली शिक्षा पाई। सिर्फ सात वर्ष की आयु में ही उन्होंने मंच पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। किशोरावस्था में ही वे कथक के मंच पर एक नायाब नाम बन चुके थे। उनकी नृत्य शैली में अद्भुत लय, मुख-मुद्राओं की कोमलता, भावनाओं की गहराई और ताल की सूक्ष्मता देखने को मिलती थी।

बिरजू महाराज केवल एक श्रेष्ठ नर्तक ही नहीं, बल्कि एक प्रखर गुरु और संगीतज्ञ भी थे। वे दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी से जुड़े कथक केंद्र के संस्थापक गुरुओं में रहे और वहां से उन्होंने असंख्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। उनकी नृत्य रचनाओं में कृष्ण-लीला, रामायण के प्रसंग, और लोकजीवन की झलकियाँ देखने को मिलती थीं। उन्होंने कथक को केवल मंदिरों या दरबारों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि रंगमंच पर उसे नई पहचान दी। फिल्म जगत में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देवदास, विश्वरूपम, उमराव जान, और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया। विशेष रूप से मोहे रंग दो लाल (बाजीराव मस्तानी) में दीपिका पादुकोण का नृत्य उनके निर्देशन की अमर झलक देता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि की अनिवार्यता

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी तकनीकी विशेषताओं ने जहां एक ओर स्वच्छ परिवहन का रास्ता खोला है, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक नई चुनौती भी पेश की है। दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक इंजनों की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। यह विशेषता कई मायनों में लाभकारी है क्योंकि इससे शोर प्रदूषण कम होता है, किंतु यह मौन संचालन पैदल यात्रियों और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सड़क पर चलते समय अधिकांश लोग आने वाले वाहन की उपस्थिति का अनुमान उसके इंजन की आवाज़ से ही लगाते है। जब वाहन बिना आवाज़ के आ जाए तो सड़क पार करने वाले व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लग पाती और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति पहले से ही बेहद चिंताजनक है। हर वर्ष लगभग डेढ़ लाख लोग इन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठते है और चार से पांच लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते है। इनमें पैदल यात्रियों की हिस्सेदारी लगभग 16 फीसदी रहती है। ऐसे में, यदि सड़क पर बड़ी संख्या में मौन इलेक्ट्रिक वाहन उतरेंगे तो दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तो यह स्थिति और भी कठिन हो सकती है क्योंकि वे वाहन की गति और दूरी का अनुमान पूरी तरह श्रवण इंद्रिय से ही लगाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के साथ यह अनिवार्य हो गया कि उन्हें एक कृत्रिम ध्वनि चेतावनी प्रणाली से लैस किया जाए।

इसी परिप्रेक्ष्य में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय का कहना है कि एक अक्टूबर 2027 से देश की सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी अवार को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। हालांकि नए मॉडल के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह नियम एक वर्ष पहले ही, अर्थात एक अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। इसके तहत हर वाहन को इस प्रकार की प्रणाली से लैस किया जाएगा, जो कम गति पर चलते समय एक कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करे और पैदल यात्रियों को वाहन की मौजूदगी का संकेत दे। इस तकनीक का आधार एआईएस-173 मानक होगा जिसमें ध्वनि से संबंधित सभी प्रावधान पहले से ही निर्धारित है।

बता दें कि ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाहन की गति और दिशा के अनुसार ध्वनि की तीव्रता और स्वर बदलते रहते हैं। यदि वाहन धीरे चल रहा है तो आवाज़ भी हल्की होगी और यदि गति अधिक है तो ध्वनि का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रणाली सामान्यतः बीस किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पर सक्रिय रहती है, क्योंकि इस सीमा के ऊपर वाहन के टायर और हवा की घर्षण ध्वनि स्वयं ही श्रव्य हो जाती है। प्रणाली से उत्पन्न ध्वनि का स्तर न तो बहुत अधिक होता है कि वह शोर प्रदूषण पैदा करे और न ही इतना कम कि

सुनाई न दे। आमतौर पर यह आवाज़ 56 से 75 डेसिबल के बीच रखी जाती है, जो मानवीय कान के लिए सुरक्षित है।

दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों में कृत्रिम ध्वनि प्रणाली के उपयोग का जहां तक सवाल है तो बता दें कि कई देश इस तकनीक को पहले ही अपना चुके है। अमेरिका में 2018 से यह नियम लागू है कि सभी नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में कृत्रिम ध्वनि प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। यूरोपीय संघ ने 2019 से और जापान ने 2010 से ही इसे लागू कर दिया था। इन देशों के अनुभव बताते है कि इस प्रणाली ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है और दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत में भी यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हमें यह समझना होगा कि ध्वनिक चेतावनी प्रणाली को सड़क सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपनाया जाना नितांत आवश्यक है चूंकि इससे पैदल यात्रियों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों को सुरक्षा का एहसास होगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, बाजारों और आवासीय कॉलोनियों में वाहन की उपस्थिति का संकेत लोगों को पहले ही मिल जाएगा। दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

हालांकि इस तकनीक को अपनाने में कुछ चुनौतियां भी है। पहला, इससे वाहन की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि कंपनियों को अतिरिक्त उपकरण लगाने होंगे। दूसरा, यदि अलग-अलग कंपनियां अलग ध्वनियों का प्रयोग करेंगी तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी एक हद तक सामने आ सकती है यदि आवाज़ का स्तर अनुचित ढंग से निर्धारित किया गया। चौथा, यह प्रणाली यदि खराब हो जाए तो वाहन फिर से असुरक्षित हो सकता है। इन सबके बावजूद, लाभ और सुरक्षा की दृष्टि से यह पहल कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का लक्ष्य है कि आने वाले पाँच से सात वर्षों में शहरी सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित हो। यदि यह लक्ष्य पूरा होता है तो रोज़ाना करोड़ों लोग इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करेंगे। ऐसे में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के बीच ध्वनिक चेतावनी प्रणाली का अनिवार्य किया जाना केवल औपचारिक प्रावधान नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का अपरिहार्य उपाय है। अपेक्षा यही है कि भविष्य में इन ध्वनियों का मानकीकरण कर पूरे देश में एक समान पहचान सुनिश्चित की जाएगी, ताकि न केवल भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा का स्तर भी नयी ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक इंजनों की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। यह विशेषता कई मायनों में लाभकारी है क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है, किंतु यह मौन संचालन पैदल यात्रियों और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सड़क पर चलते समय अधिकांश लोग आने वाले वाहन की उपस्थिति का अनुमान उसके इंजन की आवाज़ से ही लगाते हैं। जब वाहन बिना आवाज़ के आ जाए तो सड़क पार करने वाले व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लग पाती और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

अली खान
(स्वतंत्र लेखक एवं शिक्षक)
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जैसलमेर, राजस्थान में पदस्थापन।
विभाग : प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
विगत सात वर्षों से पर्यावरणीय, सामाजिक एवं तकनीकी विषयों पर सतत लेखन।

भक्ति की पवित्र परंपराओं से ओतप्रोत मां विंध्यवासिनी देवी

भारत भूमि देवी-देवताओं की आराधना और भक्ति की पवित्र परंपराओं से ओतप्रोत रही है। इन्हीं में एक प्रमुख शक्ति स्थल है सिद्ध पीठ मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी है। मां विंध्यवासिनी देवी को अधिष्ठात्री देवी माना गया है, जिनकी कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं।

मां विंध्यवासिनी का स्वरूप और महिमा : पुराणों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने असुर महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं की रक्षा हेतु दुर्गा रूप धारण किया, तो उन्होंने महिषासुर का वध करने के बाद विंध्य पर्वत पर निवास किया। तभी से वे विंध्यवासिनी कहलाईं अर्थात विंध्याचल में वास करने वाली देवी। मां का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और सौम्य है। वे तीनों शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप मानी जाती है।

तीन देवियों का त्रिकोण स्थल : विंध्याचल क्षेत्र को त्रिकूट या त्रिकोण कहा जाता है, क्योंकि यहां तीन प्रमुख शक्तिपीठ स्थित है मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा, और मां कालीखोह। कहा जाता है कि इन तीनों स्थलों की परिक्रमा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते है और जीवन में समृद्धि आती है। नवरात्र के दिनों में यहां लाखों श्रद्धालु माता की दर्शन-पूजन के लिए आते है।

मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व : विंध्याचल मंदिर का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीरामचंद्र जी ने लंका जाने से पहले यहां आकर मां विंध्यवासिनी की पूजा की थी। इतिहासकारों के अनुसार, यह मंदिर गुप्तकाल से ही अस्तित्व में है और समय-समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है।

भक्तों की आस्था और उत्सव : मां विंध्यवासिनी की पूजा पूरे वर्ष होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहां भव्य मेला लगता है। इन नौ दिनों में विंध्याचल नगरी जय माता दी के जयघोष से गूंज उठती है। भक्त दूर-दूर से पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंचते है और दर्शन-पथ पर मां के दर्शन करते है। श्रद्धालु नारियल, चुनरी, और प्रसाद अर्पित कर मां से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते है।

रीडर्स मेल

मुनाफा कमाएं पर ईमान बना रहे

व्यक्ति को भूख लगती है। उसे बस पेट भरने की बूझती है। भूख गरीब-अमीर सभी को लगती है। गरीब की बात करें वह ट्रेन में जिस मजबूरी में सफर करता है, वही जाने। ऐसे ही कुछ व्यक्ति दूसरी जगह मेहनत-मजदूरी को जाते हैं। इसलिए ट्रेन का सफर इनके लिए सहूलियत है। बीच में उन्हें भूख लगती है। भूख लगने पर व्यक्ति पूरा रेलवे स्टेशन छान मारता है कि कहीं पंद्रह रुपये में पेट भर जाए। उसे निराशा हाथ लगती है। दरअसल, यह भी मुनाफाखोरी की तस्वीर है। जब शोर मचता है तो सस्ते खाने का बोर्ड लगता है। फिर वही पुराना ढर्रा चल पड़ता है कि आदमी खाने के ज्यादा पैसे दे। इसमें रेलवे और खाने के पैकेट देने वालों की मिलीभगत है। सभी जानते हैं कि कोई चीज कम दर पर बेचने से मुनाफा कम होता है। वैसे मुनाफा कमाना बुरा नहीं है। अगर सामान बेचने वाला मुनाफा नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या लेकिन मुनाफा इतना होना चाहिए व्यक्ति का ईमान बना रहे। नहीं तो बेईमान कहलवाने पर उसकी भर्त्सना ही होती है।

रजनी अग्रवाल, रायबरेली

ओजोन परत को लेकर जागृति

ओजोन परत का संरक्षण हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ओजोन परत एक फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, जिसके तहत सूर्य की किरण में उपस्थित पराबैंगनी किरण, अवांछित धूलकण, सूक्ष्म एवं अदृश्य विकार फिल्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो जाते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश शुद्ध हो जाता है एवं वायुमंडल में पृथ्वी पर गतिमान होकर जीवन को संचालित करने में अमृत बूंद का काम करता है जो जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण एवं जरूरी है। हर साल 16 सितम्बर को अंतरराष्ट्रीय आयोजन परत दिवस मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत को संरक्षण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करने की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिन को आयोजन पर संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। वर्तमान में 196 देशों का समूह है जो ओजोन परत संरक्षण का हिस्सा बनकर जागृत कर रहा है।

तारामुनी देवी, वैशाली, बिहार

कार्की पर दारोमदार

सुशीला कार्की की नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी नेपाल के इतिहास में मील का पत्थर है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर अगले वर्ष मार्च तक के लिए उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उनको यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में बदलाव का प्रतीक हैं। कार्की के सामने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अथव्यवस्था एवं पर्यटन को वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है। चूंकि अंतरिम सरकार के गठन में उन्होंने जेन जी के प्रतिनिधियों से भी गहन विमर्श करा है तो आशा करेंगे की वह उन सब युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगी। उन्हें हरसंभव प्रयास करना होगा की इन युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और भ्रष्टाचार में लिप्त जो की ओली सरकार रही है उस छवि से अगली सरकार को मुक्त करवाएं। चीन हाल के सालों में नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो कार्की को भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत रखते हुए चीन की पकड़ को नियंत्रित करना होगा।

राम कुमार, रांची

एकजुट हों सियासी दल

यह निर्विवाद सत्य है कि मणिपुर ने पिछले ढाई वर्षों में हिंसा और अस्थिरता की लंबी त्रासदी झेली है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का प्रदेश दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शांति और विकास की राह में एक महत्त्वपूर्ण संदेश है। यह यात्रा न केवल मणिपुर के लोगों, बल्कि पूरे देश को यह भरोसा दिलाती है कि इस आग में झुलसे प्रदेश को फिर से सामान्य जीवन की ओर ले जाना केंद्र की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति से जनता को यह आश्वासन अवश्य मिला है कि राज्य की पीड़ा और चुनौतियों के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील है तथा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एकजुट होकर शांति बहाली में योगदान दें।

तरुण कुमार, हरियाणा

letter.editorsahara@gmail.com

प्लास्टिक प्रदूषण, गहराता वैश्विक संकट व असफल होती वैश्विक संधि

मुद्दा

अनिरुद्ध गौड़
वरिष्ठ पत्रकार

एक समय था जब प्लास्टिक को आधुनिक सभ्यता की बड़ी खोज माना गया था। समय बीता प्लास्टिक उत्पादन में नई खोजें हुईं और प्लास्टिक उद्योग ने पूरे विश्व में चारों ओर छा गया। लेकिन अंधाधुंध प्लास्टिक के उपयोग ने वर्तमान में विश्व के पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा कर दिया है। हाल ही में द लैसेंट जरनल की एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण से हर साल वैश्विक स्वास्थ्य पर करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का बोझ पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि यदि प्लास्टिक प्रयोग का यदि यही आलम रहा तो वर्ष 2040 तक पर्यावरण रिसाव 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। परिणाम होगा कि 2016 से 2040 के बीच प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान की राशि 281 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकती है।

मालुम हो कि सन 1950 में जहां विश्व में सिर्फ 2 मेगाटन प्लास्टिक का उत्पादन होता था, वहीं 2022 तक यह बढ़कर 475 मेगाटन तक पहुँच गया। अनुमान है कि अगले तीन दशकों में यानी 2060 तक यह उत्पादन 1200 मेगाटन तक पहुंच सकता है। विडंबना यह है कि इस विशाल मात्रा में उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10 प्रतिशत ही पुनर्चक्रण किया जा पाता है, बाकी प्लास्टिक नदियों, समुद्रों और लैंडफिल में जमा होकर प्रदूषण फैलाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर 57 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा खुले में जलाया जाता है। इससे वायु प्रदूषण की समस्या गहरा रही है। हाल यह है कि करीब 8 हजार मेगाटन प्लास्टिक कचरा ग्रह को प्रदूषित कर रहा है।

प्लास्टिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न माइक्रोप्लास्टिक अब केवल मिट्टी, पानी और वायुमंडल तक सीमित नहीं रहेय वे मानव शरीर में भी प्रवेश कर चुके है। ये सूक्ष्म कण ह्मदय, फेफड़े, आंत, रक्त और यहां तक कि गर्भस्थ शिशु तक पहुँच चुके हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए है। प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में देशों ने सर्वसम्मति से नैरोबी में प्रस्ताव 5/14 पारित किया था, जिसका उद्देश्य 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। इस लक्ष्य के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि तैयार की जानी थी, जिसके लिए अब तक पाँच अंतर-सरकारी वार्ता सत्र आयोजित हो चुके है।

चिंताजनक बात है कि इस प्लास्टिक संधि को लेकर पिछले दिनों 5-15 अगस्त, 2025 को जिनेवा में संपन्न हुआ पांचवाँ सत्र बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। मुख्य मुद्दों जैसे प्लास्टिक उत्पादन पर वैश्विक सीमा, हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध और वित्तीय सहायता पर कोई सहमति नहीं बन सकी। सौ से अधिक देश उत्पादन सीमाओं के पक्षधर रहे, वहीं सऊदी अरब, रूस, ईरान और अमेरिका जैसे पेट्रो-राष्ट्र इसका विरोध में रहे है।

विश्व के विकासशील देशों की मांग है कि उन्हें तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता मिले ताकि वे प्लास्टिक प्रदूषण से निपट सकें, जबकि अमीर देश अनिच्छुक है। साथ ही, कुछ राष्ट्र इस संधि को बाध्यकारी बनाने के बजाय स्वैच्छिक उपायों की दिशा में बढ़ना चाहते है। भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। नेचर पत्रिका के एक अध्ययन के अनुसार, भारत हर साल करीब 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग पांचवां हिस्सा है। भारत ने संधि वार्ता में विकासशील देशों के हितों की वकालत करते हुए प्लास्टिक उत्पादन सीमा का विरोध किया है।

हालांकि, भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए है। 2019 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में देश को सिंगल-यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया था। 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस पर भी उन्होंने दोहराया कि भारत सतत विकास की दिशा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए संकल्पबद्ध है।

आज प्लास्टिक का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। उत्पादों की पैकेजिंग, निर्माण, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों में भी बड़ा उपयोग है। इसका सस्ता, टिकाऊ और बहुपरकीय स्वरूप इसे व्यावसायिक दृष्टि से आकर्षक बनाता है, लेकिन इसके अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता इसे अभिशाप में बदल रही है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल करीब 40 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 90ः या तो जलाया जाता है या लैंडफिल में जमा हो जाता है। कई गरीब देशों में प्लास्टिक जलाने से वायु प्रदूषण और गंभीर बीमारियाँ फैल रही है। प्लास्टिक उद्योग पर पेट्रोकेमिकल लॉबी का दबदबा, वैश्विक राजनीतिक मतभेद और आर्थिक हितों की टकराहट इस समस्या के समाधान में सबसे बड़ी बाधा बन चुके है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की कार्यकारी निदेशक इन्गर एंडरसन का मानना है कि भले ही संधि अभी तक न बनी हो, लेकिन प्रयास जारी रहेंगे। उधर, संधि के पक्षधरों का मानना है कि कमजोर संधि बनने से यही अच्छा है कि यह नहीं हुई।

माना जाए तो जिनेवा वार्ता की विफलता केवल एक कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक चेतावनी है। यदि शीघ्र ही कोई ठोस, बाध्यकारी और सर्वसम्मत संधि नहीं बनती, तो प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़े सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्यगत संकटों की गंभीरता और बढ़ जाएगी। इस समस्या से निपटने को विश्व के सभी देश राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएं, साथ ही अपने राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाएं। यह केवल सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी प्लास्टिक खपत की आदतों में बदलाव लाना होगा। सतत विकास का रास्ता केवल तकनीकी समाधान से नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और व्यवहार परिवर्तन से ही संभव होगा। प्लास्टिक के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण को बढावा देने में जागरूकता और वैकल्पिक विकल्पों को अपनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे।

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । **स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ***।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, **फैक्स :** 2535935,2520760 **विज्ञापन**-3911455/434, **प्रसार**- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6794
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

बरेली की हिंसा और चुन्ना मियां

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 'आई लव मोहम्मद' नारे को लेकर जो कोहराम मचा हुआ वह पूरे भारत की संलिष्ठ संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) के विरुद्ध ही नहीं बल्कि नैतिक आचार के भी विरुद्ध है। जहां तक बरेली का सम्बन्ध है तो यह शहर एक तरफ जहां इस्लाम के एक फिरके का मुख्यालय है तो दूसरी तरफ स्व. फजलुर रहमान उर्फ चुन्ना मियां द्वारा बनाये गये लक्ष्मी-नारायण मन्दिर का भी साक्षी है। बरेली के साहूकारा मोहल्ले में बने इस मन्दिर के लिए चुन्ना मियां ने अपनी जमीन दी, बल्कि पचास के दशक में मन्दिर निर्माण के लिए एक लाख एक रुपये की आर्थिक मदद भी की। मन्दिर निर्माण के समय खुद चुन्ना मियां ने इस मन्दिर के लिए कारसेवा भी दी। मन्दिर में चुन्ना मियां की तस्वीर भी लगी हुई है। यह इस बात का सबूत है कि भारत के मुसलमान भी सामाजिक एकता के लिए पूरी तरह संवेदनशील रहे हैं और हिन्दू संस्कृति के प्रति भी उनका आदर भाव रहा है। चुन्ना मियां का जीवन एक सन्त जैसा था जिनके लिए सभी हिन्दू-मुसलमान सच्चे भारतीय थे। 1960 में जब यह मन्दिर चुन्ना मियां बनवा रहे थे तब भारत के पहले राष्ट्रपति स्व. राजेन्द्र प्रसाद ने भी अपनी शुभ कामनाएं चुन्ना मियां को दी थीं। अत: जिस शहर की विरासत इतनी बुलन्द हो उसमें हिन्दू-मुसलमानों के बीच भाईचारे को नजरअन्दाज करना मूर्खता होगी। मगर हम यह भी जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ और इस पूरी कौम को मुल्ला-मौलवियों व इस्लामी आलिमों के भरोसे छोड़ दिया गया। इसके चलते यह समाज शेष भारतीयों की प्रगति के साथ कदम से कदम मिला कर नहीं चल सका। इसका प्रमाण पिछली मनमोहन सिंह सरकार द्वारा मुस्लिमों की माली हालत जानने के लिए गठित सच्चर कमेटी की वह रिपोर्ट है जिसमें खुलासा किया गया था कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से भी ज्यादा खराब है। बेशक इंसान का पहला धर्म इंसानियत ही होता है जिसके बाद दुनियादारी में पहचान दिलाने वाले दूसरे धर्म आते हैं। मगर एक सप्ताह पहले गुजरे दिन शुक्रवार को बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' की आड़ में जिस प्रकार साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की उससे यही सन्देश गया कि इस्लाम बजाये शान्ति के उग्रता का परिचय देता है जबकि यह पूरी तरह गलत है।

> **इस्लाम धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जिसमें समाजवादी पुट है, क्योंकि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब सलै-अल्लाह-अलै-वसल्लम फरमा कर गये हैं कि अपने पड़ौसी का हमेशा ध्यान रखो और देखो कि उसके घर में खाना पका है कि नहीं। इसके साथ रमजान के मौके पर रोजा रखने के साथ ही हर मुसलमान को यह हिदायत है कि वह समाज के गरीब तबके के लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए अंशदान या जकात दे। ऐसा धर्म हिंसा की वकालत कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से 1922 के करीब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया व 1941 के करीब हरिजन पत्र में लिखा कि इस्लाम मूलत: शान्ति का धर्म है।**

इस्लाम धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जिसमें समाजवादी पुट है, क्योंकि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब सलै-अल्लाह-अलै-वसल्लम फरमा कर गये हैं कि अपने पड़ौसी का हमेशा ध्यान रखो और देखो कि उसके घर में खाना पका है कि नहीं। इसके साथ रमजान के मौके पर रोजा रखने के साथ ही हर मुसलमान को यह हिदायत है कि वह समाज के गरीब तबके के लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए अंशदान या जकात दे। ऐसा धर्म हिंसा की वकालत कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से 1922 के करीब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया व 1941 के करीब हरिजन पत्र में लिखा कि इस्लाम मूलत: शान्ति का धर्म है। मगर दिक्कत यह है कि मुल्ला-मौलवियों व आलिमों ने इसकी आक्रामकता के पुट को उभारा और इस पर कयामत यह हुई कि पिछली सरकारों ने केवल मुसलमानों के धार्मिक तुष्टीकरण को ही अपना कर्त्तव्य मान लिया। इस पर तुर्रा यह लग गया कि 1947 में केवल मजहब की बुनियाद पर ही मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान बनवा कर अंग्रेज सरकार लन्दन चली गई। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 के पहले स्वतन्त्रता युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच घृणा के बीज बहुत गहरे जाकर बो दिये और बीसवीं सदी में 1906 में मुस्लिम लीग बनवा कर और 1908 में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव मंडल घोषित करके भारत की संलिष्ठ संस्कृति को भीतर से ही लहूलुहान कर डाला। अंग्रेज यहीं नहीं रुके 1919 में उन्होंने सिख नागरिकों लिए भी पृथक चुनाव मंडल बना डाला।

स्वतन्त्र भारत की विडम्बना यह रही कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूरी कौम को ही अनपढ़ बनाये रखने में पूरी शक्ति लगा दी जिससे उनकी सियासी दुकानदारी फलफूल सके। बरेली में जिस तरह विगत शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा ने दंगा भड़काने का प्रयास किया वह गवाही दे रहा है कि मुस्लिम कौम को धर्म के नाम पर बहलाना-फुसलाना कितना आसान हो सकता है। भारत के मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि स्वतन्त्र भारत में वे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से उतने ही लैस होते हैं जितना कि कोई हिन्दू नागरिक। अत: उन्हें भूलकर भी आवेश में आकर किसी मुल्ला या मौलवी के चढ़ाये में नहीं आना चाहिए और न किसी दूसरे सम्प्रदाय के प्रति वैरभाव रखना चाहिए। सभी भारतीय हैं और इस वैभवशाली भारतीय धरा पर निवास करते हैं। जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न है तो उन्हें भी संविधान के दायरे में रह कर अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार करना चाहिए और किसी भी सूरत में दूसरे धर्म के अनुयाइयों के प्रति अनादर व अपमान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बीते दशहरे व नवरात्रे के अवसर पूरे भारत में रामलीलाओं का मंचन होता है जिसमें मुस्लिम नागरिक भी पूरी खुशी के साथ कलाकार बन कर भाग लेते हैं। क्योंकि कलाकार सिर्फ रंगकर्मी ही होता है। बरेली में जिस तरह जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की उसके लिए धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। भारत तो वह देश है जिसमें गुरु नानक देव जी महाराज भी हुए और कबीरदास जैसे महान सन्त भी। भारत की विविधता का वर्णन जितनी संवेदनशीलता के साथ नानकवाणी में किया गया है उसका मुकाबला क्या कोई कर सकता है। यह वाणी इस प्रकार है-

कोई बोल्लै राम-राम कोई खुदाये
कोई सेवे गुस्सैयां, कोई अल्लाये
कारन कर करण करीम, किरपाधार तार रहीम
कोई न्हावै तीरथ, कोई हज जाये
कोई करे पूजा, कोई सिर नवाये
कोई पढ़ै वेद, कोई कछेद
कोई औढ़े नील, कोई सफेद
कोई कहे तुरक, कोई कहे हिन्दू
कोई बांचै बहिश्त, कोई सुर बिन्दू
कहै नानक जिन हुकुम पछाया प्रभु साहब के तिन भेद पाया।

धरातल पर हकीकत कुछ और...

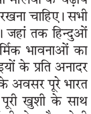

आज के नेता सड़कों पर कम, सोशल मीडिया पर अधिक नजर आते हैं,
और जनता के दुख-पीड़ा पर भी एक धारावाहिक बनाते हैं,
कैसे मुस्कुराना है और कहां आंसू बहाते हैं,
पीआर टीम नेताजी को उनका यह रोल बताते हैं,
धरातल पर हकीकत कुछ और भाषणों में जन्नत दिखाते हैं,
जनता के सवालों से दूर, कैमरों के पास आते हैं !!

गीता पाढा

राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता भरा था मल्होत्रा का व्यक्तित्व

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा के मूल संस्कार क्या हैं ? विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन, स्वयं से ऊपर सेवा भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही।

वीके मल्होत्रा जी के परिवार ने विभाजन का भयावह दौर झेला। उस आघात और विस्थापन ने उन्हें कड़वा या आत्मकेंद्रित नहीं बनाया। इसके बजाए, उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा में राष्ट्रसेवा का रास्ता नजर आया। बंटवारे का वो समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। मल्होत्रा जी ने सामाजिक कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने उन हजारों विस्थापित परिवारों की मदद की, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। उनका जीवन संवारने और उन्हें फिर से खड़े होने में मदद की। यही जनसंघ की प्रेरणा थी। उन दिनों उनके साथी मदनलाल खुराना जी और केदारनाथ साहनी जी भी बढ़-चढ़कर सेवा कार्यों में शामिल होते थे। उन लोगों की निस्वार्थ सेवा को आज भी दिल्ली के लोग याद करते हैं।

1967 के लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तब अपराजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले रहे थे। इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक कम चर्चित चुनाव भी हुआ। वो था, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का पहला चुनाव। राष्ट्रीय राजधानी में जनसंघ ने शानदार जीत दर्ज की। आडवाणी जी काउंसिल के चेयरमैन बने और मल्होत्रा जी को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की जिम्मेदारी दी गई, जो मुख्यमंत्री के लगभग बराबर का पद था। तब उनकी उम्र केवल 36 वर्ष थी। उन्होंने अपने कार्यकाल को दिल्ली की जरूरतों, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया।

इस जिम्मेदारी ने मल्होत्रा जी का दिल्ली से जुड़ाव और मजबूत कर दिया। जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर मल्होत्रा जी सक्रिय रूप से जनता के साथ खड़े होते और उनकी आवाज बुलंद करते। उन्होंने 1960 के दशक में गौ रक्षा आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जहां उनके साथ पुलिस की ज्यादतियां भी खूब हुईं। आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। दिल्ली की सड़कों पर जब सिखों का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा था, तब वे शांति और सद्भावना की आवाज बनकर सिख समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे। उनका मानना था कि राजनीति, चुनावी सफलता के अलावा सिद्धांतों, मूल्यों और लोगों की रक्षा के लिए भी है, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

1960 के दशक के उत्तरार्ध में वीके मल्होत्रा जी सार्वजनिक जीवन का एक स्थायी चेहरा बन गए थे। बहुत कम नेता ऐसा दावा कर सकते हैं कि उनके पास लोगों के बीच रहकर काम करने का इतना लंबा और ठोस अनुभव है। वो एक अथक कार्यकर्ता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक संस्था निर्माता थे। उनमें चुनावी राजनीति और संगठनात्मक राजनीति, दोनों में समान रूप से सहजता के साथ काम करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने जनसंघ और भाजपा की दिल्ली इकाई को स्थिर नेतृत्व दिया।

अपने लंबे सेवाकाल में मल्होत्रा जी ने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, राज्य विधानसभा में भी पहुंचे और देश की संसद में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ उनकी शानदार जीत समर्थकों और विरोधियों के बीच आज भी याद की जाती है। ये एक बेहद हाई-प्रोफाइल चुनाव था। कांग्रेस की पूरी ताकत उनके दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में उतर आई थी, लेकिन मल्होत्रा जी ने कभी बहस का स्तर नीचे नहीं किया। उन्होंने पॉजिटिव कैंपेन चलाया। गालियों और हमलों को नजरअंदाज किया और 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ प्रचार के दम पर नहीं मिली थी। ये जीत मल्होत्रा जी की जमीन पर मजबूत पकड़ की वजह से मिली थी। कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध बनाकर रखने और मतदाताओं के मन की थाह लेने में वो माहिर थे।

मल्होत्रा जी संसद में सटीक तैयारी के साथ अपनी बात रखते थे। वो पूरी रिसर्च करके आते थे और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते थे। यूपीए-1 के दौरान विपक्ष के उपनेता के रूप में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए एक मूल्यवान सबक की तरह है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार का प्रभावी ढंग से विरोध किया। उन दिनों मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अक्सर मल्होत्रा जी से बातचीत होती। वो हमेशा गुजरात की विकास यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे।

राजनीति, वीके मल्होत्रा जी के व्यक्तित्व का केवल एक पहलू थी। वो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद भी थे। उनके परिवार से मुझे पता चला कि उन्होंने स्कूल में डबल प्रमोशन हासिल किया। उन्होंने मैट्रिक और ग्रेजुएशन निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली। उनकी हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषणों का हिंदी अनुवाद प्राय: वही करते थे।

उन्हें नई संस्थाएं और नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी जाना जाता है। वे आरएसएस से जुड़ी कई संस्थाओं के संस्थापक और संरक्षक रहे। उनके प्रयासों से अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ और मार्गदर्शन मिला। इन संस्थाओं के माध्यम से कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन में बनी संस्थाएं प्रतिभा और सेवा की पाठशालाएं बनीं। उन्होंने एक ऐसे समाज का विजन दिया, जो आत्मनिर्भर हो और मूल्यों पर टिका हो।

मल्होत्रा जी ने राजनीति और अकादमिक जीवन से परे, खेल जगत में भी अमिट छाप छोड़ी। तीरंदाजी उनका गहरा शौक था और वो कई दशकों तक आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय तीरंदाजी को ग्लोबल पहचान मिली। उन्होंने खिलाड़ियों को मंच और अवसर दिलाने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए। खेल प्रशासन में भी उन्होंने वही गुण दिखाए जो सार्वजनिक जीवन में थे, यानी समर्पण, संगठन क्षमता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज।

वीके मल्होत्रा जी को आज लोग उनके द्वारा संभाले गए पदों के साथ ही उनकी संवेदनशीलता के लिए भी याद कर रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्तित्व की रही, जो हमेशा लोगों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। जहां भी मदद की जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटे। वे आदर्श पार्टी कार्यकर्ता थे, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे जिससे हमारे कार्यकर्ताओं या विचारधारा को ठेस पहुंचे।

कुछ दिन पहले, मैं दिल्ली भाजपा के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां मैंने स्नेहपूर्वक श्री वीके मल्होत्रा जी को याद किया था। इस वर्ष तीन दशक बाद जब भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो वो बहुत उत्साहित थे। उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिन्हें हम पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और उपलब्धियों से प्रेरणा पाती रहेंगी।

स्वामी विवेकानंद की लाहौर यात्रा

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

वह नवम्बर का ही महीना था। वर्ष था 1897, जब प्रख्यात चिंतक, विचारक व अध्यात्म-गुरु स्वामी विवेकानंद ने लाहौर की यात्रा की थी। वहां इस यात्रा के मध्य उन्होंने तीन व्याख्यान दिए थे। जब उनकी लाहौर-यात्रा का कार्यक्रम बना, तब सबसे बड़ी समस्या उन्हें ठहराने व उनके प्रवचनों के लिए मंच तैयार करने की थी। स्वामी जहां भी जाते, उनके शिष्यों की टोलियां भी साथ-साथ जाती थीं। उनकी संख्या भी सैकड़ों में होती थी। आखिर निर्णय यही हुआ कि उन्हें हीरामंडी क्षेत्र में स्थित राजा ध्यान सिंह डोगरा की हवेली में ठहराया जाए।

नवंबर (1897) में स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ आए तो उन्हें हीरामंडी स्थित राजा ध्यान सिंह की हवेली में ही ठहराया गया, जहां अतीत में जगद्गुरु शंकराचार्य भी ठहरे थे। गोस्वामी जी (तीर्थराम) और उनके शिष्यों ने उनके व्याख्यानों की व्यवस्था भी उसी स्थान पर की थी। वहां काफी खुला स्थान था फिर भी वहां इतनी भीड़ होती थी कि सभी लोगों को जगह देना संभव नहीं था। सौभाग्य से प्रो. बोस का सर्कस उन दिनों लाहौर में आ गया था। कोई विकल्प न होने के कारण स्वामी जी का व्याख्यान सर्कस के पंडाल में ही आयोजित करना पड़ा।

गोस्वामी जी ने बड़ी रुचि और उत्साह से उनके व्याख्यान सुने और दूसरों को भी उन्हें सुनने के लिए प्रेरित किया। वे स्वामी विवेकानंद जी के इतने घनिष्ठ हो गए कि उन्हें अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए भी ले आए। उनके पाश्चात्य शिष्यों ने भी वहीं भोजन किया। भोजन करने के बाद विदा लेने से पहले स्वामी जी ने गोस्वामी जी के निजी पुस्तकालय में झांका और एक पुस्तक भी उठाई। पंजाबियों के खून में यह सामान्य है कि वे किसी भी अतिथि या पवित्र व्यक्ति की पूरी तरह से सेवा करते हैं और उन्हें सबसे प्रिय चीजें उपहार में देने की कोशिश करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु, एक सोने की घड़ी दी लेकिन स्वामी जी ने इसे गोस्वामी जी की जेब में वापस रखते हुए कहा कि वे 'इसे स्वयं उपयोग करेंगे'। यद्यपि स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात वेदांती और बहुत उच्च कोटि के संन्यासी थे, फिर भी उन्होंने चंडी-पाठ कभी नहीं छोड़ा। वे बड़े चाव से इसका पाठ करते थे।

उन दिनों वहां के एक धनाढ्य धर्मपरायण व्यावसायी लाला हुकूमत राय गोस्वामी जी के विशेष रूप से जुड़े हुए भक्त थे। वह ही गोस्वामी जी के निर्देशों के अनुसार व्याख्यानों की व्यवस्था करते थे। वह गोस्वामी जी के साथ स्वामी विवेकानंद से भी मिलने जाते थे। गोस्वामी जी की यह प्रथा थी कि जब कोई प्रसिद्ध वक्ता लाहौर आता था, तो वे भक्तजी (हुकूमत रायजी) और पंडित लड्ढा मल मुरलीवाला को बुलाते थे। इसी क्रम में पंडित लड्ढा मल जी को बुलाया गया। लेकिन वह उस दिन आया जब अगले ही दिन स्वामी जी को कोलकाता के लिए प्रस्थान करना था। उस दिन गोस्वामी जी स्वामी जी से मिलने वाले थे। इसी बीच लड्ढामल जी भी आ गए और उनके साथ स्वामी जी के पास गए। रात में उनके बीच विचार-विमर्श हुआ। स्वामी विवेकानंद जी पंडित जी की योग्यता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि यदि वे उनके साथ कोलकाता चलें तो वे उनके लिए 200 रुपये मासिक वेतन की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन पंडित जी नहीं माने।

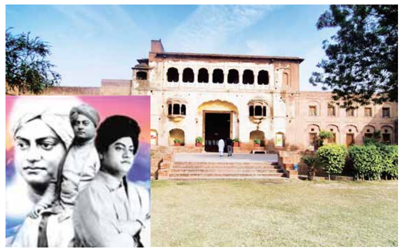

अंत में स्वामी जी ने पंडित जी को एक पाउंड स्टर्लिंग (गिनी) और एक रेशमी पगड़ी भेंट करते हुए कहा कि गांवों में तो पंडित जी जैसे योग्य व्यक्ति कम ही मिल पाते हैं। लेखक, गोस्वामी तीर्थ राम (बाद में स्वामी राम तीर्थ) के भतीजे, गोस्वामी बृजलाल भी उनके साथ वहीं रहते थे। बाद में उन्होंने अपने चाचा (स्वामी रामतीर्थ) की उर्दू में एक जीवनी लिखी (लाहौर से प्रकाशित, 1912)। उस समय गोस्वामी तीर्थराम लाहौर के एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे और बाद में स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर संन्यासी बन गए।

(रायपुर केंद्र से प्रकाशित रामकृष्ण संघ की हिंदी मासिक पत्रिका विवेक ज्योति के संपादक, स्वामी विदेहात्मानंद ने वेदांत केसरी के लिए यह जानकारी प्रदान की है)। गोस्वामी बृजलाल द्वारा 'स्वामी विवेकानंद के संस्मरण' भी उन्हीं दिनों लाहौर से प्रकाशित हुई। स्वामी विवेकानन्द ने 1897 में लाहौर की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तीन महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में उन्होंने अद्वैतवाद के महत्व पर जोर दिया और लोगों को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, का चर्चित संदेश दिया जो राष्ट्रीय जागृति और सामाजिक सुधार के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान था। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस लाहौर की यात्रा के मध्य अपने व्याख्यानों में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छुआ था। उन्होंने यहां तीन प्रमुख व्याख्यान दिए-

'कॉमन बेसिस ऑफ हिंदूइज्म' (5 नवंबर को दिया गया)
'भक्ति' (विषय पर व्याख्यान 9 नवंबर को दिया गया)
'वेदांत' (इस विषय पर 12 नवंबर को विशिष्ट प्रवचन दिया गया)

उनका 'वेदांत' पर दिया गया व्याख्यान एक गहन और प्रभावशाली भाषण था जिसकी डिजिटल प्रति 40 पृष्ठों में प्राप्त है और आज भी लोगों को प्रेरित करती है।

अद्वैतवाद का संदेश

उन्होंने लाहौर के युवाओं को अद्वैतवाद का ध्वज उठाने का आह्वान किया, यह समझाते हुए कि सभी में एक ही परमेश्वर विद्यमान हैं।

राष्ट्रीय जागृति का आह्वान

'उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए', का नारा राष्ट्रीय चेतना और जागृति का एक शक्तिशाली आह्वान था जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देता था।

आंतरिक शक्ति पर जोर

उन्होंने लोगों से हिंदू ग्रंथों से सीखकर अपनी कमजोरी की स्थिति से बाहर निकलने का आग्रह किया क्योंकि वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। स्वामी जी ने लाहौर में आर्य समाज और सनातन धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकातें की और उनसे विचारों का आदान-प्रदान किया।

इन महत्वपूर्ण व्याख्यानों के बाद, स्वामी विवेकानंद देहरादून की ओर निकले और अपने भविष्य के कार्यों को जारी रखा। स्वामी विवेकानंद का पंजाब से सीधा जुड़ाव कम रहा लेकिन वे पंजाबियों के स्वभाव और उनकी 'पंजाबियत' के कायल थे, खासकर लाहौर में उन्होंने एक विशाल जनसमूह के बीच ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था और बार-बार दोहराया था कि उन्हें स्वीकार भी किया था कि पंजाब से खास लगाव था। उन्हें पंजाब के लोगों के आत्मबल और उनकी प्रेरणादायक क्षमता में विश्वास था और उन्हें अपने आदर्शों के लिए एक मजबूत आधार मिला था। उन्हें पंजाब के लोगों के भीतर आत्मबल और प्रेरणादायक क्षमता की शक्ति का एहसास था। वर्ष 1897 में लाहौर में एक बड़े जनसमूह के सामने उन्होंने अपना ऐतिहासिक व्याख्यान दिया जिससे उनका जुड़ाव बना और लोगों में संदेश पहुंचा।

अपनी यात्राओं के दौरान वे कई राज्यों और शहरों से गुजरे लेकिन पंजाब उनके जीवन में उतना प्रत्यक्ष नहीं रहा जितना दक्षिण भारत का मद्रास या राजस्थान का अलवर लेकिन पंजाब के लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद का अपना एक खास रिश्ता था। वे भारतीय संस्कृति की पहचान को लेकर पंजाब के लोगों के योगदान को लेकर सदा उत्सुक रहते थे।

मुख्यमंत्री बदलने की बातें 'अप्रासंगिक', सिद्धारमैया पूरे करेंगे पांच साल

- **कुछ समय से अटकलें हैं कि इस साल के अंत में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है**

कोप्पल, (पंजाब केसरी): कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायारेड्डी ने मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों को रविवार को अप्रासंगिक करार दिया और कहा कि कांग्रेस विधायकों के बहुमत से इस पद के लिए चुने गए सिद्धारमैया पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी के भीतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर रायारेड्डी ने कहा कि कोई भी इस पद की आकांक्षा रख सकता है। रायारेड्डी ने कहा कि उनके अपने समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बराबर ही चुनाव जीते हैं। रेड्डी ने मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा-यह अप्रासंगिक है। पार्टी हाईकमान ने कहा है कि मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं - मुख्यमंत्री का चयन पार्टी हाईकमान ने विधायकों की राय जानने के बाद किया था।

उन्होंने कहा-मतदान हुआ, सिद्धारमैया और अन्य ने चुनाव लड़ा और सिद्धारमैया को अधिक वोट मिले। हमें यह नहीं बताया गया था कि सिद्धारमैया को अपने कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि वह पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। राज्य के राजनीतिक हलकों में, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में पिछले कुछ समय से अटकलें हैं कि इस साल के अंत में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है और इसके लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला दिया जा रहा है।

कटक में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद

- **कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समूहों में हिंसा हुई, विश्व हिन्दू परिषद ने आज शहर में दिन भर के बंद का आह्वान किया है**

कटक, (पंजाब केसरी): ओडिशा सरकार ने कटक शहर में हाल ही में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय गृह विभाग द्वारा रविवार शाम को लिया गया। कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समूहों में पिछले दिनों हुई हिंसा की घटना को लेकर विश्व हिन्दू परिषद ने सोमवार को शहर में दिन भर के बंद का आह्वान किया है। इस बीच शहर में रविवार को भी तनाव की स्थिति कायम रही। जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फैलाए जा रहे भड़काऊ और उकसाने वाले संदेशों को रोकना है, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता था। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिला प्रशासन ने इस संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की थी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कुछ लोग झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं, जिससे शहर में तनाव का माहौल बन रहा है। इसी आधार पर सरकार ने 5 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे से लेकर 6 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया।

इस निलंबन के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित समान सेवाएं, सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की डेटा सेवाएं, ब्रॉडबैंड और डायल-अप कनेक्शन तथा इंटरनेट ट्रांसमिशन के अन्य सभी माध्यम शामिल हैं। यह प्रतिबंध कटक नगर निगम क्षेत्र, कटक विकास प्राधिकरण क्षेत्र और जिले के अंतर्गत आने वाले 42 क्षेत्रों में लागू किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस सत्यव्रत साहू ने बताया कि यह निर्णय कटक में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से फैलने वाले गलत और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक था। सभी मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निलंबन आदेश का पालन करने और गृह विभाग को इसके कार्यान्वयन की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

जागरुकता सूर्य की तरह है। जब यह चीजों पर चमकती है, तो वे रुपांतरित हो जाती हैं। -थिक नात हान्ह

दो राज्यों में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा-नियामक व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। इस त्रासदी के बाद नीति नियामकों में जो सक्रियता दिख रही है, उम्मीद है कि उसके ठोस नतीजे निकलेंगे, ताकि ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो।

मासूमों की मौत

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से जहरीले कफ सिरप से ज्यादातर पांच वर्ष से कम उम्र के मासूमों की मौत की दिल दहलाने वाली खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह संकट दवा निर्माण, वितरण और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में गंभीर खामियों को दिखाता है। दरअसल, सितंबर की शुरुआत में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जब पांच वर्ष से कम आयु के कई बच्चे एकाएक स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते मरने लगे, तो अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जमीनी जांच शुरू हुई, दूषित जल स्रोत, रोग फैलाने वाले चूहे और मच्छरों की आबादी-सभी कुछ जांचा गया, लेकिन कुछ ठोस नहीं पता चल सका। माता-पिता की असहमति से बच्चों का पोस्टमार्टम न करा पाना जांच में बाधा बना रहा। फिर जब सभी बच्चों की किडनी के काम करना बंद होने की बात सामने आई, तब इसे कफ सिरप से जोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। इसी तरह राजस्थान से भी करीब तीन बच्चों के मरने की खबर है, जिनका जिम्मेदार कायसन फार्मा के एक कफ सिरप को माना जा रहा है। जांच में पाया गया कि तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे विषैले रसायन निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाए गए हैं। यह त्रासदी 2022 में गांबिया और उज्बेकिस्तान में कथित भारतीय सिरप से हुई मौतों की याद दिलाती है। सवाल उठता है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा? ऐसी घटनाएं देश की दवा-नियामक व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करती हैं। हर राज्य में ड्रग कंट्रोलर दवा के प्रत्येक बैच की जांच के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि निरीक्षण औपचारिकता बनकर रह गया है। ऐसे भी दृष्टांत हैं, जिनमें गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही दवाएं सरकारी योजना के तहत फिर से वितरित की जा रही हैं। ऐसे में, सवाल यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटी जाने वाली दवाएं कितनी सुरक्षित हैं। यह तंत्रगत भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है। ऐसी विडंबनाओं से देश की 'दुनिया के फार्मेसी हब' वाली छवि पर आघात पहुंचेगा। अब समय है कि दवा उद्योग और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। वहीं डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को भी बच्चों को कोई सिरप या एंटीबायोटिक दवा देने से पहले पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। त्रासदी के बाद दोनों राज्य सरकारों ने विवादित सिरपों पर प्रतिबंध लगाया है और जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। उम्मीद है कि यह कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहेगी और इससे व्यवस्था में ठोस बदलाव आएंगे।

ताकि दवा जहर न बन जाए

भारत का फार्मा और जेनेरिक दवा क्षेत्र जीवंत है और बच्चों की मौतों जैसे हादसे इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं। निरीक्षण, तर्कसंगत नुस्खे और पारदर्शी संचार के मजबूत तंत्रों के साथ, हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं।

डॉ चंद्रकांत लहारिया
वरिष्ठ चिकित्सक

मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौतों की हालिया खबरें जो कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं, जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि शुरुआत में यह बताया गया था कि दूषित कफ सिरप के कारण किडनी में गंभीर क्षति हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के संदूषण से इन्कार किया है। वर्ष 2022 में गांबिया में भारत में निर्मित कफ सिरप से होने वाली मौतों से जुड़ी ऐसी ही खबरें सामने आई थीं। सरकार ने उन मौतों का भी खंडन किया था और दावा किया था कि उनका कफ सिरप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से भारतीय दवाओं और सिरप की गुणवत्ता पर सवाल तो उठते ही हैं।

भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, जो देश के भीतर और अन्य निम्न व मध्यम आय वाले देशों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराता है। भारत कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां भी बनाता है। ऐसे में, ये घटनाएं देश के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकती हैं और जनता के विश्वास एवं दवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती हैं। यह घटना व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर करती है, जिनके लिए दवा नियमन और निरीक्षण में कमियों, आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों, असुरक्षित और अत्यधिक नुस्खे लिखने और देने के तरीकों की जांच और जनता के विश्वास में आई कमी का विश्लेषण बेहद जरूरी है। सबसे पहले, रिपोर्टों के बाद अधिकारियों ने नमूने जब्त कर लिए, जिनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) का स्तर खतरनाक रूप से उच्च पाया गया। डीईजी-दूषित कफ सिरप कोई नई घटना नहीं है: गांबिया में बच्चों की मृत्यु की एक अंतरराष्ट्रीय जांच में घटिया सिरप की पहचान की गई और 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की।

यह घटना दवा जांच की गड़बड़ियों की ओर इशारा करती है और ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों के प्रति जनता के मन में संदेह पैदा होता है। ऐसी मौतें और सरकारी एजेंसियों की विरोधाभासी रिपोर्टें भारतीय दवाओं के विदेशी खरीदारों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। दवाओं के निर्माण में (जिनमें सिरप भी शामिल हैं) हर कदम पर, यानी परिवहन के लिए प्रमाणित आपूर्तिकर्ता, मजबूत आंतरिक परीक्षण, कड़े बैच नियंत्रण और पारदर्शी आपूर्ति-शृंखला रिकॉर्ड इत्यादि पर गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता होती है। जब इनमें से एक भी कड़ी टूटती है, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। दीर्घावधि में, नियामकों को घटना हो जाने पर सक्रिय होने की जगह घटना से पहले ही सक्रिय रोकथाम की ओर बढ़ना होगा। बेहतर विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) ऑडिट, रियल-टाइम बैच ट्रैकिंग, और एक ऐसी उद्योग संस्कृति विकसित करनी होगी, जहां दवा अनुपालन को बढ़ावा मिले, न कि उसे टाला जाए।

यह स्थिति खांसी की दवा जैसी दवाओं के अत्यधिक उपयोग या डॉक्टर के पर्चे के बिना ली गई दवाओं की याद भी दिलाती है। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अंतर्निहित बीमारी का एक लक्षण है। ज्यादातर मामलों में, यह अपने आप ठीक हो जाती है और खांसी की दवा केवल सहायक देखभाल के काम आती है। लेकिन भारत में खांसी से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नतीजा है कि बच्चों के लिए सिरप का व्यापक और अक्सर अनावश्यक इस्तेमाल, जिससे मांग बढ़ती है और तेजी से उत्पादन और वितरण को बढ़ावा मिलता है। यह मांग बदले में, कम लागत वाले या अनुचित तरीके से परीक्षण किए गए उत्पादों के बाजार में आने का जोखिम बढ़ा देती है।

भारत में खुदरा दवाइयों का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सामुदायिक फार्मेसी सर्वेक्षणों और क्षेत्रीय अध्ययनों का अनुमान है कि देश भर में आठ लाख लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानें हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर औषधि निरीक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियों में सैकड़ों स्वीकृत निरीक्षक के पद खाली पड़े हैं, जिससे उनका निरीक्षण नहीं हो पता और राज्य भी इसी तरह की कमियों की रिपोर्ट कर रहे हैं। नियामकों और फार्मेसियों के अलावा, दवा प्रचार प्रथाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। आक्रामक विपणन रोगियों को नुकसान पहुंचाते हैं और चिकित्सकों को अधिक दवा लिखने के लिए प्रभावित करते हैं। साथ ही, भारत को जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देते रहना चाहिए, पर बाजार में आने के बाद कड़ी निगरानी और स्वतंत्र गुणवत्ता सत्यापन के साथ, ताकि चिकित्सकों और आम जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि जेनेरिक दवाएं न केवल सस्ती हैं, बल्कि सुरक्षित और उतनी ही कारगर भी हैं।

दो राज्यों में हुई बच्चों की मौतों से स्थानीय फार्मासिस्टों, चिकित्सकों और नियामकों पर भरोसा कम हो रहा है। इस आपदा को रचनात्मक सुधार में बदलने के लिए दवाओं और औषधियों के उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति के बेहतर नियमन और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरा, स्वीकृत औषधि निरीक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरना चाहिए। फार्मेसियों और अस्पतालों से निरंतर निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, तर्कसंगत दवाइयां और जनता में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा में निवेश करना चाहिए, ताकि माता-पिता अनावश्यक दवाओं की मांग कम करें। चौथा, दवाओं की मंजूरी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारों की विनियमन क्षमता लचीली है, और मंजूरी में भ्रष्टाचार की भी खबरें आती रहती हैं। राज्य दवा नियामक निकायों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। पांचवां, विश्वास बहाली के लिए पारदर्शी संचार व्यवस्था हो। परीक्षणों के परिणाम, रिकॉल की समय-सीमा और स्पष्ट सलाह क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए। तेज और ईमानदार संचार विश्वसनीयता बनाए रखता है। छठा, गुणवत्ता-आधारित जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भारत का फार्मा और जेनेरिक दवा क्षेत्र जीवंत है और ऐसी घटनाएं इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती हैं और उपभोक्ताओं को ब्रांडेड और महंगे उत्पादों की ओर धकेल सकती हैं। निरीक्षण, तर्कसंगत नुस्खे और पारदर्शी संचार के लिए मजबूत तंत्रों के साथ, हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और साथ ही सस्ती दवाओं के विशाल लाभों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हमें ऐसी घटनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि भारत में फार्मा क्षेत्र और दवाओं के नुस्खे और उपयोग प्रथाओं को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

मार्कस ऑरेलियस

प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और देखें कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। इसे अपनाने से, हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं।

अच्छे जीवन का मतलब निरंतर सुधार है

देवताओं के प्रति समर्पण करना, मानवजाति के प्रति न्यायपूर्ण होना, और प्रत्येक प्रभाव की इतनी सावधानी से जांच करना कि कोई भी ऐसी चीज प्रवेश न कर जाए, जिसकी अच्छी तरह जांच न की गई हो, यह हमेशा और हर जगह आपके वश में है। इन सिद्धांतों का पालन करना हमेशा और हर व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, और यह आंतरिक शांति और सदाचार प्राप्त करने की कुंजी है। दूसरों के विचारों के बारे में कभी भी बेतरतीब सवाल न करें, बल्कि सीधे उस लक्ष्य को देखें, जो प्रकृति ने आपके लिए निर्धारित किया है। प्रकृति या तो ब्रह्मांड की है या आपकी अपनी। पहली, आपको ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाती है और दूसरी, आपको अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब जो चीजों की संरचना के अनुकूल है, वही उन्हें उपयुक्त लगता है। प्रकृति और संसार को बुद्धिमान प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों की सेवा और उपयोग के लिए बनाया गया है और तर्कसंगत प्राणी एक-दूसरे के लाभ के लिए बने हैं। अब सामाजिक स्वभाव वह है, जिसके लिए मानव प्रकृति मुख्य रूप से अभिप्रेत है। हमारे अस्तित्व में अगली चीज भौतिक प्रभावों से सुरक्षित रहना है, क्योंकि यह तर्क का विशिष्ट विशेषाधिकार है कि वह अपने भीतर गति करे, और संवेदना या वासना को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि ये दोनों पशुवत और निम्न गुणवत्ता के हैं। लेकिन समझ का हिस्सा शासन करने का दावा करता है, और पदार्थ या इच्छा के आगे नहीं झुकता, क्योंकि वह आदेश देने और उनका उपयोग करने के लिए ही पैदा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपनी तर्कसंगत बुद्धि का उपयोग सहमति की प्रक्रिया की पवित्रता को समझने और उसे बनाए रखने के लिए करता है, तो वह अपने स्वयं के जीवन, निर्णयों और अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। और फिर वह अपनी हर चीज का स्वामी बन जाता है। भीतर की शांति मन की व्यवस्थित अवस्था है, जिसे सद्गुणों को पोषित करके और नैतिक मूल्यों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की धारा में बहते हुए, हमेशा याद रखें कि सुख और दुख, दोनों ही क्षणिक हैं, इन्हें अपनी आत्मा पर हावी न होने दें। अच्छा जीवन वह है, जिसमें हम अपनी भूमिका को समझें, जैसे कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा होकर हम दूसरों की सेवा में बिना किसी अपेक्षा के योगदान दें। हर निर्णय में स्वयं से पूछें कि क्या यह न्यायपूर्ण है, क्या यह आवश्यक है, और क्या यह मेरी आत्मा की शांति को बनाए रखेगा? सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक सद्गुणों में निहित है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और देखें कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाता है। इसे अपनाने से, हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। अच्छे जीवन का अर्थ है निरंतर सुधार की यात्रा है, जहां हर कदम हमें ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने की ओर ले जाता है। हमेशा मानव जाति के लिए कुछ-न-कुछ उपयोगी करते रहें, और इस निरंतर उदारता को ही अपने जीवन का आनंद बनाएं।

हरदम प्रयास करें

सूत्र

बाहरी विचारों को बगैर जांचे अपने जीवन में न उतारें, और कभी भी दूसरों के बारे में बेतरतीब पूछताछ न करें, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इन बातों का ध्यान रखकर ही आप आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, और बाहरी उलझनों से बच सकते हैं। हरदम पहले से खुद को बेहतर करने का प्रयास करते रहें।

दूसरा पहलू

लोग कुत्तों को अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदते हैं और सड़कों पर छोड़ देते हैं, आंकड़े चिंताजनक हैं।

वह कार कौन-सी है, जो मुझे मेरे घर ले जाएगी

भूपेंद्र कुमार

1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार, किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ना अपराध है।

वह अगस्त की एक बरसाती शाम थी, यमुना एक्सप्रेस-वे पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों के बीच दूर से वह एक काला धब्बा-सा नजर आ रहा था। छह या सात माह का काला-भूरा जर्मन शेफर्ड कारों के पीछे आड़ा-तिरछा दौड़ रहा था। इस कोशिश में कई बार वह कारों से टकराते-टकराते बचा। उसे शायद उम्मीद थी कि इन्हीं में से कोई कार उसके मालिक की होगी। वे कार रोकेंगे और उसे वापस घर ले जाएंगे। पर शायद इन्सान की दुनिया में इन्सानियत नहीं है। इस प्यारे से डॉग को उसके मालिक ने बीमार होने या किसी और वजह से यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा टोल प्लाजा के पास छोड़ दिया। यह सिर्फ उस अकेले जर्मन शेफर्ड की सच्चाई नहीं है। शौक-शौक में महंगी कीमत पर विदेशी नस्ल के श्वानों की खरीद तो होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस जिम्मेदारी को उठा पाते हैं। उन्हें तो बस अपने बच्चों के लिए एक खिलौना चाहिए होता है। एक अनुमान के तहत, देश भर में हजारों कुत्तों को उनके मालिक सड़कों पर छोड़ जाते हैं। इनमें दस फीसदी विदेशी नस्ल के शहरी पालतू कुत्ते होते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशंस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच साल में शहरों में पालतू कुत्तों को छोड़ने की प्रवृत्ति में 50 फीसदी तक इजाफा हुआ है।

शौक-शौक में विदेशी नस्ल के श्वानों की खरीद तो होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस जिम्मेदारी को उठा पाते हैं। एक अनुमान के तहत, देश भर में हजारों कुत्तों को उनके मालिक सड़कों पर छोड़ जाते हैं।

1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार, किसी पालतू जानवर को लावारिस छोड़ना अपराध है, दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो फिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? असल में किसी पिल्ले को अपनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका एहसास शौक-शौक में खरीदने वालों को उस वक्त नहीं होता। समय से टीका लगवाना, वेटरनरी डॉक्टरों को दिखाना, बाहर टहलाने ले जाना और सबसे जरूरी समय देना। कोविड के समय घर में बोर हो रहे लोगों ने बड़ी संख्या में कुत्तों को खरीदा या गोद लिया, पर कोविड बीतते ही ज्यादातर को सड़कों पर यों ही छोड़ दिया गया। आगरा में कैस्पर होम डॉग शेल्टर चलाने वाली विनीता अरोड़ा कहती हैं कि इस समस्या का समाधान माइक्रो चिप में है। इससे कुत्ते के मालिक के बारे में पता चल सकेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ज्यादातर लोग बीमार कुत्तों को छोड़ देते हैं। नोएडा में डिस्पेंसरी फॉर स्ट्रे एनिमल चलाने वाले संजय महापात्र कहते हैं कि कुत्तों को पालने का फैसला लोग सोच-समझकर नहीं करते। उनके पास माह में 15 से 20 छोड़े गए कुत्ते आते हैं। इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर आहट पर उन्हें लगता है कि उनके मालिक लेने आए हैं। यही शायद यमुना एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों के पीछे भाग रहे उस जर्मन शेफर्ड ने भी सोचा होगा।

आंकड़े

भोजन की बर्बादी

दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, जबकि ब्राजील में लोग खाना फेंकने के मामले में हर साल रिकॉर्ड बना रहे हैं।

ब्राजील	94
चीन	76
अमेरिका	73
भारत	55
फिलीपींस	26

बर्बाद खाने के आंकड़े प्रति वर्ष के हिसाब से किलोग्राम में हैं। | स्रोत : UNEP FWI

अंतर्यात्रा

एक दिन काम से लौटते हुए शिव कुमार से डाकुओं ने रास्ते में सारा सामान छीन लिया। अंत में, भगवान की लीला से डाकुओं का हृदय परिवर्तित हो गया।

सब शिव कृपा है

अंतर्यात्रा
संकलित

एक गांव में शिव कुमार नाम का एक परम भक्त रहता था। वह दिनभर काम करने के बाद भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता था। एक दिन, काम से लौटते समय जंगल के रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और पैसे मांगने लगे। शिव कुमार के पास केवल दो दिन के भोजन के लिए चावल थे, जो उसने अपने काम के बदले में लिए थे। उसने डाकुओं से कहा, 'मेरे पास पैसे नहीं हैं, केवल ये चावल हैं। कृपया मुझे छोड़ दें।' लेकिन डाकुओं ने चावल के साथ-साथ उसके गले की चांदी की माला भी छीन ली और उसे खाली हाथ छोड़ दिया।

शिव कुमार निराश होकर घर लौटा और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उधर, डाकू जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें हर रास्ता एक-सा दिखाई देने लगा। वे भटकते हुए उसी जगह पहुंच गए, जहां शिव कुमार का घर था। डाकुओं को लगा कि यह कोई जादूगर है। डरकर वे शिव कुमार के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। शिव कुमार ने कहा, 'अपनी गलतियों की माफी भगवान भोलेनाथ से मांगो। यह सब उनकी ही कृपा है।' इस घटना से डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने डकैती छोड़ दी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। वे मेहनत करके कमाने लगे और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़े।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 06 अक्तूबर, 1960

पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच तनातनी और बढ़ी

पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच तनातनी और बढ़ी
दोनों ओर से एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार

पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच बढ़ रही तनातनी अत्यंत गंभीर हो गई है। दोनों ओर से एक दूसरे के विरुद्ध जोरदार प्रहार किए जा रहे हैं और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं।

स्वच्छता, साहित्य और सीवर

उर्दू शायरी से लेकर परंपरागत हिंदी कविताओं तक में स्वच्छता और सफाईकर्मी की जान की परवाह क्यों नहीं दिखती?

श्यौराज सिंह बेचैन

मुद्दा

अभी-अभी हमने गांधी जयंती मनाई है। गांधी जी ने स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाया था। व्यावहारिक प्रयोग के तौर पर वह 'साबरमती आश्रम' के निकट बसाई गई भंगी बस्ती से जुड़ गए थे। जब 1993 में 'सिर पर मैला ढोने' की प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया और हाथ से सफाई करने-कराने और बिना सुरक्षा उपकरणों के जहरीले गैस भरे सीवरों में उतरने पर रोक लगा दी गई, तो सीवर में मौतों का सिलसिला अविराम क्यों चलता दिखाई दे रहा है?

हाल ही में दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आकर कासगंज (उत्तर प्रदेश) निवासी चालीस वर्षीय मजदूर अरविंद यादव की मृत्यु हो गई और चार मजदूर अस्पताल में मौत से जूझते रहे। ठेकेदार ने मजदूरों को लालच देकर रात के अंधेरे में सीवर के मैनहोल में उतारा था। जेहन में प्रश्न कौंधा कि ऐसी कौन-सी शिक्षा, सलाह या मानवीय प्रशिक्षण है, जिससे आम इन्सान की जान की अहमियत समझ आए, जो कार्य स्वास्थ्य के प्रतिकूल न हो, जोखिम कम से कम किए जा सकें और अप्राकृतिक मौतें रोकी जा सकें।

भारतीय साहित्य, शेरो-शायरी और कविता-कहानी में यह मसला अभिव्यक्त क्यों नहीं हुआ? तरक्कीपसंद उर्दू शायरों से लेकर परंपरागत हिंदी कवियों के यहां स्वच्छता और स्वच्छकार की जान की परवाह क्यों नहीं हुई? महबूबा के रुखसार का रोमांटिक चित्रण और मेहनतकशों के पेट की आग पर खामोशी क्यों? जब साहित्यकार आंखें बंद करे, तो सरकारों को सचेत कौन करे? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि 'जाके पांव न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई' वाली कहावत लागू हुई है। यानी जो समुदाय भुक्तभोगी है, वह तो साहित्य में रहा नहीं, जो है, उसने पराई पीर से सरोकार नहीं रखा?

ऐसा नहीं है कि मैला ढोने या मुर्दा मवेशी उठाने की प्रथा को आधुनिक तकनीक के सहारे मानव-श्रम और गरिमा के संरक्षण का सवाल बौद्धिक हल्कों में कभी उठा ही नहीं है। बेजवाड़ा विल्सन की संस्था हो या बिंदेश्वरी पाठक का शुलभ शौचालय, काम तो इधर के दिनों में भी हुए हैं, पर सरकारों से संबंधित मंत्रालयों ने क्या किया? बिना कोई प्रभावी कदम उठाए 'योजना आयोग' लंबी उम्र जीकर चला गया।

एक बार केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम ने कहा था, मलिन पेशे जब तक एक समुदाय तक महदूद रखे जाएंगे, उनकी आर्थिक दशा उन्हें वैकल्पिक पेशों में जाने नहीं देगी और लाभार्थी लोग जब तक इसे अपनी भी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक रास्ते नहीं निकलेंगे। उस समय एक हिंदी पत्रिका में प्रसिद्ध कथाकार शिवानी ने जगजीवन राम से लंबा परिवाद किया था। उनका कहना था, आखिर यह काम करना तो इन्सान को ही पड़ेगा, बाबूजी क्या सवर्णों को भी सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हैं? तब बाबूजी का जबाव था, हम आधुनिक तकनीक के जरिये विकसित देशों की तरह मशीनों से सफाई कराएंगे। तब न सीवर मौतें होंगी, न किसी और को हाथों से मानव मल उठाने का असम्मानित कार्य करना होगा। हालांकि बाबूजी के गुजर जाने के बाद मुद्दा डीप फ्रीजर में चला गया। वर्तमान सरकार ने खुले में शौच जाना बंद करवा कर घरों में शौचालयों के निर्माण की योजनाएं चलाई हैं। यह बात दीगर है कि यह पूरी तरह सफल नहीं हुई है, खासकर ग्रामीणों के बीच, जहां शौचालय हैं, पर पानी नहीं है। घर से बाहर रात में कैसे जाएं, बिजली नहीं है, निर्भरता अधिक है। स्वयं सहायता और जागरूकता इत्यादि की जरूरत है। साहित्य में सामंती शुद्धतावाद के चलते 'गंदगी' को कविता का विषय नहीं बनाया जा सकता था। दलित साहित्य अपवाद है, वहां यह समस्या चित्रित हुई है। इसी वर्ष का 'नयी धारा सम्मान' पाने वाली प्रो. रजत रानी 'मीनू' ने 1992 में जेएनयू से 'नब्बे के दशक की हिंदी दलित कविता पर आंबेडकर का प्रभाव' शीर्षक से एम.फिल का लघु प्रबंध तैयार किया था, उसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि की एक कविता 'झाड़ूवाली' का उल्लेख किया गया है। डॉ. 'मीनू' ने अपने कविता संग्रह 'पिता भी तो होते हैं मां' में स्वयं भी 'झाड़ूवाली' शीर्षक से एक कविता लिखी है।

मनुष्य की गरिमा, जीवन सुरक्षा, और सफाई की अनिवार्यता की दृष्टि से भी समस्या गंभीर है। मानव मल-मूत्र मानव ही के हाथों साफ कराया जाना कोई सम्मान की बात नहीं है। इसमें तकनीक सहायक हो सकती है। विकसित और विकासशील देशों में यह हुआ है और भारत में भी आंशिक शुरुआत हो रही है।

समाज और सरकार, दोनों के दायित्व बड़े हैं। इसलिए भी कि हमारा देश विशाल है। आबादी भी अधिक है और सफाई उपकरण कम हैं। स्वच्छता पर निवेश बढ़ाने, रोबोट व अन्य उपकरण लगाने की जरूरत है। स्वच्छता के मद में बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही नागरिकों में स्वयं स्वच्छता के भाव को राष्ट्र सेवा की तरह साहित्य, संगीत के जरिये भी विकसित किया जाना चाहिए।

-लेखक डीयू में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

विदा होता मानसून

देश से मानसून की विदाई हो रही है और विदा होते मानसून का जो रौद्र रूप बिहार, बंगाल में दिखा है, वह दुखद व चिंताजनक है। भारी बारिश, भूस्खलन, दुर्घटना, पेड़ गिरने, बिजली गिरने से करीब चालीस लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वैसे तो उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है, पर विशेष रूप से बिहार और बंगाल में जैसी बारिश हो रही है, उससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उड़ानों पर असर पड़ा है। सड़क परिवहन ही नहीं, रेल परिवहन पर भी पेड़ गिरने से असर हुआ है। कर्मनाशा नदी और उसकी सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण रोहतास और कैमूर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जबकि सासाराम शहर में व्यापक जलभराव देखा गया है। भारी बारिश के चलते पटना, सारण, सीवान और गोपालगंज जिलों में अनेक जगह गंभीर जलभराव हो गया है। बिहार में ही कम से कम 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दरअसल, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय है, जहां शुक्रवार और शनिवार को 210 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी दो-तीन दिन भारी बारिश का प्रकोप बना रह सकता है।

उधर, पश्चिम बंगाल में खासकर दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें धंस गई हैं, तो एक लोहे का पुल भी ढहा है। पहाड़ी राज्यों से मानसून जा चुका है, लेकिन वहां भी अनेक जगहों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी भारी बारिश की स्थिति है, तो पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में समुद्री तूफान शक्ति का असर देखा जा रहा है। मानसून के इस समय में सचेत रहने की जरूरत है। अनावश्यक यात्राओं से बचना जरूरी है। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाकर कुछ करना ठीक नहीं है। वास्तव में, दशहरे के दिन से ही मौसम में परिवर्तन दिख रहा था। अब तक जिन इलाकों या जिलों में कम बारिश हुई है, वहां भी भारी बारिश के मंजर हैं। उत्तर भारत में ऐसी बारिश से फसल के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है, पर वास्तव में, जलभराव से उत्पादन पर असर पड़ना तय है। केवल प्रकृति को दोष देने के बजाय प्रभावित इलाकों में शासन, प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ जरूरतमंदों के साथ खड़े होना चाहिए।

लौटते हुए मानसून के समय में पूरे भारत में कहीं बारिश, तो कहीं समुद्री तूफान का असर देखा जा रहा है, पर हम मुकाबले के लिए कितने मुस्तैद हैं?

बेशक, बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में जरूरी जल बरसा है, पर इससे समग्रता में बारिश की कमी पूरी नहीं होगी। मिसाल के लिए, इतनी बारिश के बावजूद मानसून के पूरे सत्र में मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम जल बरसा है, तो सारण में 45 प्रतिशत कम। हालिया, तेज बारिश के बावजूद समग्रता में कुशीनगर और देवरिया, दो ऐसे जिले हैं, जहां इस साल बारिश बहुत कम हुई है। राजधानियों की बात करें, तो दिल्ली, लखनऊ, पटना में सामान्य, जबकि रांची, शिमला, देहरादून में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। इस साल पूरे देश में मानसून बहुत अच्छा रहा है, पर कहीं-कहीं भारी बारिश से जान-माल को जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। बदलते पर्यावरण के साथ बारिश का मिजाज बदल रहा है और उसकी आक्रामकता को झेलने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यह बचाव के लिए हर संभव उपाय सोचने व कदम उठाने का समय है। हमें ऐसे पुख्ता इंतजाम करने होंगे कि हम अच्छी बारिश होने पर न्यूनतम नुकसान उठाते हुए अधिकतम लाभ ले पाएं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 अक्तूबर, 1950

प्रशांत क्षेत्र की समस्यायें

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। प्रशान्त क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक संस्था काफी समय से काम कर रही है। वह साहित्य का प्रकाशन करती है और सम्मेलनों द्वारा विचार-विमर्श का आयोजन भी करती है। लखनऊ का सम्मेलन उसी संस्था का एक प्रयास है। इस सम्मेलन में कनाडा, फ्रांस, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलपाइन, ब्रिटेन और अमरीका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कुछ देशों, जैसे आस्ट्रेलिया, बर्मा, लंका, मलाया, नीदरलैंड और वियेटनाम के प्रतिनिधि अतिथि सदस्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। चार-पांच अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य निरीक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य विचारणीय विषय है- 'दूर पूर्व में राष्ट्रवाद और उसके अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम।' सम्मेलन का स्वरूप गैर सरकारी है, और इसलिए सरकारी स्तर पर होने वाले सम्मेलन जितना महत्व उसे नहीं दिया जा सकता। फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे सम्मेलन विभिन्न देशों के लोगों को उनकी समस्याओं को समझने का मौका देते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने एक विचारोत्तेजक भाषण के साथ इस सम्मेलन की चर्चाओं की शुरुआत की। एशिया का महत्व इन दिनों काफी बढ़ चला है। उसके प्रांगण में होने वाली घटनाओं का दूरवर्ती प्रभाव पड़ता है। यूरोप बहुत समय तक दुनिया का भाग्य-विधाता रहा। यूरोप की छोटी से छोटी समस्या पर जितना ध्यान दिया गया, उतना एशिया की बड़ी से बड़ी समस्या पर नहीं दिया गया। किन्तु एशिया ने अब करवट बदली है। एशिया की उम्र बहुत लंबी है। उसका भूतकाल महान था। उसका तत्व ज्ञान और दर्शन अपनी विशेषता रखता है। किन्तु दुनिया में उथल-पुथल और लौट-फेर होती रहती है। जो किसी समय महान था, वह गिर गया और जो पिछड़े हुए थे, वे आगे बढ़ गये। वैज्ञानिक आविष्कारों ने पाश्चात्य देशों को आगे बढ़ाया, और वे एशिया के देशों पर हावी होने में कामयाब हो गये। किन्तु सृष्टि का चक्र बराबर घूम रहा है। एशिया के देशों ने सदियों की गुलामी के जुए को उतार फेंका है और अपने वे पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें सदियों की कमी को कुछ वर्षों में पूरा कर लेने की चिन्ता है।

सदा याद आएंगे विजय कुमार मल्होत्रा

वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के परिवार ने बंटवारे का दौर झेला था, पर उनके मन में कड़वापन नहीं था, उन्होंने स्वयं को जनसेवा में समर्पित कर दिया। स्मृति शेष :

यहां स्कैन करें

नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री, भारत

कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा के मूल संस्कार क्या हैं? विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन, स्वयं से ऊपर सेवा भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही।

वीके मल्होत्रा के परिवार ने विभाजन का भयावह दौर झेला। उस आघात और विस्थापन ने उन्हें कड़वा या आत्मकेंद्रित नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा में उन्हें राष्ट्रसेवा का रास्ता नजर आया। बंटवारे का वह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। मल्होत्रा जी ने सामाजिक कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने उन हजारों विस्थापित परिवारों की मदद की, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। यही जनसंघ की प्रेरणा थी। उन दिनों उनके साथी मदनलाल खुराना और केदारनाथ साहनी भी बढ़-चढ़कर सेवा कार्यों में शामिल होते थे। उन लोगों की निःस्वार्थ सेवा को आज भी दिल्ली के लोग याद करते हैं।

सन् 1967 के लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तब अपराजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले रहे थे। इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक कम चर्चित चुनाव भी हुआ। वह था, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कौंसिल का पहला चुनाव। राष्ट्रीय राजधानी में जनसंघ ने शानदार जीत दर्ज की। आडवाणी जी कौंसिल के चेयरमैन बने और मल्होत्रा जी को 'चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर' की जिम्मेदारी दी गई, जो मुख्यमंत्री के लगभग बराबर का पद था। तब उनकी उम्र केवल 36 वर्ष थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में दिल्ली की जरूरतों, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया।

इस जिम्मेदारी ने मल्होत्रा जी का दिल्ली से जुड़ाव और मजबूत कर दिया। जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर वह सक्रिय रूप से जनता के साथ खड़े होते और उनकी आवाज बुलंद करते। उन्होंने 1960 के दशक में गौ रक्षा आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जहां उनके साथ पुलिस ज्यादतियां भी खूब हुईं। आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। दिल्ली की सड़कों पर जब सिखों का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा था, तब वह शांति और सद्भावना की आवाज बनकर सिख समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे। उनका मानना था कि राजनीति, चुनावी सफलता के अलावा सिद्धांतों, मूल्यों और लोगों की रक्षा के लिए भी है, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

अपने लंबे सेवाकाल में मल्होत्रा जी ने 'सिविक एडमिनिस्ट्रेशन' संभाला, राज्य विधानसभा में पहुंचे और देश की संसद में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ उनकी शानदार जीत समर्थकों और विरोधियों के बीच आज भी याद की जाती है। वह एक बेहद हाई-प्रोफाइल चुनाव था। कांग्रेस की पूरी ताकत दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में उतर आई थी, लेकिन मल्होत्रा जी ने कभी बहस का स्तर नीचे नहीं किया। उन्होंने पॉजिटिव कैंपेन चलाया। गालियों और हमलों को नजरअंदाज किया और 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ प्रचार के दम पर नहीं, मल्होत्रा जी की जमीन पर मजबूत पकड़ की वजह से मिली थी। कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध बनाकर रखने और मतदाताओं के मन की थाह लेने में वह माहिर थे।

मल्होत्रा जी संसद में सटीक तैयारी के साथ अपनी बात रखते थे। वह पूरी रिसर्च करके आते थे। यूपीए-1 के दौरान विपक्ष के उपनेता के रूप में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वह राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए एक मूल्यवान सबक की तरह है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मुद्दे पर यूपीए सरकार का प्रभावी ढंग से विरोध किया। उन दिनों मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अक्सर मल्होत्रा जी से बातचीत होती। वह हमेशा गुजरात की विकास यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे।

राजनीति, वीके मल्होत्रा के व्यक्तित्व का केवल एक पहलू थी। वह एक उत्कृष्ट शिक्षाविद भी थे। उनके परिवार से मुझे पता चला कि उन्होंने स्कूल में 'डबल प्रमोशन' हासिल किया। उनकी हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषणों का हिंदी अनुवाद प्रायः वही करते थे। उन्हें नई संस्थाएं और नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी जाना जाता है। वह आरएसएस से जुड़ी कई संस्थाओं के संस्थापक और संरक्षक रहे। उनके प्रयासों से अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ और मार्गदर्शन मिला। इन संस्थाओं के माध्यम से कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने एक ऐसे समाज का विजन दिया, जो आत्मनिर्भर हो और मूल्यों पर टिका हो।

मल्होत्रा जी ने राजनीति और अकादमिक जीवन से परे, खेल जगत में भी अमिट छाप छोड़ी। तीरंदाजी में उनका गहरी दिलचस्पी थी और वह कई दशकों तक 'आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय तीरंदाजी को ग्लोबल पहचान मिली। उन्होंने खिलाड़ियों को मंच और अवसर दिलाने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए। खेल प्रशासन में भी उन्होंने वही गुण दिखाए, जो सार्वजनिक जीवन में थे, यानी समर्पण, संगठन क्षमता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज। वी के मल्होत्रा को आज लोग उनके द्वारा संभाले गए पदों के साथ ही उनकी संवेदनशीलता के लिए याद कर रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्तित्व की रही, जो हमेशा लोगों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। जहां भी मदद की जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटे। वह आदर्श पार्टी कार्यकर्ता थे, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं या विचारधारा को ठेस पहुंचे।

कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली भाजपा के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां मैंने स्नेहपूर्वक विजय कुमार मल्होत्रा जी को याद किया था। इस वर्ष तीन दशक बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो वह बहुत उत्साहित थे। उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिन्हें हम पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और उपलब्धियों से प्रेरणा पाती रहेंगी।

हिंदी लेखक को तीस लाख की रॉयल्टी मिलने पर खूब बहस

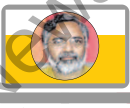

यहां स्कैन करें

प्रियदर्शन | वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार

बीते कुछ दिनों से यशस्वी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंद युग्म प्रकाशन द्वारा दी गई 30 लाख रुपये की रॉयल्टी हिंदी के संसार में विस्मय और बहस का विषय बनी हुई है। प्रकाशक ने घोषित तौर पर जानकारी दी है कि बीते छह महीने में उनकी किताबों की करीब 92 हजार प्रतियां बिकी हैं, जिनमें 88,000 से ज्यादा प्रतियां दीवार में खिड़की रहती थी के पेपरबैक संस्करण की हैं।

हालांकि, 45 करोड़ लोगों की भाषा मानी जाने वाली हिंदी में एक लेखक की किसी किताब की 88,000 से ज्यादा प्रतियों की बिक्री की खबर अगर इतना विस्मय पैदा करती है, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जाहिर है, इस विस्मय के पीछे हिंदी के प्रकाशन उद्योग की आम तौर पर बताई जाने वाली स्थिति है- कि किताबें नहीं बिकतीं, उनके संस्करण हजार से घटते हुए 500, 300 और अब 100 पर आ चुके हैं; लेखकों को जो रॉयल्टी मिलती है, वह उन्हें शर्मिंदा करने वाली होती है; किताबें सिर्फ वही बिकती हैं, जिनके लेखक किन्हीं दूसरी वजहों से चर्चित हैं। संभव है, इसमें काफी कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि हिंदीभाषी समाज पढ़ने की आदत से मुंह मोड़े बैठा दिखता है, उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं और पढ़ते हैं, तो वे आमतौर पर अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ते हैं। फिर भी 45 करोड़ लोग हर रोज कम से कम एक करोड़ हिंदी अखबार खरीदते हैं, चार दिनों में किसी फिल्म का सौ करोड़ का कारोबार करा देते हैं। इन तक किताबें पहुंचती हैं, तो किताबें भी खरीद लेते हैं, इसका प्रमाण हर साल दिल्ली में, बल्कि अब तो हर महीने अलग-अलग शहरों में लगने वाले पुस्तक मेले हैं, जहां इतनी भीड़ होती है कि तिल धरने की जगह नहीं होती है।

करीब 45 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी में किसी किताब की 88,000 से ज्यादा प्रतियों की बिक्री विस्मय पैदा करे, तो इस पर विचार करना होगा।

तो क्या प्रकाशक झूठ बोलते हैं? क्या वे अपनी किताबों की बिक्री के वास्तविक आंकड़े लेखकों को नहीं देते? यह बहुत पुराना आरोप है और इसकी पुष्टि में कई बार प्रमाण और सुबूत पेश किए जाते रहे हैं। अगर प्रकाशक यह नहीं करते, तो उन्हें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी- यह दायित्व उनका है। लेकिन अगर वे साबित कर दें कि वाकई किताबों की बिक्री का वे सही हिसाब रखते और देते हैं, तो अब उनकी पेशेवर क्षमताओं पर सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर इतने बड़े हिंदी संसार में वे तीन सौ और पांच सौ प्रतियां ही क्यों बेच रहे हैं? जिन विनोद कुमार शुक्ल की 90,000 से ज्यादा प्रतियां छह महीने में बिक गईं, उनकी किताबें पहले यही प्रकाशक वर्षों बेचते रहे और उनकी रॉयल्टी का कुल आंकड़ा किसी भी साल एक लाख तक भी क्यों नहीं पहुंचा? क्या यह वर्षों या दशकों से चली आ रही सरकारी खरीद नाम का घुन है, जिसकी वजह से किताबें एक से दूसरे गोदाम तक पहुंच जाती हैं और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का कुछ श्रमसाध्य या जरूरी काम करने का अभ्यास प्रकाशकों ने खो दिया है? आम अनुभव यही है कि लेखक अपने खर्च पर लोकार्पण करा ले तो अच्छी बात, प्रकाशक यह कष्ट भी नहीं उठाते।

हिंदी के साहित्यिक संसार की दुखती रग बस इतनी नहीं है। हिंदी में किताबों की बिक्री ही नहीं घटी है, लेखकों का पारिश्रमिक भी घटा है। साहित्यिक पत्रिकाएं तो पारिश्रमिक शब्द सुनकर हैरान रह जाती हैं। यही स्थिति हिंदी या भारतीय भाषाओं के पुरस्कारों की भी है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें, तो लगभग हर पुरस्कार अपनी शुरुआत में जितना मूल्यवान था, वह अब नहीं रह गया है। साठ के दशक में एक लाख रुपये वाला ज्ञानपीठ अब 11 लाख रुपये का पुरस्कार है, जबकि तब के एक लाख की कीमत आज पांच करोड़ से कम नहीं है।

दूसरी बात यह कि हिंदी में अब पैसे देकर किताबें प्रकाशित करवाने का चलन बहुत आम हो गया है। ऐसी किताबों से बाजार में बहुत सारा कचरा-साहित्य भी पैदा हो गया है। तीसरी बात यह कि किताबों के प्रकाशन की गुणवत्ता बेहद गिरी है। मगर यह टिप्पणी हिंदी प्रकाशन की दुनिया के संकटों पर नहीं, उन संभावनाओं पर लिखी जा रही है, जो विनोद कुमार शुक्ल को दी गई 30 लाख की रॉयल्टी के साथ पैदा हुई हैं। इस बिक्री में हिंदी समाज की ताकत पहचानें, हिंदी प्रकाशन जगत की संभावनाओं को समझें और दूसरे प्रकाशकों से भी उम्मीद करें कि वे अपने लेखक को लेखक होने का मान कर सकने लायक मानदेय जरूर देंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

रिश्तों को सहेजना सीखें

हम निरंतर लोगों से जुड़े रहते हैं, चाहे घर में या बाहर काम-काज में। कितने तरह के रिश्ते हैं और उसके लिए कितने अलग-अलग चेहरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि दिन भर में आपको कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं? कभी अकेले बैठकर शांति से इसका हिसाब लगाएं, तो चेहरों की लंबी फेहरिश्त बनेगी। परिवार और कार्यस्थल में तालमेल बिठाने में अलग-अलग जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि वह दोनों जगहों के व्यवहार को प्रभावित करता है। आदमी तो एक ही है, इसलिए स्वभावतः घर का तनाव बाहर की दुनिया में और बाहर का तनाव घर के माहौल में प्रवेश करता है। जीवन के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है।

हमारे संबंध क्लेश क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सभी लोग एक-दूसरे को वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। संबंधों के विषय में ओशो से कई बार सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि उनका जोर है संबंधों के साथ ध्यान को जोड़िए। बहुत सचेत होकर लोगों से संवाद करिए।

एक बात जेहन में उतार लें कि जीवन जीना एक कला है, उसे सीखना पड़ेगा। जीवन को एक संगीत मानें, तो हर व्यक्ति इसमें एक साज है, कोई सुरीला तो कोई बेसुरा। सबके मेल-जोल से संगीत बनता है। लोगों से ऐसे जुड़ो, जैसे आप कोई गीत गा रहे हों, या आप कोई साज बजा रहे हों। फिर आपके रवैये में बहुत अंतर होगा। संबंधित होना एक नाजुक घटना है, इसे संवेदनशीलता से निभाएं। जैसे एक चित्रकार कैनवास पर जो कर रहा है, उसके बारे में वह बहुत सतर्क रहता है। एक सच्चा चित्रकार सिर्फ एक स्ट्रोक से पूरी पेंटिंग बदल सकता है।

बहुत सावधानी से, बहुत संवेदनशील होकर लोगों से बर्ताव करें। हर संबंध एक आईना होता है, जो आपको अपनी असली तस्वीर दिखाता है। दूसरों की प्रतिक्रिया से दिखाई देगा कि आप जो कर रहे हैं, उसका दूसरे पर क्या असर हो रहा है? क्या आप उनका जीवन और दुखी बना रहे हैं? यदि ऐसा है, तो अपने तरीके को बदलें। अपने आस-पास के जीवन को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। छोटी-छोटी बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं और छोटी-छोटी बातें रिश्तों को बहुत खूबसूरत भी बना देती हैं। कभी-कभी एक सच्ची मुस्कान से दूसरे का दिल आपके लिए खुल जाता है। कभी-कभी आपकी आंखों में एक गलत भाव आ जाए, तो दूसरा बंद हो जाता है।

जीवन जीना एक कला है, उसे सीखना पड़ेगा। जीवन को एक संगीत मानें, तो हर व्यक्ति इसमें एक साज है, कोई सुरीला तो कोई बेसुरा। सबके मेल-जोल से ही संगीत बनता है।

आपकी ताकत हैं आप स्वयं। जब आप अकेले हों, तब पूरी तरह मौन होकर बैठें और स्वयं को देखें : अपनी सांसों को देखें, विचारों को देखें, अपनी स्मृतियों को देखें। स्वयं को समग्रता में देखें, आपको ऊर्जा का पुंज महसूस होगा। यह आपके स्वस्थ रिश्तों की नींव बनेगा।

अमृत साधना

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

हमारे लिए शस्त्र केवल उपकरण नहीं हैं और न ही केवल शक्ति प्रदर्शन का साधन। शस्त्र धर्म की स्थापना करने के साधन हैं। भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा ही नहीं करता, बल्कि समय आने पर उनका इस्तेमाल करना भी जानता है।

रेलवे की लापरवाही परिवारों पर पड़ती भारी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केवल वर्ष 2023 में देश में 24,678 रेल दुर्घटनाओं में 21,803 लोग मारे गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुईं। रेल दुर्घटनाओं के अलग-अलग कारणों के विश्लेषण से पता चला है कि लोगों के 'ट्रेन से गिरने या ट्रैक पर कुचलने' की घटनाएं कुल 24,678 ट्रेन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 18,480 थीं। ऐसी दुर्घटनाओं में 15,878 लोग मारे गए, जो रेल दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 72.8 प्रतिशत है। इसी तरह 2024 में कुल छह रेल दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 122 घायल हो गए।

इन रेल हादसों के मुख्य कारणों में मानवीय भूल, पुराना और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सिग्नल की गड़बड़ियां, क्रॉसिंग पर असुरक्षा और उपकरणों की विफलताएं रही हैं। इनमें भी सबसे बड़ा कारण मानवीय भूल रही है, जिसमें संकेतों का पालन न करना, तेज गति से ट्रेन चलाना और नियमों का उल्लंघन शामिल हैं। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक, पुल और सिग्नल सिस्टम पुरानी तकनीक पर आधारित हैं और अक्सर अपर्याप्त रखरखाव या प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। तकनीकी खराबी और उपकरणों की बात करें, तो सिग्नल प्रणाली की तकनीकी गड़बड़ियां या अन्य उपकरणों में खराबी भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। रेलवे ट्रैक पर कुचलकर मरने वालों की संख्या इतनी अधिक इसलिए है, क्योंकि मानव-रहित और मानव-युक्त क्रॉसिंग पर नियंत्रण न होने के कारण वाहन अक्सर ट्रेनों से टकरा जाते हैं। ये लेवल क्रॉसिंग इतने लापरवाह तरीके से संचालित हो रहे हैं कि अक्सर यहां पर कोई चेतावनी या संकेतक तक नहीं होते और रेलगाड़ियां गुजरती रहती हैं। रेलवे रूट पर आवश्यकता से अधिक ट्रेनों के चलने से भी भीड़भाड़ बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक हो जाता है। इसके साथ बवंडर, बाढ़ और तापमान के उतार-चढ़ाव से पटरियों के सिकुड़ने या फैलने के कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देश का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा बिहार में 1981 को हुआ था, जिसमें बवंडर के कारण बागमती नदी के पुल से गुजरते समय रेलगाड़ी बेपटरी हो गई थी।

लगातार होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं यात्रियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं और भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती हैं। ये दुर्घटनाएं समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं और प्रभावित परिवारों के लिए सदमा और दुख का कारण बनती हैं।

पुष्पलता, गृहिणी

अनुलोम-विलोम

रेल हादसा

दुर्घटना रोकने को उठाए जा रहे कई कदम

देश में रेल दुर्घटनाओं पर अभी पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, जिनमें अनेक परिवारों को अपने सदस्य खोने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे इन बातों को नजरअंदाज करता है या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। देश का यह सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम अपनी कार्य-कुशलता को सुधारने का लगातार प्रयत्न कर रहा है और इस क्रम में उसने कई आधुनिक मानक लागू भी किए हैं, ताकि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

रेलवे ने इसी निमित्त 2017-18 से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना की थी। इसका उपयोग ट्रैक के नवीनीकरण, सिग्नल प्रणाली ठीक करने, पुलों की मरम्मत समेत सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया गया। कोच और डब्बों को ऑटोमेटिक फायर ऐंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया। उपायों में कवच को इंस्टॉल करना भी शामिल है, जो स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा उपाय है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए जर्मनी से हल्के और सुरक्षित एलएचबी कोच लाए गए हैं। ट्रेनों में अब जीपीएस आधारित फॉग पास डिवाइस लगाए जा रहे हैं, जिससे धुंध की स्थिति में लोको पायलट को रास्ता देखने में मदद मिलती है। इसी प्रकार मजबूत और अधिक टिकाऊ पटरियां व पुल बनाए जा रहे हैं। दोषपूर्ण पटरियों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक दोष जांच तकनीक शामिल की गई है, जो पटरियों की दरारों या खामियों का पता लगाने का काम करती है। जांच के बाद खराब पटरियों को नई पटरियों से बदल दिया जाता है। पटरी के रखरखाव को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इन उपायों से मानवीय त्रुटियां कम होती हैं और पटरियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार होता है।

ट्रेनों में इंटरलॉकिंग प्रणाली भी लगाई जा रही है। इससे जमीनी स्तर पर कर्मचारियों द्वारा पॉइंट्स और सिग्नलों के मैन्युअल संचालन की जरूरत खत्म हो जाती है। यह मानवीय विफलता की संभावनाओं को भी न्यूनतम करने वाली प्रणाली है। इसके साथ ही मानव-रहित क्रॉसिंग को बंद करने, इसे मानव-युक्त करने या सबवे, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाकर धीरे-धीरे समाप्त करने पर काम किया जा रहा है। ये सब ऐसे सुधारात्मक उपाय हैं, जिनसे मानवीय चूक की आशंका नहीं रहेगी और दुर्घटनाएं कम से कम हो जाएंगी। इसमें समय लगेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति और तकनीक के विकास में समय लगता है। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है।

निमिश कुमार, छात्र

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संपादकीय जागरण

(16) सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 : आश्विन शुक्ल - 14 वि. 2082

अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवन के पुरुषार्थों की सिद्धि नहीं होती

मौसम का बिगड़ा मिजाज

मानसून के विदा लेने के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह वर्षा हो रही है, वह केवल आश्चर्य का ही विषय नहीं, परेशानी का भी कारण है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी-खासी वर्षा के आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो अरब सागर में शक्ति नामक तूफान के कमजोर होने से पहले नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। दशहरे के बाद दीवाली की प्रतीक्षा के बीच जब यह मान लिया जाता है कि वर्षा ऋतु का समय बीत गया, तब बारिश होना यही बताता है कि मौसम में परिवर्तन का चक्र तीव्र हो गया है। मौसम चक्र में बदलाव पिछले कई वर्षों से दिख रहा है, लेकिन अब बदलाव की गति कहीं अधिक तेज हो गई है। यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता तो हर स्तर पर जताई जा रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए जैसे सामूहिक प्रयास होने चाहिए, वैसे नहीं हो पा रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता है। कहना कठिन है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन को रोकने के अपने प्रयासों के प्रति कब गंभीरता का परिचय देगा? जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर बल देना होगा। यह ठीक है कि आपदा प्रबंधन के उपायों को पुष्ट किया गया है और उनका लाभ भी मिला है, लेकिन अब अतिवर्षा, बादल फटने, कम समय में अधिक बारिश होने के कारण जन-धन हानि की भारी क्षति देखने को मिलती है। इस वर्ष ऐसी घटनाओं के चलते पर्वतीय राज्यों के साथ-साथ मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी जन-धन हानि देखने को मिली। इस हानि का एक बड़ा कारण कमजोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और उसका सही तरीके से रखरखाव न किया जाना है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा दूसरे देशों में भी होती है, लेकिन उनमें और विशेष रूप से विकसित और यहां तक कि कई विकासशील देशों में अपेक्षाकृत कम जन-धन हानि होती है। भारत में मौसम के बिगड़े मिजाज से होने वाली बाढ़ एवं भूस्खलन की घटनाओं से जन-धन हानि को रोकने का उपाय यही है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण में तय मानकों का पालन किया जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एक अन्य क्षेत्र भी ऐसा है, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा और वह है जल निकासी के उचित प्रबंध का। बारिश के समय जनजीवन के बाधित होने का मुख्य कारण जगह-जगह जलभराव होना है। स्थिति यह है कि देश के बड़े महानगरों में भी थोड़ी सी ही बारिश जलभराव कर देती है और उसके चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

खेलों को बढ़ावा

प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के विकास के साथ खेलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसका फलाफल भी दिखने लगा है। बिहार ने हाकी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की मेजबानी कर खेल जगत में अलग पहचान बनाई है। इससे पहले ओडिशा में हाकी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते रहे हैं। राजगीर में एशियन रग्बी सेवेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इतना ही नहीं, पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा का विश्वकप तथा राष्ट्रीय एथलेटिक मीट का भी सफल आयोजन किया जा चुका है। राजगीर में बिहार खेल अकादमी व विश्वविद्यालय बनने के बाद वहां विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोर्ट-मैदान तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और ग्राउंड का लोकार्पण कर दिया है। अब यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच होने की राह खुल गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना भी चला रखी है। इसी के तहत 87 उत्कृष्ट खिलाडियों को सरकारी नौकरी का चयन पत्र और 812 खिलाडिय़ों के बीच करीब सात करोड़ 43 लाख रुपये की सम्मान राशि वितरित की गई। खेलों को लेकर प्रदेश में सकारात्मक माहौल बन गया है। सरकारी विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को निखारने व पहचानने के लिए मशाल कार्यक्रम चल रहा है।

> जिला एवं राज्यस्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या इजरायल-हमास में समझौते के बाद पश्चिम एशिया में शांति व्याप्त होगी?

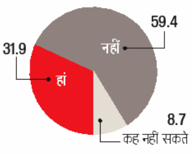

आज का सवाल
क्या शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समर्थ बनें संसदीय समितियां

हृदयनारायण दीक्षित

जब संसद आभा खो रही है। शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं, तब संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए

संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का विचार चल रहा है। सांसदों की शिकायत है कि एक साल की अवधि में किसी विषय विशेष पर वस्तुपरक अध्ययन और सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाते। सरकारें विधायिका के समक्ष जवाबदेह हैं। यह जवाबदेही संसदीय प्रश्नों, संकल्पों और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से होती है। संसदीय समितियां भी इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग करती हैं। समिति सदन का ही अंग होती हैं। राष्ट्र के सामने तमाम जटिल प्रश्न आते रहते हैं। तमाम मुद्दे आते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा में काफी समय लगता है। कुछ मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं, जिनका स्वरूप तकनीकी होता है। संसद का समय ऐसे छोटे मुद्दे एवं अनावश्यक शोर व्यवधानों को निपटाने में ही लग जाता है। समिति प्रणाली से संसद का समय बच जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति स्थायी समितियां हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अलावा लोकसभा की अलग समितियां भी हैं। किसी विषय पर गठित समितियों का कार्यकाल प्रतिवेदन देने तक सीमित रहता है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया का नियमन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सभा द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है।

संप्रति राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। संसद आभा खो रही है। सदन के भीतर हुल्लड़ है। शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए। सांसदों ने समय की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। इसके लिए समिति व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए समग्रता में विचार करना चाहिए। विधायिका में समय की कमी विचारणीय विषय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि संसद की समितियां विषय की गहराई में जाती हैं, लेकिन मुख्य सदन में समितियों जैसा अनौपचारिक शांत वातावरण नहीं मिलता। समितियों की कार्यवाही का संचालन मुख्य सदन की भांति ही होता है। मुख्य सदन एवं समितियों के विशेषाधिकार समान हैं। समिति का वातावरण प्रेमपूर्ण होता है। समिति में विचाराधीन सभी विषयों की गहन समीक्षा होती है। संबंधित संस्था या व्यक्ति समिति की कार्यवाही के सामने जवाब देता है। समिति अपने विचाराधीन जांच योग्य अथवा अन्वेषणाधीन विषय के संबंध में संबंधित व्यक्ति से मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकती है। प्रत्येक समिति के पारस साक्षियों को व्यक्तिगत रूप में बुलाने तथा पत्र और रिकार्ड मांगने के अधिकार हैं। स्थायी समितियों के समक्ष भी राष्ट्रजीवन से जुड़े लगभग सभी विषय आते हैं। इसीलिए स्थायी समितियों की संख्या सन 2004 में 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाती है। ऐसी समिति अपने देश में काफी लोकप्रिय हुई है। आम जनता को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला आदि की जांच में गठित संयुक्त संसदीय समितियां याद हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोकसभा या राज्यसभा में गहन विचार विमर्श संभव नहीं था। जो समस्याएं मूल रूप में संपूर्ण सदन के सामने आई थीं, वही विषय समितियों में आकर आसानी से निष्कर्ष तक कैसे पहुंच गए। मूलभूत प्रश्न है कि संसद व्यवस्थित रूप में क्यों नहीं चलती? महत्वपूर्ण विधायन भी बिना बहस पारित होते हैं।

अवधेश राजपूत

ब्रिटेन में भी समितियां हैं। सेलेक्ट कमेटी सरकारी विभागों की निगरानी करती है। इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकव्यय की जांच करती है। संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। भारत की तरह अपने निश्चित अनुपात में विपक्षी दलों को भी सदस्यता मिलती है। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुने जाते हैं। अमेरिकी व्यवस्था में भी समितियां हैं। यहां दोनों सदनों की अलग-अलग समितियां हैं। अब भारत की तरह अमेरिका में भी स्थायी समितियां हैं। अमेरिका में विदेश मामलों और वित्त से जुड़ी स्थायी समिति है। संयुक्त संसदीय समिति अमेरिका में भी है। जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस और कनाडा में भी समिति प्रणाली है। कनाडा में नागरिक, विशेषज्ञ और एनजीओ किसी मामले में गवाही दे सकते हैं। यहां की लोक लेखा समिति में विपक्षी दल के सांसद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये समितियां शक्तिशाली हैं और लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। आस्ट्रेलिया में प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च और बजट की गहराई से जांच करती है। जापान में स्थायी समितियां और मंत्रालय से संबंधित समिति भी हैं।

समितियों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। मर्यादा पर कई खूबसूरत बातें कही गई हैं। एक समिति के अध्यक्ष ने 1959-60 की बैठक में समिति के कृत्य को समझाया और कहा, 'आपका काम नीति निर्धारित करना नहीं है। संसद द्वारा जिस नीति का निर्धारण किया जाता है, आपका कर्तव्य यह है कि आप यह देखें कि उस नीति का पालन हो... साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसके भिन्न वित्तीय प्रभाव न पड़ें। आप नीति संबंधी केवल उसी विषय की जांच कर सकते हैं-आपको उसका अधिकार तभी तो मिलता है, जिसमें खर्च अंतर्निहित होता है और आप यह देखें कि वह नीति ठीक ढंग से नहीं चल रही है। जहां नीति के फलस्वरूप धन का अपव्यय होता है, आपको उसके संबंध में उचित ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार है।' संसद और विधानमंडल की कार्यवाही में एकता है। समिति प्रणाली की मजबूती से विधानसभाओं का कामकाज भी तेजस्वी होगा। संप्रति कार्यकाल बढ़ाने की मांग विचारणीय है। अच्छा हो कि इस विषय के औचित्य पर समग्र विचार करना जरूरी हो। इस पर यथास्थिति नियम समिति/संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचारण हो।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

नए बाजारों तक पहुंच बनाता भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

भारत द्वारा विभिन्न देशों से किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते टैरिफ की चुनौतियों से निपटने में कारगर हो रहे हैं

इस समय भारत तेजी से नए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), नए व्यापार गठबंधनों और नए निर्यात बाजारों में कदम बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में बीते एक अक्टूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिस्टेंस्टिन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच एफटीए लागू हो गया है। इस व्यापार समझौते पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के कारण यह समझौता अब लागू हुआ है। वस्तुतः मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है, जहां वे साझेदार देशों से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म कर देते हैं या कम करने पर सहमत होते हैं। एफ्टा देशों के साथ यह समझौता भारत द्वारा अलग-अलग देशों और क्षेत्रीय समूह के साथ किया गया 14वां व्यापार समझौता है। यह मोदी सरकार के समय किया गया पांचवां व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ने मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ एफटीए किए हैं।

भारत और एफ्टा देशों के बीच लागू हुआ यह व्यापार समझौता यूरोप के एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लाक के साथ भारत के विदेश व्यापार को नई दिशा देगा। इस समझौते के तहत भारत ने एफ्टा देशों की 80-85 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क शून्य किया है। इसके बदले में भारत को 99 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त बाजार तक पहुंच मिलेगी। जहां कृषि, डेरी, सोया एवं कोयला सेक्टर को इस व्यापार समझौते से दूर रखा गया है, वहीं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रीन एवं विंड एनर्जी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में एफ्टा देश भारत में निवेश करेंगे, जिससे इन सेक्टरों में हमारा आयात कम होगा और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। भारत के हिसाब से इस व्यापार समझौते का सबसे बड़ा लाभ एफ्टा देशों से मिली निवेश प्रतिबद्धता है। अब यह समझौता लागू होने के बाद आगामी 10 वर्षों के भीतर एफ्टा देशों से भारत में 50 अरब डालर का निवेश और अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब डालर निवेश की उम्मीद है। इससे 15 वर्षों में भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की आस है। बहरहाल भारत ने ऐसा पहला समझौता किया है, जिसमें बाजार तक पहुंच निवेश से जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में एफ्टा देशों को भारत ने 1.97 अरब डालर मूल्य का वस्तु निर्यात किया और 22.44 अरब डालर का आयात किया। इन देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यद्यपि अभी एफ्टा के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, लेकिन अब नए व्यापार समझौते से एफ्टा देशों के साथ भारत के विदेश व्यापार का परिदृश्य भारत के लिए अनुकूल होने की संभावना है। खासतौर से इस समझौते से डिजिटल व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में इन चार देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के बड़े बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

निर्यात के लिए नए बाजार तलाशता भारत ● फाइल

उल्लेखनीय है कि हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच भी एफटीए हुआ है। भारत और ओमान के बीच एफटीए पर बातचीत पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस वर्ष के अंत तक यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए लागू होने की पूरी संभावना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर दिखाई दे रही है। इस नीति से ट्रंप टैरिफ के बीच पिछले अगस्त और सितंबर माह में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में भारत के निर्यात बढ़े हैं। कल तक भारत को डेड इकोनमी बताने वाले ट्रंप ने अब अपना तेवर बदलते हुए भारत के साथ व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के संकेत दिए हैं। यह भारत की आर्थिक-कूटनीतिक जीत है। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का अनुकूल परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। इससे संभावना जताई जा रही है कि भारत पर रूसी तेल खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को अमेरिका वापस ले सकता है।

अमेरिका के अलावा भारत कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इजरायल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी व्यापार समझौता करने जा रहा है। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि एफटीए तभी लाभकारी होते हैं, जब वे सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जाएं। इसके लिए सरकार को निर्यातकों और छोटे व्यवसायियों को नए बाजारों के लाभ से संबंधित पर्याप्त जानकारी देकर नए मौकों का फायदा उठाने के लिए जागरूक बनाना होगा। सरकारी निकायों द्वारा गैर शुल्क बाधाओं संबंधी समाधान के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन देना होगा। इसके साथ-साथ एफटीए के तहत निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और कारोबार की सुगमता के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। उम्मीद करें कि ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच एफटीए भारत के निर्यात और निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

त्याग

मानव जीवन निरंतर गति और परिवर्तन का पर्याय है। इसमें त्याग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए अशुद्ध वायु को बाहर निकालना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन की प्रगति के लिए अनावश्यक वस्तुओं, विचारों और भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है। त्याग केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और मानसिक स्तर पर भी जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करता है।

भोजन की इच्छा तब तक नहीं होती जब तक पेट में अवशेष शेष रहता है। यह प्राकृतिक नियम है कि पहले अनावश्यक तत्वों का त्याग हो और फिर नई ऊर्जा को स्थान मिले। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम बीते अनुभवों, नकारात्मक भावनाओं और अनुपयोगी वस्तुओं को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नए अवसरों और नई ऊर्जा को स्थान कैसे मिलेगा? संग्रह जीवन की गति में अवरोध पैदा करते हैं और मनुष्य को स्थिर बना देते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम परिस्थितियों, वस्तुओं और विचारों से अनावश्यक बंधन समाप्त करें। हम सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुंचने के बाद उसे छोड़ना पड़ता है। यदि हम उसी सीढ़ी से चिपके रह जाएं तो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संसार में प्रगति के लिए त्याग अनिवार्य है।

त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और द्वेष जैसे मानसिक विकार जब तक मनुष्य को जकड़े रहते हैं, तब तक वह शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये विकार छूटते हैं, वैसे ही दया, प्रेम, करुणा और श्रद्धा जैसी शुभ प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से मन में जाग्रत होने लगती हैं। यह उसी तरह है जैसे द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश सहज ही भीतर प्रवेश कर जाता है।

अवधविहारी शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

आदिवासी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाए संघ

'आरएसएस की सफलता के सूत्र' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त का कहना सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफलता का मूल कारण उसके विचार भारतीय समाज के डीएनए का हिस्सा होना है। जिस प्रकार सनातन संस्कृति पर चौतरफा आक्रमण उसके अस्तित्व को मिटा नहीं पाए, उसी तरह से संघ भी चौतरफा आक्रमण के बावजूद निरंतर उत्कर्षशील है। किसी विचारक ने सही कहा है कि यदि किसी को संघ को समझना है तो पहले उसे भारतीयता और सनातन संस्कृति को समझना होगा। यदि यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आज यदि सनातन संस्कृति पर मतांतरण, लव जिहाद और अपसंस्कृति जैसे आक्रमण हो रहे हैं तो उसमें संघ की सक्रियता बेहद अहम हो जाती है। आजकल यह धारणा बन रही है कि सत्ता का स्वाद चखने के बाद स्वयंसेवकों की वैचारिक प्रतिबद्धता, सक्रियता एवं एकनिष्ठा में कमी आ गई है। आज ऐसे समर्पित स्वयंसेवकों का अभाव है, जो भुने चने खाकर अपने कर्तव्य निर्वहन में लगे रहते थे। इसी प्रकार संघ को समाज में एक व्यापक पैठ बनानी पड़ेगी तथा दलितों एवं आदिवासियों को अपने से जोड़ना होगा। साथ ही समाज में घर कर गई जातिवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। आज आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग करने का षड्यंत्र एवं आदिवासी अंचलों में मतांतरण का सुनियोजित चक्र चल रहा है तो उसे रोकने के लिए संघ को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी।

विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

गुणवत्ता की कड़ी जांच हो

संपादकीय आलेख 'जानलेवा दवाएं' (पांच अक्टूबर) पढ़ा। दवा हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। हमारे देश में दवा की तुलना संजीवनी बूटी से की जाती रही है। यह आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण का कोई नियम नहीं है। दवा कंपनियां स्वयं ही अपने दवाओं की गुणवत्ता का सत्यापन करती हैं। इस समय भारत 185 से अधिक देशों को दवा का निर्यात कर रहा है, लेकिन देश में ही नकली सीरप से मध्यप्रदेश और राजस्थान में बारह बच्चों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ वर्ष पूर्व अफ्रीकन देशों में भारतीय कफ सिरप से कुछ बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन सरकार अभी तक नकली दवाओं कों रोकने में विफल रही है। बाजार में आने से पूर्व दवा की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। नकली दवा निर्माताओं पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, और दुनिया के कुल जेनेरिक उत्पादन का लगभग बीस प्रतिशत आपूर्ति करता है। दवा की गुणवत्ता के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना होगा। सरकार को देश में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

राहुल की विदेश यात्राएं

'कोलंबिया में राहुल गांधी' संपादकीय आलेख पढ़ा। वहां इंजीनियरिंग के छात्रों के समक्ष राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल और कार के वजन और यात्री क्षमता के बारे में जिस तरह का प्रश्न रखा, पता नहीं वहां के छात्र हमारे देश के राजनेताओं के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी किस आधार पर विदेशों में छात्रों से चर्चा करते हैं। ना तो वह कोई अकादमिक हैं, ना तो कोई प्रोफेसर हैं और ना ही किसी विषय के विशेषज्ञ हैं। फिर कौन लोग हैं, जो विदेशों में उनके कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। कहीं ऐसे कार्यक्रम किसी विशेष प्रयोजन के लिए पर्दे का काम तो नहीं करते, क्योंकि जिस तरह वह भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और बड़े देशों से हस्तक्षेप करने का आह्वान करते हैं, उनकी विदेश यात्राएं निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आती हैं। वह ऐसी बात करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हम नहीं जीते तो खेल के नियम सही नहीं। राहुल गांधी झूठ को बार बार दोहराते हैं, उनको लगता है झूठ को अगर लगातार परोसा जाए तो भारत के मतदाता इसको सही मान लेंगे। परंतु, ऐसा होता नहीं है, जो प्रतिबद्ध व परिपक्व मतदाता हैं, वे हर हाल में वोट करेंगे ही। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं, पर लोकतंत्र पर कोई खतरा है।

सुब्रत कुमार, राजपुर पुल, पटना

पोस्ट

भारत में पाकिस्तानपरस्त टिप्पणीकारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हैरानी की बात यह है कि आइएसआइ से भी उन्हें कोई खैरात नहीं मिलती। वे तो बस भारत से नफरत करते हैं और लिखते हैं।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

गिल को वनडे कप्तान बनाया जाना कोई हैरानी की बात नहीं। विश्व कप में दो ही साल बचे हैं। इससे उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ ताल मिलाने में मदद मिलेगी। रोहित को टीम में शामिल करके भी चयनकर्ताओं ने यही संकेत दिया है कि विश्व कप में उनका खेलना फार्म और फिटनेस पर निर्भर होगा। यही बात विराट पर लागू होती है।

अयाज मेमन@cricketwallah

कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का सफर बेहद शानदार रहा। दो आइसीसी ट्राफी और सीमित ओवरों की क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन जैसे कि हर सुखद कहानी का एक अंतिम पड़ाव आता है, इस मामले में भी कुछ वैसा ही है। गिल को शुभकामनाएं कि वह इस विरासत को दमदार तरीके से आगे बढ़ाएं।

वीरेंद्र सहवाग@virendersehwag

जनपथ

तैयारी आयोग की है अबकी भरपूर,
गलतफहमियां आप भी कर लीजै अब दूर।
कर लीजै अब दूर टूर अब छोड़ विदेशी,
मांगो घर-घर वोट धूर अब फांको देसी।
नहीं मिलेगी जीत किसी को देकर गारी,
जीते वही चुनाव करेगा जो तैयारी!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 173

****

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 06 अक्टूबर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मासूम मौतें, बेफिक्र सरकार

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और राजस्थान में पिछले एक महीने में कम से कम 15 बच्चों की मौत केवल इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें दवा के नाम पर जहर पीने को मिला। यूं तो निर्दोषों की अकाल मौत पर दुख होता है, नाराजगी होती है, लेकिन मासूम बच्चे जब सरकारी लापरवाही का शिकार होकर दम तोड़ें तो दुख और नाराजगी के साथ बेबसी भी जाहिर होती है कि आखिर हम किस तरह के शासन में रह रहें हैं, जहां कुछ लोगों के लालच और फायदे में मासूमों की जान चली जाए और इस पर केवल अफसोस की रस्म अदायगी हो। दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो अब इस्तीफे की उम्मीद करना बेकार है। याद करें, उत्तरप्रदेश में इसी तरह ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी और बजाय दोषियों को सजा देने के, इसमें भी हिंदू-मुसलमान का एंगल तलाश लिया गया। अब मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस भाजपा सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे तो मांग रही है, लेकिन इस मांग की कहीं सुनवाई नहीं होगी, यह तय है। कायदे से तो देश का प्रधानमंत्री होने के नाते नरेन्द्र मोदी को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें पं.नेहरू की तरह बच्चों का पसंदीदा बनने का बड़ा ख्वाब है, इसीलिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं, अपनी रैलियों में बच्चों से मिलते हैं, लेकिन नेहरूजी या शास्त्रीजी की तरह नैतिक हिम्मत दिखाकर शासन नहीं कर सकते। वैसे भी श्री मोदी का सारा ध्यान इस समय बिहार चुनाव पर लगा है, इसके बाद तमिलनाडु, केरल, प.बंगाल, असम पर फोकस चला जाएगा। मध्यप्रदेश और राजस्थान तो भाजपा जीत ही चुकी है, इसलिए अब यहां कुछ भी होता रहे, कम से कम अगले चुनावों तक उसे फर्क नहीं पड़ेगा।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में 7 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुल 11 बच्चों की किडनी ख़राब होने से मौत हो चुकी है, और कम से कम पांच बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चों की मौत किडनी को चोट पहुंचने से हुई है। बच्चों की रीनल बायोप्सी जांच के बाद यह पता चला था कि किसी जहरीले पदार्थ से किडनी को चोट पहुंची और उसने काम करना बंद कर दिया जिसके बाद बच्चों की मौत हुई। इन बच्चों ने कफ सिरप पी थी और उसमें ही जहरीला पदार्थ होने की बात सामने आई है।

कोल्ड्रिफ नाम के इस कफ सिरप में अत्यधिक ज़हरीली रसायन डायथाइलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी पाई गई। इसके बाद शनिवार को मध्यप्रदेश सरकार ने इस सिरप की बिक्री, वितरण और निपटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला लैब टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें सिरप को 'अधिकारिक रूप से खराब और मिलावटी' घोषित किया गया। कोल्ड्रिफ को तमिलनाडु के एक संयंत्र में बनाया जा रहा था। जब तमिलनाडु सरकार में इसकी शिकायत की गई तो फौरन ही सिरप की जांच कराई थी, जिसमें पाया गया कंपनी गलत ढंग से सिरप को तैयार कर रही थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को ही इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी, क्योंकि इसमें तमाम जानलेवा बैक्टीरिया छोटे बच्चों की मौत की वजह बने। लेकिन बताया जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई तो केंद्र सरकार की एजेंसियों ने तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश की। बेशक यह कफ सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स में बन रहा था। लेकिन कंपनी पर कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के पास है। लिहाजा कार्रवाई की पहल वहीं से होनी चाहिए थी। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि केंद्र सरकार को इस जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया लेकिन वहां से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

गनीमत यह है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार ने अब ऐसे विषाक्त कफ सिरप पर रोक लगाई है और बच्चों की मौत पर अफसोस भी जाहिर किया है। लेकिन इससे जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। तमिलनाडु सरकार ने जब दवा की जांच एक दिन में पूरी कर रिपोर्ट जारी कर दी, तो मध्यप्रदेश और राजस्थान में यही काम पहले क्यों न हो सका। क्यों बिना जांच के दवा सरकारी अस्पतालों तक पहुंची। बच्चों के मामले में तो खिलौनों, कपड़ों, जूतों से लेकर खाने-पीने के सामान तक अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है, क्योंकि उन्हें सही या गलत, ठीक या खराब गुणवत्ता की परख नहीं होती है। मासूम बच्चे ये भी नहीं बता पाते कि उन्हें किस चीज के सेवन से तबियत ठीक नहीं लग रही है। इस बारे में माता-पिता अनुमान लगाते हैं और डॉक्टरों के भरोसे ही रहते हैं। डॉक्टरों ने जो दवा लिखकर दे दी, उस पर आंख मूंदकर यकीन करते हुए अपने बच्चों को पिला देते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश और राजस्थान में इस यकीन को ऐसा चकनाचूर किया गया कि मां-बाप को जीवन भर का दुख दे गया।

क्या फर्क पड़ता है कि अब कितनी दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, कितने डॉक्टरों का निलंबन हुआ है। मासूमों की मौत पर समाज में जो बड़े पैमाने पर उद्वेलन दिखना चाहिए था, वह नदारद है। सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है कि लोगों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने में उसे सफलता मिल चुकी है। मीडिया इसमें सरकार का पूरा साथ दे रहा है। अन्यथा अब तक इसे सांगठनिक हत्या मानकर सरकार से जवाबदेही की मांग सुर्खियों में रहती।

नोटबंदी में मौतें, कोरोना काल और लॉकडाउन में असंख्य मौतों से जब सरकार का दिल नहीं पसीजा तो अब क्या कोई फर्क पड़ेगा, यह देखना होगा।

2015 की तरह इस बार भी बिहार में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा

क्या बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण बनने जा रहा है? लगता यही है और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बिहार के किसी नेता की वजह से नहीं, दूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की वजह से बना है। सोशल मीडिया में जो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला मंच है वहां बीजेपी के लोगों के बीच ही मोहन यादव घिर गए हैं।

मोहन यादव को वह सब गाली दी जा रही हैं जो बीजेपी के भक्त, ट्रोल कांग्रेस को और दूसरे लोगों को देते रहते हैं। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से कहा जा रहा है उन्हें बर्खास्त कर दो।

मोहन यादव का कसूर क्या है? आज की बीजेपी में यही मालूम नहीं पड़ता है। जगदीप धनखड़ का गुनाह क्या था? किसी को नहीं मालूम। खुद शायद धनखड़ को भी नहीं। इसी तरह सोनम वांगचुक अचानक देशद्रोही कैसे हो गए? वे भी मोदी मोदी करने में अव्वल थे। मगर आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) में अंदर हैं।

मोहन यादव को अचानक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन शिवराज सिंह चौहान को हटाकर जिन्होंने मध्यप्रदेश में बीजेपी की 5 बार सरकार बनवाई। मगर अब मोहन यादव को ही सबसे बड़े खलनायक बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या किया?

किया कुछ नहीं। केवल एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जो अभी 14 प्रतिशत है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 अक्टूबर से रोज सुनवाई करने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य में 51 प्रतिशत से अधिक ओबीसी हैं। बाकी वंचित समुदाय में 15. 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) और 21. 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) है। सब मिलाकर वंचित समूह 87 प्रतिशत से अधिक होता है। इसलिए जनसंख्या के लिहाज से और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए।

संक्षेप में कुल मामला यह है। लेकिन चूंकि मोहन यादव खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए बीजेपी के अंदर उनको लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के बनाए हुए सोशल मीडिया के ट्रोल अब मोहन यादव के पीछे ही पड़ गए हैं।

लेकिन यहां भी बीजेपी के फैलाए नफरत और विभाजन का असर दिखने लगा है। जो सवर्ण ट्रोल हैं या भक्त हैं। वे मोहन यादव को हर वह गाली दे रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस, मुसलमान, अखिलेश, तेजस्वी, लालू को देने के लिए सिखाई गई थी। जाहिर है जो पिछड़े इतने दिनों से बीजेपी की सेवा में लगे थे वे एक तो आरक्षण का विरोध और फिर जातिगत आधार पर गाली देने से विचलित हो गए।

शकील अख्तर

बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली है। वहां यह मुद्दा सबसे बड़ा बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी शुरुआत हो गई है। और बीजेपी ने सोशल मीडिया और गोदी मीडिया दोनों को इतना ताकतवर बना दिया है कि देश का अजेंडा अब वही तय करते हैं। और इस बार यह अजेंडा आरक्षण बन गया है। क्या होगा इसका असर? बीजेपी का असली मुद्दा यही है।

हिन्दू एकता के नाम पर उन्हें दूसरों को गाली देने के लिए इकट्ठा किया गया था। मगर अब उन्हें हिन्दू नहीं जातिगत आधार पर छोटा दिखाकर बुरा-भला कहा जा रहा है साथ ही बीजेपी को धमकी दी जा रही है कि अगर उसने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया तो उसे बिहार में हरवा दिया जाएगा।

कह तो मोहन यादव को भस्मासुर रहे हैं। मगर ट्रोल या कहें बड़े वाले ट्रोल खुद अपने आपको इतना ताकतवर समझ रहे हैं कि वे चुनाव हरवा सकते हैं। हो सकता है सही भी हो। क्योंकि मोदी को 11 साल सत्ता में बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। मोदी के पक्ष में और राहुल के खिलाफ नरेटिव (धारणाएं) बनाने में ट्रोलों और भक्तों का सबसे ज्यादा यूज किया गया है। अब तो जब यह आपस में जातिगत आधार पर लड़ रहे हैं जो यह कहा जाता है कि गंदे लोगों की आपस में लड़ाई में कुछ छूटता नहीं तो यह एक दूसरे का बता रहे हैं कि आईटी सेल और फलाने नेता से किसको कितना मिलता है।

वह जब कहा जाता था कि एक ट्वीट के दो रुपए मिलते हैं तो सही बताएं हमें यकीन नहीं आता था। मगर अब तो आपस में एक दूसरे को नंगा किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि झूठी खबरें चलाने पर जब किसी पर मामला दर्ज हुआ तो वह किस तरह डर गया था।

कहने को यह ट्रोल कहते हैं कि हम नहीं डरते। मगर अब जब सब एक दूसरे की हकीकत बता रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि कानून से सब डरते हैं।

सोशल मीडिया पर जब भी ट्रोल गालियां दें, झूठ फैलाएं, चरित्र हनन करें तो इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहिए। कांग्रेस को यह बात ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसके शासित प्रदेशों कर्नाटक, तेलंगाना में जब इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्टें हुईं तो यह सब से ज्यादा डरे, रोए। और अधिकांश मामलों में जिनके लिए काम करते थे, माहौल बनाते थे वे मदद करने नहीं आए। घर परिवार व्यक्तिगत दोस्तों की वजह से ही बचे।

इस सारे प्रकरण से एक बात और साफ हो गई। जिस मुस्लिम के नाम पर यह दलित पिछड़ों को जोड़ते थे वह असली दुश्मन नहीं है। न ही कांग्रेस है। मोहन यादव हटाओ अभियान में साफ लिख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस आ जाए, मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाए मगर यादव को हटाकर रहेंगे।

वास्तव में मनुवाद का असली निशाना दलित और पिछड़े ही हैं। मगर उनका वोट चाहिए और तादाद में ज्यादा है जैसा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिए अपने शपथ पत्र में कहा कि 87 प्रतिशत से ज्यादा तो इन्हें मुसलमान का झूठा डर दिखाकर साथ लिया जाता है।

लेकिन अब मुसलमान बीच में कहीं नहीं है। पहले भी नहीं था। सिर्फ एक काल्पनिक शत्रु बनाकर बीजेपी हिन्दुओं को डराती है। मगर अब जब ओबीसी को हक देने का सवाल आया तो बताया जाने लगा कि हमारी नौकरी, उच्च शिक्षा में सीटें मुस्लिम ने नहीं ली हैं, दलित ने ली हैं और अब पिछड़े अपना आरक्षण 14 से 27 प्रतिशत बढ़वाकर लेने वाले हैं।

बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली है। वहां यह मुद्दा सबसे बड़ा बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी शुरुआत हो गई है। और बीजेपी ने सोशल मीडिया और गोदी मीडिया दोनों को इतना ताकतवर बना दिया है कि देश का अजेंडा अब वही तय करते हैं। और इस बार यह अजेंडा आरक्षण बन गया है।

क्या होगा इसका असर? बीजेपी का असली मुद्दा यही है। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी नेताओं ने खुलकर 400 से ऊपर सीटें मांगी थीं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार। बीजेपी के नेताओं ने कहा था संविधान बदलने के लिए इतनी सीटें दो तिहाई चाहिए। अगर मिल गई होतीं तो आरक्षण खतम हो गया होता।

2014 में बीजेपी की जीत के बाद भी भाजपा और संघ इसी एक सूत्रीय कार्यक्रम पर शुरू हो गए थे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। मगर परिणाम उल्टा निकला। भाजपा हार गई।

इस बार 2025 में संघ और भाजपा खुद न कहकर अपने सोशल मीडिया ट्रोलों से कहलवा रहे हैं। क्या होगा परिणाम? देखना दिलचस्प होगा। अगर आरक्षण का मुद्दा केन्द्र में आ गया जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि 8 अक्टूबर से इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है तो पूरा चुनाव आरक्षण समर्थक और आरक्षण के विरोध में हो जाएगा। बीजेपी को शायद ही यह सूट करे। उसे 2015 की याद आ जाएगी। जब आरक्षण के मुद्दे ने उसे हरा दिया था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

अयोध्या और काशी पर बवाल भारत के लिए अशुभ

■ **पी. सुधीर**

यह विचित्र बात है कि अयोध्या और काशी मुद्दे फिर से उलझने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों के कारण ये प्रश्न काफी समय से अधर में लटके रहे। कई लोगों के लिए, अयोध्या का फैसला एक पहेली था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उससे वास्तव में बाबरी मस्जिद को आपराधिक रूप से ध्वस्त करने वालों को उसके स्वामित्व से पुरस्कृत किया जाना था और जिससे राम मंदिर के निर्माण में मदद मिलनी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए इस न्यायिक मान्यता को रेखांकित किया था। जाहिर है, इसके विपरीत, हमें स्पष्ट रूप से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'फैसला सुनाया है, न्याय नहीं'।

लेकिन अब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पूरे सवाल को फिर से खोल दिया है। न्यूज़लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन को 24 सितंबर को प्रकाशित एक साक्षात्कार में, चंद्रचूड़ ने कहा, 'पुरातात्विक उत्खनन से पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। अब, पुरातात्विक उत्खनन का साक्ष्य मूल्य क्या है, यह एक अलग मुद्दा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पुरातात्विक रिपोर्ट के रूप में साक्ष्य मौजूद हैं।'

न्यायिक निर्णय, खासकर उच्च न्यायपालिका के, सूक्ष्म बारीकियों के साथ गढ़े जाते हैं ताकि 'धुएं के परदे' की तरह काम करने वाले खुरदुरे पहलुओं को छिपाया जा सके। जब तक लेखक स्वेच्छा से उनका खुलासा नहीं करते, तब तक वे कभी ज्ञात नहीं होंगे, समझे जाने की तो बात ही छोड़ दें। अयोध्या फैसले के सटीक पाठ को देखते हुए, यह विशेष रूप से सच है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश का विवादास्पद जवाब जैन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर था: 'तर्क यह है कि (मस्जिद के) भीतरी प्रांगण पर विवाद हिंदुओं द्वारा अपवित्रीकरण और अशांति फैलाने जैसे अवैध कृत्यों का परिणाम था; यह तथ्य कि मुसलमानों ने बाहरी प्रांगण में ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो यह उन्हें दंडित करने का लगभग आधार बन जाता है। यह तथ्य कि आपने विरोध नहीं किया, जबकि हिंदुओं ने किया, वास्तव में मुसलमानों के विरुद्ध है, वास्तव में निर्णय की एक आलोचनात्मक व्याख्या है।'

चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, 'जब आपने कहा कि हिंदू ही भीतरी प्रांगण को अपवित्र कर रहे थे, तो अपवित्रता के मूल कृत्य- मस्जिद के निर्माण- के बारे में क्या? आप वह सब भूल गए जो हुआ था? हम भूल गए कि इतिहास में क्या हुआ था?'

न्यायिक निर्णय, खासकर उच्च न्यायपालिका के, सूक्ष्म बारीकियों के साथ गढ़े जाते हैं ताकि 'धुएं के परदे' की तरह काम करने वाले खुरदुरे पहलुओं को छिपाया जा सके। जब तक लेखक स्वेच्छा से उनका खुलासा नहीं करते, तब तक वे कभी ज्ञात नहीं होंगे, समझे जाने की तो बात ही छोड़ दें। अयोध्या फैसले के सटीक पाठ को देखते हुए, यह विशेष रूप से सच है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साक्षात्कार में जो कहा वह पुरातात्विक निष्कर्षों के संबंध में फैसले के मूल पाठ से पूरी तरह भिन्न था। 'रिपोर्ट विवादास्पद स्थल पर पाए गए वास्तुशिल्पीय अवशेषों और संरचना की प्रकृति के आधार पर यह निष्कर्ष निकालती है कि यह हिंदू धार्मिक मूल से निकली थी। रिपोर्ट इस संभावना को खारिज करती है (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जोर दिया गया) कि अंतर्निहित संरचना इस्लामी मूल की है। लेकिन एएसआई रिपोर्ट ने उसे सौंपे गए कार्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उत्तर नहीं दिया है, जैसे यह निर्धारित करना कि क्या मस्जिद के निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था? इस पहलू पर एक विशिष्ट निष्कर्ष देने में एएसआई की असमर्थता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य परिस्थिति है जिसे अंतिम विश्लेषण में संपूर्ण साक्ष्य के संचयी प्रभाव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।'

आदेश में आगे कहा गया है कि- 'इस चरण में एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिस पर स्वामित्व के प्रश्न का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाएगा। वह मुद्दा यह है कि क्या स्वामित्व का निर्धारण एएसआई के निष्कर्षों के आधार पर किया जा सकता है? और क्या 1528 ई. (450 वर्ष से भी पहले) में एक पूर्ववर्ती धार्मिक संरचना (जो बारहवीं शताब्दी की है) की नींव पर एक मस्जिद के निर्माण से स्वामित्व के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष निकल सकता है, यह एक अलग मामला है। इस स्तर पर, यह नोट करना पर्याप्त होगा कि स्वामित्व का निर्धारण स्पष्ट रूप से एएसआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। यह एक ऐसा मामला है जिस पर न्यायालय को इस निर्णय में बाद में स्वामित्व के मुद्दे पर विचार करते समय एक सुविचारित और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होगी।' इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय कभी भी इस निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि 'मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था' जैसा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साक्षात्कार में दावा किया है - 'पुरातात्विक उत्खनन से पर्याप्त साक्ष्य मिले थे'।

काशी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर खुदाई की अनुमति देने और यह सिफारिश करने पर कि 'धार्मिक संरचना के स्वरूप की जांच की जा सकती है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता', न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए बेशर्म आत्म-विरोधाभास पर भी यही बहुसंख्यकवादी रुख देखा जा सकता है। पूजा स्थल अधिनियम के आलोक में, अयोध्या को छोड़कर, कोई अन्य धार्मिक स्थल कानूनी चुनौती के लिए खुला नहीं था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के रुख ने अन्य स्थलों के संबंध में विवाद, घृणा और हिंसा का मार्ग प्रशस्त किया है।

न्यूज़लॉन्ड्री का साक्षात्कार सार्वजनिक होने के बाद से, चारों ओर कोहराम मच गया है। हालांकि, दुर्भाग्य से सार्वजनिक चर्चा और बहस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की भूमिका और व्यक्तित्व तक ही सीमित रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश की भूमिका वाले कई अन्य फैसले संदर्भ के लिए आ रहे हैं, खासकर वे जिनमें आरएसएस-भाजपा को राजनीतिक लाभ हुआ प्रतीत होता है।

नि:संदेह, यह अपरिहार्य है। लेकिन केवल व्यक्तिपरक विचार तक सीमित रहना 'वास्तविकता को नज़रअंदाज़ करने' के समान होगा। भारतीय गणराज्य में जिस तरह का बदलाव आया है, उसे हम अपने ही नष्ट होने के जोखिम पर नज़रंदाज़ कर सकते हैं। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ पर आधारित है। इस नई दिशा की प्रकृति ही एक ऐसे आदर्श बदलाव की पूर्वकल्पना करती है जहां लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को व्यापक क्षरण और क्षति का सामना करना पड़ेगा।

यह स्पष्ट है कि राज्य केवल कार्यपालिका और विधायिका तक ही सीमित नहीं है; बल्कि इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। इसलिए, जहां संविधान को ही समाप्त करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, वहीं साथ ही, न्यायपालिका को हिंदुत्व के रथ के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गणतंत्रीय न्यायशास्त्र और संविधानवाद के सिद्धांतों के प्रति न्यायिक प्रतिबद्धता के कुछ उज्ज्वल उदाहरणों के बावजूद, यह एक भटकाव है। दुर्भाग्य से, न तो अयोध्या और न ही ज्ञानवापी मामले के फैसले ऐसे संवैधानिक सिद्धांतों और उन पर आधारित देश के कानूनों को कायम रखते हैं।

आपके पत्र

धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत नहीं बल्कि नैतिक आस्था

धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील आधारशिला है। यह केवल संविधान की पंक्तियों में लिखा गया शब्द भर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन का प्राणतत्व है। भारतीय राजनीति की आत्मा इसी से पोषित होती है परंतु दुखद है कि आज धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कई बार केवल संवैधानिक औपचारिकताओं तक सीमित रह जाती है। मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में साम्प्रदायिक झगड़ों की घटनाओं ने इस सिद्धांत की आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई है और इसके संवैधानिक अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म से विद्वेष रखना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में इसे 'सर्वधर्म समभाव' कहा गया है। पश्चिमी संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है- राज्य और धर्म का परस्पर हस्तक्षेप न करना तथा व्यक्ति और उसके अधिकारों को सर्वोच्च मान्यता देना। वहीं भारतीय संदर्भ में यह और अधिक व्यापक है—यह न केवल धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल देता है, बल्कि समाज में विविध धार्मिक मतों के बीच सहिष्णुता, आदर और समान अवसर की स्थापना का भी उपक्रम करता है। भारत की आज़ादी के बाद से धर्मनिरपेक्षता ने लोकतंत्र को शक्ति दी है। यहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है; सब नागरिक कानून और व्यवस्था की दृष्टि से समान हैं। हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म अपनाने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। संविधान का 42वां संशोधन (1976) इस भावना को और स्पष्ट करता है, जिसमें 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया—अर्थात राज्य किसी विशेष मत को न अपनाएगा और न ही किसी धर्म के प्रति भेदभाव करेगा। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, नेहरू, पटेल और शास्त्री जैसे राष्ट्र पुरुषों ने धर्मनिरपेक्षता को केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि नैतिक आस्था माना। स्वतंत्रता संग्राम से पहले हुए सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी इस मार्ग को प्रशस्त किया। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति विविधता में एकता रही है—और इस एकता का मूल मंत्र धर्मनिरपेक्षता ही है। आज भारत विकास की सीढ़ियां चढ़कर एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम धर्मनिरपेक्षता की इस स्वस्थ परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें। लोकतांत्रिक दलों, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आम नागरिक—सभी को यह संकल्प लेना होगा कि वे इसे केवल नारों और चुनावी मुद्दों तक सीमित न रखें। क्योंकि जब-जब राजनीति ने धर्मनिरपेक्षता को अपने स्वार्थ के लिए हथियार बनाया, समाज का संतुलन बिगड़ा और आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमें तर्क, विवेक और स्वतंत्रता की संस्कृति देती है। यह न केवल वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती है, बल्कि हर नागरिक को आत्मसम्मान और समान अवसर का आश्वासन भी देती है। इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है—जो विविधता को एकता में रूपांतरित कर, भारत को विश्व के लिए आदर्श प्रतिमान बना सकती है।

-संजीव ठाकुर

ललित सुरजन की कलम से

आप किसे वोट देंगे?

'जब राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो जाए तो विचारों की बलि अपने आप चढ़ जाती है। हमें चारों दिशाओं में एक भी ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो मीडिया को अपने अंगूठे के नीचे न रखना चाहता हो। आम जनता भले ही आज भी अखबार पर भरोसा करती हो, हकीकत यही है कि मीडिया को अब जनहित की परवाह नहीं है। राजनेता यह समझने में असमर्थ हैं कि इस नियंत्रण-नीति में उनका ही नुकसान है। उन तक सही सूचनाएं सही वक्त पर नहीं पहुंच पातीं। वे प्रचारतंत्र का शिकार हो जाते हैं। जनमत परखने के इस बहुमूल्य साधन की अवज्ञा या तिरस्कार का स्वाभाविक परिणाम होता है कि जो लोकहितकारी योजनाएं पूरे पांच साल समगति से जारी रहना चाहिए, वे चार साल ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं और जब चुनाव सिर पर आते हैं तो उनका ढोल पीटा जाता है। इस बीच की अवधि में सत्तासीन दल दूसरी कलाबाजियों में व्यस्त रहा आता है। मतदाता यदि सचमुच इतना भोला है तो इससे प्रभावित हो सकता है। हां, यदि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो नीर-क्षीर विवेचन कर उचित निर्णय पर पहुंच सकता है।'

(देशबन्धु में 11 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2018/10/blog-post_10.html

पावन प्रसंग

हर स्थिति में मुस्कराइये और आनन्द पाइये

जीवन में सुख और दु:ख का क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। दिन-रात की तरह कभी सुख तो कभी दु:ख का आना, जीवन का क्रम है। सुख तो सभी चाहते हैं, पर दु:ख आने पर व्यक्ति धैर्यहीन बन जाता है। जिस तरह से हम सुख चाहते हैं, उसी प्रकार दु:ख को सहने की भी आदत डालनी चाहिए। सुख आने पर अहंकारवश मन में फूलना और दु:ख आने पर पीड़ा की अनुभूति से अपने स्वरूप को भूलना विकास में बाधक है। सुख हो अथवा दु:ख, दोनों ही संयोगजन्य हैं। सुख है तो गुजर जाएगा एवं दु:ख है तो भी गुजर जाएगा, यदि इस तरह की धारणा या विचार बन जाये तो व्यक्ति कभी भी आकुलता-व्याकुलता का अनुभव नहीं करेगा और वह समताभाव की ओर बढ़ने लगेगा।

मानव यदि चाहे तो दु:ख में भी सुख की अनुभूति कर सकता है। जीवन है तो दु:ख भी है। वस्तुत: जीवन का प्रवर्तन ही दु:ख से होता है। जीवन के हर मोड़ पर कई प्रकार के दुख-ही-दुख मिलते हैं और फिर अन्त तो दुख से ही जुड़ा होता है।

दुखों से घबराना, दु:खों को देखकर आंसू बहाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग दु:खों को अपने सामने देखकर मायूस हो जाते हैं, वे जीवन में पिछड़ जाते हैं। आज भी दुनिया में लाखों, करोड़ों हैं,वे अभावग्रस्त हैं।

जीव मात्र का स्वभाव अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग एवं सुख से परिपूर्ण है तो फिर जीवन में दु:ख आये तो क्यों और कैसे आये? इस संसार में सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दु:खी होना नहीं चाहता तो फिर आखिर हमें दु:खी बनाता कौन है? कौन है वह जो हमें दु:ख देता है? भगवान महावीर से प्रश्न किया गया- भंते! दुक्खे केण कड़े? भगवन! यह फरमाइये कि दु:ख कौन देता है?

भगवान ने समाधान दिया- दुक्खे, जीवेण कड़े पमाएण। अर्थात् जीव अपने ही प्रमाद के कारण दु:खी होता है। स्वीकृत प्रमाद के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई भी शक्ति दु:खी बनाने वाली नहीं है। प्रमाद से अनेक प्रकार की कुंठायें उपजती हैं और ये कुंठायें व्यक्ति को घुटन एवं टूटन की ओर ले जाती हैं। इस तरह मानव की, उसके सम्पूर्ण जीवन की दुर्दशा होती है। प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमाद से प्रेरित बनकर व्यक्ति हँसते हुए अशुभ कर्मों का बन्ध कर लेता है और जब वे कर्म उदय में आते हैं तो वह पीड़ित एवं परेशान हो जाता है।

यहां आप यह भी समझ लें कि प्रमाद क्या है? इन्द्रियों की व्यर्थ चेष्टा, कुछ का कुछ समझना, अकरणीय को करणीय समझकर करना अथवा अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना प्रमाद है। प्रमाद को मिथ्याबोध भी कह सकते हैं। इस तरह जब हमारे भीतर आनन्द का अक्षय स्त्रोत परमात्मस्वरूप आत्मा है, हम स्वयं आत्मा ही हैं तो बाहर देह और देह के विस्तार संसार में सुख देखना प्रमाद है। यही प्रमाद दु:ख का मूल है। दुनिया का यह दस्तूर है कि रोने वाले के साथ इस दुनियां में कोई भी नहीं रोता। दु:खों में आप मुस्कराते रहो। आप मुस्कराओगे तो सारा जमाना आपके साथ मुस्कराएगा।

-कांतिलाल मांडोत

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

पहाड़ों पर बार-बार क्यों पड़ रही प्रकृति की मार

हिमाचल प्रदेश और उतराखंड पर प्रकृति की मार से उभर भी नहीं पाए थे कि दार्जिलिंग में मौसम ने कहर बरपा दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित पहाड़ों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार बरसात के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुए। इन भूस्खलनों से 40 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग अभी तक लापता हैं। भूस्खलन के कारण कई घर पूरी तरह से बह गए। इन घरों में रहने वाले लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। सड़कें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं या मलबे से भर गईं। असल में भूटान में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी उत्तर बंगाल में बह रहा है। केवल 12 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। जिसने जमकर बर्बादी की है। इससे आवागमन पूरी तरह से रुक गया है। कई दूरदराज के गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से टूट गया है। भूस्खलन और सड़क मार्ग पर अवरोधों के कारण पूरे क्षेत्र में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार और प्रशासन उन्हें किसी तरह आपदा से बाहर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले से ही दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में छह अक्टूबर तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। साथ ही, मिट्टी की नाजुक स्थिति के कारण और अधिक भूस्खलन और सड़कों पर अवरोध पैदा होने की चेतावनी दी गई थी। असल में अब पहाड़ों का जानलेवा होना कोई नया नहीं रह गया है। कई सालों से लगातार देखने में आ रहा है कि पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। 2010 से 2025 के बीच पहाड़ों पर हुईं भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने 5949 से अधिक लोगों की जान ले ली। ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण कहीं न कहीं मनुष्य और आबादी क्षेत्र का विस्तार है। यह अंधाधुंध विकास और पर्यावरण के असंतुलन का परिणाम है। बीते कुछ दशकों में हमने अपने पहाड़ों की संपदा का 40 से 50 प्रतिशत दोहन बढ़ा दिया है। इससे न केवल जल चक्र प्रभावित हुआ बल्कि सीधे तौर पर मानव जीवन और पर्यटन अर्थ आवासीय संरचना को काफी बढ़ाया है। इन क्षेत्रों में लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। ऐसे में वह उन जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके अलावा पहाड़ों पर लगातार हो रही घटनाओं का कारण भूमि स्ट्रक्चर में बदलाव को भी माना जा रहा है। बीते वर्षों में केदारनाथ त्रासदी 2013, चमोली त्रासदी 2021, जोशीमठ त्रासदी 2023 और इस साल उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं। वह सब इसी के एक बड़ा उदाहरण हैं। मौजूदा समय में हम क्लाइमेट चेंज के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर मौसम बिल्कुल अनिश्चित है। कभी गर्मी का मौसम लंबा खिंचता है तो कभी सर्दी का, इसने हमारे इको सिस्टम को प्रभावित किया है। इसी का असर है कि जिन बादलों को मैदान की तरफ जाकर बरसना चाहिए, वह जलवायु दबाव के कारण पहाड़ों पर ही अचानक से बरस जा रहे हैं। इसके अलावा धरती और समंदर दोनों लगातार गर्म हो रहे हैं। ऐसे में बादलों के बरसने का जो नियम है वह पहाड़ों पर ठंडा मौसम होने के कारण वहां पर अधिक विकराल रूप ले रहा है। अगर हम भी नहीं चेते तो तय है कि ये प्रकृतिक आपदाएं और भी विकराल रूप ले लेंगी। इससे पहाड़ों में जीवन ही कठिन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें। उससे ज्यादा छेड़छाड़ पूरी मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है।

श्रद्धांजलि
नरेंद्र मोदी

भारतीय जनता पार्टी परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा के मूल संस्कार क्या हैं। विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन, स्वयं से ऊपर सेवा भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही। मल्होत्रा के परिवार ने विभाजन का भयावह दौर झेला। उस स्थिपन ने उन्हें कड़वा या आत्मकेंद्रित नहीं बनाया।

उपलब्धियों से भरा रहा मल्होत्रा का जीवन

कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सेवा से भरा जीवन जिया। उनके जीवन को देखकर समझा जा सकता है कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा के मूल संस्कार क्या हैं। विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन, स्वयं से ऊपर सेवा भावना, साथ ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, यह उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान रही। वीके मल्होत्रा के परिवार ने विभाजन का भयावह दौर झेला। उस आघात और विस्थापन ने उन्हें कड़वा या आत्मकेंद्रित नहीं बनाया। इसके बजाए, उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा में राष्ट्रसेवा का रास्ता नजर आया।

बंटवारे का वो समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। मल्होत्रा ने सामाजिक कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने उन हजारों विस्थापित परिवारों की मदद की, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। उनका जीवन संवारने और उन्हें फिर से खड़े होने में मदद की। यही जनसंघ की प्रेरणा थी। उन दिनों उनके साथी मदनलाल खुराना और केदारनाथ साहनी भी बढ़-चढ़कर सेवा कार्यों में शामिल होते थे। उन लोगों की निःस्वार्थ सेवा को आज भी दिल्ली के लोग याद करते हैं। 1967 के लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तब अपराजेय मानी जाने वाली कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले रहे थे। इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक कम चर्चित चुनाव भी हुआ। वो था, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का पहला चुनाव। राष्ट्रीय राजधानी में जनसंघ ने शानदार जीत दर्ज की।

आडवाणी काउंसिल के चेयरमैन बने और मल्होत्रा को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की जिम्मेदारी दी गई, जो मुख्यमंत्री के लगभग बराबर का पद था। तब उनकी उम्र केवल 36 वर्ष थी। उन्होंने अपने कार्यकाल को दिल्ली की जरूरतों, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया। इस जिम्मेदारी ने मल्होत्रा जी का दिल्ली से जुड़ाव और मजबूत कर दिया। जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर मल्होत्रा सक्रिय रूप से जनता के साथ खड़े होते और उनकी आवाज बुलंद करते। उन्होंने 1960 के दशक में गौ रक्षा आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जहां उनके साथ पुलिस की ज्यादतियां भी खूब हुईं। आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। दिल्ली की सड़कों पर जब सिखों का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा था, तब वे शांति और सद्भावना की आवाज बनकर सिख समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे। उनका मानना था कि राजनीति, चुनावी सफलता के अलावा सिद्धांतों, मूल्यों और लोगों की रक्षा के लिए भी है, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में वीके मल्होत्रा सार्वजनिक जीवन का एक स्थायी चेहरा बन गए थे। बहुत कम नेता ऐसा दावा कर सकते हैं कि उनके पास लोगों के बीच रहकर काम करने का इतना लंबा और ठोस अनुभव है। वो एक अथक कार्यकर्ता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक संस्था निर्माता थे। उनमें चुनावी राजनीति और संगठनात्मक राजनीति, दोनों में समान

रूप से सहजता के साथ काम करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने जनसंघ और भाजपा की दिल्ली इकाई को स्थिर नेतृत्व दिया। अपने लंबे सेवाकाल में मल्होत्रा ने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, राज्य विधानसभा में भी पहुंचे और देश की संसद में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 1999 के लोकसभा चुनाव में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ उनकी शानदार जीत समर्थकों और विरोधियों के बीच आज भी याद की जाती है। ये एक बेहद हाई-प्रोफाइल चुनाव था। कांग्रेस की पूरी ताकत उनके दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में उतर आई थी। लेकिन मल्होत्रा ने कभी बहस का स्तर नीचे नहीं किया। उन्होंने पॉजिटिव कैंपेन चलाया। गालियों और हमलों को नजरअंदाज किया और 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ प्रचार के दम पर नहीं मिली थी। ये जीत मल्होत्रा की जमीन पर मजबूत पकड़ की वजह से मिली थी। कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध बनाकर रखने और मतदाताओं के मन की थाह लेने में वो माहिर थे। मल्होत्रा संसद में सटीक तैयारी के साथ अपनी बात रखते थे। वो पूरी रिसर्च करके आते थे और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते थे। यूपीए-1 के दौरान विपक्ष के उपनेता के रूप में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए एक मूल्यवान सबक की तरह है। उन दिनों मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अक्सर मल्होत्रा से बातचीत होती। वो हमेशा गुजरात की विकास यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। राजनीति, वीके मल्होत्रा के व्यक्तित्व का केवल एक पहलू थी। वो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद भी थे। उनके परिवार से मुझे पता चला कि उन्होंने स्कूल में डबल प्रमोशन हासिल किया। उन्होंने मैट्रिक और ग्रेजुएशन निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली। उनकी हिंदी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषणों का हिंदी अनुवाद प्रायः वही करते थे। वे आरएसएस से जुड़ी कई संस्थाओं के संस्थापक और संरक्षक रहे। उनके प्रयासों से अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ और मार्गदर्शन मिला। इन संस्थाओं के माध्यम से कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने एक ऐसे समाज का विजन दिया, जो आत्मनिर्भर हो और मूल्यों पर टिका हो। मल्होत्रा ने राजनीति और अकादमिक जीवन से परे, खेल जगत में भी अमिट छाप छोड़ी। तीरंदाजी उनका गहरा शौक था और वो कई दशकों तक आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय तीरंदाजी को ग्लोबल पहचान मिली। उन्होंने खिलाड़ियों को मंच और अवसर दिलाने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए। खेल प्रशासन में भी उन्होंने वही गुण दिखाए जो सार्वजनिक जीवन में थे, यानी समर्पण, संगठन क्षमता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज।वी के मल्होत्रा जी को आज लोग उनके द्वारा संभाले गए पदों के साथ ही उनकी संवेदनशीलता के लिए भी याद कर रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्तित्व की रही, जो हमेशा लोगों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। जहां भी मदद की जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटे। वे आदर्श पार्टी कार्यकर्ता थे, कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे जिससे हमारे कार्यकर्ताओं या विचारधारा को ठेस पहुंचे।

कुछ दिन पहले, मैं दिल्ली भाजपा के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां मैंने स्नेहपूर्वक वीके मल्होत्रा को याद किया। इस वर्ष तीन दशक बाद जब भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो वो बहुत उत्साहित थे। उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं, जिन्हें हम पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और उपलब्धियों से प्रेरणा पाती रहेंगी।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

पर्यावरण

ज्ञानेन्द्र रावत

हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों से तबाही का खतरा

जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों के पिघलने की गति जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी गति से ग्लेशियर झीलों की तादाद भी बढ़ रही है। इस हिमालयी इलाके में ग्लेशियर झीलों की बेतहाशा बढ़ती तादाद निचले इलाकों में रहने वालों के लिए भीषण खतरा बन गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों के आकार में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने वैज्ञानिकों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अध्ययन इस बात के जीते-जागते सबूत हैं कि ग्लेशियर झीलों के विस्तार भविष्य में 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसी भीषण आपदा का सबब बन सकती है। इसलिए इस पर तत्काल अंकुश लगाये जाने की जरूरत है। यदि हिमालयी राज्य उत्तराखंड को लें, तो इसके उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगभग 1266 से भी अधिक ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें 13 तो बेहद खतरनाक हैं। इनमें भी पांच उच्च जोखिम वाली क्षेणी में हैं। इनमें बहुतेरी झीलें ऐसी हैं जो विभिन्न कारणों से बनती-बिगड़ती रहती हैं। हाल ही में एक नयी आफत दस्तक दे रही है। वह यह है कि पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के ऊपर करीब सात सौ मीटर लम्बी और छह सौ मीटर चौड़ी ग्लेशियर झील ने वैज्ञानिकों को अचरज में डाल दिया है। सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि इस झील के आकार में बीते दिनों करीब तीस फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अरुणाचल में 197 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। ये अपना खतरनाक स्तर पर विस्तार कर रही हैं। इनके बाद लद्दाख में 120, जम्मू-कश्मीर में 57, सिक्किम में 47, हिमाचल में 6 और उत्तराखंड में 5 झीलें हैं। कुल मिलाकर 2025 में ही 1,435 ग्लेशियर झीलों का विस्तार हुआ है जो तबाही का संकेत है। गौरतलब है कि ग्लेशियर झीलों का मुद्दा 2013 में केदारनाथ आपदा के समय महत्वपूर्ण बन गया जबकि चौराबाडी ग्लेशियर की झील के फटने से तबाही आई थी। जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 968 ग्लेशियर हैं जिनमें 12000 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। देखा गया है कि आये दिन उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर से बनने वाली झीलों में जरूरत से ज्यादा पानी आने के कारण बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। इनको लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी द्वारा इन बर्फीली वादियों में बनी झीलों पर बीते महीनों में किये गये अध्ययनों में कई हैरानी वाली बातें सामने आयीं हैं। इसकी पुष्टि वाडिया इंस्टीटयूट आफ हिमालयन जियोलाजी के शोध में भी की गई है। शोध में खुलासा हुआ है कि इन झीलों में पानी बढ़ने से इनका आकार तेजी से विकराल रूप लेता जा रहा है। इसके चलते हमेशा आउटबर्स्ट का खतरा बना रहता है। 2021 में हिमनद का एक हिस्सा टूटने से चमोली में धौलीगंगा नदी में बाढ़ और 2013 में केदारनाथ त्रासदी इसकी जीती-जागती मिसाल है। चूंकि हिमालयन क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से काफी संवेदनशील है, इसलिए यह खतरा और बढ़ जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हिमालयी अंचल में बनी इन झीलों से आने वाले भीषण खतरों के प्रति काफी चिंतित हैं। इस सच्चाई को दरगुजर नहीं किया जा सकता कि भारत में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है।

वैज्ञानिकों के शोध-अध्ययन और रिपोर्ट इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में मौजूद 432 ग्लेशियर झीलों में बहुतेरी ऐसी हैं जिनका आकार जून 2025 के दौरान बढ़ा है। केन्द्रीय जल आयोग की मानें तो देश में सबसे अधिक हिमनद झीलें अपने विस्तार में चिंताजनक रुझान दिखा रही हैं जो खतरनाक संकेत हैं। याद रखना होगा कि ग्लेशियर मात्र बर्फीले शिखर ही नहीं हैं, वे हमारे भविष्य की जड़ें हैं। फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बर्फ के पिघलने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र बदल जाता है जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। बढ़ते खतरे से निपटने की दिशा में हमें तत्काल कार्रवाई, फंडिंग के साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। इसके अलावा हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र में मानवीय दखलंदाजी पर अंकुश, जलवायु परिवर्तन के दानव और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगानी ही होगी, तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हिमालय की धारायें मौन हो जाएंगी, हम बूंद-बूंद पानी के लिए तरस जायेंगे, खेत सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। निष्कर्ष यह कि आपदा प्राकृतिक हो या मानवीय निर्मित ,प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन जागरूकता, सतर्कता और सावधानी से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कदम प्राथमिकता के आधार पर तो हम उठा ही सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संपत्ति को परमार्थ में न लगाना ही असफलता

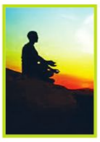

संकलित
दर्शन

संतोष सभी गुणों में सर्वोपरि है। जीवन में संतुष्टि है, तो सद्गुणों को अपनाना सहज है। जहां सद्गुणों का वास है, वहां दुर्गुणों का नाश हो ही जाता है। क्योंकि, असंतुष्टि अशांति व अवगुणों की जननी है। असंतुष्टि का कारण अप्राप्ति है, किसी न किसी इच्छा या अपेक्षा की अपूर्ति है। ईश्वरीय ज्ञान, गुण व शक्तियों की प्राप्ति, धारणा व उपार्जन से इंसान की सभी सदिच्छाओं व आवश्यकताओं की सहज पूर्ति हो जाती है। संतुष्ट आत्मा बनने का अर्थ है सदा सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलना। संतोष द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान होता है, जिससे सर्व अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाती है। जीवन में अप्राप्ति या असंतुष्टि का कारण अंदर की कमियां या कमजोरियां ही हैं, जो परमात्म ज्ञान और योग साधना की प्राप्तियों से दूर हो जाती हैं। जिन्हें सर्व प्राप्तियां हैं, उसके चिह्न उनके मुख और व्यक्तित्व में प्रसन्नता के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल लोगों के चेहरे पर सदा प्रसन्नता की झलक देखने को नहीं मिलती है। इंसान कभी प्रसन्नचित्त है तो और कभी प्रश्नचित्त बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम क्यों, क्या, कैसे, कब... जैसे प्रश्नों से प्रश्नचित्त बन जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सदा प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होता है। जो प्राप्तियों से सम्पन्न होता है, उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है, उसमें हलचल होती है। स्वयं से पूछिए कि क्या मैं सदा प्रसन्नचित्त रहता या रहती हूं? यदि प्रसन्नता कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति की इच्छा है।

एक सत्संग ऐसी भी

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठजी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता हैं कि सेठजी आप रोज कहाँ जाते है। सेठजी बोले कि, सत्संग में ज्ञान सुनने जाते है। तोता कहता है, सेठजी संत महात्मा से एक बात पूछना कि में आजाद कब होऊंगा। सेठजी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते है कि महाराज हमारे घर जो तोता है उसने पूछा हैं की वो आजाद कब होगा? संत जी ऐसा सुनते हीं बेहोश होकर गिर जाते है। घर आते ही तोता सेठजी से पूछता है कि सेठजी संत ने क्या कहा। सेठजी कहते है तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। दूसरे दिन सेठजी सत्संग में जाने लगते है तब तोता पिंजरे में जानबूझ कर बेहोश होकर गिर जाता हैं। सेठजी उसे मरा हुआ मानकर जैसे हीं उसे पिंजरे से बाहर निकालते है, तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठजी को पूछते है कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना अब वो कहाँ हैं। सेठजी कहते हैं, हाँ महाराज आज सुबह-सुबह वो जानबुझ कर बेहोश हो गया , मैंने देखा की वो मर गया है इसलिये मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठजी से कहा की देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह-माया के पिंजरे में फंसे हुए हो और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आये मेरा एक इशारा समझ कर आजाद हो गया।

अंतर्मन

आज की पाती

पशुओं के संरक्षण-संवर्धन का संकल्प लें

चार अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। देश में पशु जगत की दुर्दशा को देखकर मन विचलित हो जाता है। गोधन की दुर्दशा देखकर हृदय कंपित हो उठता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पशुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति अभूतपूर्व थी। पशुओं के संरक्षण के लिए आज हमें ठोस प्रयास करने होंगे। पशुओं का अनिवार्य रूप से संरक्षण होना चाहिए। सामूहिक रूप से हिंसा उन्मूलन के प्रयास तेज होने चाहिए। उससे अहिंसात्मक मूल्यों की प्राणप्रतिष्ठा हो सकती है। पशु दुर्व्यवहार एक तरह से जानबूझ कर करने वाला कार्य जैसे मारना, जलाना, भोजन-पानी, आश्रय, देखभाल में कमी जैसी उपेक्षा से पशुओं को पीड़ा होती है। पशु शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।

- अशोक दुबे, दुर्ग

करंट अफेयर

चरमपंथी लेबनानी पॉप स्टार का आत्मसमर्पण

पॉप स्टार से वांछित इस्लामी चरमपंथी बने लेबनान के एक व्यक्ति ने 12 साल बाद शनिवार को खुद को देश की सैन्य खुफिया सेवा के हवाले कर दिया। न्यायिक और सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

लेबनान के शहर सिडोन में जून 2013 में सुन्नी मुस्लिम चरमपंथियों और लेबनानी सेना के बीच सड़क पर हुए खूनी संघर्ष के बाद से फदल शकर फरार था। उसकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया गया और 2020 में एक 'आतंकवादी समूह' को समर्थन देने के आरोप में 22 साल जेल की सजा सुनाई गई। दो सुरक्षा और दो न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की रात एक लेबनानी सैन्य खुफिया बल सिडोन के पास ऐन अल-हिल्वेह के फिलस्तीनी शरणार्थी शिविर में पहुंचा और शकर को हिरासत में ले लिया, जो 12 साल से अधिक समय से इसी शिविर में छिपा हुआ था। नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि शकर लेबनानी अधिकारियों की गिरफ्तारी में है, उससे पूछताछ की जाएगी और सेना के खिलाफ अपराध करने के नए आरोपों पर मुकदमे की तैयारी की जाएगी। शकर एक पॉप स्टार था, जो 2002 में अपने एक जबरदस्त हिट गाने के साथ पूरे अरब जगत कें बेहद लोकप्रिय हुआ था।

ऑफ बीट

रात में अच्छी नींद कैसी होनी चाहिए?

बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे तकिये पर सिर रखेंगे तो उन्हें गहरी और आरामदेह नींद आनी चाहिए और लगभग आठ घंटे के बाद तरोताजा महसूस

करते हुए उठना चाहिए। वास्तव में, पूरी रात स्वस्थ नींद चक्रीय होती है क्योंकि आप नींद के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और अक्सर कई बार जागते हैं। कुछ लोगों को इनमें से एक या अधिक बार जागना याद रहता है लेकिन कई लोगों को यह भी याद नहीं रहता कि वे रात में कितनी बार नींद से जागे। एक वयस्क के रूप में, हमारी नींद अलग-अलग चक्रों से गुजरती है और रात के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर के लिए नींद टूटती है। प्रत्येक नींद का चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। गहरी नींद में जाने से पहले और सपनों की दुनिया (रैपिड आई मूवमेंट-आरईएम) में खोने से पहले हम रात में हल्की नींद से शुरुआत करते हैं। यदि हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हम अपनी अधिकांश गहरी नींद रात के पहले भाग में पूरी कर लेते है और रात के दूसरे भाग में हमें सपने आने लगते हैं। वयस्क आमतौर पर रात में पांच या छह नींद के चक्रों से गुजरते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए जागना पूरी तरह सामान्य है। इसका मतलब है कि हम रात में पांच बार जाग सकते हैं।यह बढ़ती उम्र के साथ बढ़ सकता है और हम फिर भी स्वस्थ रह सकते हैं।

ट्रेंड

दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना

दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण हुई दुखद जनहानि से मैं बेहद दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएँ उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मेरी गहरी संवेदनाएं

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से कई लोगों की मौत और कई के लापता होने की खबर बेहद दुखद है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

जवाबदेही तय करे सरकार

यह बेहद शर्म की बात है कि भाजपा सरकार में ऐसी आदर्श योजना भी बदनाम हो रही है क्योंकि खांसी की दवा से मौतें हो रही हैं। राज्य सरकार इन मौतों की जवाबदेही तय करने के बजाय (इन्हें) स्वीकार ही नहीं कर रही है।

-अशोक गहलौत, पूर्व सीएम, राजस्थान

इंसानों की सेवा

आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता गोवा को ठीक करने के लिए कर रहा काम। पार्टी राजनीति में सेवा करने के लिए आई है। इंसानों की सेवा करने से भगवान की पूजा करने के समान पुण्य मिलता है। हमारी सभी धार्मिक किताबें इंसानों की सेवा करने का ज्ञान देती हैं।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवन के पुरुषार्थों की सिद्धि नहीं होती

मौसम का बिगड़ा मिजाज

मानसून के विदा लेने के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह वर्षा हो रही है, वह केवल आश्चर्य का ही विषय नहीं, परेशानी का भी कारण है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी-खासी वर्षा के आसार हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो अरब सागर में शक्ति नामक तूफान के कमजोर होने से पहले नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। दशहरे के बाद दीवाली की प्रतीक्षा के बीच जब यह मान लिया जाता है कि वर्षा ऋतु का समय बीत गया, तब बारिश होना यही बताता है कि मौसम में परिवर्तन का चक्र तीव्र हो गया है। मौसम चक्र में बदलाव पिछले कई वर्षों से दिख रहा है, लेकिन अब बदलाव की गति कहीं अधिक तेज हो गई है। यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता तो हर स्तर पर जताई जा रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए जैसे सामूहिक प्रयास होने चाहिए, वैसे नहीं हो पा रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता है। कहना कठिन है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन को रोकने के अपने प्रयासों के प्रति कब गंभीरता का परिचय देगा? जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर बल देना होगा। यह ठीक है कि आपदा प्रबंधन के उपायों को पुष्ट किया गया है और उनका लाभ भी मिला है, लेकिन अब अतिवर्षा, बादल फटने, कम समय में अधिक बारिश होने के कारण जन-धन हानि की भारी क्षति देखने को मिलती है।

इस वर्ष ऐसी घटनाओं के चलते पर्वतीय राज्यों के साथ-साथ मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी जन-धन हानि देखने को मिली। इस हानि का एक बड़ा कारण कमजोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और उसका सही तरीके से रखरखाव न किया जाना है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा दूसरे देशों में भी होती है, लेकिन उनमें और विशेष रूप से विकसित और यहां तक कि कई विकासशील देशों में अपेक्षाकृत कम जन-धन हानि होती है। भारत में मौसम के बिगड़े मिजाज से होने वाली बाढ़ एवं भूस्खलन की घटनाओं से जन-धन हानि को रोकने का उपाय यही है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण में तय मानकों का पालन किया जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एक अन्य क्षेत्र भी ऐसा है, जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा और वह है जल निकासी के उचित प्रबंध का। बारिश के समय जनजीवन के बाधित होने का मुख्य कारण जगह-जगह जलभराव होना है। स्थिति यह है कि देश के बड़े महानगरों में भी थोड़ी सी ही बारिश जलभराव कर देती है और उसके चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

शिक्षा क्षेत्र में छलांग

पटना के बिहटा प्रखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) का नया कैंपस बिहार में शैक्षणिक परिवेश के निर्माण में एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया। राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलाजी, कानून आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पहल की, वह सराहनीय है। राज्य में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से यहां के विद्यार्थियों को लाभ तो होगा ही, पठन-पाठन के एक स्तरीय वातावरण के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। किसी राज्य में आइआइटी, एनआइटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसे संस्थानों के होने का महत्व है। इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जो पहल की गई, उसी का परिणाम है कि एनआइटी कैंपस के पहले चरण का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब शिक्षक-विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकेंगे। तीन वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाना एक उपलब्धि है, जहां ढाई हजार विद्यार्थियों के पठन-पाठन एवं आवास की व्यवस्था हो चुकी है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऐसे संस्थानों की स्थापना से स्थानीय छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, देश के दूसरे हिस्सों से भी विद्यार्थी यहां आएंगे। आशा की जा सकती है कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को आने वाले समय में और गति मिलेगी तथा इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

> उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही, सांस्कृतिक रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी

समर्थ बनें संसदीय समितियां

हृदयनारायण दीक्षित

जब संसद आभा खो रही है। शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं, तब संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए

संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का विचार चल रहा है। सांसदों की शिकायत है कि एक साल की अवधि में किसी विषय विशेष पर वस्तुपरक अध्ययन और सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाते। सरकारें विधायिका के समक्ष जवाबदेह हैं। यह जवाबदेही संसदीय प्रश्नों, संकल्पों और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से होती है। संसदीय समितियां भी इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग करती हैं। समिति सदन का ही अंग होती हैं। राष्ट्र के सामने तमाम जटिल प्रश्न आते रहते हैं। तमाम मुद्दे आते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा में काफी समय लगता है। कुछ मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं, जिनका स्वरूप तकनीकी होता है। संसद का समय ऐसे छोटे मुद्दे एवं अनावश्यक शोर व्यवधानों को निपटाने में ही लग जाता है। समिति प्रणाली से संसद का समय बच जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति स्थायी समितियां हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अलावा लोकसभा की अलग समितियां भी हैं। किसी विषय पर गठित समितियों का कार्यकाल प्रतिवेदन देने तक सीमित रहता है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया का नियमन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सभा द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है।

संप्रति राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। संसद आभा खो रही है। सदन के भीतर हुल्लड़ है। शांति से समाधान खोजने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में संसदीय समितियों को शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होना चाहिए। सांसदों ने समय की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। इसके लिए समिति व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए समग्रता में विचार करना चाहिए। विधायिका में समय की कमी विचारणीय विषय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि संसद की समितियां विषय की गहराई में जाती हैं, लेकिन मुख्य सदन में समितियों जैसा अनौपचारिक शांत वातावरण नहीं मिलता। समितियों की कार्यवाही का संचालन मुख्य सदन की भांति ही होता है। मुख्य सदन एवं समितियों के विशेषाधिकार समान हैं। समिति का वातावरण प्रेमपूर्ण होता है।

अवधेश राजपूत

समिति में विचाराधीन सभी विषयों की गहन समीक्षा होती है। संबंधित संस्था या व्यक्ति समिति की कार्यवाही के सामने जवाब देता है। समिति अपने विचाराधीन जांच योग्य अथवा अन्वेषणाधीन विषय के संबंध में संबंधित व्यक्ति से मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकती है। प्रत्येक समिति के पारस साक्षियों को व्यक्तिगत रूप में बुलाने तथा पत्र और रिकार्ड मांगने के अधिकार हैं। स्थायी समितियों के समक्ष भी राष्ट्रजीवन से जुड़े लगभग सभी विषय आते हैं। इसीलिए स्थायी समितियों की संख्या सन 2004 में 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाती है। ऐसी समिति अपने देश में काफी लोकप्रिय हुई है। आम जनता को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला आदि की जांच में गठित संयुक्त संसदीय समितियां याद हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोकसभा या राज्यसभा में गहन विचार विमर्श संभव नहीं था। जो समस्याएं मूल रूप में संपूर्ण सदन के सामने आई थीं, वही विषय समितियों में आकर आसानी से निष्कर्ष तक कैसे पहुंच गए।

ब्रिटेन में भी समितियां हैं। सेलेक्ट कमेटी सरकारी विभागों की निगरानी करती है। इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकव्यय की जांच करती है। संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। भारत की तरह अपने निश्चित अनुपात में विपक्षी दलों को भी सदस्यता मिलती है। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुने जाते हैं। अमेरिकी व्यवस्था में भी समितियां हैं। यहां दोनों सदनों की अलग-अलग समितियां हैं। अब भारत की तरह अमेरिका में भी स्थायी समितियां हैं। अमेरिका में विदेश मामलों और वित्त से जुड़ी स्थायी समिति है। संयुक्त संसदीय समिति अमेरिका में भी है। जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस और कनाडा में भी समिति प्रणाली है। कनाडा में नागरिक, विशेषज्ञ और एनजीओ किसी मामले में गवाही दे सकते हैं। यहां की लोक लेखा समिति में विपक्षी दल के सांसद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये समितियां शक्तिशाली हैं और लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। आस्ट्रेलिया में प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च और बजट की गहराई से जांच करती है। जापान में स्थायी समितियां और मंत्रालय से संबंधित समिति भी हैं।

समितियों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। मर्यादा पर कई खूबसूरत बातें कही गई हैं। एक समिति के अध्यक्ष ने 1959-60 की बैठक में समिति के कृत्य को समझाया और कहा, 'आपका काम नीति निर्धारित करना नहीं है। संसद द्वारा जिस नीति का निर्धारण किया जाता है, आपका कर्तव्य यह है कि आप यह देखें कि उस नीति का पालन हो... साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसके भिन्न वित्तीय प्रभाव न पड़ें। आप नीति संबंधी केवल उसी विषय की जांच कर सकते हैं-आपको उसका अधिकार तभी तो मिलता है, जिसमें खर्च अंतर्निहित होता है और आप यह देखें कि वह नीति ठीक ढंग से नहीं चल रही है। जहां नीति के फलस्वरूप धन का अपव्यय होता है, आपको उसके संबंध में उचित ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार है।' संसद और विधानमंडल की कार्यवाही में एकता है। समिति प्रणाली की मजबूती से विधानसभाओं का कामकाज भी तेजस्वी होगा। संप्रति कार्यकाल बढ़ाने की मांग विचारणीय है। अच्छा हो कि इस विषय के औचित्य पर समग्र विचार करना जरूरी हो। इस पर यथास्थिति नियम समिति/संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचारण हो।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

नए बाजारों तक पहुंच बनाता भारत

डा. जयंतीलाल भंडारी

भारत द्वारा विभिन्न देशों से किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते टैरिफ की चुनौतियों से निपटने में कारगर हो रहे हैं

इस समय भारत तेजी से नए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), नए व्यापार गठबंधनों और नए निर्यात बाजारों में कदम बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में बीते एक अक्टूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिस्टेंस्टिन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच एफटीए लागू हो गया है। इस व्यापार समझौते पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के कारण यह समझौता अब लागू हुआ है। वस्तुतः मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है, जहां वे साझेदार देशों से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म कर देते हैं या कम करने पर सहमत होते हैं। एफ्टा देशों के साथ यह समझौता भारत द्वारा अलग-अलग देशों और क्षेत्रीय समूह के साथ किया गया 14वां व्यापार समझौता है। यह मोदी सरकार के समय किया गया पांचवां व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ने मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ एफटीए किए हैं।

भारत और एफ्टा देशों के बीच लागू हुआ यह व्यापार समझौता यूरोप के एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लाक के साथ भारत के विदेश व्यापार को नई दिशा देगा। इस समझौते के तहत भारत ने एफ्टा देशों की 80-85 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क शून्य किया है। इसके बदले में भारत को 99 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त बाजार तक पहुंच मिलेगी। जहां कृषि, डेरी, सोया एवं कोयला सेक्टर को इस व्यापार समझौते से दूर रखा गया है, वहीं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रीन एवं विंड एनर्जी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में एफ्टा देश भारत में निवेश करेंगे, जिससे इन सेक्टरों में हमारा आयात कम होगा और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। भारत के हिसाब से इस व्यापार समझौते का सबसे बड़ा लाभ एफ्टा देशों से मिली निवेश प्रतिबद्धता है। अब यह समझौता लागू होने के बाद आगामी 10 वर्षों के भीतर एफ्टा देशों से भारत में 50 अरब डालर का निवेश और अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब डालर निवेश की उम्मीद है। इससे 15 वर्षों में भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की आस है। बहरहाल भारत ने ऐसा पहला समझौता किया है, जिसमें बाजार तक पहुंच निवेश से जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में एफ्टा देशों को भारत ने 1.97 अरब डालर मूल्य का वस्तु निर्यात किया और 22.44 अरब डालर का आयात किया। इन देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यद्यपि अभी एफ्टा के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, लेकिन अब नए व्यापार समझौते से एफ्टा देशों के साथ भारत के विदेश व्यापार का परिदृश्य भारत के लिए अनुकूल होने की संभावना है। खासतौर से इस समझौते से डिजिटल व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में इन चार देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के बड़े बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

निर्यात के लिए नए बाजार तलाशता भारत। फाइल

उल्लेखनीय है कि हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच भी एफटीए हुआ है। भारत और ओमान के बीच एफटीए पर बातचीत पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस वर्ष के अंत तक यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए लागू होने की पूरी संभावना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर दिखाई दे रही है। इस नीति से ट्रंप टैरिफ के बीच पिछले अगस्त और सितंबर माह में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में भारत के निर्यात बढ़े हैं। कल तक भारत को डेड इकोनमी बताने वाले ट्रंप ने अब अपना तेवर बदलते हुए भारत के साथ व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के संकेत दिए हैं। यह भारत की आर्थिक-कूटनीतिक जीत है। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का अनुकूल परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। इससे संभावना जताई जा रही है कि भारत पर रूसी तेल खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को अमेरिका वापस ले सकता है।

अमेरिका के अलावा भारत कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इजरायल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी व्यापार समझौता करने जा रहा है। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि एफटीए तभी लाभकारी होते हैं, जब वे सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जाएं। इसके लिए सरकार को निर्यातकों और छोटे व्यवसायियों को नए बाजारों के लाभ से संबंधित पर्याप्त जानकारी देकर नए मौकों का फायदा उठाने के लिए जागरूक बनाना होगा। सरकारी निकायों द्वारा गैर शुल्क बाधाओं संबंधी समाधान के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन देना होगा। इसके साथ-साथ एफटीए के तहत निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और कारोबार की सुगमता के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। उम्मीद करें कि ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच एफटीए भारत के निर्यात और निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

त्याग

मानव जीवन निरंतर गति और परिवर्तन का पर्याय है। इसमें त्याग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए अशुद्ध वायु को बाहर निकालना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन की प्रगति के लिए अनावश्यक वस्तुओं, विचारों और भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है। त्याग केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और मानसिक स्तर पर भी जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करता है।

भोजन की इच्छा तब तक नहीं होती जब तक पेट में अवशेष शेष रहता है। यह प्राकृतिक नियम है कि पहले अनावश्यक तत्वों का त्याग हो और फिर नई ऊर्जा को स्थान मिले। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम बीते अनुभवों, नकारात्मक भावनाओं और अनुपयोगी वस्तुओं को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नए अवसरों और नई ऊर्जा को स्थान कैसे मिलेगा? संग्रह जीवन की गति में अवरोध पैदा करते हैं और मनुष्य को स्थिर बना देते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम परिस्थितियों, वस्तुओं और विचारों से अनावश्यक बंधन समाप्त करें। हम सीढ़ी के सहारे चढ़ते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुंचने के बाद उसे छोड़ना पड़ता है। यदि हम सीढ़ी से चिपके रह जाएं तो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संसार में प्रगति के लिए त्याग अनिवार्य है। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और द्वेष जैसे मानसिक विकार जब तक मनुष्य को जकड़े रहते हैं, तब तक वह शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये विकार छूटते हैं, वैसे ही दया, प्रेम, करुणा और श्रद्धा जैसी शुभ प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से मन में जाग्रत होने लगती हैं। यह उसी तरह है जैसे द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश सहज ही भीतर प्रवेश कर जाता है।

अवधविहारी शुक्ल

प्रतिस्पर्धा की दौड़ में खोती जिंदगियां

देवेंद्रराज सुथार

> पिछले 10 वर्षों में जहां देश में कुल आत्महत्या के मामलों में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं छात्रों की आत्महत्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में देश में लगभग 13900 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जो बात और भी चिंताजनक है वह यह कि पिछले 10 वर्षों में जहां देश में कुल आत्महत्या के मामलों में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं छात्रों की आत्महत्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी छात्रों में आत्महत्या की दर सामान्य दर से ढाई गुना तेजी से बढ़ रही है। आखिर छात्र इतनी कम उम्र में जीवन से हार क्यों मान रहे हैं। जो उम्र सपने बुनने की होती है, वह उम्र मौत को गले लगाने की क्यों बन गई है। इसके पीछे कई कारण हैं और सभी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। आजादी के सत्तर साल बाद भी हम शिक्षा को अंकों की दौड़ से अलग नहीं कर पाए हैं। बच्चे की काबिलियत, उसकी रुचि, उसकी रचनात्मकता सबकुछ अंकतालिका में सिमट गई है।

कोचिंग संस्कृति ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में हजारों छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं। छोटी-छोटी कोठरियों में रहना, घर से दूर रहने का अकेलापन, असफलता का डर और लगातार प्रतिस्पर्धा का दबाव उन्हें तोड़ देता है। परिवार और समाज का दबाव एक अन्य बड़ा कारण है। बच्चों पर अपेक्षाओं का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि वे उसके नीचे दब जाते हैं। बच्चे की रुचि क्या है, वह क्या बनना चाहता है, इस पर कोई बात नहीं होती। रिश्तेदारों और समाज की टिप्पणियां भी इस आग में घी का काम करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता भी एक बड़ी समस्या है। भारतीय समाज में अभी भी मानसिक बीमारियों को कलंक की तरह देखा जाता है। अवसाद, चिंता और तनाव को गंभीरता से नहीं लिया जाता। स्कूलों और कालेजों में काउंसलिंग की व्यवस्था या तो है ही नहीं या फिर अपर्याप्त है। जिन संस्थानों में यह सुविधा है भी, वहां छात्र काउंसलर के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे।

समाधान केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर जरूरी है। शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दरकार है। परीक्षा के बोझ को कम करना होगा और बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना होगा। हर स्कूल-कालेज में प्रशिक्षित मनोविज्ञानियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अभिभावकों को भी संवेदनशील होना होगा। बच्चों के साथ खुली बातचीत करनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग है। हर किसी को एक ही सांचे में ढालना गलत है। जीवन में सफलता की परिभाषा केवल डाक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। हमें तय करना होगा कि हमें अंक चाहिए या जीवन।

(लेखक लोकनीति विश्लेषक हैं)

आदिवासी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाए संघ

'आरएसएस की सफलता के सूत्र' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त का कहना सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफलता का मूल कारण उसके विचार भारतीय समाज के डीएनए का हिस्सा होना है। जिस प्रकार सनातन संस्कृति पर चौतरफा आक्रमण उसके अस्तित्व को मिटा नहीं पाए, उसी तरह से संघ भी चौतरफा आक्रमण के बावजूद निरंतर उत्कर्षशील है। किसी विचारक ने सही कहा है कि यदि किसी को संघ को समझना है तो पहले उसे भारतीयता और सनातन संस्कृति को समझना होगा। यदि यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आज यदि सनातन संस्कृति पर मतांतरण, लव जिहाद और अपसंस्कृति जैसे आक्रमण हो रहे हैं तो उसमें संघ की सक्रियता बेहद अहम हो जाती है। आजकल यह धारणा बन रही है कि सत्ता का स्वाद चखने के बाद स्वयंसेवकों की वैचारिक प्रतिबद्धता, सक्रियता एवं एकनिष्ठा में कमी आ गई है। आज ऐसे समर्पित स्वयंसेवकों का अभाव है, जो भुने चने खाकर अपने कर्तव्य निर्वहन में लगे रहते थे। इसी प्रकार संघ को समाज में एक व्यापक पैठ बनानी पड़ेगी तथा दलितों एवं आदिवासियों को अपने से जोड़ना होगा। साथ ही समाज में घर कर गई जातिवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। आज आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग करने का षड्यंत्र एवं आदिवासी अंचलों में मतांतरण का सुनियोजित चक्र चल रहा है तो उसे रोकने के लिए संघ को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी।

विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

मेलबाक्स

संध्याजी की कला अमर रहेगी

प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्याजी का शनिवार को निधन हो गया। 1959-1969 के दशक में विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में निभाई गई भूमिकाओं के लिए वह प्रसिद्ध थीं। झनक झनक पायल बाजे, नवरंग, सेहरा और दो आंखें बारह हाथ जैसी हिंदी फिल्मों में वह नायिका रहीं। वह मशहूर निर्माता-निर्देशक वी. शांताराम की पत्नी थीं। गीत ''अरे जा रे हट नटखट'' आज भी बेहद लोकप्रिय है। इस गीत के लिए उन्होंने विशेष रूप से शास्त्रीय नृत्य सीखा। उनके अन्य उल्लेखनीय हिंदी चित्रपट हैं- तीन बत्ती चार रास्ता, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली और परछाई। पंख होती तो उड़ आती रे, ए मालिक तेरे बंदे हम और अरे जा रे हट नटखट जैसे अमर गीत उन पर फिल्माए गए। नवरंग फिल्म में ''अरे जा रे हट नटखट'' गीत के दौरान स्त्री और पुरुष-दोनों वेशभूषा में उनका किया हुआ नृत्य हिंदी सिनेमा का अद्भुत प्रयोग माना जाता है। यह होली गीत आज भी असंख्य श्रोताओं की स्मृतियों में बसा है। संध्याजी की फिल्में, उनके अभिनय, कला और उनके नृत्य हमेशा अमर रहेंगे।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

सीट बंटवारे का पेच

बिहार की राजनीति में महागठबंधन का भविष्य इस बार काफी हद तक सीट बंटवारे पर निर्भर करता दिख रहा है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत और सामाजिक समीकरणों के बदलते स्वरूप ने गठबंधन की स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल की असली परीक्षा यही है कि कितनी सहमति वे सीटों के बंटवारे में बना पाते हैं। जहां एक ओर कांग्रेस अपने पुराने अनुभव और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल अपनी जमीनी पकड़ और हालिया चुनावी प्रदर्शन के दम पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि बार-बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन अपने अंदरूनी मतभेदों को किनारे रखकर सामूहिक लड़ाई लड़ पाएगा या फिर सीटों को लेकर खींचतान चुनावी रणनीति को कमजोर कर देगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए अपनी एकजुटता साबित करने की परीक्षा भी है। यदि महागठबंधन आपसी सहमति और लचीलापन दिखाने में सफल रहता है, तो निश्चित रूप से भाजपा-जेडीयू गठजोड़ के लिए यह एक मजबूत चुनौती बन सकता है।

आयुष्मान पाण्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPapersPaid

हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

बात है मुद्दे की

बिहार में जारी अंतिम मतदाता सूची में ज्यादा खामियां नहीं हैं, तो अब 'वोट चोरी के मुद्दे पर विराम लग जाएगा। वैसे भी यह मुद्दा विपक्षी कार्यकर्ताओं को जितना गोलबंद कर पाया, आम मतदाताओं पर इसका उतना असर नहीं दिखा था। बिहार में विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि वह बूथ-वार समीक्षा के बाद अपनी विस्तृत राय बताएगा, मगर शुरुआती प्रतिक्रियाओं के मुताबिक विपक्षी दल मोटे तौर पर अंतिम सूची से संतुष्ट नजर आए हैं। आरजेडी, सीपीआई (माले) और कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि उनके अभियान ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मकसद को नाकाम कर दिया। अंतिम सूची के मुताबिक लगभग 68 लाख नाम हटाए गए, जबकि 21 लाख से अधिक नए नाम जोड़े गए। नतीजतन, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अगले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 47 लाख कम वोटर होंगे। इस सूची में अगर ज्यादा खामियां नहीं हैं, तो कम-से-कम बिहार में अब 'वोट चोरी के मुद्दे पर विराम लग जाएगा। वैसे भी यह मुद्दा विपक्षी कार्यकर्ताओं को जितना गोलबंद कर पाया, आम मतदाताओं पर इसका उतना असर नहीं दिख रहा था। तो अब समस्या आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के सामने चुनावी कथानक की है। आरजेडी और कांग्रेस ने पहले जातीय जनगणना की मांग को सहारा बनाने की कोशिश की। मगर केंद्र ने इसका एलान कर यह मुद्दा उनसे छीन लिया। तो वोट चोरी के इल्जाम पर महागठबंधन ने खुद को केंद्रित किया। चूंकि निर्वाचन आयोग ने प्रावधान कर दिया है कि आगे मतदाता सूची में बदलाव की अर्जी आधार से जुड़े फोन नंबर से ही दी जा सकेगी, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की मतगणना पूरी की जाएगी और अब कमोबेश एसआईआर भी ठीक-ठाक हो गया है, तो चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन मुद्दा-विहीन हो गया दिखता है। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए ने रेवड़ियां बांट कर अपने शासन की खामियों और प्रशासन के खोट को भरने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रशांत किशोर के जन सुराज ने शिक्षा और पलायन के अपने मुख्य मुद्दे के साथ-साथ सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ आरोपों की आक्रामक झड़ी लगाकर कम-से-कम नैरेटिव में अपनी एक खास जगह बना ली है। इसके बावजूद महागठबंधन की नैया पार लगती है, तो वैसा घोर एंटी-इन्कंबैंसी से ही हो सकता है।

बुजुर्ग : बोझ नहीं, संस्कृति का स्तम्भ

आरती कुमारी

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिवस का उद्देश्य वृद्धों के अधिकारों, उनकी गरिमा और उनके योगदान को रेखांकित करना है। यह दिन हमें यह सोचने को विवश करता है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, जिसे कभी सम्मान और अनुभव का प्रतीक माना जाता था, आज वह उपेक्षा, अकेलेपन और असुरक्षा का पर्याय क्यों बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2030 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग पूरी दुनिया में 1.4 अरब से अधिक हो जाएंगे और 2050 तक यह संख्या दोगुनी होकर लगभग 2.1 अरब तक पहुँच जाएगी। विकसित देशों में वृद्धजन आबादी का चौथाई हिस्सा बन चुके हैं, वहीं विकासशील देशों में भी उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन विडंबना यह है कि इस बढ़ती जनसंख्या के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में वृद्धजन पेंशन और हेल्थकेयर से तो सुरक्षित हैं, परंतु वहाँ अकेलेपन और मानसिक अवसाद की समस्या विकराल है। एशिया और अफ्रीका में, जहां परिवार व्यवस्था मजबूत मानी जाती थी, अब संयुक्त परिवार टूटने से वृद्धजन आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत 1991 में हुई थी और इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र की आबादी के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा वृद्धजनों के अधिकारों और योगदान को पहचानना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस पर वृद्धजनों को समर्थन देने वाली प्रणालियों को मज़बूत करने का आह्वान किया जाता है और उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। समाज में उनके बहुमूल्य योगदान को मान्यता देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल, सामाजिक सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मज़बूत करना, वृद्धजनों को वैश्विक विकास प्रयासों में शामिल करना और शहरी वातावरण को उनके लिए अधिक समावेशी बनाना आदि इस दिवस को मनाने के उद्देश्य हैं। इस दिवस को मनाते हुए वृद्ध व्यक्तियों की डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच प्रदान करने के महत्व पर जोर देना और यह सुनिश्चित करना कि सभी आयु वर्गों के लिए समानता को बढ़ावा दिया जाए और वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकारों का पालन हो आदि बातों पर विशेष बल दिया जाता है। इस दिवस की 2025 की थीम 'समावेशी भविष्य के लिए वृद्धजनों की आवाज़ को सशक्त बनाना' है, जो वृद्धजनों की आवाज़, अनुभव और ज्ञान को पहचानने तथा उनके अनुभवों के आधार पर समावेशी समाजों के निर्माण पर जोर देती है। यह थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि वृद्धजन लचीले और समतामूलक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत एवं आदर्श समाज के निर्माण में वृद्धजनों की आवाज़, उनके दृष्टिकोण और अनुभव को विशेष महत्व है। वृद्धावस्था में कठिनाइयां अनेक रूपों में सामने आती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय रोग, मधुमेह, जोड़ों के दर्द और डिमेंशिया जैसी बीमारियाँ उन्हें घेरे रहती हैं, परंतु चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित है। आर्थिक दृष्टि से पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हर वृद्धजन तक नहीं पहुँचतीं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी दयनीय है। सामाजिक स्तर पर आधुनिक जीवन की दौड़ में वृद्धजन अकेलेपन, उदासी और उपेक्षा से पीड़ित हैं। मानसिक दृष्टि से आत्मसम्मान को ठेस, भूमिका से वंचित होना और बेकारपन का एहसास उन्हें भीतर तक तोड़ देता है। भारत में वृद्धों की स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। जबकि वृद्धजन भारतीय समाज की धरोहर मानी जाती रही हैं, उन्हें अनुभव और ज्ञान का भंडार मानते हैं। इसके बावजूद यदि हम उन्हें उपेक्षित करेंगे तो यह केवल अन्याय ही नहीं, बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति की पराजय होगी। वृद्धजन केवल जीवित बोझ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के संरक्षक हैं। उनका सम्मान करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है बल्कि एक बेहतर, संवेदनशील और संतुलित समाज के निर्माण की अनिवार्यता है। भारत जैसे विकसित देश के नागरिकों की औसत आयु 60 वर्ष से अधिक 65 हो रही है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण देश में वृद्धजन की संख्या बढ़ रही है, देश में 2011 में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक थे, जिनके 2050 तक बढ़कर 30 करोड़ होने का अनुमान है। अनुमान है, कि 2050 तक हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। यह बात भारत के नीति आयोग ने कही है, इसी के कारण बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में परंपरागत भारतीय परिवार व्यवस्था में वृद्धजनों को सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की अहम भूमिका प्राप्त थी। लेकिन आज शहरीकरण, परमाणु परिवार, प्रवास और उपभोक्तावादी सोच ने उनकी भूमिका को हाशिए पर पहुँचा दिया है। परिवार के भीतर उन्हें आर्थिक बोझ समझा जाने लगा है, पीढ़ीगत टकराव और मूल्यों में बदलाव ने दूरी बढ़ा दी है, नौकरी-पेशा बच्चों के व्यस्त जीवन में धैर्य और देखभाल की कमी स्पष्ट हो रही है और संपत्ति तथा अधिकारों को लेकर तनाव आम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप वृद्धजन शारीरिक बीमारियों से जूझते हैं, पर पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिलती। वे अकेलेपन और मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और कभी-कभी घरेलू हिंसा और संपत्ति विवादों में भी उलझना पड़ता है। प्रश्न है कि दुनिया में वृद्ध दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों वृद्धों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिन्तन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि वृद्धों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को रोके। क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। वृद्धावस्था जीवन की सांझ है। वस्तुतः वर्तमान के भागदौड़, आपाधापी, अर्थ प्रधानता व नवीन चिन्तन तथा मान्यताओं के युग में जिन अनेक विकृतियों, विसंगतियों व प्रतिकूलताओं ने जन्म लिया है, उन्हीं में से एक है वृद्धों की उपेक्षा। वस्तुतः वृद्धावस्था तो वैसे भी अनेक शारीरिक व्याधियों, मानसिक तनावों और अन्यान्य व्यथाओं भरा जीवन होता है और अगर उस पर परिवार के सदस्य, विशेषतः युवा परिवार के बुजुर्गों/वृद्धों को अपमानित करें, उनका ध्यान न रखें या उन्हें मानसिक संताप पहुँचाएं, तो स्वाभाविक है कि वृद्ध के लिए वृद्धावस्था अभिशाप बन जाती है। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए परिवार, समाज और सरकार- सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। परिवार व्यवस्था का पुनर्जीवन जरूरी है, बच्चों में बचपन से ही सेवा, सहानुभूति और सम्मान की भावना विकसित की जाए। सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार हो, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और वृद्धाश्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में जेरियाट्रिक देखभाल को प्राथमिकता दी जाए, प्रत्येक नगर और गाँव में वृद्धजन के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हों। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, अकेलेपन से लड़ने के लिए सामुदायिक केंद्र, क्लब और वृद्धजन मंच सक्रिय किए जाएँ। वृद्धजनों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्हें सामाजिक और पारिवारिक संवाद में सक्रिय बनाया जाए। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब नया भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, तब यह आवश्यक है कि इस विकास यात्रा में वृद्धजन उपेक्षित न हों बल्कि उन्हें इसका सक्रिय भागीदार बनाया जाए। न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचाए। साथ ही "डिजिटल इंडिया" और "स्किल इंडिया" जैसी योजनाओं से वृद्धजनों को जोड़ा जाए ताकि वे सामाजिक संवाद और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय बने रहें। वृद्धाश्रमों और डे-केयर सेंटर्स की गुणवत्ता और संख्या बढ़ाई जाए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग केंद्र स्थापित हों और "सेवा भाव" को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान चलाए जाएँ। जब भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, तब उसके अनुभव-संपन्न वृद्धजन राष्ट्र की अमूल्य पूंजी हैं, इसलिए मोदी सरकार को उनके लिए संवेदनशील और समग्र कल्याणकारी नीतियां लागू करनी चाहिए।

गए थे मूर्ति विसर्जन को खुद विसर्जित हो गए

मनोज कुमार अग्रवाल

देश भर में दुर्गा नवमी के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को नदी तलाब आदि मे जल विसर्जन किया गया आस्था श्रद्धा के साथ अति उत्साह और जोश खरोश के चलते की स्थानों पर दुर्घटनाएं घटित हुई है। तीस से अधिक लोग जो मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे लापरवाही और उद्दंडता भरे जोश में खुद विसर्जित हो गए ।इन में ज्यादातर युवा व किशोर लड़के शामिल हैं। आगरा में दुर्गा प्रतिमा को जल प्रवाहित करते 20 किशोर तलाब में डूब गए इन में से 13 की डूब कर मृत्यु हो गई। गांव में हाहाकार मचा है। इसी तरह मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में भी एक ट्रेक्टर ट्राली तलाब में पलट गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने आए 11 लोगों की तलाब में डूब कर मौत हो गई। जबकि कई लोग जलूस में शामिल वाहन पर धातु के पोल में ध्वज लिए थे और हाइटैंशन बिजली तारों से छूने के कारण झुलस कर जान गंवा गए। आपको बता दें कि विजयादशमी के दिन गुरुवार को मध्यप्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में गए लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पोखर में गिर गई. इस हादसे में 10 बच्चियों सहित 11 लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हुई. यहां दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग डूब गए. इंदौर (ग्रामीण) रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने बताया कि यह हादसा तब हुआ, जब पंधाना क्षेत्र में दुर्गा देवी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली श्रद्धालुओं समेत तालाब में पलट गई। उन्होंने बताया, " तालाब से कई श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं. पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान जारी है। यूपी के आगरा में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. खैरागढ़ क्षेत्र की ऊटंगन नदी में विसर्जन के लिए पहुंचे 20 लोग डूब गए. इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है. यह पूरा मामला झुंगरवाला क्षेत्र का है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है. इस दुखद घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया आगरा में ये हादसा खेरागढ़ क्षेत्र में हुआ। यहां कुसियापुर गांव के ग्रामीण दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन उटांगन नदी के लिए किया जाता था। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 किशोरों की जिनमे की नाबालिग शामिल है नदी के पानी में डूब कर मौत हो गई । हादसा दोपहर 1 बजे हुआ। खेरागढ़ के गांव कुसियापुर में चामड़ माता के मंदिर के पास नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई थी। दशहरा पर मूर्ति के विसर्जन के लिए गांव के 40-50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे उटंगन नदी के पास पहुंचे। इनमें विष्णु (20), ओमपाल (25), गगन (24), हरेश (20), अभिषेक (17), भगवती (22), ओके (16), सचिन पुत्र रामवीर (26), सचिन पुत्र ऊना (17), गजेंद्र (17) और दीपक (15) गहरे पानी में चले गए। गांव कुशियापुर में 4 फुट की दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के बाद हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा था। 10 दिन तक सुबह-शाम की आरती के बाद गांव की गलियों में देवी के गीतों से माहौल भक्तिमय हो जाता था। दशहरा आया तो प्रतिमा विसर्जन के लिए क्या बड़े, क्या छोटे, सब नदी किनारे चल पड़े। मगर हादसे की जानकारी आई तो पूरे गांव में करुण क्रंदन गूंज उठा। पानी में डूबने से बचने के लिए एक-दूसरे ने अपने हाथ पकड़ रखे थे। एक हाथ से मूर्ति को पकड़ लिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर गड्ढा बना हुआ है, जिसमें पानी गहरा है। उस गड्ढे में अचानक एक युवक का पैर फिसल गया। उसे बचाने के लिए पीछे वालों ने हाथ पकड़ा। मगर, वह उसे संभाल नहीं सके। एक-एक करके 9 युवक और 5 किशोर पानी में समा गए। दो और युवक गगन और अमित पानी में डूब रहे थे। पीछे की तरफ गांव का भोला भी था। उन्हें देखकर उसने पीछे से हाथ पकड़ लिए। वह तत्काल दोनों को कम पानी की तरफ ले गए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. इस पर प्रधानमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है। मिली जानकारी के अनुसार पंधाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला में ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पर पलट गई जिससे उसमें सवार 20 से 25 लोग तालाब में गिर गए. इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों में ज्यादातर बच्चियां शामिल हैं.अर्दला और जामली गांव के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर विसर्जन के लिए तालाब पहुंचे थे. ट्रॉली को पुलिया पर खड़ा किया गया था लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे. ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने से यह पलट गई और लोग तालाब में गिर पड़े. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया. अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं और कई घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों के नाम आरती (18), दिनेश (13), उर्मिला (16), शर्मिला (15), गणेश (20), किरण (16), पाटलीब (25), रेवसिंह (13), आयुष (9), संगीता (16) है. एक बच्ची लापता बताई जा रही है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई तहसील में दर्दनाक हादसा हो गया. ग्राम खमरिया से पवई की पतने नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने 60 से 70 लोग जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 16 लोगों को कुचल दिया. जिसमें 14 को कटनी के अस्पताल रेफर किया है एवं दो लोगों का इलाज पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के लोटन में नवरात्र विसर्जन के दौरान एक दुखद घटना घटी। दुर्गा प्रतिमा ले जा रही पिकअप 11 हजार वोल्ट के तार से छू गई जिससे दस लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी और विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।नवरात्र समापन पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार को ठोठरी चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा ले जा रही एक पिकअप में लगी सजावटी पाइप ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार से छू गई। संपर्क होते ही पूरे वाहन में करंट उतर आया, जिससे पिकप पर सवार दस लोग झुलस गए। प्रतापगढ़ में गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे सिस्टम से साउंड बॉक्स उतारते समय 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, महराजगंज में जुलूस के समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग लोग झुलस गए. सिद्धार्थनगर में 9 बच्चों की झुलसने की सूचना है. वहीं, महराजगंज के झुगुअवा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस के समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग लोग झुलस गए. गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सिद्धार्थनगर के ही थाना इटवा के भिलौरी नाले में गुरुवार की शाम मूर्ति विसर्जन के बाद पानी में डूबे 20 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार सुबह घटना के पास मिला। स्थानीय लोग पानी में खोज रहे थे, तभी उसका शव मिला। युवक की मौत पर स्वजन में मातम फैल गया। शहडोल में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है. दुर्गा विसर्जन के लिए अमरकंटक जा रही एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई. यह पिकअप सिंहपुर थाना क्षेत्र के बोडरी गांव से अमरकंटक जा रही थी, पिकअप में श्रद्धालु बैठे थे. जैसे ही पिकअप धनपुरी थाना क्षेत्र के मुड़कटिया नाला के पास पहुंची और वहां पलट गई. हादसे में 14 साल के मुकेश कोल की मौत हो गई. वहीं 8 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इन हादसों में अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें जरा सी सावधानी से टाला जा सकता था लेकिन धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों खासकर किशोरों में अभिभावकों की सलाह और रोकटोक को. दरकिनार कर अति उत्साह और जोश में होश खोना नई बात नही है अभी एक पखवाड़ा पहले ही गणेशोत्सव के अंतिम दिन प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी ऐसे हादसे देखने को मिले। हर साल प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस तरह के हादसे सामने आते हैं क्योंकि की बार बरसात के बाद होने वाले इन उत्सवों पर तलाब नदियों में जल स्तर अधिक होता है किनारे पर काई की वजह से फिसलन होती है जव प्रवाह अधिक होने से गढ्ढे बन जाते हैं इस पर एक दूसरे से होड़ लगी होने के कारण कब जिंदगी हाथ से निकल जाती है संभलने का मौका तक नही मिलता जरूरत इस बात की है कि प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन युवाओं किशोरों के देखरेख के लिए गणमान्य लोगों के संरक्षण के लिए कमेटी गठित कराए और तभी विसर्जन शोभायात्रा और विसर्जन की इजाजत दी जाए। जिन घरों के चिराग इन हादसों में बुझ गए उनकी जीवन पर्यन्त चलने वाली पीड़ा की कोई भरपाई नहीं है।

मेष राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, इससे आपके कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। किसी कार्य को पूरा करने में पुरानी कम्पनी का अनुभव काम आएगा। अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं।

वृष राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाये रखें, जल्द ही भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालेंगे, बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। लवमेट एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। छात्रों को थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। सफलता के योग बने हुए हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। परीक्षा का बेहतर परिणाम हासिल होगा।

मिथुन राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपनी बातों से किसी को प्रभावित कर देंगे। समाज में किये गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे, जिससे आपको गर्व होगा। शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ होगा। स्टूडेंट अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, जल्द ही सफलता मिलेगी।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका कोई काम जो काफी दिनों से रुका था, आज पूरा हो जाएगा। साथ ही आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ सकता है। मित्रों की सलाह भी ले सकते हैं। किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें।

सिंह राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। मानवहित में किये गये कार्यों के कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत पर ध्यान देंगे। व्यवसायिक गतिविधियां मन मुताबिक चलेंगी। काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। अवसर मिलने पर उसका फायदा उठाएं।

कन्या राशिः आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। किसी से बहस की स्थिति बन सकती है, ऐसे में मौन रहना बेहतर होगा। पब्लिक प्लेस पर छवि खराब न होने दें। लवमेट के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होगा।

तुला राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके काम करने के तरीकों से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। बातचीत के दौरान अपनी निजी बातें शेयर न करें। जिस काम की शुरुआत करेंगे, वह समय पर पूरा होगा।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। मित्रों से मन की बात शेयर करने से सुकून मिलेगा। आपको नई जानकारियां भी हासिल होंगी। रिश्तेदार से शुभ संदेश मिलेगा, जिससे खुशी दोगुनी होगी। बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, लेकिन कॉम्पटीशन के दौर में कार्य करने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे और तारीफ करेंगे।

धनु राशिः आज आपका दिन सामान्य रहेगा। निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। भावनाओं में आकर कोई फैसला न लें। ज्यादा काम के कारण थकान हो सकती है।छोटी-छोटी परेशानियां जल्द दूर होंगी। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। व्यापार में मिली जिम्मेदारियों को सफलता से निभाएंगे।

मकर राशिः आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। शाम का समय माता-पिता के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिससे अच्छा समाधान मिलेगा। किसी काम की शुरुआत करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना बेहतर होगा। समाज में किये गए कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा। कोई विश पूरी होगी जिससे खुशी मिलेगी।

कुम्भ राशिः आज का दिन परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। काम को लेकर आपके सपने काफी हद तक पूरे होंगे। स्वयं को साबित करने के लिए बेहतर दिन है। परिवार में सामंजस्य से शांति का माहौल रहेगा। प्रकृति के बीच समय बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक होगी।

मीन राशिः आज का समय आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक समस्या हल होगी और रुके काम में गति आएगी। सकारात्मक लोगों की सलाह फायदेमंद होगी। मेहनत का उचित फल जल्द मिलेगा। अफवाहों पर ध्यान न दें। ऑफिसियल यात्रा संभव है, जो शुभ होगी। जीवनसाथी के साथ डिनर प्लान करेंगे। छात्रों के लिए सफलता का दिन साबित होगा, बस थोड़ी और मेहनत करें।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला - "ईएमआइ चुकाने से संपत्ति पति की नहीं होती"

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना।

भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है, बल्कि यह दो परिवारों और परंपराओं का भी संगम है। विवाह के बाद पति-पत्नी एक साथ जीवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आर्थिक सहयोग, संपत्ति निर्माण और जिम्मेदारियों का निर्वाह भी शामिल होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विवाह के दौरान या विवाहोपरांत पति-पत्नी मिलकर संपत्ति अर्जित करते हैं। किंतु जब वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है और मामला अदालत तक पहुँचता है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी संपत्ति किसकी मानी जाएगी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि यदि पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी गई है, तो यह पति की अकेली नहीं हो सकती है, भले ही ईएमआई उसने चुकाई हो। ऐसी संपत्ति पर पति-पत्नी दोनों समान रूप से हकदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल थे, ने एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि संयुक्त संपत्ति पति की नहीं मानी जाएगी केवल इस आधार पर कि उसने लोन की किस्तें भरी हैं। ऐसी संपत्ति पर पति और पत्नी दोनों 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। यदि पति यह दावा करता है कि चूँकि किस्तें उसने चुकाईं, इसलिए वह संपत्ति का अकेला मालिक है, तो यह बेनामी लेनदेन अधिनियम (Benami Act) की धारा 4 का उल्लंघन होगा। पत्नी का यह तर्क भी अदालत ने खारिज कर दिया है कि ऐसी संपत्ति को उसके "स्त्रीधन" का हिस्सा माना जाए। अदालत ने कहा कि "स्त्रीधन" केवल वही है, जो विवाह से पहले या बाद में उपहार स्वरूप दिया जाता है और जो केवल स्त्री के स्वामित्व और उपभोग के लिए होता है। संयुक्त संपत्ति उपहार नहीं होती है, बल्कि यह दोनों पक्षों के प्रयास और योगदान से बनी हुई संपत्ति है। भारतीय पारिवारिक और दांपत्य कानून में स्त्रीधन (Stridhan) और संयुक्त संपत्ति (Joint Property) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। "स्त्रीधन" को विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाहोपरांत उसके माता-पिता, रिश्तेदार, पति या ससुराल वालों द्वारा दिए गए उपहार, आभूषण, नकद, संपत्ति आदि "स्त्रीधन" कहलाता है। यह केवल स्त्री का होता है और उसके पति या ससुराल वालों का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता और हिन्दू विवाह अधिनियम में "स्त्रीधन" को स्त्री की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मान्यता मिली हुई है। विवाह के दौरान पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से खरीदी गई संपत्ति। इसे परिवार के सामूहिक कोष से अर्जित किया जाता है। चाहे पति कमाता हो या पत्नी, योगदान का मतलब केवल पैसों तक सीमित नहीं है घर चलाना, बच्चों का पालन-पोषण करना, घरेलू कार्य भी योगदान माना जाता है। इस संपत्ति पर पति और पत्नी दोनों का समान हक होता है। बेनामी लेनदेन अधिनियम (1988) की धारा 4 के अनुसार, कोई व्यक्ति यदि किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो उस संपत्ति पर मालिकाना हक उसी व्यक्ति का माना जाएगा, जिसके नाम पर संपत्ति दर्ज है। पति यदि पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो वह उसका बेनामी मालिक नहीं कहलाएगा, बल्कि पत्नी भी वैधानिक मालिक मानी जाएगी। इसी तरह, यदि दोनों ने मिलकर संपत्ति खरीदी है, तो दोनों बराबर के मालिक होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि पति यदि यह दावा करता है कि ईएमआई उसने भरी है, इसलिए उसका हक ज्यादा है, तो यह बेनामी लेनदेन की परिभाषा के विपरीत होगा। भारत में लंबे समय से यह धारणा रही है कि घर-परिवार चलाने और संपत्ति अर्जित करने की जिम्मेदारी पति की है। पत्नी को "गृहिणी" मानकर केवल घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में पति-पत्नी दोनों मिलकर आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। यह फैसला एक तरह से सामाजिक समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। अब पति यह नहीं कह सकता कि उसने ईएमआई चुकाई, इसलिए घर सिर्फ उसका है। पत्नी का योगदान, चाहे वह घर संभालने का हो या सीधे आर्थिक, दोनों का महत्व है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए भी राहतकारी है, जो वैवाहिक विवादों के दौरान आर्थिक सुरक्षा खोने के डर से समझौता करने पर मजबूर हो जाती थी। अधिकतर मामलों में पति संपत्ति पर अपना अधिकार जताता था। तलाक या विवाद की स्थिति में पत्नी को सिर्फ भरण-पोषण (maintenance) तक सीमित कर दिया जाता था। संयुक्त संपत्ति को अक्सर पति की कमाई मानकर पत्नी को उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला स्पष्ट करता है कि संयुक्त संपत्ति में पत्नी का भी 50% हिस्सा है। तलाक के मामलों में संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष होगा। इससे महिला की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह फैसला स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता और समान अधिकार को मजबूती देता है। स्त्री को अब यह भरोसा रहेगा कि यदि उसने विवाह के दौरान अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार और बच्चों को समर्पित किया है, तो उसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जाएगा। पति और पत्नी दोनों के अधिकार बराबर होंगे, जिससे विवाह संस्था में न्याय और विश्वास मजबूत होगा। भारत में विवाह और संपत्ति के अधिकार को लेकर कई बदलाव हुए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) विवाह, तलाक, भरण-पोषण और दांपत्य अधिकारों को कानूनी रूप प्रदान किया है। स्त्रीधन की मान्यता अदालतों ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि स्त्रीधन पर केवल स्त्री का अधिकार है। हालिया फैसला अब अदालतें यह भी मान रही हैं कि संयुक्त संपत्ति केवल पति की कमाई नहीं है, बल्कि पत्नी के घरेलू योगदान का भी परिणाम है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में "Community Property Law" है, जिसके अनुसार विवाह के बाद अर्जित संपत्ति पति-पत्नी की संयुक्त मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी तलाक की स्थिति में संपत्ति का समान बंटवारा होता है। भारत अब धीरे-धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। इस फैसले के बावजूद कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण भारत में अभी भी स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार दिलाना कठिन है। कई पुरुष इसे अपने खिलाफ मान सकते हैं और विवादों में वृद्धि हो सकती है। संपत्ति के दस्तावेजों में यदि केवल पति का नाम हो, तो पत्नी को अधिकार दिलाना जटिल होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। इसने यह संदेश दिया है कि विवाह केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समानता का संबंध है। पति और पत्नी दोनों के योगदान की मान्यता जरूरी है, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक। यह फैसला आने वाले समय में भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष समानता, विवाह में न्याय और पारिवारिक संपत्ति के निष्पक्ष बंटवारे की नींव रखेगा।

https://t.me/AllNewsPapers

सवालोंमें रेल सुरक्षा

सुखद और सुरक्षित रेल यात्राका संकल्प अवश्य ही श्रेयस्कर है लेकिन जमीनी वास्तविकता कुछ अलग है, जो चिन्ता बढ़ाने वाली है। भारतीय रेल अपने संकल्पके अनुरूप प्रयासरत तो है लेकिन इस दिशामें अभी बहुत कुछ करनेकी जरूरत है। एक बड़ी चिन्ताकी बात रेल हादसोंको लेकर है, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार लगभग २२ हजार लोग प्रतिवर्ष ट्रेनोंसे गिरकर अथवा टकराकर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह आकड़ा वर्ष २०२३ का है, जिसमें कहा गया है कि देशमें प्रतिदिन ६० लोग रेल हादसोंके शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्रमें वर्ष २०२३ में ५,५५९ हादसे हुए जो कुल दुर्घटनाओंका २२.५ प्रतिशत है। इसी क्रममें उत्तर प्रदेशमें ३,२१२ हादसे हुए, जो १३ प्रतिशत है। महाराष्ट्रमें इन हादसोंमें ३,४४५ मौते हुई जबकि उत्तर प्रदेशमें ३,१५९ लोग असमय मौतके शिकार हुए। विशेष बात यह है कि सबसे अधिक रेल हादसे शाम छह बजेसे नौ बजेके दौरान हुए। एनसीआरबीकी रिपोर्ट रेलकी सुरक्षापर गम्भीर सवाल खड़े करते हैं। आलोच्य वर्षके दौरान ३,०१४ लोग हादसोंमें घायल हुए। पूरे देशमें रेलवे दुर्घटनाओंके कुल २४,६७८ मामले दर्ज किये गये, जो वर्ष २०२२ की तुलनामें ६.७ प्रतिशत अधिक है। रिपोर्टमें यह भी कहा गया है कि सबसे अधिक ७४.९ प्रतिशत अर्थात् १८,४८० लोग ट्रेनसे गिरने या ट्रैकपर टकरानेके शिकार हुए। इसमें कुल १५,८७८ लोगोंकी मौत हुई, जो कुल मौतोंका लगभग ७२.८ प्रतिशत है। इसी प्रकार क्रासिंगपर रेल दुर्घटनाओंके कुल २,४८३ मामले दर्ज किये गये, जिसमें २,२४२ लोगोंकी मृत्यु हुई। रेलवे हादसोंके कई और भी कारण हैं, जिनमें लोको पायलटकी गलती भी है। इसी तरह मैकेनिकल फाल्ट जैसे ट्रैककी खराबी, पुल या सुरंग गिरनेसे भी रेल हादसे हुए। इन रेल हादसोंके लिए भारतीय रेलवेमें सुरक्षा और संरक्षापर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस सन्दर्भमें चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती सेफ्टी कैटेगरीमें पर्याप्त कर्मचारियोंकी कमीसे सम्बन्धित है। ये वे पद हैं जो ट्रेन संचालन और ट्रैक, सिग्नलिंग, स्टेशन प्रबंधन और मार्ग निरीक्षण आदिसे जुड़े हैं। वैसे रेलवेने विगत कुछ वर्षोंमें सुरक्षासे जुड़े सुधारोंमें काम तो किया है लेकिन रिक्त पदोंकी संख्या और कर्मचारियोंपर दबाव बढ़ा है। इससे ट्रेन दुर्घटनाओंको रोकनेमें बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। रेलवे सुरक्षा श्रेणीमें लगभग डेढ़ लाखसे अधिक पद रिक्त हैं। जून २०२३ तक ग्रुप-सीमें दो लाख ७४ हजार ५८० पद रिक्त हैं। कर्मचारियोंकी कमीके चलते रेलवेकी सुरक्षा और संरक्षा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। परिणामस्वरूप रेल हादसोंकी संख्या बढ़ रही है। इसलिए रेल मंत्रालयको इस दिशामें युद्धस्तरपर काम करनेकी जरूरत है।

मुंहतोड़ जवाबकी तैयारी

पाकिस्तानको मुंहतोड़ जवाब देनेके लिए भारतीय सेनाका सीमावर्ती आबादी वाले इलाकोंमें एके-६३० एयर डिफेंस गन सिस्टम तैनात करनेका निर्णय सकारात्मक कदम है। इसमें लगा इलेक्ट्रो आप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम हर मौसममें लक्ष्य पहचान सकता है, जो ड्रोन, राकेट, तोपखाना और मोर्टारके हमलोंको विफल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि आपरेशन सिन्दूरके दौरान सशस्त्र संघर्षमें पाकिस्तानी ड्रोनने जम्मू-कश्मीर और पंजाबमें नागरिक ठिकानों और धर्मस्थलोंपर सीधे हमले किये थे। इसको देखते हुए सुरक्षाकी दृष्टिसे पहलेसे ही तैयारी कर लेना सेनाकी दूरदर्शिता और आजकी आवश्यकता है। मिशन सुदर्शन चक्रके तहत पाकिस्तानकी सीमासे सटे आबादी वाले इलाकों और आस्थाके केन्द्रोंकी सुरक्षाके लिए भारतीय सेनाने एक स्वदेशी कम्पनीसे छह एके-६३० एमएम बन्दूकें खरीदनेकी तैयारी की है, जो पाकिस्तानके किसी भी नापाक हमलोंको नाकाम करनेमें मीलका पत्थर साबित होगा। एके-६३० एमएम गन एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो प्रति मिनट तीन हजार राउड फायरिंग कर सकता है और चार किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यको निशाना बना सकता है। आपरेशन सिन्दूरके दौरान पाकिस्तानी सेनाके हमलेसे सबक लेते हुए एयर डिफेंस सिस्टमकी खरीदके लिए टेण्डर जारी किया जा चुका है, जो भारतीय सेनाकी तत्परताको दर्शाती है। इस सिस्टमको पाकिस्तानकी सीमा और लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) से लगे इलाकोंकी सुरक्षाके लिए तैनात किया जायगा। आपरेशन सिन्दूरके दौरान भारतने स्वदेशी अस्त्रोंका खुलकर परीक्षण किया, जो उम्मीदोंपर खरे उतरे और पाकिस्तानको सीजफायरके लिए गिड़गिड़ानेको बाध्य कर दिया। इस आपरेशनमें जो कमियां दिखीं उनसे सबक लेते हुए भारतीय सेना उसे दूर करनेमें पूरी तरह जुट गयी है। एके-६३० नये एयर डिफेंस गन सिस्टमका एक हिस्सा है, जो पाकिस्तानके लिए बड़ी चुनौती भी है और सन्देश भी।

लोक संवाद

पहला परमाणु अस्त्र

महोदय,-महाभारतमें कई घटना, संबंध और ज्ञान-विज्ञानकेरहस्य छिपे हुए हैं। महाभारतका हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओंकी गाथाओंतक सीमित नहीं है। महाभारतसे जुडे शाप, वचन और आशीर्वादमें भी रहस्य छिपे हैं। इन्हीं रहस्योंमें से एक है ब्रह्मास्त्र। संभवतः दुनियाका पहला परमाणु बम छोड़ा था अश्वत्थामाने। आधुनिक कालमें जे. रॉबर्ट ओपनहाइमरने गीता और महाभारतका गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारतमें बताये गये ब्रह्मस्त्रकी संहारक क्षमतापर शोध किया और अपने मिशनको नाम दिया ट्रिनिटी (त्रिदेव)। रॉबर्टकेनेतृत्वमें १९३९ से १९४५ का बीच वैज्ञानिकोंकी एक टीमने यह कार्य किया। १६ जुलाई १९४५ को इसका पहला परीक्षण किया गया। शोधकार्यकेबाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तवमें महाभारतमें परमाणु बमका प्रयोग हुआ था। ४२ वर्ष पहले पुणेके डाक्टर एवं लेखक पद्माकर विष्णु वर्तकने अपने शोधकार्यकेआधारपर कहा था कि महाभारतके समय जो ब्रह्मस्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बमके समान ही था। डा. वर्तकने १९६९-७० में एक किताब लिखी स्वयंभू इसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतमें कहीं-कहीं ब्रह्मस्त्रकेप्रयोग किये जानेका वर्णन मिलता है। रामायणमें भी मेघनादसे युद्ध हेतु लक्ष्मणने जब ब्रह्मस्त्रका प्रयोग करना चाहा तब श्रीरामने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जायगी। ब्रह्मस्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्रको छोड़ता था वह इसे वापस लेनेकी क्षमता भी रखता था लेकिन अश्वत्थामाको वापस लेनेका तरीका नहीं याद था जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गये थे। रामायण और महाभारतकालमें ये अस्त्र गिने-चुने योद्धाओंके पासथा। रामायणकालमें जहां यह विभीषण और लक्ष्मणके पास यह अस्त्र था वहीं महाभारतकालमें यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुनके पास था। अर्जुनने इसे द्रोणसे पाया था। द्रोणाचार्यको इसकी प्राप्ति राम जामदग्नेयसे हुई थी। ऐसा भी कहा गया है कि अर्जुनको यह अस्त्र इंद्रने भेंट किया था। **-शत्रुंजय प्रताप, वाया ईमेल।**

संकटमें है एर्दोआनकी सत्ता

एर्दोआनकी सत्ता संकटमें है। एर्दोआनके बाद भविष्यको लेकर बहस तेज हो गयी है। वर्ष २०१७ में जनमत संग्रहके बाद तुर्कीकी सरकार संसदीय प्रणालीसे राष्ट्रपति प्रणालीमें बदल गयी। बिलाल एर्दोआन राष्ट्रपतिके बेटे हैं। मुख्य वंशवादी उत्तराधिकारी और अखिल तुर्कवादके दूतके रूपमें दिखते हैं, लेकिन उनकी छवि कमजोर है।

❒ पुष्परंजन

एर्दोआन खैरियतसे नहीं हैं। एर्दोआनके करीबी लोगोंमें, उनके बादके भविष्यको लेकर बहस फिरसे तेज हो गयी है। हालांकि पार्टीका एक हिस्सा दावा करता है कि राष्ट्रपति रेजेप तैय्यिप एर्दोआन खुद २०२८ में पद छोड़नेका इरादा नहीं रखते, लेकिन पार्टीकी अंदरूनी स्थिति उबालपर है। वर्ष २०१७ में एक जनमत संग्रहके बाद, तुर्कीकी सरकार संसदीय प्रणालीसे राष्ट्रपति प्रणालीमें बदल गयी। तुर्कीमें संभावित उत्तराधिकारियोंके नाम तेजीसे चर्चामें आ रहे हैं। हकान फिदान २०१० से २०२३ तक तुर्की खुफिया एजेंसीके प्रमुख रहे हैं और अब विदेशमंत्री हैं। वह एर्दोआनके सबसे भरोसेमंद लोगोंमेंसे एक हैं, लेकिन राष्ट्रपति परिवारमें उन्हें लेकर थोड़ी सावधानी बरती जाती है। इब्राहिम कालिन २०१४ से तुर्की राष्ट्रपतिके प्रेस सचिव और २०२३ से राष्ट्रीय खुफिया एजेंसीके प्रमुख हैं। उन्हें एक बुद्धिजीवी और शासनके सबसे करीबी विचारकोंमेंसे एक माना जाता है। बिलाल एर्दोआन राष्ट्रपतिके बेटे हैं, मुख्य 'वंशवादी' उत्तराधिकारी और अखिल तुर्कवाद् के दूतके रूपमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी छवि कमजोर है। उनका अतीत निन्दनीय रहा है, खासकर २०१३ के टेलीफोन रिकार्डके दौरान 'लाखों लोगोंके लापता होनेके मामले' को लेकर। सेल्कुक बयारकतार एर्दोआनके दामाद हैं, जो बयारकतार ड्रोनके डिजाइनर हैं। वे तुर्की राष्ट्रवादियोंके प्रतीक हैं। बेरात अल्बयारक एक और दामाद हैं, जो पूर्व वित्त और ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके कार्यकालमें तुर्कीमें संकट शुरू हुआ था। लेकिन आर्थिक विफलता और घोटालोंके बाद, उन्हें अपना पद खोना पड़ा। सुलेमान सोयलू एक पूर्व गृहमंत्री हैं जो सुरक्षा हलकोंमें प्रभावशाली हैं। लेकिन पेकरके घोटालों और आरोपोंने उनकी दावेदारी बहुत कमजोर कर दी। विदेशमंत्री हकान फिदान रूसके लिए सबसे अच्छा विकल्प लगता है। कठोर, लेकिन व्यावहारिक। सबसे विवादास्पद सेल्कुक बयारकतार हैं, जो रूसी संघके खिलाफ पश्चिमी गठबंधनके पैरोकार हैं। वह साल १९९४ था, जब एर्दोआन इस्तांबुलके मेयर बने, जबकि उनके अब कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक्रेम इमामोग्लूने व्यवसाय प्रशासन संकायसे स्नातक किया। इमामोग्लू और एर्दोआनने अपने राजनीतिक करियरको एक जैसे तरीकेसे बनाया है। दोनों इस्तांबुलके मेयर रहे हैं और दोनों ही उस पदपर रहते जेल गये हैं। एर्दोआन १९९४ में इस्तांबुलके मेयर बने, लेकिन पांच साल बाद एक राजनीतिक रैलीमें राष्ट्रवादी कविता-कश्मीनारें हमारी संगीनें हैं और गुंबद हमारे हेलमेट हैं। पढ़नेके बाद धार्मिक नफरत भड़कानेके आरोपमें उन्हें जेल भेज दिया गया। उस समय धर्मनिरपेक्ष अदालतोंने कविताको एक खतरेके रूपमें देखा था। राष्ट्रपति बननेसे पहले एर्दोआन प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने २० से ज्यादा वर्षोंतक तुर्कीपर कब्जा बनाये रखा और वहांके लोकतंत्रपर अपनी पकड़ मजबूत की और एर्दोआनके ही रास्तेपर चलते हुए इमामोग्लू तुर्कीके सबसे बड़े शहर इस्तांबुलके मेयर बने। इमामोग्लू लम्बे समयसे अपनी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के नेता रहे हैं और अब उन्हें एर्दोआनका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। १९ मार्च, २०२५ को, इस्तांबुलके मेयर और विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टीके राष्ट्रपति पदके उम्मीदवार एक्रेम इमामोग्लूको फर्जी डिग्री, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, धन शोधन और आतंकवाद, विशेष रूपसे पीकेकेका समर्थन करनेके सन्देहमें तुर्की पुलिसने हिरासतमें लिया था। तुर्कीमें राष्ट्रपति पदके लिए चुनाव लड़नेके लिए, उम्मीदवार द्वारा उच्च शिक्षा पूरी कर ली होनी चाहिए। लेकिन १८ मार्चको देशकी विपक्षी पार्टी द्वारा इमामोग्लूको अपना राष्ट्रपति पदका उम्मीदवार घोषित करने और एर्दोआनके खिलाफ आधिकारिक चुनाव लड़नेसे कुछ ही दिन पहले, उनकी डिग्री रद कर दी गयी। इस गिरफ्तारीके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये। दो हजारसे अधिक लोग गिरफ्तार हुए, जिनमेंसे अधिकांश अभी जेलमें हैं। लोगोंने राष्ट्रपति एर्दोआनकी डिग्रीको भी जुगाड़ वाला बताया। राष्ट्रपति एर्दोआनकी आधिकारिक जीवनी, एक्सटर्नल, में लिखा है कि उन्होंने १९८१ में मरमरा विश्वविद्यालयके आर्थिक और वाणिज्यिक विज्ञान संकायसे स्नातककी उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन हालके दिनोंमें तुर्कोंने ट्विटरपर (या तो अपनी डिग्री दिखाओ या फिर इस्तीफा) वायरल करते हुए राष्ट्रपतिपर झूठ बोलनेका आरोप लगाया है। इस हैशटैगका इस्तेमाल करके हजारों री-ट्वीट किये गये हैं। एक म्यूजिक वीडियो भी है, जिसमें राष्ट्रपतिसे अपनी उच्च शिक्षाका प्रमाण प्रस्तुत करनेका आह्वान किया गया है। राष्ट्रपति एर्दोआनको इस मामलेमें मरमरा विश्वविद्यालयकी आधिकारिक वेबसाइटसे कोई मदद नहीं मिली है, जहां बताया गया है कि उपरोक्त संकाय कभी अस्तित्वमें ही नहीं था, बल्कि आर्थिक एवं प्रशासनिक विज्ञान संकायकी स्थापना १९८२ में हुई थी।

एर्दोआनकी डिग्रीकी प्रामाणिकतापर संदेह सबसे पहले २०१४ में, उनके राष्ट्रपति चुने जानेसे पहले, एक विपक्षी सांसदने जताया था, जिसमें दावा किया गया था कि २०१४ के राष्ट्रपति चुनावके दौरान मरमरा विश्वविद्यालयके अभिलेखागार बंद कर दिये गये थे और पिछले कुछ दिनोंमें पुरानी रिपोर्टोंके फिरसे साझा होनेके परिणामस्वरूप यह चर्चा फिरसे शुरू हो गयी है, जिसमें कहा गया है कि मरमरा विश्वविद्यालयके अभिलेखागार फिरसे खोल दिये गये हैं, लेकिन राष्ट्रपतिकी डिग्री नहीं मिल रही है। तुर्कीमें राष्ट्रपति बननेके लिए आधिकारिक तौरपर चार सालकी डिग्री होना अनिवार्य शर्त है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि उनकी डिग्री असली नहीं पायी गयी तो क्या उन्हें पदसे हटाया जा सकता है। एर्दोआन चाहे जितना भी राष्ट्रवाद बघार लें, इस देशकी अर्थव्यवस्था खराब हालतमें है। एर्दोआनके अपने मतदाता भी उच्च मुद्रास्फीति, आय असमानता, आवास और रसोईकी लागत और युवाओंके लिए बेरोजगारीका सामना कर रहे हैं। बेहतर जीवन बनानेके आर्थिक अवसर और भी अधिक मायावी होते जा रहे हैं। वास्तवमें, जैसे ही डिप्लोमा रदके विरुद्ध लोग सड़कपर उतरे, बाजारोंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केन्द्रीय बैंकको मुद्रा भंडारसे पैसे निकालने पड़े। मुद्रास्फीतिका मुकाबला करनेके लिए अबतक ४० अरब डालरका उपयोग करना पड़ा। तुर्कीमें सबसे बदनाम अदालतें हुई हैं, जो एर्दोआनकी तरफदारी कर रही हैं। दो सालसे तुर्कीका जेन-जेड उनकी असलियत उजागर करनेमें लगा है। एर्दोआन कबतक जेन-जेडको दबाये रखेंगे। यह भी एक सवाल है।

तुर्कीके राष्ट्रपति एर्दोआनकी सत्ता संकटमें है। आर्थिक मंदी और व्यापक विरोध प्रदर्शनोंने उनकी छविको प्रभावित किया है। राजनीतिक उत्तराधिकारियोंपर बहस तेज हो रही है, जिससे पार्टीमें अस्थिरता बढ़ गयी है। एर्दोआनके अपने मतदाता भी उच्च मुद्रास्फीति, आय असमानता और बेरोजगारीका सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकको मुद्रा भंडारसे पैसे निकालने पड़े। मुद्रास्फीतिका मुकाबला करनेके लिए अबतक ४० अरब डालरका उपयोग करना पड़ा। अदालतें एर्दोआनकी तरफदारी कर रही हैं। दो सालसे तुर्कीका युवा असलियत उजागर करनेमें लगा है।

संघ की विचारधारा एवं योगदान

❒ सुरेश रुंगटा

समाज ही व्यक्ति को दिशा देता है तथा व्यक्ति के संस्कार से समाज का स्वरूप तय होता है। जब व्यक्ति संयम, अनुशासन और सेवा की भावना से सशक्त बनता है तो समाज संगठित होता है और राष्ट्र सामर्थ्यवान। लगभग ८०० सालों की गुलामी से भारत के लोग हीन भावना से ग्रसित हो गये थे। धर्म के प्रति पाश्चात्य विद्वानों के नकारात्मक पक्ष को कायरतापूर्ण अनुसरण किए जाने लगा था। विदेशी शक्तियों ने भारत पर राज करने के लिए धर्मान्तरण एवं पाश्चात्मीकरण करने के लिए भारतीयों के मनोबल को तोड़ा तथा उसमें फूट डालने के लिए जातीयता का बीजारोपण कर दिया। कहीं यदि भारतीय पुर्नजागरण का प्रयास होता भी था तो उसे प्रतिगामी करार देकर उसकी निंदा करना वामपंथी बुद्धिजीवियों का हथकंडा बन गया था। हिन्दू धर्म के केवल नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर उस पर आक्रमण करने की प्रवृति बढ़ गई थी। शांति प्रकृति के हिन्दुओं में प्रत्याक्रमण की उन्मुखता खत्म हो चुकी थी। हिन्दुओं को आदिम-कालीन, अपरिष्कृत और असभ्य कहा जाने लगा था। हिन्दुओं को इस बात पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हो गए? क्या हमारी एकता का अभाव इसका मुख्य कारण था? हम विभाजित क्यो हैं? सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी आंखों के सामने समाज का भयानक उत्पीड़न देखने के बाद भी निष्क्रिय एवं अविरोधी कैसे हो गए? बौद्धिक ओजस्विता तथा आत्मविश्वास का अभाव क्यों हो गया? हम अपनी सत्ता एवं अस्तित्व के आग्रही क्यों नहीं रहे? विवादों से बचने की प्रवृति कैसे घर कर गई? हम अपने में ही दोष ढूंढ़ने वाले कैसे बन गए? जवाब है- सामाजिक एकता का अभाव, अपने विचारों का प्रभावी ढंग से बौद्धिक प्रस्तुतिकरण की कमी।

विश्व का एकमात्र सर्वाधिक प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, जिसका न कोई एक विशेष प्रवर्तक है और न ही इसके प्रारंभ होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। हां, इस धर्म का जन्म भारत भूमि में ही हुआ और यही यह पुष्पित, पल्लवित एवं संपोषित हुआ। अतः इस धर्म की अस्मिता एवं इसकी गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाये रखने का दायित्व भी हमारा है। इसी वृहद उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विजयादशमी के शुभ दिन २७ सितंबर १९२५ को डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में स्वयंसेवक आधारित एक संगठन बनाया, जो देश में सामाजिक सेवाभाव व अनुशासनपूर्ण सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय पुनर्निमाण के लिए एक अनूठा जन-पोषित आंदोलन है। इसके उद्देश्य को सदियों के विदेशी शासन के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसके निरंतर विकास का श्रेय धर्म में निहित भारत के राष्ट्रीय गौरव व इसके विजन की भावनात्मक प्रतिध्वनी को दिया जाता है। संघ का मुख्य जोर देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर है। इसका प्रयास मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करना है। संघ का अंतिम लक्ष्य भारत के वैभव को श्रेष्ठतम ऊंचाई पर पहुंचाने का है। जिसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक समर्पित भाव से लगे रहते हैं। वर्तमान विजयादशमी के दिन संघ की यात्रा १०० वर्ष की पूरी होकर १०१वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ७ अप्रैल १९२६ में इस संगठन का नाम 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' रखा गया तथा २८ मई १९२६ से नागपुर में इसकी पहली शाखा की शुरूआत सिर्फ ५ स्वयंसेवकों के साथ हुई थी, जबकि आज ८३ हजार से ज्यादा शाखाएं पूरे देश में लगती हैं। जिसमें एक करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' को लोग 'आरएसएस' या 'संघ' के नाम से ज्यादा जानते हैं। संघ का स्वंयसेवक होने के लिए कोई विशेष पात्रता या आयु का बंधन नहीं है। देश का हर नागरिक इसके लिए पात्र है। इस हेतु किसी पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं है। बस, जहां संघ की शाखा संचालित होती है, वहां गणवेश में आना है और इसकी गतिविधियों में भाग लेना है। भगवाध्वज को नमस्कार करना जरूरी है, क्योंकि इसे संघ में गुरू माना गया है। इस ध्वज के पास ही व्यायाम और बौद्धिक चर्चाएं होती हैं, तथा प्रार्थना के उपरांत समापन होता है। रोज सुबह लगभग सवा घंटे का यह अभ्यास प्रायः खुले मैदान में होता है। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि संघ है क्या? इस आलेख को पढ़कर या सुनकर संघ को समझना कठिन होगा। तो फिर संघ को जानें, तो कैसे जानें? इसके लिए आपको पूर्वाग्रह का त्याग कर शुद्ध जिज्ञाशा भाव से संघ की शाखा में कुछ दिनों तक आना होगा। क्योंकि संघ केवल एक ही काम करता है-शाखाएं चलाना। जहां आसपास के लोग समय पर आते हैं, शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ कुछ चर्चाएं करते हैं एवं राष्ट्रगान दोहराते हैं और ध्वज प्रणाम कर समय से घर चले जाते हैं। धीरे-धीरे एक स्वयंसेवक अपने में परिवर्तन महसूस करने लगता है। उसमें समय का अनुपालन, शिष्टता का भाव परिलक्षित होने लगता है। वास्तव में संघ एक विचार मंच है । संघ का अपना कोई निजी विचार नहीं है। देशकाल की परिस्थितियों के अनुरूप एवं शाखा में उपस्थित होने वाले स्वयंसेवकों के विचारों पर चर्चा होती है। साथ ही स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर अभी तक के राष्ट्र उत्थान हेतु किये गये कार्यों के अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी बुराईयों का परित्याग कर देश के लिए जितना भी बन सके, निःस्वार्थ भाव से कार्य करने का संकल्प लिया जाता है। यह संकल्प होता है- समाज को एक करना, एकत्रित करना। संघ का विचार सत्य पर आधारित है, जो असत्य विचार होते हैं वे इतने सारे संकटों के आगे टिक ही नहीं सकते। संघ का अधिष्ठान शुद्ध एवं सत्य है, किसी के विरोध में नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं सिखाया जाता। यह सबको सत्य पथ पर, सत्यकर्म का पालन करने का रास्ता बताता है। दूसरी जो बड़ी बात है, इन शुद्ध विचारों को, व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को, तैयार करने का कार्य संघ करता है। ६ दशकों से मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। संघ को जितना समझा, वह लिखा हूं। आप भी आइये, स्वंय का अनुभव प्राप्त कीजिए और लोगों को बताइए।

देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां संघ पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाते रहतीं हैं। इसका मुख्य कारण है कि संघ इन आरोपों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता । जबकि सच्चाई यह है कि संघ के हजारो स्वयंसेवक देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों को न्योछावर किया था। संघ के संस्थापक डाक्टर हेडगेवार ने भी प्राइमरी स्कूल काल में विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण के समय बांटी गई मिठाई को खाने से इंकार कर इसे कूड़े में फेंक दिया था। जिस कारण उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। बाद के दिनों में कांग्रेस की सभा में भड़काऊ भाषण करते हुए वे गिरफ्तार हुए तथा जज ने उनको एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी थी। राजगुरू जब भूमिगत हुए तो नागपुर में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। १९४७ में अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन गोवा से लेकर दादर, नगर हवेली, पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा। इसके लिए डाक्टर लोहिया ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को बराबर सशस्त्र बल का प्रयोग कर इसे आजाद करवाने की मांग करते रहे। लेकिन नेहरू जी ने अंग्रेजों से पूर्व आये पुर्तगालियों को भारत से बाहर करने को तैयार नहीं हुए, इस कारण गोवा, दीव, दमन और दादरा नगर हवेली के स्वतंत्र होने की आशा धूमिल हो गई थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारी मातृभूमि का एक पश्चिमी हिस्सा परतंत्र ही था। भारत सरकार इस संबंध में निष्क्रिय थी। सरकार का यह कहना था कि भारत किसी पर हमला नहीं करेगा। इस निष्क्रियता के कारण महाराष्ट्र-गुजरात के स्वयंसेवकों में काफी रोष था। उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो, इन चारों जगहों से पुर्तगालियों को भगाकर इसे मुक्त करवायेंगे। आवश्यक शस्त्र, बंदूक, गोली, बम के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया । इस काम में लता मंगेश्कर जी ने काफी योगदान दिया था।

छोटी-बड़ी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा शस्त्र एवं अन्य सामग्री इकट्ठा होने के पश्चात बाबाराव भिंडे ने पुणे के तरूणों को प्रतिज्ञा दिलाई और 'मेरा रंग दे बसंती चोला' गीत के साथ रेल से वापी शहर पहुंचे । भारत माता की जय के नारों के साथ हजारों स्वयंसेवकों ने चढ़ाई कर दी। इसमें सैकड़ो स्वयंसेवक मारे गये। अंततः पुर्तगाली सैनिक स्वयंसेवकों के आगे टिक नहीं पाये और वे शरणागत हो गये। इस प्रकार पुर्तगाल का झंडा नीचे उतारकर उसके स्थान पर भारत का तिरंगा फहराया गया। ५० वर्ष पूर्व की यह सशस्त्र क्रांति राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की बलिदान की कहानी है। जिसका कही कोई जिक्र नहीं होता। इस सशस्त्र क्रांति में कितने स्वयंसेवक हंसते-हंसते बलिदान हो गये, आज कितने लोग उन्हें याद करते हैं? वामपंथी इतिहासकारों ने इस संग्राम को बिल्कुल भुला दिया। जबकि इस केन्द्र शासित प्रदेश को भारत में मिलाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था।

१९६२ के भारत-चीन युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने देश के कई शहरों एवं नगरों में पुलिस की कमी होने पर उनके स्थान पर अपनी सेवा देकर देश भर में शासन को सहयोग देने का काम किया था। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने १९६३ के गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। भोपाल गैस त्रासदी, असम के दंगे, विभिन्न भागों में रेल दुर्घटनाएं, तमिलनाडु का सुनामी, गुजरात का भूकंप, आंध्रप्रदेश में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी प्राकृति आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में आरएसएस के स्वंयसेवक ही सबसे पहले जरूरतमंदों तक पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.टी. टॉमस के अनुसार 'यदि किसी संगठन को देश में लगे आपातकाल से मुक्त कराने का श्रेय देना हो, तो मैं यह श्रेय आरएसएस को दूंगा''। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस अपने स्वंयसेवकों में 'राष्ट्र की रक्षा के लिए अनुशासन का संचार करता है। मैं आरएसएस की इस शिक्षा और विश्वास की प्रशंसा करता हूं कि शारीरिक शक्ति का उद्देश्य स्वंय को खतरों से बचाना है । मैं समझता हूं कि आरएसएस का शारीरिक प्रशिक्षण विदेशी आक्रमण के समय राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए जरूरी है'।

महिलाओंके खिलाफ बढ़ते अपराधसे वैश्विक चिन्तन नगण्य

❒ योगेंद्र

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष २०२३ के महिला अपराधोंके आंकड़े देशकी तरक्कीके आंकड़ोंको मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश एक तरफ जहां रक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रोंमें लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं महिलाओंके साथ होनेवाले अपराधोंके मामलोंमें शर्मसार हो रहा है। एनसीआरबीकी रिपोर्टके अनुसार २०२३ में उससे पिछले दो सालोंकी तुलनामें महिलाओंके खिलाफ अपराधके ज्यादा मामले सामने आये हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेशमें दर्ज किये गये। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। रिपोर्टके अनुसार २०२३ में पूरे देशमें ऐसे करीब ४.५ लाख मामले दर्ज किये गये। वर्ष २०२३ में महिलाओंके खिलाफ अपराधके कुल ४४८२११ मामले दर्ज किये गये, जबकि २०२२ में ४४५२५६ और २०२१ में ४२८२७८ मामले थे। उत्तर प्रदेशमें सबसे अधिक ६६३८१ मामले दर्ज किये गये, उसके बाद महाराष्ट्रमें ४७१०१, राजस्थानमें ४५४५०, पश्चिम बंगालमें ३४६९१ और मध्यप्रदेशमें ३२३४२ मामले दर्ज किये गये। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्यापर १२४.९ अपराध दरके साथ शीर्षपर रहा, जबकि इसके बाद राजस्थान ११४.८, ओडिशा ११२.४, हरियाणा ११०.३ और केरलमें ८६.१ अपराध दर दर्ज की गयी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ४९८ के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरताके मामले सबसे ज्यादा थे, जिनमें १३३६७६ मामले दर्ज किये गये और इनकी दर १९.७ रही। महिलाओंके अपहरण और बंधक बनानेके ८८६०५ मामले दर्ज किये गये और इनकी दर १३.१ रही। महिलाओंकी गरिमा भंग करनेके इरादेसे हमला करनेके ८३८९१ मामले आये, जबकि बलात्कारके २९६७० मामले दर्ज किये गये। अट्ठारह वर्ष और उससे अधिक आयुकी महिलाओंसे बलात्कारके २८८२१ मामले आये और १८ वर्षसे कम आयुकी लड़कियोंसे बलात्कारके ८४९ मामले आये। बलात्कारके प्रयासके २७९६ मामले दर्ज किये गये। यौन अपराधोंसे बच्चोंका संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चोंसे बलात्कारके ४००४६ मामले, यौन उत्पीड़नके २२१४९ मामले, यौन प्रताड़नाके लिए २७७८ मामले, पोर्नोग्राफीके लिए बच्चोंका इस्तेमाल करनेके ६९८ मामले और कानूनके अन्य प्रावधानोंके तहत ५१३ मामले दर्ज किये गये। पुलिसके निबटारा आंकड़ोंसे पता चला कि पिछले वर्षोंसे १८५९६ मामले जांचके लिए लंबित थे, जबकि ४४८२११ नये मामले दर्ज किये गये और ९८७ स्थानांतरित किये गये। इस तरह कुल ६३५१५९ मामले थे। एसिड अटैकके ११३ मामले दर्ज किये गये। साल २०१२ में दिल्लीमें निर्भयाके बलात्कार और हत्याके बाद जमीनपर ज्यादा कुछ बदला नहीं दिखता। कठोर कानून मौजूद हैं, परन्तु वे कितने प्रभावी हैं। साल २०२२ के लिए उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओंके खिलाफ अपराधके कुल ४४५२५६ मामले दर्ज किये गये, जो साल २०२१ से चार फीसदी ज्यादा थे। महिलाओंके खिलाफ अपराधका सबसे बड़ा हिस्सा पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (३१.४ फीसदी) के तहत दर्ज हुआ, जबकि सभी अपराधोंमें शील हननकी नीयतसे महिलाओंपर हमलेका हिस्सा १८.७ फीसदी था और बलात्कार ७.१ फीसदीपर रहा। डब्ल्यूपीएस इंडेक्स (महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक) की २०२३ की रिपोर्ट में भारतकी रैंकिंग साल २०२३ में १२८वें स्थान पर रही। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्वीडन शीर्षपर रहे, जबकि अफगानिस्तान, यमन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थानपर रहे। रिपोर्टमें यह भी कहा गया है कि २०२२ में महिलाओंको निशाना बनाकर की जानेवाली राजनीतिक हिंसाके मामलेमें भारत शीर्ष दस सबसे खराब देशोंमें शामिल है। मैक्सिको ५३७ ऐसी घटनाओंके साथ इस सूचीमें शीर्षपर है, उसके बाद ब्राजील (३२७) का स्थान है, जबकि भारत इस सूचीमें १२५ घटनाओं (प्रति १००००० महिलाओंपर) के साथ सातवें स्थानपर है, जहां विशेष रूपसे राजनीतिक हिंसाके लिए महिलाओंको निशाना बनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०१९-२१) में पाया गया कि १८-४९ वर्षकी आयुकी २९.३ फीसदी महिलाओंने अपने जीवनकालमें पति द्वारा हिंसाका अनुभव किया है। यदि अपराध दर्ज भी हो जाते हैं तो न्याय धीमा हो सकता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अकसर पीड़ितोंको ही दोषी ठहराते हैं या उनकी गवाहीको हतोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप, कई मामले आधिकारिक रिकार्ड में दर्ज ही नहीं होते। विशेषज्ञोंका कहना है कि सांस्कृतिक शर्मिंदगी और प्रतिशोधका डर रिपोर्ट दर्ज करानेमें बड़ी बाधाएं हैं। भारतमें महिलाओंके खिलाफ अपराधोंका कारण पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा और जागरूकताकी कमी, कानूनोंका कम प्रभावी कार्यान्वयन और महिलाओंके प्रति समाजकी घटती संवेदनशीलता जैसे सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक कारक हैं। भारतकी चुनौती वैश्विक रुझानोंके समान और उनसे भी बदतर है। कई देशोंकी तरह, भारत भी कम रिपोर्टिंग और कलंकसे जूझ रहा है। लेकिन गहरी जड़ें जमाये हुए लैंगिक पूर्वाग्रह और विशाल जनसंख्या घनत्वका मतलब है कि अघोषित अपराधोंका एक छोटा-सा प्रतिशत भी बहुत बड़ी संख्यामें तब्दील हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ोंकी तुलना इस बातपर जोर देती है कि समाधानोंमें हर देशकी हिस्सेदारी है, अंतरराष्ट्रीय समझौतोंको लागू करनेसे लेकर सर्वोत्तम प्रथाओंको साझा करनेतक। कानूनों और जागरूकताके मामलेमें भारतमें हालमें हुए सुधार सकारात्मक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई समकक्षोंसे पीछे है। भारत वह देश है जहां नवरात्रोंके दौरान कन्या पूजनकी प्रथा है। इसके बावजूद हमारे समाजमें महिलाओंका पर्याप्त सम्मान नहीं है, उनकी सुरक्षामें कमी है तो यह चिन्तनीय विषय है। यही कारण है कि हमारे देशके लगभग सभी राज्योंमें महिला-पुरुष लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। बच्चोंके पीछे पर्याप्त संख्यामें बच्चियां नहीं हैं। यह स्थिति हमें फिर ओर ले जा रही है, यह सोचनेकी बात है। समूह समाजको इसपर चिन्तन करना चाहिए। परन्तु वैश्विक स्तरपर चिन्ता न होना आश्चर्यचकित करता है।

साइबर अपराधियों का बढ़ता जाल

कैसी विडंबना है कि भोले-भाले लोगों से छल करके खून-पसीने से हासिल जीवन भर की पूंजी ऑनलाइन डकैती में लूट ली जाती है। जिसकी वापसी के लिए तंत्र की कोई जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं है। जब तंत्र लगातार ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिये प्रेरित करता है तो उसे जनधन की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़े इस संकटपूर्ण स्थिति का खुलासा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि वर्ष 2023 में साइबर क्राइम की घटनाओं में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई है। जिसके आने वाले वर्षों में और अधिक होने की आशंका जतायी जा रही है। जो इस बात का प्रमाण है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से निबटना अब दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। निश्चित रूप से साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के आंकड़े जुटाने की एनसीआरबी की पहल महत्वपूर्ण है, जो इस संकट से निबटने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अपराधों से निबटने के लिये कैसे रणनीति बनाते हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि कैसे वे साइबर अपराधियों के संजाल में फंसने से बच सकते हैं। लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि दैनिक जीवन में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हुए अपने गोपनीय डेटा की सुरक्षा कैसे करें। विडंबना यह है कि साइबर अपराधी नित नए तौर-तरीकों से लोगों को लूटने लगते हैं। कुछ समय पहले साइबर लुटेरों ने स्पूफिंग तकनीक से लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। वे सोशल मीडिया अकाउंट में घुसपैठ करके धन की उगाही करने लगते। व्यक्ति को संकट में दिखाकर उसके रिश्तेदारों से धन ऐंठने लगते। विडंबना यह है कि साइबर ठगी की तकनीक उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों और ई-मेल खातों तक भी पहुंच गई। दरअसल, कभी हैकिंग, तो कभी स्पूफिंग के कपटपूर्ण छल का मकसद लोगों की जमा-पूंजी को निशाना बनाना ही रहा है। जब तक लोग ठगी के इन तौर-तरीकों को समझ पाते, साइबर ठग नई तकनीक के सहारे लोगों को भ्रमित कर चूना लगाने की नई कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच सवाल उठता है कि हमारा तंत्र इन घटनाओं में पर प्रभावी रोक लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता ? आखिर फोन व कंप्यूटर में मजबूत एंटी वायरस और इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर क्यों कामयाब नहीं होते ? आखिर क्यों साइबर घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती ? इन पर रोक के लिए कोई कारगर व्यवस्था व मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है ? ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सावधानी और सजगता-सतर्कता मददगार साबित हो सकती है। खासकर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते वक्त अतिरिक्त सावधानी से ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।

जातिवाद, वैचारिक विरोधी और संघ

उमेश चतुर्वेदी

(वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार)

यह संयोग ही है कि ठीक सौ साल पहले राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, ठीक उसके कुछ ही महीने बाद छब्बीस दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सौ साल की यात्रा को जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जोर-शोर से शुरू हुआ भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन भारत भूमि पर दम तोड़ता नजर आ रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा लगातार आगे बढ़ रही है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक मोर्चे पर संघ की वैचारिकी की प्रगति यात्रा जारी है।

एक ही वक्त पर शुरू दोनों वैचारिकी में एक विशेष अंतर रहा। वाम आंदोलन के निशाने पर सदा संघ की विचारधारा और संगठन रहा। संघ के खिलाफ कभी सत्ता के सहयोग से तो कभी किसी और तरीके दुष्प्रचार खूब फैलाया गया। उसी में एक विचार ऐसा है कि संघ मुसलमानों के खिलाफ है। वैचारिक और सामाजिक मोर्चे पर यह भी स्थापित करने की कोशिश की गई कि संघ भारत भूमि से मुस्लिम धर्म का समूल खात्मा चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। संघ की प्रतिनिधि सभा के सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार जी के संयोजन में साल 2002 से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम का संगठन काम कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम मानने वाले भारतीय लोगों के बीच राष्ट्र प्रथम की भावना के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीयता के विचार को बढ़ावा देना है। संघ का कोई घोषित या अघोषित उद्देश्य नहीं है कि भारत भूमि मुस्लिम लोगों से मुक्त हो।

एक ही वक्त पर शुरू दोनों वैचारिकी में एक विशेष अंतर रहा। वाम आंदोलन के निशाने पर सदा संघ की विचारधारा और संगठन रहा। संघ के खिलाफ कभी सत्ता के सहयोग से तो कभी किसी और तरीके दुष्प्रचार खूब फैलाया गया। उसी में एक विचार ऐसा है कि संघ मुसलमानों के खिलाफ है। वैचारिक और सामाजिक मोर्चे पर यह भी स्थापित करने की कोशिश की गई कि संघ भारत भूमि से मुस्लिम धर्म का समूल खात्मा चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। संघ की प्रतिनिधि सभा के सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार जी के संयोजन में साल 2002 से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम का संगठन काम कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम मानने वाले भारतीय लोगों के बीच राष्ट्र प्रथम की भावना के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीयता के विचार को बढ़ावा देना है। संघ का कोई घोषित या अघोषित उद्देश्य नहीं है कि भारत भूमि मुस्लिम लोगों से मुक्त हो। संघ का प्रयास है कि भारत के मुसलमानों को लेकर स्थापित छवि बदले और राष्ट्र निर्माण में भी उनकी भूमिका हो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरू जी रचित किताब ब्रंच ऑफ थॉट का हवाला देकर अक्सर संघ को मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक होने का प्रयास किया जाता है। वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवियों को जब भी संघ पर हमला करना होता है, 1966 में प्रकाशित इसी किताब का वे हवाला देते हैं। संघ के मौजूदा सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी इस बारे में अपनी राय खुलकर जाहिर कर चुके हैं। सात साल पहले सितंबर 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई तीन दिनों की विशेष व्याख्यान माला के आखिरी दिन 20 सितंबर को संघ प्रमुख ने श्रोताओं से आमंत्रित प्रश्नों का जवाब दिया था। उसमें ब्रंच ऑफ थॉट को लेकर भी एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के जवाब में मोहन राव भागवत ने कहा था, रही बात, बंच ऑफ थॉट्स की, तो बातें जो बोली जाती हैं वे परिस्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संदर्भ में बोली जाती हैं। वे शाश्वत नहीं रहतीं। इसी सवाल के जवाब में भागवत जी ने आगे कहा था, आरएसएस कोई संकीर्ण संगठन नहीं है. समय के साथ हमारे विचार और इनका प्रकटीकरण भी बदलता है।

संघ प्रमुख मुसलमान समुदाय को लोगों को भी अपना ही मानते हैं। इसी व्याख्यान माला में उन्होंने कहा था कि, हम एक देश की संतान हैं, भाई-भाई जैसे रहें। इसलिए संघ का अल्पसंख्यक शब्द को लेकर रिजर्वेशन है। संघ इसको नहीं मानता. सब अपने हैं, दूर गए तो जोड़ना है। संघ को लेकर एक आरोप लगता है कि वह जातिवादी है। विशेषकर संघ विरोधी बुद्धिजीवी कहने से नहीं हिचकते कि संघ में उच्च जातियों का वर्चस्व है। के एस भारती द्वारा संपादित और 1988 में प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एमिनेंट थिंकर के सातवें खंड में दिए विवरण के अनुसार महात्मा गांधी 1934 में वर्धा में आयोजित संघ के एक शिविर का दौरा किया था। तब वे बगल में ही सेवाग्राम आश्रम में ठहरे हुए थे। संघ के शिविर का जिज्ञासावश दौरा करने पहुंचे गांधी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि गांधीजी को इस बात से और भी आश्चर्य हुआ कि वर्धा शिविर में अस्पृश्यता, जातिगत उपेक्षा या अन्य भेदभावपूर्ण तौर-तरीके बिलकुल नहीं थे। गांधी जी के दौरे वक्त संघ के शिविर में अप्पाजी जोशी थे। इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे।

संघ और गांधी के संबंधों को लेकर भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन गांधी वांग्मय में संग्रहीत तथ्यों से इससे जुड़े वैचारिक कुहासे से भी भी पर्दा उठता है। गांधी वांग्मय के 87वें खंड में मिलता है। इसके अनुसार अप्रैल 1947 में दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम एकता के संदर्भ में हुई एक प्रार्थना सभा में, गांधीजी ने बताया था कि उन्हें संघ से एक पत्र मिला है, जिसमें इस बात से इनकार किया गया है कि हाल ही में गांधीजी द्वारा अपनी सभाओं में कुरान की आयतों को गीता की आयतों के साथ रखने के विरोध में संघ का कोई हाथ था। गांधीजी ने कहा कि उन्हें इस खंडन के बारे में सुनकर खुशी हुई, और आगे कहाः कोई भी संगठन जीवन या धर्म की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि वह पूरी तरह से खुले तौर पर काम न करे। सितंबर 1947 में गांधीजी नई दिल्ली में संघ कार्यकताओं से मिले थे। तब गांधी जी उनसे कहा था कि वास्तव में उपयोगी होने के लिए, आत्म-बलिदान के साथ-साथ पवित्र उद्देश्य और सच्चे ज्ञान का भी समावेश होना आवश्यक है।

संघ के जातिवादी होने के सवाल पर विज्ञान भवन के कार्यक्रम में भागवत जी ने कहा था कि अगर भारत में अंतरजातीय विवाहों की गणना किया जाए तो अंतरजातीय विवाह करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या संघ के स्वयंसेवकों की होगी। संघ पर वामपंथी लोगों का विरोधी होने का भी आरोप लगता है। लेकिन संघ प्रमुख इसे भी साफ कर चुके हैं। राष्ट्र हित के संदर्भ में वाम विचारधारा पर सवाल उठने जायज हैं। वाम विचारधारा भारतीयता की धारणा को तार-तार करती है। लेकिन उसे मानने वाले लोगों से संघ कभी घृणा नहीं करता, नहीं विद्वेष भाव रखता है। संघ प्रमुख तो अब बार-बार कहते हैं कि भारत में जो भी हैं, सब अपने हैं। उन्हें अपने साथ जोड़ना है।

संघ ने शताब्दी वर्ष में जो पंच प्रतिष्ठा निर्धारित की है, उसमें तीसरा सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता के संदर्भ में संघ का मानना है कि भारत भूमि में रहने वाले सभी लोग अपने हैं। कुछ भटके हुए हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ना है और भारत राष्ट्र को स्वावलंबी और मजबूत बनाना है। यह तभी संभव होगा, जब समूचे भारत का समाज एक होगा।

गांधी पर कुछ अटकलपच्चू

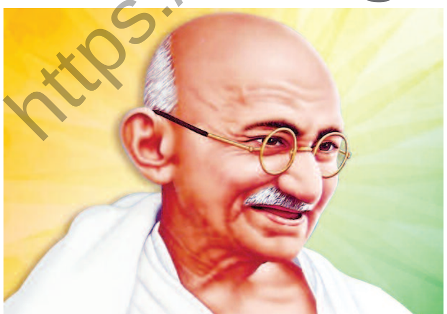

प्रेमकुमार मणि

(लेखक और चिंतक)

इस से शायद ही कोई असहमत होगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय और बहुत कुछ विश्व जनमन को प्रभावित किया। भारत के निपट गांव से लेकर बकिंघम पैलेस तक उनकी चर्चा होती थी। सम्मानजनक ढंग से होती थी। भारत में ब्रिटिश राज के आखिरी वायसराय लार्ड माउंटबेटन की छोटी बेटी पामेला की डायरी को उनकी बेटी इंडिया हिक्स ने संपादित किया है। पामेला जब पिता के साथ भारत आई थी तब अठारह वर्ष की थी। सब जानते हैं माउंटबेटन का वायसराय काल भारत में राजनीतिक घटनाक्रम से घनीभूत था। कहावत है बच्चे बेहतर गवाह होते हैं। पामेला की डायरी से उस दौर की बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। उसी से हमें गांधी के व्यक्तित्व की कुछ झलकियां भी मिलती हैं। पामेला बताती हैं वायसराय हाउस के कर्मचारी और अनुसेवक उन्हें भगवान मानते थे। दिन-रात उनकी चर्चा होती थी। वह किंवदंती पुरुष थे।

यह स्थिति केवल वायसराय हाउस की नहीं थी। दुनिया के बहुत सारे लोग उन्हें ऐसा मानते थे। उनकी हत्या के बाद वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जब यह कहा कि आने वाली नस्लों को शायद ही यकीन हो कि हाड़-मांस का ऐसा पुतला भी कभी इस दुनिया में था। यह अलग बात है कि उस दौर में भी उन्हें सिर-फिरा मानने वाले कम नहीं थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और टोरी नेता चर्चिल और सावरकर जैसे लोग उन्हें सिर-फिरा ही समझते थे। नाथूराम गोडसे को लगा कि यह गांधी देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए उस ने उन्हें गोली मार देना मुनासिब समझा।

गांधी को अनेक लोगों ने अपनी तरह से देखा समझा। जवाहरलाल के देखने का नजरिया अपना था, सुभाष का अपना। आंबेडकर उन्हें आधा संत और आधा राजनेता मानते थे और उनकी आकांक्षा थी कि गांधी पूरे संत क्यों नहीं हो रहे। वह उन्हें कबीर और फुले की तरह सत्यरूप देखना चाहते थे। सुभाष चाहते थे कि वह संतत्व का लबादा त्याग दें और पूरी तरह राजनीतिक हो जायें। जवाहरलाल उन्हें वैज्ञानिक नजरिए के साथ देखने के आकांक्षी थे और देश के आमजन जो किसान थे, उन्हें लगता था कि गांधी बिलकुल उनकी ही तरह धैर्यवान हैं। बहुत कुछ नियतिवादी। फसल सूख जाएगी या डूब जाएगी इसकी चिंता किए बगैर चुप-चाप खेती करते रहना है। हम परिणाम की चिंता किए बगैर अनासक्त भाव से काम करते हैं। किसानों को लगता था हम जिस भाव से खेती करते हैं गांधी उसी भाव से राजनीति करते हैं। राजनीति उनके लिए देश समाज की सेवा है।

गांधी की दृष्टि किसान दृष्टि थी। 1909 में उनकी एक छोटी-सी किताब छपती है ' हिन्द स्वराज. ' उस में वह इटली का उदाहरण रखते हैं। कहते हैं इटली में मेजिनी और गैरीबाल्डी के नजरिए में भेद है। गैरीबाल्डी के लिए इटली का अर्थ है वहां का राजा और उसके दरबारी और मेजिनी के लिए इटली का अर्थ है वहां के किसान। गांधी ने मेजिनी के नजरिए को अपनाया। उनके लिए भारत का मतलब था यहाँ के किसान। किसानों की दृष्टि उनकी ही वेश-भूषा और उनकी ही सादगी। इससे सभ्यता को कोई खतरा नहीं होगा। यूरोप में मशीनी विकास की बुराइयों से वह परिचित थे. उनसे कुछ पूर्व कार्ल मार्क्स ने औद्योगिकीकरण से निकले नए वर्ग मजदूर वर्ग को केंद्र में रख कर एक विचार-सरणी तैयार की थी। गांधी किसानों को केंद्र में रख कर एक विचार गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किसानों में धार्मिकता गहरी थी। उन्हें विश्वास में लेकर उन्हें राजनीतिक बनाना था। किसानों के बिना लोकतंत्र की कोई संभावना नहीं हो सकती। वह जानते थे कि ये किसान ही सच्चे धार्मिक हैं और इनका धर्म नफरत की बुनियाद पर नहीं है।

वह यह भी जानते थे कि भारत को किस दिशा में जाना है या जाना चाहिए। विज्ञान और वैज्ञानिक नजरिए से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि मशीनों से उनकी इतनी ही शिकायत थी कि मनुष्य उनके गुलाम न हो जाएं। मनुष्य की आजादी के महत्त्व को वह समझते थे। आज कृत्रिम बौद्धिकता के जमाने में हम मनुष्य की इसी आजादी की चिन्ता कर रहे हैं। गांधी समझते कि उनका रास्ता न सुभाष का है, न पटेल का। वह समझते थे कि मुझे कोई समझ सकता है तो जवाहर है। इसीलिए उन्होंने जवाहरलाल को अपना वैचारिक उत्तराधिकारी घोषित किया। कृष्ण की तरह वह भीड़ की भाषा नहीं, धर्म (विचार) की भाषा समझते थे। जहाँ धर्म है, विचार है, वहाँ जीत होगी। जीत अक्षौहिणी सेना नहीं, सद्विचार तय करेंगे।

लोगों को समझने में कठिनाई होती है कि जिस जवाहरलाल ने अनेक स्थलों पर गांधी के विचारों की खुली आलोचना की है वह गांधी विचार-परंपरा के वाहक कैसे हो सकते हैं। ऐसे लोग परंपरा और परिपाटी के अंतर को नहीं समझते। वह यह भी नहीं जानते कि वेदांत (वेदों का अंत) ही वैदिक परंपरा का विकास है। पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु का विकास है। अच्छा पुत्र और शिष्य पिता और गुरु की मान्यताओं को माथे पर ढोने वाला नहीं, उंनका परिमार्जन करने वाला होता है। न्यूटन का विकास आइंस्टीन होगा, जो उनकी कुछ मान्यताओं को खारिज भी करता है। विकास हमेशा नवीनता यानी प्रणवता की ओर होता है. पीछे की दिशा में विकास प्रेत विकास होगा. कुछ लोग गांधी के जमाने में जमे रहने को गांधीवाद मानते हैं। लकीर के फकीर हर जगह होते हैं। गांधी की दुकान खोले और उनके हिन्द स्वराज को डफली बनाए लोग गांधीवाद के हरकीर्तन गाते हर जगह मिल जाएंगे। इन लोगों के निहितार्थ को समझना मुश्किल नहीं है।

जून 1905 में गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। उनका उद्देश्य था राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित लोगों की एक ऐसी टीम बनाना जो संवैधानिक तरीकों से जनता की आवाज बन सके और जो उन्हें प्रबुद्ध बना सके। इसका उद्देश्य जाति और मजहब से उठ कर एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो आधुनिक और दूरदर्शी हो।

गोखले के गुरु महादेव गोविन्द रानाडे थे, जिन्होंने 1867 में बंगाल के ब्रह्म समाज की तरह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 1873 में जोतिबा फुले ने इस से दो कदम आगे बढ़ कर सत्यशोधक समाज बनाया। हिन्दी भारत में 1875 में दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना की थी। हम देखेंगे कि गोखले की संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन सब का विकास और एकीकृत रूप था। यह भारत की पहली स्वयंसेवी संस्था

वह यह भी जानते थे कि भारत को किस दिशा में जाना है या जाना चाहिए। विज्ञान और वैज्ञानिक नजरिए से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि मशीनों से उनकी इतनी ही शिकायत थी कि मनुष्य उनके गुलाम न हो जाएं। मनुष्य की आजादी के महत्त्व को वह समझते थे। आज कृत्रिम बौद्धिकता के जमाने में हम मनुष्य की इसी आजादी की चिन्ता कर रहे हैं। गांधी समझते कि उनका रास्ता न सुभाष का है, न पटेल का। वह समझते थे कि मुझे कोई समझ सकता है तो जवाहर है। इसीलिए उन्होंने जवाहरलाल को अपना वैचारिक उत्तराधिकारी घोषित किया। कृष्ण की तरह वह भीड़ की भाषा नहीं, धर्म (विचार) की भाषा समझते थे। जहाँ धर्म है, विचार है, वहाँ जीत होगी। जीत अक्षौहिणी सेना नहीं, सद्विचार तय करेंगे। लोगों को समझने में कठिनाई होती है कि जिस जवाहरलाल ने अनेक स्थलों पर गांधी के विचारों की खुली आलोचना की है वह गांधी विचार-परंपरा के वाहक कैसे हो सकते हैं। ऐसे लोग परंपरा और परिपाटी के अंतर को नहीं समझते। वह यह भी नहीं जानते कि वेदांत (वेदों का अंत) ही वैदिक परंपरा का विकास है। पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु का विकास है। अच्छा पुत्र और शिष्य पिता और गुरु की मान्यताओं को माथे पर ढोने वाला नहीं, उंनका परिमार्जन करने वाला होता है। न्यूटन का विकास आइंस्टीन होगा, जो उनकी कुछ मान्यताओं को खारिज भी करता है। विकास हमेशा नवीनता यानी प्रणवता की ओर होता है. पीछे की दिशा में विकास प्रेत विकास होगा. कुछ लोग गांधी के जमाने में जमे रहने को गांधीवाद मानते हैं। लकीर के फकीर हर जगह होते हैं। गांधी की दुकान खोले और उनके हिन्द स्वराज को डफली बनाए लोग गांधीवाद के हरकीर्तन गाते हर जगह मिल जाएंगे। इन लोगों के निहितार्थ को समझना मुश्किल नहीं है। जून 1905 में गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। उनका उद्देश्य था राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित लोगों की एक ऐसी टीम बनाना जो संवैधानिक तरीकों से जनता की आवाज बन सके और जो उन्हें प्रबुद्ध बना सके। इसका उद्देश्य जाति और मजहब से उठ कर एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो आधुनिक और दूरदर्शी हो।

थी जो अपनी प्रकृति में सेकुलर और राजनीतिक थी। जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से आजादी के बाद इसे भारत सेवक समाज के रूप में संगठित किया गया। किन्तु जल्दी ही यह महत्वाकांक्षियों और पाखंडियों की जमात में परिवर्तित हो गया। आज बीएसएस के पतन और आरएसएस के उत्थान पर सोचने का दिन होना चाहिए। दही की दूकान क्यों बंद हुई और शराब की दूकान भीड़ से क्यों भर गई ? इस पर सोचने का दिन आज होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –**वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

वैश्विक रैंकिंग फार्मूले में बदलाव की सार्थक पहल

अलग-अलग क्षेत्रों को लेकर जारी होने वाली दुनिया के देशों की रैंकिंग को उनकी तरक्की और क्षेत्र विशेष में प्रदर्शन को मापने का जरिया माना जाता रहा है। प्रति वर्ष कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां विभिन्न मापदंडों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी रैंकिंग रिपोर्ट जारी करती है। ये आरोप भी लगते आए हैं कि रैंकिंग फार्मूला ऐसे एकतरफा दृष्टिकोण से लागू किए जाते हैं जिसमें कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की जाती है। ऐसी ही शंकाओं के बीच भारत ने अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (आइआइएएस) के अध्यक्ष के रूप में नया इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा है।

सवाल सिर्फ गवर्नेंस इंडेक्स का ही नहीं है। भारत की यह चिंता उन तमाम दूसरे वैश्विक सूचकांकों से भी जुड़ी है जिनके आधार पर भारत व अन्य देशों की छवि धूमिल करने के प्रयास होते रहे हैं। न केवल भारत बल्कि दूसरे कई देशों का भी यही मन्तव्य रहता आया है कि अलग-अलग आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक व राजनीतिक संरचना वाले देशों को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। आरोप तो ये भी लगते आए हैं कि इस तरह की रैंकिंग तैयार करने में विकसित कहे जाने वाले देशों का स्वार्थ भी होता है। यह बात भी सामने आती रही है कि वैश्विक सूचकांक कई उपसूचकांकों के आधार पर तैयार होते हैं जिनमें अधिकांश कुछ विशेषज्ञ संस्थानों की व्यक्तिगत राय पर आधारित होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सदैव सवाल उठते आए हैं। रैंकिंग के घालमेल को पिछले मार्च में ही जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग से ही आसानी से समझा जा सकता है। इस रैंकिंग में दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में भारत को भुखमरी व राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पड़ोसी देश नेपाल व पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया। इससे पहले वर्ष 2022 में हंगर इंडेक्स में भी भारत को 107वें स्थान पर रखा गया तो भारत सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। यह भी एक तथ्य है कि आगामी वर्षों में विकसित देशों में शामिल होने जा रहे भारत की छवि को कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें वैश्विक सूचकांकों के जरिए धूमिल करने के प्रयासों में जुटी हुई हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में खुशी के मानक निर्धारित करने के जो पैमाने तय किए जाते हैं उनकी तार्किकता व विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

भारत यह कहता आया है कि खास तौर से विकासशील देशों के लिए वैश्विक रैंकिंग तय करने का फार्मूला उनकी विशेष परिस्थितियों व तरक्की की रफ्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नया इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स बनाने का भारत का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। ऐसे प्रयासों को वैश्विक मान्यता मिले, ये प्रयास भी जरूरी हैं। इतना ही नहीं, सभी क्षेत्रों में वैश्विक रैंकिंग का फार्मूला तय करने के लिए भी इस तरह की पहल होनी चाहिए।

भू-राजनीति : पुतिन का बयान भारत के प्रति विश्वास और निर्भरता का सूचक, भारतीय आत्मसम्मान का भी आदर

भारत-रूस संबंध : रणनीतिक भरोसे की मिसाल

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

रूस जानता है कि भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ खड़ा है, न ही किसी और गुट का अंग। यह एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभरता राष्ट्र है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव बन सकता है। पुतिन का बयान भारत के व्यापारिक रुख की सराहना तथा पश्चिमी 'दबाव-नीति' की आलोचना है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच रूस की रणनीतिक दिशा का संकेत है। वर्तमान विश्व व्यवस्था, जहां अमरीका-चीन प्रतिद्वंद्विता, यूरोप की ऊर्जा असुरक्षा और पश्चिमी प्रतिबंधों की नीति तीव्र चरम पर हैं, वहां पुतिन का यह वक्तव्य भारत के प्रति रूस के विश्वास और निर्भरता का सूचक बनता है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस लगातार पश्चिम के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करता रहा, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इन संबंधों की अंतिम कड़ी भी तोड़ दी। नाटो के विस्तार और यूरोपीय संघ की कठोर नीतियों ने रूस को विवश किया है कि वह एशिया की ओर नए साझेदारी मार्ग खोजे। इसी संदर्भ में भारत उसकी 'पूर्वमुखी नीति' का केंद्रीय स्तंभ बन गया है। भारत के साथ रूस के संबंध न केवल रक्षा सहयोग पर टिके हैं, बल्कि ऊर्जा, दवा उद्योग, अंतरिक्ष और परमाणु तकनीक तक विस्तारित हैं। पुतिन का यह बयान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मान्यता देने वाला है। रूस जानता है कि भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ खड़ा है, न ही किसी और गुट का अंग। यह एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभरता राष्ट्र है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव बन सकता है। पुतिन ने जब कहा कि भारत 'शुद्ध आर्थिक गणना' के आधार पर निर्णय लेता है, तो यह न केवल भारत के व्यापारिक रुख की सराहना थी, बल्कि पश्चिमी 'दबाव-नीति' की आलोचना भी। पुतिन का यह कथन कि 'भारत का नागरिक किसी के आगे झुकने की कल्पना नहीं करेगा', भारतीय सभ्यता और आत्मसम्मान के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है।

रूस अब केवल तेल और गैस निर्यातक के रूप में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह भारत के साथ संतुलित व पारस्परिक व्यापार चाहता है। वर्तमान व्यापार असंतुलन में भारत का झुकाव ऊर्जा आयात की ओर अधिक है। साथ ही, दोनों देशों के बीच रुपया-रूबल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं ताकि पश्चिमी स्विफ्ट जैसी प्रणालियों पर निर्भरता घटाई जा सके। यह आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो भारत की 'वित्तीय स्वायत्तता' को भी मजबूती देता है। अमरीका और यूरोपीय देशों ने रूस के राजस्व स्रोतों को सीमित करने के लिए कई आर्थिक दंडात्मक नीतियां अपनाई हैं। हाल में ट्रंप का यह बयान कि 'भारत और चीन यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित कर रहे हैं' रूस को चेतावनी और भारत के प्रति गुस्सा जाहिर करना है। इस तरह के वक्तव्य पश्चिम की उस रणनीति को उजागर करते हैं, जो विकासशील देशों को अपने पक्ष में झुकाने का प्रयास करती है। पुतिन की वास्तविक चिंता यह है कि कहीं यह आर्थिक या कूटनीतिक दबाव भारत को पश्चिम के अधिक निकट न ले जाए। रूस जानता है कि भारत उसकी 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' का सबसे अहम स्तंभ है। यदि भारत इस संतुलन से हटता है, तो रूस की एशियाई नीति कमजोर हो जाएगी। इसी कारण पुतिन बार-बार भारत की प्रशंसा करते हैं, ताकि यह दोस्ती केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक आधार पर भी मजबूत बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में रणनीतिक स्वायत्तता को विदेश नीति का मूल सिद्धांत बनाया है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी और भू-राजनीतिक विश्वसनीयता तीनों अनिवार्य हैं और रूस इन तीनों क्षेत्रों में प्रमुख सहयोगी रहा है।

मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत भी रूस की भागीदारी बढ़ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई विमान अपग्रेड और न्यूक्लियर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में दोनों देशों की साझेदारी भारत की रक्षा स्वावलंबन में निर्णायक भूमिका निभा रही है। इसी सहयोग को पुतिन 'विवेकशील और राष्ट्रोन्मुख नेतृत्व' की दृष्टि से देखते हैं। पुतिन की प्रशंसा को केवल कूटनीतिक बयान कहना उसके आशय को कम करना होगा। दरअसल पश्चिमी आलोचना के बीच भारत की प्रशंसा दर्शाती है कि रूस आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक साझेदारी का आधारस्तंभ मानता है। निःसंदेह, रूस आज चीन के साथ समीकरणों को सशक्त कर रहा है, परंतु पुतिन यह भी जानते हैं कि किसी एक महाशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता, विशेषकर विस्तारवादी प्रवृत्ति वाले चीन पर, दीर्घकालिक दृष्टि से संकटपूर्ण हो सकती है। इसीलिए भारत के साथ संतुलित और बहुआयामी साझेदारी केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि रूस की रणनीतिक अपरिहार्यता है। भारत की लोकतांत्रिक चेतना, बढ़ता बाजार और वैश्विक विश्वसनीयता जैसे तत्त्वों ने उसे रूस के लिए एक स्थायी, विश्वसनीय और विवेकशील सहयोगी बना दिया है।

पुतिन का मोदी पर वक्तव्य रूस की भू-राजनीतिक विवशता, रणनीतिक जरूरतों और भावनात्मक कूटनीति की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। इसमें संकेत हैं कि आने वाला दशक एशिया केन्द्रित शक्ति-संतुलन का होगा, जिसमें भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारत के लिए यह सम्मान और जिम्मेदारी का क्षण है। पुतिन की बातें केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि यह संदेश हैं कि वर्तमान विश्व राजनीति की विभाजित परिस्थितियों में भी भारत-रूस के भरोसे का रिश्ता दशकों पुराना और अटूट बना हुआ है।

फैक्ट फ्रंट

ब्लू लोटस

ब्लू लोटस एक ऐसा फूल है, जो न केवल अपनी सुंदरता से बल्कि गुणों से भी आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। प्राचीन मिस्र में इसे 'आत्मा को जाग्रत करने वाला फूल' माना जाता था। यह नीला कमल जल पर तैरता हुआ सूर्य की लय में सांस लेता है और सूर्योदय के साथ खिलता और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। इस गुण ने इसे प्रकृति की जीवंत घड़ी बनाया है। ब्लू लोटस में प्राकृतिक रासायनिक तत्त्व होते हैं, जो मन को शांत और एकाग्र करते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि इसके अर्क में न्यूरो-कैल्मिंग यौगिक होते हैं जो तनाव, चिंता व अनिद्रा में राहत देते हैं। यह फूल केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह अपने आसपास के पानी से हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को सोखकर जल को शुद्ध करता है, जिससे यह प्राकृतिक शोधक कहलाता है। ब्लू लोटस आज भी हर्बल चाय और अरोमाथेरेपी में उपयोग होता है। प्राचीन मिस्र में ब्लू लोटस को सूर्य देवता 'रा' और सृजन से जोड़ा जाता था। इसे मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था।

चिकित्सा

कफ सिरप से दवा सुरक्षा पर सवाल

किसी दवा के लेने से तबीयत बिगड़ गई, किसी इंजेक्शन को लगाने से मौत हो गई... इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं। हाल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी कफ सिरप के चलते लोगों की तबीयत खराब होने एवं कुछ बच्चों की मृत्यु की खबरें भी सामने आई हैं। दवाओं के दुष्प्रभावों को लेकर ज्यादातर लोगों में यह धारणा होती है कि दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव किसी स्वास्थ्य सेवाप्रदाता की ओर से गलत दवा या गलत खुराक लिखे जाने के कारण होते हैं जबकि वास्तविकता इससे परे भी हो सकती है। दवाओं के दुष्प्रभाव की समस्या वर्तमान में इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनके कारणों को जानना बहुत जरूरी है एवं बिना फार्माकोडायनामिक्स का जिक्र करे इन कारणों को जानना अधूरा-सा है, जिसका सीधा सा अर्थ है 'कोई भी दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है'। किसी भी दवा की क्रिया अथवा प्रतिक्रिया मरीज के शरीर, उम्र, लिंग, जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। हर दवा की खुराक उम्र के अनुसार बदलती है और कुछ दवाएं तो बच्चों को दी ही नहीं जा सकती है। इसी प्रकार दवा देने का समय, दवा देने का रूट (मुंह से, जीभ के नीचे, मलद्वार त्वचा द्वारा, नाक से सूंघ कर या इंजेक्शन द्वारा) शरीर में पहले से कोई बीमारी होना (लीवर या किडनी संबंधी बीमारी) भी दवा की क्रिया-प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। इन सभी घटकों में जरा से बदलाव पर भी दवाओं के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते है। दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों का एक प्रमुख कारण दवाओं का दूषित होना भी हो सकता है, जो दवा बनने के जीवन चक्र के किसी भी चरण में यानी कि निर्माण से लेकर भंडारण और परिवहन के दौरान कभी भी हो सकता है।

डॉ. पंकज जैन
वरिष्ठ चिकित्सक
@patrika.com

दवाओं का संदूषण भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्मजीवी स्तर पर कहीं भी हो सकता है और इसके अनेकानेक स्रोत हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उपरोक्त परिस्थितियों से निपटा नहीं जा सके। आवश्यकता है तो बस बहुस्तरीय संदूषण रोकथाम रणनीति की। दवा संदूषण रोकने के लिए उत्पादन के सभी चरणों में मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियां विकसित की जाए। कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों को सख्त परीक्षण से गुजारा जाए। दवा निर्माण के उपकरणों के लिए सफाई प्रोटोकॉल और सत्यापन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन हो। उत्पादों के साथ कम से कम मानवीय संपर्क हो एवं कर्मचारियों का हाइजीन संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्य हो। इसके साथ ही आमजन भी कोई दवा चिकित्सक की सलाह के बिना न लें। दवाओं का सेवन विशेषज्ञ के परामर्श पर, पूरी अवधि व खुराक के अनुरूप ही किया जाए।

अद्भुत शिल्प : बागवानी के साधारण औजार से जन्मा कला का रूप

यह फोटो रूस के मास्को में जीईएस-2 हाउस ऑफ कल्चर के बाहर ली गई है, जिसमें लोग प्लांटॉयर के पास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लांटॉयर अमरीकी कलाकारों, क्लेस ओल्डेनबर्ग और कूस्जी वैन ब्रुगेन की ओर से बनाया गया एक विशाल गार्डन ट्रॉवेल (बागवानी का टूल) का शिल्प है। जीईएस-2 हाउस ऑफ कल्चर, जो एक पूर्व पावर स्टेशन को सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करके बनाया गया है, अब मास्को के कला और सांस्कृतिक जीवन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्लांटॉयर की विशालता और आकार न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि यह कला के प्रति अनुभव को चुनौती देता है। इसमें कलाकारों ने सामान्य जीवन के तत्त्व को कला में रूपांतरित किया है।

नेतृत्व

नैतिकता : विचार, वचन और आचरण का मिश्रण

लीडर केवल निर्णय नहीं लेते, बल्कि वे संस्कृति भी रचते हैं

आज के समय में जहां गति, प्रदर्शन और आकर्षण को ही सफलता का माप माना जाता है, वहां नैतिकता वह शांत व महत्त्वपूर्ण आधार है जिस पर सच्चा नेतृत्व निर्मित होता है। नैतिकता केवल सत्य बोलना नहीं, बल्कि विचार, वचन और आचरण का मिश्रण है, जो स्वयं में ईमानदार और दूसरों के लिए विश्वासयोग्य होने की प्रेरणा देती है।

नैतिकता का अर्थ: भीतर-बाहर की एकरूपता- नैतिक लीडर निजी मूल्य और सार्वजनिक निर्णयों में भेद नहीं रखते। वे दोहरा व्यक्तित्व नहीं जीते और जो सोचते हैं, वही कहते हैं व उसी के अनुरूप काम करते हैं।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

विश्वास ही नेतृत्व की वास्तविक पूंजी- नेतृत्व केवल निर्देश देना या प्रभुत्व नहीं है, बल्कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। सभी अधीनस्थ किसी पद या कौशल के नहीं, चरित्र और भरोसे के अनुसरण में चलते हैं।

'ना' कहने की नैतिक दृढ़ता- सही कार्य करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है गलत को अस्वीकार करने का साहस। नेतृत्व निरंतर परीक्षा देता है - लाभ का दबाव, पद का आकर्षण, स्वार्थ की चुनौती- ये सभी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।

नेतृत्व से बनता है चरित्र का वातावरण- लीडर केवल निर्णय नहीं लेते, वे संस्कृति रचते हैं। उनका आचरण ही संगठन का चरित्र बनाता है। यदि लीडर अपने वचनों पर स्वयं खरे उतरते हैं, तो अन्य लोगों का भी आचरण स्वतः उसी दिशा में विकसित होता है।

नैतिकता मूल्य भी मांगती है- कभी-कभी नैतिकता का पालन सरल नहीं होता। कई बार कोई अवसर का त्याग करना पड़ता है, कोई संबंध टूट सकता है क्योंकि आप समझौता नहीं करते। नैतिक लीडर भले ही हर बार विजेता न प्रतीत हों, परंतु वे हर परिस्थिति में स्वाभिमान और निडरता से अडिग बने रहते हैं और यही उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रतिबंध से राहत विदेशी जुए पर रोक लगाने के लिए भी राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाए

रियल मनी गेमिंग : एक लत पर सही समय पर प्रहार

रियल मनी गेमिंग पर नए कानून के तहत लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध एक सही और समय पर लिया गया कदम है। हालांकि इस रोक के बाद कई तरह की दलीलें सामने आईं। कहा गया कि इससे एक उभरता उद्योग खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा और यह भी कि कौशल वाले खेलों को भाग्य पर आधारित खेलों से अलग मानना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों साधारण भारतीय पहले ही इसके जाल में फंस चुके थे। चमकदार विज्ञापनों ने उन्हें घर-घर तक लुभाया, उनकी जेब तक घुसपैठ की और आखिर में उन्हें ऐसे सौदे में धकेल दिया, जिसमें सिर्फ नुकसान ही था। इन झूठे और भ्रामक वादों के भरोसे लोगों ने पैसा और भविष्य दोनों दांव पर लगा दिया।

विज्ञापनों का असर इतना गहरा था कि वे स्थानीय भाषाओं में भी गांव-गांव तक पहुंच गए। यहां तक कि गृहिणियों को 'रम्मी' खेलने का न्योता दिया गया। उन्हें घर बैठे कमाई का सपना दिखाकर नकद इनाम और बोनस का लालच दिया गया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि नामी-गिरामी सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल इन खेलों को बढ़ावा देने में करने लगे। कंपनियों की आधुनिक और ताकतवर मार्केटिंग ने साधारण मनोरंजन को एक खतरनाक लत और विनाशकारी गतिविधि में बदलने की पूरी कोशिश की। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 लागू होने से अब यह सब थम चुका है।

इस कानून के बाद ज्यादातर बड़ी गेमिंग कंपनियों ने अपनी रियल मनी गेमिंग सेवाएं बंद कर दीं, लेकिन साथ ही अदालत भी चले गए हैं। उनका कहना है कि यह कानून व्यवसाय करने की मौलिक आजादी के खिलाफ है, इससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और इसमें कौशल आधारित व भाग्य आधारित खेलों के बीच फर्क नहीं किया गया। फिलहाल अलग-अलग उच्च न्यायालयों में दाखिल हुई याचिकाओं को मिलाकर अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। भारत की कानूनी व्यवस्था हमेशा स्पष्ट रही है। कानून लागू होने के बाद कंपनियों ने भले ही यह गेमिंग बंद कर दी हो, लेकिन विदेशी प्लेटफॉर्म अब भी खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए यह क्षेत्र, जो पिछले बीस सालों से चुपचाप चल रहा था, अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2020 में 36 करोड़ से बढ़कर 2024 में अनुमानतः 50 करोड़ से ऊपर हो गई। प्रतिबंध लगने के बाद इस लत के शिकार कई खिलाड़ी अब असुरक्षित विदेशी जुए की ओर रुख कर रहे हैं। कंपनियों के गेम बंद करने के बाद अब अवैध विदेशी प्लेटफॉर्म, मटका नेटवर्क और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर सक्रिय हो गए हैं। इनमें न सुरक्षा है, न उपभोक्ता संरक्षण और न ही कराधान। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने मांग की है कि विदेशी जुए पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाए। वर्षों से यह एक नशे से भरी दुनिया रही है- घूमते पहियों, ताश के पत्तों और पासे के साथ करोड़ों जीतने के वादे किए जाते रहे हैं। 'इंस्टेंट विन' और 'नो पे' जैसे शब्दों ने लोगों को आकर्षित किया। मनोचिकित्सकों और हेल्पलाइंस पर 40 साल से कम उम्र के नौकरीपेशा, व्यापारी या छात्रों से बड़ी संख्या में कॉल्स आ रही हैं। शुरू में छोटी जीत से बड़े लालच जगते हैं और अंत में खिलाड़ी भारी नुकसान झेलते हैं। 1लाइफ नामक आत्महत्या-निवारण हेल्पलाइन के अनुसार वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों की कॉल्स में से 60 प्रतिशत कॉल ऑनलाइन बेटिंग में नुकसान उठाने वालों की थी। ये आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन आश्चर्यपूर्ण नहीं।

लेखा रत्तनानी
वरिष्ठ पत्रकार
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

राज्यसभा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अनुमानतः 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया। साधारण नागरिकों की सुरक्षा और विज्ञापनों पर नियंत्रण आवश्यक था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूरी था और यह तेज व निर्णायक ढंग से किया गया।

आपकी बात

स्वास्थ्य ही असली सम्पत्ति

स्वस्थ शरीर के बिना जीवन में सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। चाहे धन-दौलत बहुत हो, रोग लगने पर वह सब व्यर्थ प्रतीत होता है। इसलिए भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। **- प्रियव्रत चारण,** जोधपुर

गांवों में प्रदूषण चिंता का विषय

सरकार को केवल शहरों के प्रदूषण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से देखना आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण बहुत अधिक होता है, जिससे लोग दमा और अस्थमा जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। **- अजीतसिंह सिसोदिया,** बीकानेर

उच्च शिक्षा में सुधार होना जरूरी

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को एप विकसित करना चाहिए जिसमें महत्त्वपूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो। फीस में कमी, गरीब विद्यार्थियों के लिए योजना, कौशल प्रशिक्षण, ई-शिक्षा और ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। **- आलोक वालिम्बे,** बिलासपुर

आज का सवाल
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?
ईमेल करें: edit@epatrika.com

संघ शताब्दी वर्ष संघ का आरंभ पुस्तकालयों में नहीं, खेल के मैदानों में हुआ, खुद को समाज से पृथक संगठन नहीं माना

नूतन भारत के शक्तिशाली उत्कर्ष का प्रतीक बनेगा संघ

तरुण विजय
पूर्व राज्यसभा सांसद
@patrika.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली ही ऐसी है, जिसमें नवीन रक्त, नवीन प्राण और नवीन चैतन्य की अनिवार्यता निहित है। प्रारंभिक शाखा के खेलों से लेकर कंप्यूटर और नवीनतम बिजनेस मॉडल तक- संघ ने सदैव जोखिम उठाने, नई चुनौतियों का सामना करने और परिणाम की चिंता किए बिना लक्ष्य तक बढ़ने के 'सुप्रीम रिस्क फैक्टर' को अपनाया है।

संघ का प्रादुर्भाव अपने समय की लीक और रूढ़िगत परंपराओं से अलग हटकर हुआ। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार युगदृष्टा थे, जो सौ वर्ष आगे का विचार कर सकते थे। उन्होंने संघ की स्थापना करते समय कभी यज्ञ, हवन या पूजा का उल्लेख नहीं किया। मंदिर में घंटी बजाते या आरती करते उनका कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। वे पक्के सनातनी हिंदू थे, जिन्हें वास्तव में हिंदू धर्म का रक्षक वीर योद्धा कहा जा सकता है। उनके लिए भारत ही सर्वोच्च देवता और संपूर्ण राष्ट्र ही आराध्य मंदिर था। उन्होंने हिंदू संगठन में मिलिट्री अनुशासन का समावेश किया। पथसंचलन की परंपरा प्रारंभ की और प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी में आज्ञाएं देने में भी संकोच नहीं किया।

उनका मानना था कि यदि शरीर कमजोर है तो किसी की रक्षा क्या, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाओगे। यही कारण था कि संघ का आरंभ पुस्तकालयों में नहीं, खेल के मैदानों में हुआ। शाखा में खेले जाने वाले खेल भारतीय परंपरा से जुड़े और शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने वाले थे। प्रतिदिन शाखा में विचार-विमर्श केवल इस बात पर होता कि अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया जाए। राष्ट्र की स्वतंत्रता सर्वोच्च उद्देश्य था और उसके लिए सशक्त शरीर पहली शर्त। आगामी सौ वर्ष संघ के विकास को सीधे-सीधे भारत के उत्कर्ष और शक्ति वर्धन से जोड़ते हैं। संघ ने स्वयं को कभी समाज से पृथक संगठन नहीं माना। वह समाज की प्रगति और समरसता का ही प्रतिबिंब है। आने वाले वर्षों में संघ नूतन भारत के शक्तिशाली उत्कर्ष, सामाजिक समरसता, नारीशक्ति के बहुमुखी विकास और युवा शक्ति के प्रौद्योगिकी प्रभुत्व का प्रतीक बनेगा।

आज सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, नासा जैसी वैश्विक कंपनियों से लेकर बेंगलूरु, हैदराबाद और डीआरडीओ तक शीर्ष हिंदू इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, एआइ विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वे पूरी दुनिया में हिंदुत्व की नई तरंग के प्रतिनिधि हैं। उनके लिए श्रीगणेशाय नमः से कार्यारंभ करना और न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू से लेकर कर्तव्यपथ के डिजिटल नियंत्रण कक्षों तक हिंदू पहचान का गौरव अनुभव करना स्वाभाविक है। इन्हें सबसे अधिक आकृष्ट करता है- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैदिक और सांस्कृतिक स्वरूप। यह हेडगेवार की भारतभक्ति का ही चमत्कार है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, वित्त, कला, वास्तुशिल्प और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले अनेक युवा आज संघ के प्रचारक हैं और स्वयंसेवक के रूप में समाज की सेवा में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।

भविष्य का संघ आधुनिकतम वैश्विक तकनीक का वाहक और सनातन धर्म का रक्षक बनेगा। यह भारत को उस दिशा में ले जाएगा, जहां राष्ट्र एक सशक्त युवा आंदोलन का प्रतीक होगा। इस आंदोलन के युवाओं की पहचान होगी- हिंदू धर्म में अटूट आस्था और सभी समुदायों के प्रति सहचरी भाव। ऐसा भारत संपूर्ण विश्व को सज्जन शक्ति के प्रभाव में लाएगा और पश्चाताप-विहीन दुष्टों का संहार करेगा। यही संघ का परम अभीष्ट है।